दुनिया के सर्वहारा तथा तमाम
मेहनतकश जनता और उत्पीड़ित
राष्ट्रीयताओं की जनता एक हो!

लाल चिनगारी

वर्ष–13 अंक–33 अप्रैल–जून 2017

मुखपत्र

बिहार–झारखण्ड
स्पेशल एरिया कमेटी

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी
(माओवादी)

लाल चिनगारी संपादकमंडल के नाम एक पाठक का खत व उसका जवाब

प्रिय लाल चिनगारी सम्पादकमण्डल

क्रांतिकारी अभिवादन के साथ लाल सलाम!

लाल चिनगारी का एक नियमित पाठक के नाते सहर्ष कहना चाहूंगा कि हाल में लाल चिनगारी सम्पादक मण्डल के तरफ से इआरबी सचिव कामरेड किसान के साथ हुई भेंट-वार्ता का मूल अंश लाल चिनगारी के अंक 29 में प्रकाशित किया गया। यह मूल अंश पढ़कर निज की समझदारी में निश्चित तौर पर कुछ बढ़ोत्तरी हुई। उम्मीद है कि और-और पाठकों को भी इससे राजनीतिक लाभ अवश्य ही प्राप्त हुआ होगा। हमारे पार्टी कमेटियों, जनमुक्ति छापामार सेना के सभी फार्मेशनों, क्रांतिकारी जनसंगठनों सहित परिवर्तनकारी जनवादी ताकतों व प्रगतिशील तबको के राजनीतिक मान को और उन्नत करने में बहुत ही सहायक सिद्ध हुआ होगा। अत: इस तरह की भेंटवार्ता कर विभिन्न पहलुओं को छुते हुए अर्थात राजनीतिक, सांगठनिक और व्यावहारिक पहलुओं पर भेंटवार्ता हमेशा ही अपने पत्रिका में प्रकाशित करने का सिलसिला जारी किया जाए। अब लाल चिनगारी की छपाई में हुई कुछ अशुद्धियों के बारे में- वर्ष 12 अंक 29 अप्रैल-जून 2016 के पृष्ठ 8 में का0 गाजो हांसदा उर्फ पंकज हांसदा का शहादत तिथि 17 जून 2016 दर्ज है, वहीं भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की स्थापना की 12वीं वर्षगांठ को क्रांतिकारी जोश-खरोश के साथ मनावें शीर्षक के लेख में लाल चिनगारी के पृष्ठ संख्या 13 में 24 जून 2016 दर्ज है। इस फर्क को दूर किया जाए। 17 जून 2016 सही है। फिर इसी पत्रिका में या मुखपत्र में देशभक्ति या राष्ट्रभक्ति क्या है? ये लेख संख्या 32-33 में छपा है इसका शेष पृष्ठ 40 पर कहा गया है। फिर पृष्ठ 46 में एक बॉक्स में लेख के उपर पृष्ठ संख्या 27 का शेष कहा गया है, जो बताये गए पृष्ठ संख्या के अनुसार फर्क है। फिर, आगे की और एक भूल पर लाल चिनगारी के अंक 30 पर का0 पंकज के फोटो के नीचे 24 जून 2016 को शहादत तिथि अंकित है। इसे भी सुधारा जाए।

क्रांतिकारी अभिवादन के साथ

बंधु

12. 1. 2017

प्रिय कामरेड बंधु

हार्दिक लाल सलाम!

सबसे पहले तो देर से जवाब देने के लिए माफी चाहूंगा। आपने जो इच्छा प्रकट की है कि भेंट वार्त्ता अक्सर प्रकाशित किया जाए, ताकि हमारे कैडरों का राजनीतिक मान उंचा उठे, हम जरूर कोशिश करेंगे कि ऐसी भेंट वार्त्ता आगे भी प्रकाशित हो। साथ ही साथ, आपने जो हमारी गलतियों पर हमारा ध्यान आकृष्ट कराया है, उसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं। साथ ही कहना चाहते हैं कि आपको जो अंक 29 भेजा गया था, गलती से आपको अपूर्ण कॉपी भेज दिया गया था, क्योंकि आपके खत आने के बाद जब हमने मिलान किया तो पाया कि पृष्ठ संख्या वाली गलती नहीं है। हां, अमर शहीद कामरेड पंकज के शहादत तिथि में दोनों जगह फर्क जरूर है, उसे हमने सुधार लिया है।

आपका खत हमारे लिये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप हमें खत लिखकर अपनी मनोभावानाओं से अवगत कराएंगे और हमारी गलतियों की तरफ जरूर ही ध्यान आकृष्ट कराएंगे।

क्रांतिकारी अभिवादन के साथ

संपादकमंडल, लाल चिनगारी

लाल चिनगारी

वर्ष- 13 अंक: 33
अप्रैल - जून 2017

विषय सूचीः

1. सम्पादकीय 1
2. ऐ लाल फरेरे तेरी कसम 10
3. भारत में वसंत का वज्रनाद 14
4. का. सीएम का 8वां दस्तावेज 16
5. गरीब विरोधी बजट 25
6. आर्थिक असमानता 28
7. पीयूडीआर की रिपोर्ट 30
8. कामरेड माओ का लेख 31
9. पीडब्ल्यू का सम्पादकीय 35
10. महिला सवाल- जनयुद्ध-जनमुक्ति 39
11. 8 मार्च की रिपोर्ट 48
12. महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति एक समझदारी 53
13. कविताएं 60
14. पीएलजीए की महत्वपूर्ण कार्रवाइयों की रिपोर्ट 64

सहयोग राशि - 20 रूपये

सम्पादकीय

ऐतिहासिक नक्सलबाड़ी सशस्त्र किसान विद्रोह की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर उस विद्रोह के तात्पर्य व महत्व को कभी न भूलें यानी नक्सलबाड़ी ही जनमुक्ति का एकमात्र सही मार्ग है, इसे भी कभी न भूलें।

(ऐतिहासिक महान नक्सलबाड़ी सशस्त्र किसान विद्रोह की 50वीं वर्षगांठ पर हमारी पार्टी की केन्द्रीय कमेटी की इआरबी सचिव कामरेड किसान के आह्वान के विशेष महत्व को देखते हुए हम इसे इस अंक के संपादकीय के रूप में दे रहे हैं। उम्मीद है सभी पाठकगण ध्यान से इस लेख को पढ़ेंगे और इस आह्वान की रोशनी में नक्सलबाड़ी सशस्त्र किसान विद्रोह की ऐतिहासिक महत्व और वर्त्तमान महत्व को भी समझने की कोशिश करेंगे। - संपादकमंडल, लाल चिनगारी)

हम सच्चे कम्युनिस्टों को मालूम है कि सन् 1967 के मई में बतौर एक वज्रघोष ऐतिहासिक नक्सलबाड़ी सशस्त्र किसान संघर्ष का बिगुल बज उठा था। इसने भारत में दीर्घकाल से चली आ रही कम्युनिस्ट आंदोलन के अंदर जो संशोधनवादी धारा हावी रह रही थी, उसमें गुणात्मक रुप से भिन्न एक प्रक्रिया यानी विच्छेद व छलांग (rupture and leap) की प्रक्रिया के जरिए जबरदस्त चोट पहुंचाया था। जिसके परिणामस्वरुप घोर संशोधनवादी सी.पी.आई. व सी. पी.आई.एम. पार्टी से सच्चे कम्युनिस्ट क्रांतिकारी लोग राजनीतिक-सांगठनिक तौर पर अंतिम रुप से अपना पिंड छुड़ाने में समर्थ हुए थे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खुश्चेव संशोधनवाद के खिलाफ कामरेड माओ के नेतृत्व में जो महान बहस की शुरुआत हुई थी, जिसमें यह मुद्दा कि संशोधनवाद बनाम सशस्त्र संग्राम का जो विचारधारात्मक-राजनीतिक-सैद्धांतिक बहस व वितर्क चला, उसमें महान माओ के नेतृत्वाधीन तत्कालीन चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) के सशस्त्र संग्राम के मत को ही नक्सलबाड़ी संघर्ष ने और जोरदार ढंग से बुलंद किया।

नक्सलबाड़ी किसान विद्रोह का तात्पर्य क्यों ऐतिहासिक व निर्णायक है?

इस विषय से जुड़े हुए कई मूल बिंदुओं पर सच्चे कम्युनिस्टों को अवश्य-ही गहराई से सोचना होगा और एक सही समझदारी हासिल करनी होगी। वे बिंदुएं हैं:

I. सन् 1921 में देश के बाहर और 1925 में देश के अंदर गठित भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) के नेतृत्व के प्रभावशाली अंश के द्वारा शुरु से ही भारत की जनता की मुक्ति की सही राजनीतिक-सांगठनिक-सामरिक लाइन का तय नहीं कर पाना, चीनी क्रांति का सफल मार्ग यानी सशस्त्र

कृषि-क्रांति तथा दीर्घकालीन लोकयुद्ध के मार्ग को भारत की विशेषता की पृष्ठभूमि में अपनाने में अक्षम रह जाना इत्यादि मूल कमजोरी बार-बार दिखाई पड़ी, इसे भलीभांति याद रखना होगा व ध्यान में रखना होगा। कभी दक्षिणपंथी तो कभी 'वाम' भटकाव का रुझान अविभाजित पार्टी में हावी रहा। मसलन, कभी डांगे व अजय घोष के घोर दक्षिणपंथी-संशोध नवादी लाइन तो कभी विपरीत में बी.टी. रणदिवे की 'वाम' भटकाववादी लाइन पार्टी में हावी रही। फिर, 1964 में अविभाजित भारत की कम्युनिस्ट पार्टी यानी सी.पी.आई. जब विभाजित होकर सी.पी.आई.एम. बनी, तब भी हकीकत में दोनों पार्टी के नेतृत्व के स्तर में संशोधनवादी-सुधारवादी लाइन ही हावी रही और व्यावहारिक तौर पर संसदीय रास्ते का पैरोकार बनकर मौजूदा धोखाधड़ीपूर्ण चुनावी व्यवस्था के अंदर वोट के खेल में पूरी तरह डुबे रहने की कार्यशैली व कार्यवाही ही हावी रही। उक्त दोनों पार्टी के सर्वोच्च स्तर पर चुनाव में हिस्सा लेने की लाइन, जो सामान्यत: मार्क्सवादी-लेनिनवादी नीति का एक कार्यनीतिक दृष्टिकोण ही था, उससे पूरी तरह विपरीत दिशा में कलाबाजी खाकर घोर संशोधनवादी व कम्युनिस्ट आंदोलन में विभाजन लाने वाला गद्दार ख्रुश्चेव की 'शांतिपूर्ण रास्ते से समाजवाद में संक्रमण' की लाइन के पैरोकार बनकर रणनीतिक (Strategical) दृष्टिकोण के तहत ही हर प्रकार की कार्यवाही लेने की लाइन हावी हो गयी और सशस्त्र क्रांति की बात को सम्पूर्ण रुप से त्यागते हुए कामरेड लेनिन की भाषा में 'सुअरबाड़े' यानी विधानसभा, लोकसभा व पंचायत चुनाव के जरिए कुर्सी दखल के खेल में हिस्सा लेने का काम ही एकमात्र काम बना रहा। ठीक इसी समय में, यानी सी.पी.आई. से विभाजित होकर सी.पी.आई.एम. बनने के समय से ही सी.पी.आई.एम. पार्टी की चरम दक्षिणपंथी-संशोधनवादी लाइन व कार्यवाही के खिलाफ पश्चिम बंग सहित विभिन्न प्रांतों में पार्टी के अंदर रहकर ही तीखा सैद्धांतिक-राजनीतिक संघर्ष चलाने की जरूरत महसूस हुई। फलस्वरूप, भारत के विभिन्न स्थानों में पार्टी के अंदर ही आंतरिक बहस चलाने के लिए कई ग्रुपों का उदय हुआ। जैसे कि पश्चिम बंग के दार्जीलिंग जिला में कामरेड चारू मजुमदार के नेतृत्व में और कामरेड चारू मजुमदार द्वारा फरवरी, 1965 से लिखित ऐतिहासिक आठ दस्तावेजों की श्रृंखला (पहला दस्तावेज फरवरी 1965 में लिखा गया था और आखिरी आठवां दस्तावेज अप्रैल, 1967 में लिखा गया) पर आधारित होकर संशोधनवाद विरोधी तीखा संघर्ष का प्रारंभ हुआ और फिर कोलकाता के आसपास के क्षेत्र में कामरेड कन्हाई चटर्जी के प्रत्यक्ष देख-रेख में 1965 से ही प्रचारित 'चिंता' दस्तावेजों पर आधारित होकर तीखा संघर्ष का संचालन प्रारंभ हुआ। ऐसा कि 1964 में आयोजित सी.पी.आई.एम. की 7वीं कांग्रेस के आधिकारिक दस्तावेजों में निहित संशोधनवादी लाइन व कार्यक्रम को खुली चुनौती देकर उसके विपरीत में कोलकाता जिला सम्मेलन में कामरेड कन्हाई चटर्जी द्वारा एक वैकल्पिक दस्तावेज पेश करने की विशेष घटना भी घटी थी।

इन सारे बहस व वितर्क के निचोड़ व निष्कर्ष का व्यावहारिक प्रतिविम्ब हुआ- ऐतिहासिक नक्सलबाड़ी सशस्त्र किसान संघर्ष। हकीकत में नक्सलबाड़ी सशस्त्र किसान संघर्ष ने इसी संसदवादी-सुधारवादी-संशोधनवादी लाइन व कार्यवाही पर एक प्रचंड व निर्णायक विभाजन रेखा खींचनेवाली चोट पहुंचाया। ऐतिहासिक नक्सलबाड़ी सशस्त्र किसान संघर्ष के महत्व को देखते हुए महान माओ के नेतृत्व में तत्कालीन चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने 28 जून, 1967 को पीकिंङ रेडियो के जरिए नक्सलबाड़ी सशस्त्र किसान संघर्ष का स्वागत व समर्थन कर इसकी खुली घोषणा की और फिर 5 जुलाई, 1967 को 'पीपुल्स डेली' (सीपीसी का आधिकारिक मुखपत्र) में ''भारत में वसंत का वज्रनाद'' शीर्षक से एक महत्वपूर्ण आलेख को भी प्रकाशित किया। यह घोषणा व लेख भारत के कम्युनिस्ट क्रांतिकारी खेमा के अंदर एक नया जोश व उमंग पैदा किया और विशाल संख्या में छात्र-नौजवानों को सशस्त्र क्रांति में कूद पड़ने के लिए प्रेरित किया। इस कारण से ही 'नक्सलबाड़ी सशस्त्र किसान संघर्ष' को बतौर ऐतिहासिक संघर्ष कहा जाता है;

II. जब से भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ, तब से सशस्त्र संघर्ष का सवाल कभी भी उनके बैठक के एजेंडा (बैठक की विषय-सूची) में नहीं रहा। 'नक्सलबाड़ी सशस्त्र किसान विद्रोह' ने ही चली आ रही इस घोर संशोधनवादी ध ारा को जबरदस्त चोट पहुंचा कर एक गुणात्मक बदलाव लाया और सशस्त्र संघर्ष के जरिए 90 प्रतिशत मेहनतकश जनता की सही मुक्ति के मार्ग के सवाल को स्थायी तौर पर कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों के मूल एजेंडा में ला दिया। इस कारण से भी नक्सलबाड़ी सशस्त्र किसान संघर्ष को ऐतिहासिक महत्व रखने वाला संघर्ष कहा जाता है;

III. 'नक्सलबाड़ी सशस्त्र किसान संघर्ष' ने प्रमाणित किया कि यह संघर्ष केवल कुछ जमीन पर कब्जा जमाने का

या केवल जमीन के लिए संघर्ष नहीं था। बल्कि राजसत्ता पर कब्जा जमाने का संघर्ष था। हालांकि नई जनवादी क्रांति के स्तर में जमीन का सवाल एक महत्वपूर्ण मुद्दा जरुर है, मगर राजसत्ता पर कब्जा जमाने का मूल लक्ष्य नहीं रहने से किसानों को जिंदगी भर केवल जमीन की लड़ाई में ही फंसे रहना पड़ेगा और सदियों से चली आ रही मामूली किस्म की घिसी-पिटी मांगों की अदायगी के लिए केवल बीडीओ के सामने मांगपत्र पेश की लड़ाई में फंसे रहना होगा। इस कारण से 'नक्सलबाड़ी सशस्त्र किसान संघर्ष' को ऐतिहासिक कहा गया;

IV. 'नक्सलबाड़ी सशस्त्र किसान संघर्ष' ने केवल राजसत्ता पर कब्जा जमाने के सवाल को ही सामने नहीं लाया, बल्कि सशस्त्र कृषि-क्रांति तथा दीर्घकालीन लोकयुद्ध से जनता की जनवादी अधिनायकत्व वाला समाज की स्थापना के लिए क्रांति के पहले स्तर के बतौर नव जनवादी क्रांति की समूची राजनीति को भी सामने लाया;

साथ ही साथ नक्सलबाड़ी सशस्त्र किसान संघर्ष ने नव जनवादी क्रांति के स्तर में ''कौन दोस्त व कौन दुश्मन है'' इस बारे में और सही दुश्मनों के खिलाफ सही दोस्तों को लामबंद करने के बारे में भी एक धारणा दी है। जैसे, बतौर दुश्मन अमरीका सहित तमाम साम्राज्यवादी ताकतें, सामंतवाद यानी बड़ा जोतदार-जमींदार वर्ग और साम्राज्यवाद के दलाल भारत के बड़े पूँजीपति को दर्शाया है, वैसे ही बतौर दोस्त मजदूर-किसान, निम्न-पूँजीपति व राष्ट्रीय पूँजीपति को दर्शाया है। हालांकि आज के जैसी इतनी स्पष्टता के साथ तत्कालीन समय में दोस्त और दुश्मन के बारे में विश्लेषण नहीं हो पाया था। फिर भी, अतीत में संशोधनवादी नेतृत्व द्वारा बार-बार किये गये मूल वर्ग-विश्लेषण से गुणात्मक रुप से भिन्न वर्ग-विश्लेषण रख पाने में समर्थ हुई थी। इस कारण से 'नक्सलबाड़ी सशस्त्र किसान संघर्ष' को ऐतिहासिक कहा गया;

V. भारत में, अतीत के कम्युनिस्ट आंदोलन पर नजर दौड़ाने से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि आंध्र राज्य कमेटी के नेतृत्व व देख-रेख में चीनी क्रांति के मार्ग का अनुसरण कर तेलंगना सशस्त्र संघर्ष की शुरुआत हुई थी तथा एक ओर तत्कालीन पार्टी नेतृत्व द्वारा गद्दारी करने और दूसरी ओर संघर्षरत कामरेड लोग विचारधारात्मक-राजनीतिक लाइन पर अंत तक अडिग नहीं रह पाने के कारण और ''उचित सवाल पर विद्रोह करना ही न्याय-संगत है'' का. माओ के इस लाइन को समझदारी व अमल में लेते हुए, जरुरत पड़ने पर सांगठनिक विच्छेद के लिए तैयार रहने की दृढ़ता भी नहीं दिखा पाने के कारण तेलंगना आंदोलन की मशाल अस्थायी तौर पर बुझ गयी थी। जो नक्सलबाड़ी में और व्यापक व गुणात्मक रुप से भिन्न रुप लेकर पुनः जल उठी। क्योंकि, पुराने संशोधनवादी-सुधारवादी चिंतन व कार्य-पद्धति के साथ पूरी तरह से एक विच्छेद या खंडन व छलांग की प्रक्रिया के जरिए नक्सलबाड़ी सशस्त्र किसान विद्रोह का उद्भव हुआ। इसलिए भी नक्सलबाड़ी सशस्त्र किसान आंदोलन को एक ऐतिहासिक तात्पर्य रखनेवाला आंदोलन कहा गया;

VI. 'नक्सलबाड़ी सशस्त्र किसान संघर्ष' तमाम कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों का घोर संशोधनवादी सीपीएम व सीपीआई, जो अंतर्वस्तु व रुप (content and form) यानी संशोधनवादी विचार और संशोधनवादी सांगठनिक स्वरुप व कार्यशैली- दोनों ओर से भरपूर है, से पूर्णरुप से अलग होकर सही लाइन-नीति व कार्यपद्धति पर आधारित एक क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पार्टी का गठन की जरुरत को दर्शाया है। साथ-ही 'नक्सलबाड़ी सशस्त्र किसान संघर्ष' ने यह शिक्षा भी दिया है कि (i) ऐसी एक क्रांतिकारी पार्टी का नेतृत्व जो उपर से थोपा हुआ नेतृत्व न होकर बल्कि नेतृत्व केवल सिद्धांत व व्यवहार में तालमेल बैठाकर और क्रांतिकारी संघर्ष में हिस्सा लेकर ही निर्मित होगा; (ii) राजसत्ता पर कब्जा जमाने का मार्ग होगा दीर्घकालीन लोकयुद्ध तथा जनयुद्ध का मार्ग; (iii) ग्रामीण क्षेत्रों में आधार इलाका स्थापित करने के लिए जनमुक्ति फौज का गठन व इलाकावार सत्ता दखल करना होगा और उसे क्रमागत विस्तार करते हुए दुश्मन के सशक्त अड्डा स्थल यानी शहरों को घेर लेना होगा और अंत में शहरों को भी कब्जा करना होगा;

VII. 'नक्सलबाड़ी सशस्त्र किसान संघर्ष' ने मजदूर वर्ग के नेतृत्व में नव जनवादी क्रांति के स्तर में मूल शक्ति के रुप में व्यापक किसानों को लामबंद कर व मजदूर-किसान की मजबूत एकता की नींव डालने के महत्व को सामने लाया है और साथ ही किसानों के साथ एकात्म होने के काम को शहरों से बीच-बीच में गांव जाकर कुछ भाषण देने से ही नहीं होता है, बल्कि खुद को वर्गच्युत कर और एक कठिन व कष्टकर प्रक्रिया को अपनाकर ही उस एकात्म होने के काम में कुछ हद तक कामयाबी मिल सकती है- यह भी दर्शाया है। इसलिए भी नक्सलबाड़ी सशस्त्र किसान आंदोलन को एक ऐतिहासिक तात्पर्य रखने वाला आंदोलन के रुप में कहा गया है।

नक्सलबाड़ी किसान विद्रोह का तात्पर्य आज भी उतना-ही प्रासंगिक है जितना कि पहले था

ऐतिहासिक नक्सलबाड़ी सशस्त्र किसान संघर्ष आज 50 वर्ष पार करने वाला है। 50 वर्ष कोई मामूली समयकाल नहीं है। फिर भी, हमें आज भी नक्सलबाड़ी किसान विद्रोह उतना ही प्रासंगिक कहना पड़ रहा है जितना कि पहले था। स्वाभाविक रुप से ही सवाल उठता है कि ऐसा क्यों?

आज की समझदारी व अनुभव के आधार पर जहां तक स्पष्ट धारणाएं हमें प्राप्त हुई है, उसपर आधारित होकर हम कह सकते हैं कि केवल ''नक्सलबाड़ी मुक्ति का एकमात्र सही मार्ग है'' ''नक्सलबाड़ी एक-ही रास्ता'' कहना ही यथेष्ठ नहीं है, बल्कि उसे भारत की धरती पर व्यावहारिक तौर पर कार्यान्वित करना ही मुख्य काम है। इस मुख्य काम को पूर्णरुप से कार्यान्वित कर सफल बनाने के लिए एक सही सैद्धांतिक, राजनीतिक, सांगठनिक व सामरिक लाइन रहना आवश्यक है और उस सिद्धांत के मार्गदर्शन में ही और कई बुनियादी गाइड लाइन संबंधी दस्तावेजों का रहना भी आवश्यक है। जैसा कि हमारी पार्टी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का रणनीति-कार्यनीति दस्तावेज के प्रस्तावना में कहा गया है, ''रणनीति और कार्यनीति का उद्देश्य हमेशा किसी भी क्रांति की किसी खास मंजिल को उस मंजिल के कार्यक्रम के आधार पर सफलतापूर्वक सम्पन्न करना होता है। यहां कामरेड स्तालिन द्वारा बताए गये दिशा-निर्देशक उसूल को याद रखना महत्वपूर्ण है कि सिद्धांत को कार्यक्रम का मार्गदर्शन करना चाहिए, कार्यक्रम को रणनीति का मार्गदर्शन करना चाहिए और रणनीति को मार्गदर्शन करना चाहिए कार्यनीति का। मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद के सिद्धांत और उसके कार्यक्रम से प्राप्त सामग्री और उनसे निकले निष्कर्षों को आधार बनाकर ही रणनीति को सही-सही निर्धारित किया जा सकता है।

हमारे देश की मौजूदा ठोस परिस्थिति में मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद की सार्वभौमिक सच्चाई को सृजनात्मक रूप से लागू करने के जरिए ही भारतीय क्रांति की रणनीति और कार्यनीति को निर्धारित करना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि भारतीय समाज के वस्तुगत वर्ग-विश्लेषण, भारतीय राज्य के चरित्र और बुनियादी व प्रधान अन्तरविरोधों पर आधारित होकर तथा भारतीय परिस्थिति की चारित्रिक विशिष्टताओं एवं उसकी खास लाक्षणिक विशिष्टताओं तथा अन्यान्य खासियतों को दिमाग में रखते हुए ही रणनीति और कार्यनीति का निर्धारण करना चाहिए।

इस प्रकार भारतीय क्रांति की वर्तमान मंजिल की रणनीति को चाहिए कि वह नव जनवादी क्रांति को सफलतापूर्वक सम्पन्न कर नव जनवादी कार्यक्रम को कार्यान्वित करने की जरूरतों को पूरा करे। साथ ही कार्यनीति को विभिन्न क्षेत्रों में और विभिन्न समय में आंदोलन में आ रहे प्रत्येक मोड़ों व घुमावों के मुताबिक निर्धारित होना चाहिए और उसे उपरोक्त रणनीति को कारगर रूप से लागू करने की जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ उसके मातहत होना चाहिए। भारतीय क्रांति के कार्यक्रम और उसकी रणनीति तथा कार्यनीति के बीच इसी तरह के द्वन्द्वात्मक अन्तरसंबंध मौजूद हैं।''

उपरोक्त उद्धरण के आलोक में यह बिलकुल साफ है कि भारतीय क्रांति को सफल बनाने के लिए न्यूनतम रुप से हमारे पास मालेमा, पार्टी कार्यक्रम, रणनीति-कार्यनीति, पार्टी संविधान, राजनीतिक प्रस्ताव इत्यादि रहना ही चाहिए। साथ में और कई व्यावहारिक कामों को सफल बनाने के लिए विशेष-विशेष गाइड लाइन से संबंधित विशेष-विशेष पॉलिसी दस्तावेज भी रहना चाहिए। फिर कई बुनियादी दस्तावेज व पॉलिसी-कार्यक्रम संबंधी दस्तावेज रहने से ही नहीं होगा, साथ में सिद्धांत व व्यवहार के जरिए सबसे अगुआ कामरेडों को शामिल कर एक मजबूत पार्टी का निर्माण करने तथा भारतीय क्रांति का मार्ग बगावत या दीर्घकालीन लोकयुद्ध (Protracted Peoples War-PPW) की रणनीति-कार्यनीति कौन-सा होगा, उसे निर्धारित करने की गाइड लाइन भी रखनी होगी, अगर दीर्घकालीन लोकयुद्ध (PPW) की लाइन होगी, तो फिर उस लाइन को आगे बढ़ाने के लिए रणनीतिक क्षेत्र चुनकर उपल्ब्ध ताकतों को तैनात करने, फौज व आधार क्षेत्र के निर्माण को प्रधान, केंद्रीय व फौरी कर्त्तव्य के रुप में निर्धारित करने, सशस्त्र संघर्ष की प्रक्रिया के जरिए चार दोस्त वर्गों यानी मजदूर, किसान, पेटी बुर्जुआ व राष्ट्रीय बुर्जुआ को लेकर संयुक्त मोर्चा का निर्माण करने तथा मौजूदा नव जनवादी क्रांति को सफल बनाने के तीन जादुई हथियार पार्टी, जनसेना व संयुक्त मोर्चा निर्माण करने संबंधी स्पष्ट धारणाएं भी रखनी होगी।

अब उल्लिखित मानदंडों की कसौटी पर ही 50 वर्ष पहले घटित नक्सलबाड़ी सशस्त्र किसान विद्रोह की आकांक्षित सफलता अभी तक क्यों नहीं मिली, उसके कारणसमूह ढूंढ़ने होंगे। ढूंढ़ने के लिए समीक्षा की जाती है। 1971-72 से नक्सलबाड़ी आंदोलन के पीछे हटने के बाद ऐसे अनेकों समीक्षा हमारे सामने मौजूद हैं।

समीक्षा के द्वारा जो बातें सामने आयी हैं उसके आधार पर हम कह सकते हैं यद्यपि कि हमारी आम लाइन सही थी, फिर भी उसके मातहत विशेष-विशेष लाइन व विशेष-विशेष कार्यनीति व कार्यक्रमों को सटीक तौर पर नहीं अपनाया जा सका। जिसके फलस्वरुप जैसे कि एकता कांग्रेस-9वीं कांग्रेस द्वारा पारित सी.पी.आई. (एम.एल.) पी.डब्ल्यू. की पी.ओ. आर. में लिखा हुआ है ''कुछ विचारधारात्मक, राजनीति एवं सांगठनिक कमजोरियों, जिसमें गम्भीर कार्यनीतिक भूलें शामिल है; तीखे दमन व बड़े नुकसानों; अनुभवहीनता तथा दक्षिणपंथी अवसरवादियों द्वारा अंदरुनी तोड़-फोड़ की कार्रवाईयों और इनके फलस्वरुप हुई सामयिक पराजय तथा राजनीतिक/विचारधारात्मक भ्रांतियों के परिणामस्वरुप पार्टी में फूट पड़ने लगी।'' फिर, नक्सलबाड़ी सशस्त्र किसान आंदोलन के प्रणेता व हमारे एक संस्थापक, शिक्षक व नेता कामरेड चारु मजूमदार की 28 जुलाई, 1972 को पुलिस हिरासत में रहते समय उन पर किये गये अत्याचार के कारण शहादत देनी पड़ी। उनकी शहादत भारतीय क्रांति व समूचे एम.एल. आंदोलन के लिए बहुत ही भारी क्षति साबित हुई। उसके बाद आंदोलन धक्का खाया व सेट-बैक का शिकार बन गया। उपर में दर्शायी गई कमी-कमजोरियों के कारण ही नक्सलबाड़ी संघर्ष के 50 वर्ष बीत जाने के बाद भी देखने को मिल रहा है कि आकांक्षित सफलता हमें नहीं मिल पायी है।

इसलिए अतीत के आंदोलन से सबक लेकर जारी मौजूदा भारतीय क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए आज भी हम भाकपा (माओवादी) की रहनुमाई में अनेकों प्रकार के जटिल व कठिन समस्याओं को तथा उतार-चढ़ाव की स्थितियों को झेलते हुए दृढ़कदम आगे बढ़ाने में संकल्पबद्ध हुए हैं। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि नक्सलबाड़ी आंदोलन का ऐतिहासिक तात्पर्य आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि पहले था।

संशोधनवाद के हर रुप व पैंतरे के खिलाफ निरंतर संघर्ष की बात व जरुरत को कभी न भूलें

जबसे मार्क्सवाद सामने आया, तब से उसके विपरीत में संशोधनवाद भी सामने आया। दो विपरीत वस्तु की एकता व विरोध के पहलू के बतौर मार्क्सवाद बनाम संशोधनवाद के बीच का संघर्ष भी प्रारंभ हुआ। मार्क्सवाद बनाम संशोधनवाद की लड़ाई की धारावाहिकता में ही एक समय तेलंगना आंदोलन का उभार हुआ (जो सैद्धांतिक तौर पर दृढ़ नहीं रह पाने और तत्कालीन संशोधनवादी नेतृत्व की गद्दारी के कारण अंत तक पूरी तरह विफल हो गयी और उक्त तेलंगना आंदोलन की मशाल बुझ गयी थी) और फिर 1967 के मई में बतौर एक वज्रघोष ऐतिहासिक नक्सलबाड़ी सशस्त्र किसान आंदोलन फूट पड़ा। इस आंदोलन की सबसे बड़ी खूबी व सकारात्मक पहलू यह रहा कि सी.पी.एम. पार्टी नेतृत्व द्वारा अपनायी गयी चरम संशोधनवादी लाइन व कार्यधारा के खिलाफ समझौताहीन संघर्ष चलाने में यह समर्थ हुआ और उचित समय पर सांगठनिक विच्छेद भी कर लेने में समर्थ हुआ। इस तरह से मार्क्सवादी द्वंद्वात्मक भौतिकवादी तमाम नियमों के या सूत्रों के अंदर एक मूल नियम या सूत्र, विच्छेद व छलांग का सूत्र को व्यवहार में लागू कर उसके ऐतिहासिक तात्पर्य से संबंधित नतीजा को दिखाने में समर्थ हुआ।

फिर, 1971-72 में मार्क्सवादी-लेनिनवादी क्रांतिकारी आंदोलन जब कुछ पीछे हटना प्रारंभ किया, तब विभिन्न तरह के गलत व संशोधनवादी लाइन को सर खड़ा करने का मौका मिला। लगभग ये सारे लाइन 'नई बोतल में पुरानी शराब' की लोकोक्ति जैसा क्रांतिकारी लिबास में पूरे के पूरे संशोधनवादी लाइन व कार्यधारा परोसा जाने लगा। उदाहरणस्वरुप, घोर संशोधनवादी व पार्टी तोड़क सत्यनारायण सिंह की सौ-प्रतिशत संशोधनवादी लाइन तो विशेष उल्लेख योग्य है। (इस लेख में इसकी विस्तृत चर्चा करने की जरुरत नहीं है, क्योंकि इसकी चर्चा पहले से ही यथेष्ठ रुप से मौजूद है)।

आज के संदर्भ में भी जब हमारा समग्र आंदोलन एक कठिन दौर में और कहीं पर धक्का खाने की स्थिति में है, इस मौके पर दीर्घकालीन लोकयुद्ध की लाइन को ही चौपट करने के मकसद से पुनः विभिन्न प्रकार की संशोधनवादी-सुधारवादी गलत लाइनों का सर खड़ा करने का खतरा और उसके खिलाफ कड़ा संघर्ष की भी जरुरत को रेखांकित किया गया। वाकई में, ये सब गलत लाइन अभी केवल खतरा की संभावना ही नहीं, बल्कि हमारे लिए कड़ा वैचारिक संघर्ष चलाने के कर्त्तव्य को एक फौरी कर्त्तव्य के रुप में और अतिआवश्यक राजनीतिक कर्तव्य के रुप में चलाए जाने की जरुरत को भी रेखांकित किया गया। जैसे कि हमारी पार्टी की सीसी-4 बैठक द्वारा लिये गये प्रस्ताव में कहा गया है, ''ऐसी परिस्थिति में वाम और दक्षिणपंथी लाइनें सामने आ सकती हैं। जहां दक्षिणपंथी अवसरवादी, विघटनकारी और संशोधनवादी तर्कों को सामने लाया जा रहा है, वहीं वामपंथी लाइन की आड़ में दक्षिणपंथ सामने लाया जा रहा है।..... कुछ लोग यह तर्क सामने ला रहे हैं कि भारत में अर्द्ध उपनिवेशी और अर्द्ध

सामंती उत्पादन संबंध बदल चुके हैं और पूँजीवादी उत्पादन के संबंध स्थापित हो चुके हैं। इसके आधार पर यह कुतर्क सामने लाया जा रहा है कि भारत में दीर्घकालीन जनयुद्ध की लाइन कारगर नहीं हो सकती। पार्टी की सही लाइन को लागू करने की आड़ में कुछ लोग संकीर्णतावादी और नौकरशाही रुझानों के साथ बरताव करते हुए पार्टी और आंदोलन को नुकसान पहुंचा रहे हैं।..... आंदोलन को कठिन स्थिति से आगे बढ़ने की स्थिति में पहुंचाने के लिए हमें रणनीतिक योजना तैयार कर लेनी चाहिए। इसमें सबसे पहला बिंदु है समूची पार्टी को सैद्धांतिक व राजनीतिक रुप से मजबूत बना लेना तथा मार्क्सवाद विरोधी बुर्जुआ व संशोधनवादी सिद्धांतों का खंडन कर व पर्दाफाश कर पराजित करना। इसके तहत मौजूदा परिस्थिति में आधुनिकोत्तरवादी सिद्धांतों का हमें सामना करना होगा। हमारी पार्टी की राजनीतिक लाइन से कटिबद्ध होकर समूची पार्टी को शिक्षित करना चाहिए।''

पूरी पार्टी को बोल्शेवीकरण की प्रक्रिया के जरिए ही उसे हर तरह से मजबूत किया जा सकता है तथा पार्टी व आंदोलन में निहित कमी-कमजोरियों को उतार फेंका जा सकता है और पुनर्गठन के कामों को आगे बढ़ाया जा सकता है

हमारी पार्टी द्वारा उक्त महत्वपूर्ण काम को सटीक ढंग से आगे बढ़ाने के लिए पूरी पार्टी को बोल्शेवीकरण करने का आह्वान किया गया। केवल एक सामान्य आह्वान ही नहीं, बल्कि उक्त आह्वान को हकीकत में सफल बनाने के लिए सामान्य आह्वान के मातहत ही कई सरकुलर व जरुरतमंद लेखों को भी कतारों के अंदर जारी किया गया है। समग्र रुप से बोल्शेवीकरण का अर्थ है:

1) समूची पार्टी के राजनीतिक-सैद्धांतिक समझदारी के स्तर को क्रमागत रूप से आगे बढ़ाने के लिए सैद्धांतिक-राजनीतिक शिक्षा देने के काम को एक मुहिम के बतौर नियमित रूप से चलाना; नेतृत्व देने लायक कामरेडों को चुनकर विशेष ध्यान देते हुए सिद्धांत व व्यवहार दोनों पहलुओं की ओर से शिक्षित करने की प्रक्रिया लागू करना ताकि कुछ योग्य व कुशल नेतृत्व देने लायक कामरेड तैयार हो सके; पिछले 30 वर्षों के दौरान आर्थिक-राजनीतिक क्षेत्र (परिदृश्य) में क्या बदलाव आया है या आ रहा है उसके बारे में भी जांच-पड़ताल करनी होगी व जानकारी हासिल करनी होगी। ताकि जरूरत के अनुसार हम कार्यनीति तय कर सकें

2) पार्टी के अंदर पनपे पेटी-बुर्जुआ व बुर्जुआ रूझान सहित विभिन्न गैर-सर्वहारा रूझान व व्यवहार को पूरी तरह से दूर हटाने के लिए एक मुहिम के बतौर दोष-निवारण आंदोलन को ऊपर से नीचे सभी स्तरों में चलाते रहना;

3) संशोधनवाद के हर रूप चाहे 'दक्षिण हो या वाम' के खिलाफ लगातार सैद्धांतिक व राजनीतिक संघर्ष जारी रखना और उत्तर-आधुनिकता संबंधी विचार व चिंतन तथा भारत के हर क्षेत्र में पूंजीवादी विकास हो गया, जैसी सोच व लाइन के खिलाफ लगातार संघर्ष की प्रक्रिया अपनाना; पार्टी को क्रमश: सर्वहारा दर्शन व सर्वहारा गुणों से लैस करने की प्रक्रिया के रूप में बोल्शेवीकरण की प्रक्रिया अपनाना तथा द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी विश्लेषण के तौर-तरीके और पार्टी में 'दो विपरीत चीज की एकता' के नियम और हर विषय को 'एक को दो में विभाजन कर' देखने का नियम के बारे में गहरी समझदारी हासिल करने के लिए लगातार प्रयास चलाना;

4) सर्वोच्च कमेटी के यानी सीसी से लेकर एरिया कमेटी तक सभी नेतृत्वकारी कामरेडों की रक्षा करना; पीएलजीए के सभी फॉरमेशनों के पार्टी कमेटी की यानी प्लाटून पार्टी कमेटी, कम्पनी पार्टी कमेटी व बटालियन पार्टी कमेटी के सदस्यों की, तमाम कमांडरों व डिप्टी कमांडरों की तथा विभिन्न स्तर के कमान के सदस्यों की रक्षा करना; आरपीसी, केकेसी, सहित अन्यान्य जन-संगठनों के नेता व कार्यकर्त्ताओं की रक्षा करना;

5) पार्टी की जड़ को वर्ग लाइन के अनुसार और मजबूत करने हेतु वर्ग-लाइन व जन-लाइन का अनुसरण कर जनता के बीच ले जाने और गांव को ही इकाई के रूप में लेकर तथा पार्टी का बुनियादी आधार मानकर पार्टी, पीएलजीए, केकेसी, आरपीसी व अन्यान्य विभिन्न जन-संगठनों का निर्माण करने पर विशेष जोर लगाना होगा ताकि पार्टी का आधार ऐसा मजबूत हो जिसे कि कितना भी धक्का क्यों न लगे, फिर भी टिका हुआ व खड़ा रहे। इस तरह से पार्टी संगठन के विभिन्न रूपों को जमीनी स्तर से मजबूत करते हुए उसमें से चुनकर कुछ को पेशेवर के रूप में तैयार कर उचित सांगठनिक स्तर में रिक्रुट करना; इत्यादि-इत्यादि।

6) किसी भी कार्य में अथवा समग्र रुप से जारी क्रांतिकारी लड़ाई में सफलता हासिल करनी है तो 'दो विपरीत चीज की एकता व विरोध' के नियम तथा व्यवहार में 'एक को दो में विभाजित करने' के नियम को लागू करने

में महारत हासिल करना जरुरी है।

अतीत के समय से भारत के कम्युनिस्ट आंदोलन में निहित आम कमजोरियों और मूलतः हावी रही संशोधनवादी लाइन व संशोधनवादी कार्यवाही और फिर कभी-कभी हावी रही 'वाम' भटकाववादी लाइन व कार्यवाही के पीछे के कारण समूह को तथा आंदोलन के जरिए प्राप्त सकारात्मक उपलब्धियां व नकारात्मक पहलुओं के बारे में सही विश्लेषण व निष्कर्ष तब ही हम निकाल सकते हैं जब 'दो विपरीत चीज की एकता व विरोध' के नियम तथा व्यवहार में 'एक को दो में विभाजित करने के नियम को लागू करने में महारत हासिल करेंगे। पर, ऐसा करने में हमारी ज्यादा ही खामियां रह जा रही है। अतः उक्त उसूलों को व्यवहार में लागू करने के लिए हमें अवश्य ही महारत हासिल करनी होगी।

नक्सलबाड़ी दिवस की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर सीपीआई (माओवादी) का उदात्त आह्वान है कि भाकपा (माओवादी) की रहनुमाई में जारी क्रांतिकारी लड़ाई में पूर्ण जीत हासिल करके पहले जनता का जनवाद स्थापित कर बाद में समाजवाद व साम्यवाद की स्थापना की ओर आगे बढ़ने हेतु जी-जान से प्रयास करें

एकीकृत व नवगठित सीपीआई (माओवादी) के आविर्भाव के वज्रघोष के बाद से आज तक चला आ रहा अन्यायपूर्ण व आक्रामक युद्ध और इसके खिलाफ न्यायपूर्ण व प्रतिरोध युद्ध की स्थिति भारत के अवाम के सामने यह साबित कर दिया है कि नक्सलबाड़ी के ऐतिहासिक विद्रोह से लेकर अभी तक पार्टी द्वारा अपनायी गयी कृषि-क्रांति तथा दीर्घकालीन लोकयुद्ध की लाइन बिलकुल सही है। खासकर, पिछले 10 वर्षों के दौरान जिस तरह से ऑपरेशन ग्रीन हण्ट के नाम पर आक्रामक युद्ध व उसे पूरी तरह परास्त करने के लिए जवाबी प्रतिरोध युद्ध का घमासान जारी है, वह आज भारत के राजनीतिक परिदृश्य में एक प्रमुख चर्चा का विषय बन गया है। इस प्रकार से कृषि क्रांतिकारी गुरिल्ला युद्ध की लाइन को व्यवहार में लागू करने की प्रक्रिया के दौरान तथा उतार-चढ़ाव की स्थिति तथा कठिन दौर व धक्का खायी हुई स्थिति से बाहर आने के कार्यक्रमों को कार्यान्वयन के दौरान हमारी रणनीति व कार्यनीति अधिक समृद्ध हुई है। फिर भी हमारी पार्टी अभी भी जरूरत की अपेक्षा बहुत कमजोर है। पार्टी के अंदर बहुत गैर-सर्वहारा रुझान व पितृसत्तात्मक आचार-आचरण मौजूद हैं। इसलिए इन तमाम गलत रुझानों के खिलाफ निरंतर संघर्ष चलाते हुए इसे निर्मूल करना तथा साथ ही साथ पार्टी को लगातार बोल्शेवीकरण करने की प्रक्रिया को दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ाना होगा। पार्टी में हो रहे नुकसानों को हर हालत में रोकना होगा।

एकीकृत पार्टी के गठन के साथ-साथ पार्टी के नेतृत्व में बतौर जनसेना जन मुक्ति छापामार सेना या पीएलजीए की स्थापना कर भारत की क्रांतिकारी लड़ाई की अग्रगति में एक छलांग लायी गई है। इसी समय के दौरान मालेमा के आलोक में युद्ध-विज्ञान को भी कुछ हद तक हम समझ पाए हैं। युद्ध की गतिशीलता (डायनामिज्म) को भी कमोबेश समझ पाए हैं। अनुभव दिखाया है कि 'युद्ध के जरिए युद्ध सीखने' के तरीके से तथा अनगिनत बहादूर कमांडर व योद्धाओं के बलिदानों के बदौलत जो शिक्षा मिली उसके जरिए ही हम कमोबेश युद्ध-कला को विकसित करने में सक्षम हुए हैं। दीर्घकालीन लोकयुद्ध की लाइन को लागू करते हुए हम आधार क्षेत्रों के निर्माण के लक्ष्य पर कई छापामार जोनों का निर्माण कर सके हैं। काफी शक्तिशाली शत्रु सेना का साहस-बुद्धि व धरातल के अनुसार गुरिल्ला युद्ध के दाव-पेंच का इस्तेमाल के जरिए मुकाबला करते हुए हमने अनेक कार्यनीतिक जीतें हासिल की हैं। इससे हमें अपने छापामार युद्ध को चलायमान युद्ध की ओर आगे बढ़ाने में मदद मिल रही है और फौरी, प्रधान व केन्द्रीय कार्यभार को आगे बढ़ाया है, रणनीतिक क्षेत्रों पर केन्द्रित कर पार्टी लाइन को लागू करते हुए आधार क्षेत्रों की स्थापना के परिप्रेक्ष्य के साथ लाल प्रतिरोध क्षेत्र तथा छापामार जोनों का निर्माण किया है और छापामार आधार इलाकों की स्थापना की है। हमने छापामार युद्ध को चलायमान युद्ध में, पीएलजीए को पीएलए में और छापामार जोन को आधार क्षेत्रों में बदल डालने के दृढ़निश्चय के साथ मौजूदा जनयुद्ध को तेज करने का भरसक प्रयास किया है। भारी नुकसान झेलते हुए भी हमने कुछ जीतें हासिल की हैं। कुछ गंभीर नुकसान उठाने के बावजूद तथा सेट-बैक की स्थिति में पहुंचने के बावजूद छापामार युद्ध को अधिक उन्नत स्तर तक विकसित करने की बड़ी सम्भावनाएं मौजूद हैं। पर, हमें आत्मसंतुष्टि की भावना को पूरी तरह त्याग देना होगा। और हमें अपनी गलतियों की पुनरावृत्ति से बचना होगा। विपरीत में, हमें अपनी उपलब्धियों से प्रेरणा लेनी होगी, विफलताओं से निराशा नहीं बल्कि सबक लेना होगा और परिस्थिति तथा अपनी आत्मगत शक्तियों के अनुरूप ठोस कार्यभार निर्धारित करना होगा।

हालांकि देश के अंदर कहीं-कहीं एकदम निचले स्तरों से

लेकर एरिया स्तर तक हमने जनता की क्रांतिकारी सेना के निकायों को स्थापित कर पाया। पर, वस्तुगत स्थिति, संभावना व जरूरत के परिप्रेक्ष्य में देखने से एक बड़े क्षेत्र को लेकर जनता की वैकल्पिक जनवादी व्यवस्था का वास्तविक रूप नहीं दे पाये। यह हमारी एक भारी कमजोरी ही है। जिसे जल्द से जल्द दूर हटाना हमारा फौरी कर्तव्य होगा। जाहिर है कि आज की अंतरराष्ट्रीय व घरेलू परिस्थिति पहले के किसी भी समय की अपेक्षा क्रांति के लिए ज्यादा अनुकूल है। इस अनुकूल पहलू का सही रूप से इस्तेमाल करते हुए हम हमारी कमी-कमजोरियों व खामियों को भी एक निश्चित समय-सीमा के अंदर प्रतिबद्धता के साथ पूरी तरह सुधार सकते हैं। पिछले दस वर्षों से हमारे जनयुद्ध की अग्रगति के दौरान प्राप्त सकारात्मक व नकारात्मक प्रभावों की पृष्ठभूमि में क्रांतिकारी युद्ध में छलांग लगाने की बड़ी सम्भावना है। हमें जनयुद्ध को आगे बढ़ाते हुए चार वर्गों (मजदूर, किसान, निम्न पूंजीपति व राष्ट्रीय बुर्जुआ) के संयुक्त मोर्चा का निर्माण करने के लिए साम्राज्यवाद, सामंतवाद व दलाल नौकरशाह पूंजीवाद के खिलाफ सभी शक्तियों को गोलबंद करने के कार्यभार पर ध्यान केन्द्रित करना होगा। हमें मजदूर, किसान, आदिवासी, दलितों के बीच पार्टी की जड़ को और अंदर तक ले जाना होगा तथा उनके बीच से भारी संख्या में युवक-युवतियों को भर्ती करने पर ध्यान केन्द्रित करना होगा और पीएलजीए को पीएलए में रूपान्तरित करने के लिए जुट जाना होगा। हमें अपनी कार्यनीति को सृजनात्मक ढंग से लागू करते हुए और दुश्मन के बलों के खिलाफ कार्यनीतिक प्रत्याक्रमण की कार्रवाई तथा ऑपरेशन ग्रीन हण्ट के तहत चलाये जा रहे बर्बर सामरिक अभियान या आक्रामक युद्ध के खिलाफ मुंहतोड़ जवाबी प्रतिरोधी कार्रवाईयों को संचालित करते हुए दुश्मन के लगातार आक्रमणों, माओवादी सफाया अभियानों, 'घेरा डालो-विनाश करो' अभियानों तथा विभिन्न प्रतिक्रांतिकारी अभियानों को शिकस्त देनी होगी। हमें छापामार युद्ध को चलायमान युद्ध में विकसित करते हुए तथा जनता की क्रांतिकारी सत्ता के निकायों की स्थापना करते हुए अपने रणनीतिक क्षेत्रों में छापामार जोनों को आधार क्षेत्र में रूपांतरित करना होगा; हमें समूचे देहाती क्षेत्र में नये-नये छापामार जोन तथा लाल प्रतिरोध क्षेत्र विकसित करना होगा और छापामार युद्ध को फैला देना होगा। इस तरह हमें क्रांति का एक उफान खड़ा कर देना होगा। अपने फौरी कार्यभारों को लागू करते हुए हमें रणनीतिक दृढ़ता तथा कार्यनीतिक लचीलापन दिखाना होगा। नेतृत्व के सचेत प्रयासों के जरिए हमें प्रतिकूल कारकों को अनुकूल कारकों में रूपांतरित करने में जुट जाना होगा। हमें दुश्मन को कार्यनीतिक रूप से असली बाघ और रणनीतिक रूप से कागजी बाघ के रूप में लेते हुए अपनी कार्यनीति को विकसित करना होगा। इस प्रकार हमें देशभर में तीन जादुई हथियारों- पार्टी, जनसेना और क्रांतिकारी संयुक्त मोर्चा का निर्माण करने और इन्हें मजबूती देने में जुट जाना होगा।

2008 के समय से अमेरिकी साम्राज्यवाद सहित तमाम साम्राज्यवाद आज क्रमशः गहराते जा रहे एक गंभीर व अभूतपूर्व आर्थिक-राजनीतिक संकट का सामना कर रहा है। दुनिया के सभी बुनियादी अंतरविरोध पहले की अपेक्षा अधिक तीखे होते जा रहे हैं। पूंजीवादी-साम्राज्यवादियों तथा प्रतिक्रियावादी शासक वर्गों द्वारा शोषण, उत्पीड़न तथा लूट के खिलाफ जन आंदोलन, राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष और क्रांतिकारी आंदोलन उमड़ रहे हैं। आवें, देश के मौजूदा जनयुद्ध में महान छलांग लगाने के लिए इस अनुकूल परिस्थिति का लाभ उठाएं।

कामरेडों, मोदी सरकार द्वारा माओवादी पार्टी व माओवादी आंदोलन को पूरी तरह कुचल डालने की योजना, निश्चित रूप से मोदी सरकार का एक प्रमुख काम के बतौर उजागर हुआ है। लेकिन, यह केवल भारत की किसी एक पार्टी की सरकार का अपना मनमौजी निर्णय नहीं है और ऐसा हो भी नहीं सकता है। क्योंकि भारत के शासक पार्टियां साम्राज्यवाद के दलाल हैं। इसलिए किसी भी पार्टी या किसी भी रंग की सरकार क्यों न हो उसे साम्राज्यवाद खासकर अमरीकी साम्राज्यवाद का निर्देशन-अनुसार एलआईसी पॉलिसी (या कम तीव्रता वाला युद्ध) के विभिन्न पहलुओं को पूरी तरह लागू करना पड़ता है। वैसा-ही यूपीए जमाने में हुआ है और अभी एनडीए जमाने में भी हो रहा है। इसलिए यह केवल मोदी सरकार गद्दी पर बैठने के बाद ही सरकार का प्रमुख काम बन गया- ऐसा नहीं है। अगर हमलोग यूपीए-1 व यूपीए-2 सरकार के जमाने पर एकबार नजर दौड़ाते हैं तो हम देख पाते हैं कि यूपीए-1 और यूपीए-2 दोनों ने ही माओवादी पार्टी व माओवादी आंदोलन को ही 'देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा' बताकर हमारी पार्टी व आंदोलन को खत्म करने के काम को सबसे प्रमुख काम के बतौर चलाया था। 'ऑपरेशन ग्रीन हंट' का पहला व दूसरा चरण उसी सरकार का जमाना था। मगर परिणाम क्या निकाला? इतिहास गवाह देता है कि वे पूरी तरह से विफल रही। उल्टे, माओवादी पार्टी व आंदोलन की जड़ जनता के अंदर तक चली गयी है और हजारों

कामरेडों की शहादतों के कारण हुआ भारी नुकसान झेलने के बावजूद पार्टी अनेकों अनुभव व सबक लेकर मजबूत हुई है।

अब मोदी सरकार द्वारा अमरीकी साम्राज्यवाद सहित अन्य तमाम साम्राज्यवादियों व प्रतिक्रियावादियों से हर प्रकार की मदद लेकर ही क्रांतिकारी आंदोलन को पूरी तरह रौंद डालने के लिए 'ऑपरेशन ग्रीन हंट' के तीसरे चरण की योजना को लागू किया जा रहा है। 'घेरा डालो-विनाश करो' अभियान हो या किसी भी प्रकार के दमनात्मक अभियान, सरेंडर पॉलिसी हो या मनोवैज्ञानिक लड़ाई के बतौर दुष्प्रचार चलाने की पॉलिसी, चाहे विभिन्न प्रकार के तथाकथित सुधार कार्यक्रम हो या तथाकथित विकास का ढोल पीटने का कार्यक्रम- सभी में मोदी सरकार द्वारा एक ओर आमूल-चूल बदलाव लाया गया है। मोदी सरकार गद्दी पर बैठते न बैठते ही माओवादियों को उखाड़ फेंकने की घोषणा की। दूसरी ओर, और ज्यादा संख्या में अर्द्धसैनिक बलों के बटालियन बनाकर माओवादी इलाके में तैनाती की बात कही जा रही है। फिर 'काँटा से काँटा निकालने' की चरम प्रतिक्रियाशील नीति के तहत कहीं 'बस्तरिया बटालियन' तो कहीं 'स्थानीय आदिवासी बटालियन का गठन कर 'आदिवासियों को आदिवासियों के खिलाफ लड़वाने' जैसी प्रतिक्रियावादी एलआईसी पॉलिसी को बहुत वफादारी के साथ लागू किया जा रहा है।

दूसरा घृणित तरीके के बतौर यूपीए सरकार द्वारा अपनायी गयी सरेण्डर या आत्मसमर्पण पॉलिसी को उसके कथनानुसार ''और लुभावना'' बनाने के लिए पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा रूपए मिलने का लोभ-लालच दिया जा रहा है।

उपरोक्त तमाम क्रांति-विरोधी पॉलिसियों का मुकाबला करने के लिए हमारा पहला व प्रधान काम है, सीसी से एसी व जन संगठनों के नेतृत्व तक रक्षा करना, पार्टी को और बोल्शेवीकरण करना तथा दुश्मन के चौतरफा हमले का मुकाबला चौमुखी जवाबी हमला के जरिए करने के लिए पूरी पार्टी कतार व लड़ाकू जनता को हर प्रकार से शिक्षित-दीक्षित करना व न्यूनतम रूप से प्रतिरोधी कार्रवाई चला सके, इसलिए प्रशिक्षण देना ताकि जवाबी हमले को सही मायने में जनयुद्ध के रूप में बदल दिया जा सके। हमें अवश्य-ही राजनीतिक-सांगठनिक व सैनिक तैयारियों के काम को एक अभियान के बतौर आगे बढ़ाना होगा, सैनिक हमले का जवाबी प्रतिरोधी लड़ाई, दुष्प्रचार का जवाबी प्रचार अभियान व ज्वलंत जन-समस्याओं को लेकर जन-आंदोलन का निर्माण आदि के लिए हमें जी-तोड़ प्रयास चलाना होगा।

कामरेडों, भारतीय क्रांति की अग्रगति के अगले दौर को भारी चुनौतीभरी परिस्थिति का सफलतापूर्वक मुकाबला करके ही हम आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए हमें हर प्रकार की चुनौती का मुकाबला करने हेतु सभी प्रकार की तैयारियों को पूरी करनी होगी। इसका मतलब है, उल्लिखित जितने किस्म की कमजोरियों व कर्त्तव्यों की बातों का जिक्र किया गया है तथा उसे सुधारने के उपायों को भी पूरी तरह से कार्यान्वित करना हमारा फौरी व अहम् कर्त्तव्य है।

ऐसा करके ही हम क्रांति के तीन जादुई हथियार यानी पार्टी, जनसेना व संयुक्त मोर्चा को निर्माण व लगातार मजबूती प्रदान कर सकते हैं। हमें याद रखना है कि पार्टी को सही अर्थ में बोल्शेवीकरण किये बिना एक कदम भी हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आवें, हर प्रकार की कमी-कमजोरी को केवल कथनी में ही नहीं, करनी में दूर हटाने के लिए संकल्पबद्ध हो जाएं और पार्टी की अन्दरूनी एकता को आंख की पुतली जैसी रक्षा करते हुए उसे और मजबूत बनाएं तथा हर प्रकार के संशोधनवादी, चाहे 'वाम' संशोधनवाद हो या दक्षिण, उसे परास्त करते हुए पार्टी की सही लाइन, नीति व कार्यशैली का दृढ़तापूर्वक अनुसरण करें।

निस्संदेह, रास्ता टेढ़ा-मेढ़ा, कठिन व जटिल है, पर मालेमा व पार्टी लाइन पर अडिग रहने से हम सारी बाधाओं को लांघते हुए भारत की नई जनवादी क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए गुरिल्ला युद्ध को चलायमान युद्ध में बदल डालो, पीएलजीए को पीएलए में बदल डालो और गुरिल्ला जोन को आधार क्षेत्रों में बदल डालो जैसे अहम् व फौरी कर्त्तव्य को तेज गति से आगे बढ़ा सकते हैं।

आवें, महान शहीदों के अधूरे कार्यों व सपने को पूरा करने हेतु साहस के साथ वर्गयुद्ध के मैदान में कूद पड़ें।

इतिहास गवाह है कि अन्तिम जीत जनता की ही होगी। रात के अंधकार के बाद भोर की लाल किरण दिखाई पड़ेगी ही। भारतीय क्रांति सफल होगी ही यानी पहले नव जनवादी क्रांति और इसके तुरन्त बाद समाजवादी क्रांति भी सफल होगी ही। ऐतिहासिक नक्सलबाड़ी सशस्त्र किसान विद्रोह द्वारा दिखाया गया 'नक्सलबाड़ी मुक्ति का एकमात्र सही मार्ग' व 'नक्सलबाड़ी एक-ही रास्ता' की नारे सरजमीं पर कार्यान्वित व वास्तवायित होगी ही। यही हमारी पार्टी का उदात्त आह्वान है।

हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता व पोलित ब्यूरो सदस्य तथा अमर शहीद कामरेड नारायण सन्याल उर्फ कामरेड विजय दा को शत्-शत् लाल सलाम!

विदित हो कि विगत 17 अप्रैल, 2017 को रात्रि 10 बजकर 50 मिनट में कोलकाता के एक निजी अस्पताल में कैंसर की चिकित्सारत हालत में हमारे वरिष्ठ सदस्य कामरेड नारायण सन्याल का निधन हो गया। मृत्यु के समय उनकी उम्र लगभग 82 वर्ष की थी। निस्संदेह उनके जैसे एक वरिष्ठ कामरेड की मृत्यु हमारी पार्टी के लिए एक अपूरणीय क्षति है।

कामरेड नारायण सन्याल 1967 में ऐतिहासिक नक्सलबाड़ी किसान विद्रोह के समय से ही भारत में लम्बे समय से चली आ रही संशोधनवादी लाइन, व्यवहार व कार्यशैली के खिलाफ तीखा संघर्ष चलाते हुए सक्रिय रूप से क्रांतिकारी राजनीति में हिस्सा लेना प्रारंभ किए। तब से अनेकों बांक-मोड़, उतार-चढ़ाव व धक्का के बावजूद कभी पीछे की ओर नहीं सोचे। बल्कि अच्छा-खासा सकारात्मक सोच के तहत अतीत से सबक लेकर भविष्य की अग्रगति के लिए हर संभव कोशिश करते गए। उनकी यह कोशिश अंतिम सांस लेने तक भी जारी रही। साथ-ही, वे हर समय पार्टी, क्रांति व आम जनता के स्वार्थ को ही सर्वोच्च स्थान देते रहे। यानी लगभग पचास वर्षों तक के उनके राजनीतिक जीवन हम सबों के लिए बहुत ही प्रेरणादायी स्रोत है।

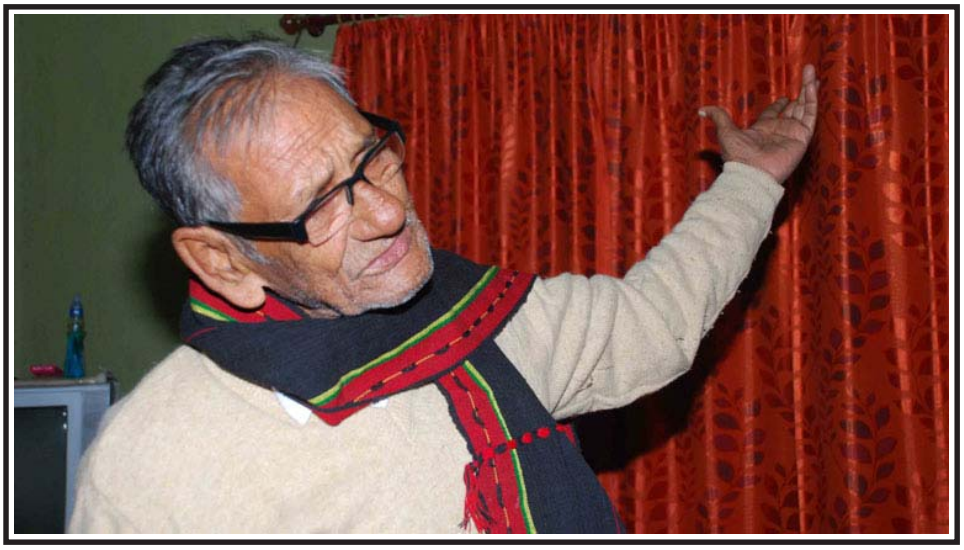

उनके दीर्घ राजनीतिक जीवन के अंदर एकबार 1971 से 1977 तक यानी 6 वर्षों तक और दूसरी बार 2005 से 2014 तक यानी 9 वर्षों से भी अधिक समय जेल जीवन के हैं। उनके जेल जीवन की खासियत या सबसे ज्यादा सकारात्मक पहलू यह रहा कि दोनों बार अत्याचारी शासक गुट व उनके पहरेदार पुलिस व इंटेलिजेन्स (खुफिया) विभाग के आला अफसरों द्वारा बंदी नारायण सन्याल के शरीर पर अनेकों अत्याचार एवं मानसिक रूप से काफी परेशान करने व टॉर्चर करने के बावजूद लम्बे कद के व सर उंचा उठाकर चलनेवाले कामरेड नारायण सन्याल को कभी भी थोड़ा सा के लिए भी सर झुकाने के लिए मजबूर करना संभव नहीं हुआ। कामरेड नारायण सन्याल के जेल जीवन शासक वर्गों के सरेंडर पॉलिसी (आत्मसमर्पण की नीति) को घृणा के साथ लात मारकर उसे पूरी तरह खारिज कर देने का एक उज्ज्वल उदाहरण है। एक कम्युनिस्ट क्रांतिकारी दुश्मन के हाथ में चले जाने तथा क्रूर अत्याचार झेलने के बावजूद सर कटाना जानते हैं, पर सर झुकाना नहीं- यह बात अक्षरशः कामरेड नारायण सन्याल के बंदी जीवन में प्रमाणित होती है। आज जब दुश्मन की आत्मसमर्पण नीति के फंदे में जाकर कई अधःपतित लोग आत्मसमर्पण कर पार्टी, क्रांति व जनता के साथ गद्दारी कर चुके हैं, तब कामरेड नारायण सन्याल द्वारा उसे लात मारकर घृणा के साथ ठुकरा देने का उदाहरण हमारे लिए एक प्रेरणादायी सीख है।

संशोधनवाद के खिलाफ, चाहे वो दक्षिण हो या वाम, संघर्ष में कामरेड नारायण सन्याल अग्रिम पंक्ति के एक जबरदस्त योद्धा थे। उनका यह पक्ष भी हम सबों के लिए बतौर एक उज्ज्वल मिसाल मौजूद है।

पार्टी के संविधान व अनुशासन को वे अपने राजनीतिक जीवन में काफी तरजीह देते थे। किसी भी विषय पर उनके व्यक्तिगत मत को वे बिना कोई हिचकिचाहट से सीधा-सीधी, लेकिन पार्टी संविधान के नियमों को मानकर, लिखित अथवा मौखिक रूप से पार्टी के संबंधित कमेटी में रखते थे और बहस भी चलाते थे।

एक पुराने व उम्रदराज कामरेड होने के नाते वे अनेकों

प्रकार के अनुभवों का भंडार थे। आज हमारे बीच ऐसे वरिष्ठ कामरेड का न रहना, हमारी नयी पीढ़ी व पार्टी के लिए एक भारी कमी का महसूस होना लाजिमी है। ऐसे एक वरिष्ठ साथी कामरेड नारायण सन्याल का निधन सचमुच ही हमारे लिए पहाड़ से भी भारी है। इसलिए, कामरेड नारायण सन्याल की मृत्यु एक महान शहीद की मृत्यु है।

आवें, महान शहीद कामरेड नारायण सन्याल के अधूरे सपने व अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए हम सब आगे बढ़ें।

आवें, आम जनता के स्वार्थ में, क्रांति व पार्टी के स्वार्थ में उनके अमूल्य प्राण को न्यौछावर करने के अंदर निहित गुणों को आत्मसात करते हुए उसे कार्यान्वित करें।

अमर शहीद कामरेड नारायण सन्याल को शत्-शत् लाल सलाम!

(नोटः- अमर शहीद कामरेड नारायण सन्याल की विस्तृत जीवनी हम अगले अंक में प्रकाशित करने की कोशिश करेंगे - संपादकमंडल, लाल चिनगारी)

अमर शहीद कामरेड रामचंद्र महतो उर्फ चिराग (प्रमोद/योधन) को शत्-शत् लाल सलाम!

विगत् 29 जनवरी 2016 को जमुई जिला के चकाई थाना और चंद्रमंडी थाना की सीमा पर स्थित बमदाह मोड़ और चकाई बाजार के बीच ताराखार गांव के समीप बोलेरो में धोती-खालता का वेश बदलकर एम्बुश पर तैनात सीआरपीएफ वालों ने हमारी पार्टी के पूर्वी बिहार-पूर्वोत्तर झारखण्ड स्पेशल एरिया कमेटी के सदस्य कामरेड रामचंद्र महतो उर्फ चिराग को उस समय गिरफ्तार किया, जब उनका मोटरसाइकिल वहां पहुँचा । असल में उनका साथ मोटरसाइकिल चलाने वाला ही कोवर्ट (भीतरघाती) था। साथी चिराग को इसकी जानकारी ही नहीं थी। जैसे ही मोटरसाइकिल ताराखाार मोड़ के पास पहुंचा, वैसे ही उस गद्दार ने मोटरसाइकिल खड़ा कर दिया और अपना दोनों हाथ को उपर उठाया। तब पुलिस वालों ने विसिल बजाया। एक कम्बल से कामरेड चिराग के माथा व पूरे शरीर को ढक दिया और बोलेरो में चढ़ाकर गुप्त स्थान पर ले जाया गया। जहां उनके उपर दरिंदा पुलिस वालों ने काफी यातनाएं दी और बाद में इसी जिला के ही चरकापत्थर थानान्तर्गत असरखों जंगल में लाकर वहां पर एक पेड़ में बांध दिया और उस पर गोली चलाकर निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी। सरकार पोषित भाड़े की सेना ने मुठभेड़ का दिखावे के लिए कारतूस (पेरा लाइट) मोर्टर फायरिंग किया और मीडिया ने पुलिस का दिया हुआ समाचार प्रचार किया कि नक्सली और पुलिस के साथ हुई भीषण मुठभेड़ में नक्सली नेता चिराग मारा गया। दरअसल ये सभी सरासर झूठ है। हकीकत में एक सोची-समझी साजिश के तहत फर्जी मुठभेड़ के जरिए उनकी हत्या की गई है। इस तरह से हमारी पार्टी के पूर्वी बिहार-पूर्वोत्तर झारखण्ड स्पेशल एरिया कमिटी के एक महत्वपूर्ण कॉमरेड रामचंद्र महतो उर्फ चिराग को हम सबों से सदा के लिए दुश्मनों ने छीन लिया।

कामरेड चिराग की बचपन की तस्वीर

अमर शहीद का. रामचंद्र महतो उर्फ चिराग का जन्म झारखण्ड प्रान्त के बोकारो जिला के नावाडीह थानान्तर्गत पीपराडीह उपरघाट इलाके के लहिया नारायणपुर के बगल के पीपराडीह गांव में एक मध्यम किसान परिवार में हुआ था। सन् 1998 में वे छात्र जीवन में ही पार्टी के सम्पर्क में आये और पार्टी के निर्णयानुसार युवा संगठन में जुड़े। वे झारखण्ड मे कम्युनिस्ट युवा लीग के सदस्य के रुप में कार्यरत रहे। सन् 2002 में उनको युवा संगठन से गुप्त संगठन के सदस्य के रुप में लिया गया।

इसी बीच जिलंगा पहाड़ में ''हील टॉप'' के नाम से दुश्मनों का एक बड़ा अभियान जारी होने वाला था। इसी अभियान के प्रतिरोध के लिए तीन प्लाटून पीएलजीए बल का गठन किया जाना तय हुआ था। इसमें दो प्लाटून बल मौजूद था, लेकिन एक प्लाटून बल नहीं था। तब चंचल व दक्षिणी

डुमरी क्षेत्र में कार्यरत साथियों को लेकर एक नया पीएल यानी प्लाटून नं. 34 का गठन किया गया। इस प्लाटून में कामरेड चिराग भी थे। प्लाटून नं. 34 का डिप्टी कमांडर के रुप में पार्टी से उनको जिम्मेवारी दिया गया। वखूबी उन्होंने अपना जिम्मेवारी निभाया। कुछ दिन के बाद उनके प्लाटून को ही चंचल एरिया भेजा गया। चंचल एरिया में झारखण्ड के तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबुलाल मरांडी के नेतृत्व में दमन अभियान व्यापक रुप से चलाया जा रहा था, माओवादी आंदोलन के खिलाफ उसने सेंदरा गुण्डा गिरोह का गठन किया था। इस सेंदरा गुण्डा गिरोह ने पूरे चंचल एरिया को ही अपने कब्जे में ले लिया। तब रीजनल कमेटी के निर्णयानुसार गिरिडीह जिला के उत्तरी हिस्सा, जो पार्टी में चंचल एरिया के नाम से जाना जाता है, को जेबी जोन से ही देख-रेख करने का निर्णय हुआ। तब कामरेड चिराग का प्लाटून नं. 38 जेबी-जोन की ओर ही आयी। जेबी जोन के चरकापत्थर एरिया से चंचल एरिया की देख-रेख करना शुरु किया गया। इसी बीच कामरेड चिराग को प्लाटून नं. 38 का कमांडर बनाया गया। कुछ दिन के अन्तराल में ही जेबी-जोनल कमेटी का सदस्य भी बनाया गया। उनके कामकाजों को देखते हुए चंचल एरिया में पार्टी के कामकाजों के विस्तार के लिए जल्द ही रीजनल कमिटी में उन्हें को-ऑप्ट किया गया। सन् 2011 के दिसम्बर में बीजे सैक का दूसरा प्लेनम हुआ। जिसमें वे सैक सदस्य के रुप में निर्वाचित हुए। जेबी जोन से एक सैक सदस्य की गिरफ्तारी के बाद जेबी-जोन के कामकाजों को सम्भालने में उन्होंने अहम भूमिका निभाया तथा 8 महीना के अंदर ही गिरिडीह जेल में बंद सैक सदस्य सहित 6 साथियों को कैदी वैन पर हमला कर दुश्मन के कैद से मुक्त कराने की संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। उनके काम काजों व दुश्मन को तंग करने के लाल आतंक को देखकर स्थानीय राजनेताओं, सामंती तत्वों, ठेकेदारों, सेंदरा गुण्डों व झारखण्ड-बिहार दोनों प्रांतों के दलाल शासक सरकारों के लिए बौखलाहट का कारण बना, अंत में उक्त गठजोड़ ने कामरेड रामचंद्र महतो उर्फ चिराग को अपनी जाल में फंसाने का षड़यंत्र रचा और हमारी पार्टी के इने-गिने समर्थकों को रुपया-पैसा का लोभ-लालच व दबाव देकर अपना कोवर्ट बनाया और हमारे भीतर घुसाकर उसको ऐसा आदमी बनाया, जो पार्टी को पूरा विश्वास दिला सके। पार्टी के लिए ठहरने की जगह, खाना व एक जगह से दूसरी जगह तक गाड़ी से पहुंचा देने व बाजार से सामानों को खरीद कर ला देने का काम करना- इस तरह कोवर्ट की भूमिका का पलन करता रहा और अन्ततः मौका पाते ही दुश्मन की पूरी योजना के मुताबिक कामरेड चिराग को गिरफ्तार कर यातनाएं दी गयी और बाद में कामरेड चिराग ने अपनी जान की कुर्बानी देना पसंद किया, पर हजारों यातनाएं व टॉर्चर के बावजूद 'नो सरेंडर (सरेंडर नहीं)' पर अडिग रहा। कामरेड चिराग मतलब 'नो सरेंडर', जो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। जब कामरेड चिराग ने पार्टी का एक भी गुप्त बात नहीं खोला, तब फर्जी मुठभेड़ में उनकी हत्या कर सदा के लिए हम सबों से छीन लिया।

अमर शहीद कामरेड चिराग के योगदान पर दो-चार बात कहा जाये, तो- 11 नबम्बर 2005 को गिरिडीह होमगार्ड शस्त्रागार पर हमला में एक टीम का डिप्टी कमांडर की भूमिका निभाया। तोपचांची (धनबाद) ब्लॉक में तैनात जेएपी कैम्प पर हमला करने की कार्रवाई में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। इस लड़ाई में वे हाथ में चोट लगने से घायल भी हो गये थे। जिसके कारण उनका एक अंगुली सीधा ही रहता था। केंद्रीय कमेटी के द्वारा आयोजित ओड़िशा के उदयगिरी जेल ब्रेक और एक कैम्प पर हमला कर साथियों को जेल से मुक्त करना और भारी मात्रा में हथियार जब्त करने की कार्रवाई में शामिल था। उसमें भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। सन् 2008 में सर्वप्रथम उपरी कमेटी के सलाहनुसार उनके कमांड में मुंगेर जिला के ऋृषिकुंड पर्यटक स्थल में सुरक्षा के नाम पर तैनात सैप जवानों पर हमला कर 4 पुलिस वालों को मार गिराकर दो एके 47 और एक इंसास तथा एक एसएलआर जैसे अत्याधुनिक हथियार जब्त करने की कार्रवाई तथा पूरी टीम का संचालन करने में अच्छा योगदान दिया था। सन् 2008 में झाझा रेलवे पुलिस थाना पर हमला कर 42 हथियार को जब्त करने की कार्रवाई में डिप्टी कमांडर की भूमिका निभाया तथा एक टीम यानी स्टॉप पार्टी 1 का जिम्मेवारी लिया और दुश्मन को एक इंच भी आगे नहीं आने दिया। सन् 2009 के फरवरी में नवादा जिला के महुलियाटांड गांव में रविदास जयंती के अवसर पर आयोजित मेला को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आयी स्कॉट पार्टी पर हमला कर 14 आधुनिक हथियारों को जब्त किया गया था, उस कार्रवाई में भी जमीनी तौर पर एक सलाहकार की भूमिका निभाया। उसी साल 23 जून 2009 को लखीसराय कोर्ट परिसर में हमलाकर पोलित ब्यूरो सदस्य तथा पूर्वी रीजनल ब्यूरो का कमांडर इन चीफ को पुलिस हिरासत से छुड़ाकर सुरक्षित अपने गुरिल्ला आधार इलाके में लाने के मामले में एसाल्ट पार्टी में डिप्टी कमांडर

की महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। उसी साल ही जमुई जिला के सोनो चौक पर स्काउट पार्टी पर हमला कर हथियार जब्त करने की कार्रवाई में भी एक सलाहकार की भूमिका निभाया था। गिरिडीह जिला और कोडरमा जिला में झाविमो के सुप्रीमो बाबुलाल मराण्डी के नेतृत्व में क्रांतिकारी आंदोलन को कुचलने के लिए ग्राम रक्षा दल (सेंदरा) का गठन किया था। हमारे पार्टी के साथ गोलबंद हुए जनता को पार्टी से अलग-थलग करने के लिए जनता पर सेंदरा गुण्डों ने मारपीट, जेल भेजना, यातनाएं देने और पार्टी को सपोर्ट करने वाले को जान से मार डालने जैसे कुकर्म को चलाया है और चला रहा है। इसमें राज्य सरकार व सामंती तत्वों की प्रत्यक्ष भूमिका है। इस सरकार पोषित गुण्डों के उपर हमला चलाकर पुनः अपने कब्जे में इलाके को हासिल करने की योजना के मुताबिक सीसी के दिशा-निर्देश पर बीजे सैक (अब इबी इएनजे सैक) ने कामरेड चिराग को ही एक स्पेशल प्लाटून बनाकर जिम्मेवारी दिया। जिम्मेवारी देने के बाद वह बखूबी अपने क्षेत्र में गये और सेंदरा गुण्डों के उपर पल्टा कार्यवाही चलाना शुरु किये। फलस्वरुप सेंदरा गुण्डों को भागना पड़ा व कुछ को डर के मारे चुपचाप रहना पड़ा। कुल मिलाकर कहा जाय तो दुश्मन के प्रति उनकी काफी नफरत थी। इसलिए वे हर समय दुश्मन को घृणा के दृष्टिकोण से ही देखते थे। दुश्मनों पर कार्रवाई करने के मामले में पीछे नहीं हटते थे और न ही किसी ठेकेदारों से दोस्ती करते थे। ठेकेदार व कुछ मुखिया तो उनके नाम और बोली से ही डर जाता था। वे क्रांति के लिए हर हमेशा समर्पित रहते थे। वे कहते भी थे कि दुश्मन हमें जब पकड़ेगा, तो डायरेक्ट सूट ही कर देगा। पर हम दुश्मनों को तो छोड़ने वाले नहीं हैं। पूरे पार्टी लाइफ में वे क्रांति के प्रति सदा अडिग रहे।

अंत तक राजनेता, सामंत, भूस्वामी व पुलिस के आलाधिकारियों की मिलीभगत के जरिए कामरेड चिराग की हत्या करने के लिए एक सोची-समझी साजिश रची गयी। इस साजिश के तहत ही दिनांक 29/01/2016 को कामरेड चिराग को गिरफ्तार कर एक ही दिन के अंदर पूरी यातनाएं देकर व मुठभेड़ का दिखावा कर ठंडे दिमाग से पेड़ से बांधकर गोली मारकर हत्या कर दी गयी।

अमर शहीद कामरेड चिराग का दुश्मन ने निर्ममतापूर्वक हत्या कर दिया और कामरेड चिराग सदा-सदा के लिए शहीद हो गए । कामरेड चिराग की शहादत से भाकपा (माओवादी) पार्टी के लिए खास कर पूर्वी बिहार-पूर्वोत्तर झारखंड स्पेशल एरिया कमिटी के लिए तथा सैक के अंतर्गत शेखपुरा-नवादा-कोडरमा सीमांत जोनल कमेटी के लिए अपूरणीय क्षति हुई है।

आज कामरेड चिराग की हत्या भले ही कर दी गई है, पर उनके विचार सदैव मजदूर-किसानों के दिलो दिमाग में अमर रहेगा तथा उनके अधूरे सपने को पूरा करने के लिए संकल्प लेंगे तथा क्रांतिकारी आंदोलन को तब तक आगे बढ़ाते रहेंगे, जब तक वर्गहीन-शोषणहीन समाज की यानी समाजवाद-साम्यवाद की स्थापना नहीं होगी।

अमर शहीद कामरेड काजल कुमारी को शत्-शत् लाल सलाम!

अमर शहीद कामरेड काजल कुमारी हमारे बीच नहीं रहे। दिनांक.... को लखीसराय जिला के पीरी बजार थाना अंतर्गत बंगालीबांध में गम्भीर मलेरिया बीमारी से शहीद हो गये। अमर शहीद कामरेड काजल कुमारी लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा थाना अंतर्गत कटेहर गांव में कानू साह जाति के गरीब किसान परिवार में पैदा हुई थे। चूंकि यह क्षेत्र समतल मैदानों से घिरा हुआ क्षेत्र है। यहां करीब-करीब बहुत लोग शिक्षित है। उनके माता-पिता के अंदर भी शिक्षा का कुछ प्रभाव था। इसीलिए अपने बेटी की पढ़ाई पर ध्यान दिये और उनकी पढ़ाई मैट्रिक तक हुई। पर बोर्ड परीक्षा देने के पहले ही उनके गोतिया वाले ने जमीन हड़पने के लिए उनके पिता और माता तथा भाई की हत्या कर दी। इस तरह वे अकेली थी। उनकी चचेरी मामी जमुई क्षेत्र के संगठन से प्रभावित गांव की है, ने ही पार्टी के बारे में बताया कि जनता को न्याय दिलाने वाली एक मात्र पार्टी भाकपा (माओवादी) है। आप जाएं फलाने जगह में और पार्टी से सम्पर्क करें। सभी समस्या हल हो जाएगा । क्यों पुलिस-प्रशासन, थाना-ब्लॉक, कोर्ट-कचहरी तथा मुखिया-सरपंच के पास दौड़ रहे हैं? सभी लूटेरे हैं, घुसखोर हैं व भ्रष्टाचारी हैं, यहां से कुछ नहीं होगा।

इसी बातों को सुनकर व समझकर पार्टी को खोजने के

शेष पृष्ठ संख्या 20 पर

भारत में वसंत का वज्रनाद

(चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय कमेटी के मुखपत्र पीपुल्स डेली (5 जुलाई, 1967) में प्रकाशित इस अतिमहत्वपूर्ण लेख ने ऐतिहासिक नक्सलबाड़ी किसान संघर्ष का अभिनंदन किया था और इसके महत्व को बताया था, इस लेख में अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट नेतृत्व द्वारा भारतीय क्रांति का आधारभूत मूल्यांकन किया गया है। - सम्पादकमंडल, लाल चिनगारी)

भारतभूमि पर वसंत का वज्रनाद गड़गड़ा उठा है। दार्जिलिंग इलाके के क्रांतिकारी किसान विद्रोह कर उठे हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के एक क्रांतिकारी हिस्से के नेतृत्व में, भारत में ग्रामीण क्रांतिकारी सशस्त्र संघर्ष का एक लाल इलाका कायम किया जा चुका है। भारतीय जनता के क्रांतिकारी संघर्ष के लिए यह विकास काफी महत्वपूर्ण है।

पिछले कुछ महीनों में, इस इलाके के किसान जनसमुदाय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के एक क्रांतिकारी हिस्से के नेतृत्व में आधुनिक संशोधनवाद की जंजीरों को तोड़ डाला है और उन्हें जिन बंधनों ने बांध रखा था, उन्हें चकनाचूर कर डाला है। उन्होंने जमींदारों और चाय बगान मालिकों से अनाज, जमीन और हथियार जब्त कर लिया है, स्थानीय जुल्मियों और बुरे शरीफजादों को सजा दी है तथा प्रतिक्रांतिकारी सेना और पुलिस को, जो उन्हें दबाने के लिए आई थी, एम्बुश किया है। इस तरह उन्होंने किसानों के क्रांतिकारी सशस्त्र संघर्ष के प्रचंड ताकत का प्रदर्शन किया है। तमाम साम्राज्यवादी, संशोध नवादी, भ्रष्ट पदाधिकारी, स्थानीय जुल्मी और बुरे शरीफजादों तथा प्रतिक्रांतिकारी सेना और पुलिस उन क्रांतिकारी किसानों, जो उन्हें धूल में मिला देने को कमर कसे हैं, की नजरों में कुछ भी नहीं हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के क्रांतिकारी हिस्से के द्वारा एक बिल्कुल सही चीज की गई है और उन्होंने इसे शानदार ढंग से किया है। दार्जिलिंग इलाके के भारतीय किसानों के इस क्रांतिकारी तूफान का अभिनंदन चीनी जनता आनंद विभोर होकर करती है, जैसे कि दुनिया भर की मार्क्सवादी-लेनिनवादी और क्रांतिकारी जनता करती है।

यह एक अनिवार्य तथ्य है कि भारत के किसान विद्रोह करेंगे ही और भारतीय जनता क्रांति करेगी ही, क्योंकि, प्रतिक्रियावादी कांग्रेस शासन ने उनके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं छोड़ा है। कांग्रेस शासन के अंतर्गत भारत नाममात्र को ही स्वतंत्र है: दरअसल यह एक अर्ध-औपनिवेशिक और अर्ध-सामंती देश के अलावा और कुछ नहीं। कांग्रेस शासन भारतीय सामंत राजकुमारों, बड़े जमींदारों और दलाल नौकरशाह पूंजीपतियों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है। देश के अंदर एक ओर, वह भारतीय जनता की निर्ममतापूर्वक दमन करती है और खून चूसती है, तो दूसरी ओर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वह अपने पुराने आका ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अलावे, नए मालिक अमेरिकी साम्राज्यवाद और उसके अव्वल दर्जे का साझीदार सोवियत संशोधनवादी शासक गुट की खिदमत करता है और इस तरह राष्ट्रीय हितों को बड़े पैमाने पर बेचता है। अत: साम्राज्यवाद, सोवियत संशोधनवाद, सामंतवाद और दलाल नौकरशाह, पूंजीवाद भारतीय जनता खासकर मेहनतकश मजदूर-किसान जनता की पीठ पर भारी पहाड़ों की तरह लदे हैं।

कांग्रेस शासन ने पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता के दमन और शोषण को और भी तेज कर दिया है तथा राष्ट्रीय गद्दारी की नीति अपनाई है। साल-दर-साल अकाल चक्कर काटती रहती है, खेत अनाहार और भूखमरी से मरे लोगों की लाशों से पटी है। भारतीय जनता और सर्वोपरि, भारतीय किसानों के लिए जीना दुर्लभ हो गया है। दार्जिलिंग इलाके के क्रांतिकारी किसान अब विद्रोह के लिए उठे खड़े हुए हैं, हिंसक क्रांति के लिए उठ खड़े हुए हैं। यह लाखों-करोड़ों जनता की भारतव्यापी हिंसक क्रांति की प्रस्तावना है। भारतीय जनता निश्चय ही इन पहाड़ों को पीठ पर से उतार फेंकेगी और पूरी मुक्ति हासिल करेगी। यह भारतीय इतिहास की आम प्रवृत्ति है, जिसे धरती की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती, न अटका सकती है।

भारतीय क्रांति को कौन सा रास्ता अपनाना है? यह भारतीय क्रांति की सफलता और 50 करोड़ भारतीय जनता के भाग्य को प्रभावित करने वाला एक बुनियादी सवाल है, भारतीय क्रांति को किसानों पर भरोसा करने, देहातों में आधार इलाका कायम करने, दीर्घकालीन सशस्त्र संघर्ष में डटे रहने और शहरों को देहातों से घेर लेने तथा अंत में उनपर कब्जा कर लेने का रास्ता अपनाना चाहिए। ये माओ त्सेतुंग का रास्ता है, यह वह रास्ता है, जिसने चीनी क्रांति को विजय तक पहुंचाया, यह तमाम उत्पीड़ित राष्ट्रों और जनता की क्रांति के विजय का एकमात्र रास्ता है।

हमारे महान नेता चेयरमैन माओ त्सेतुंग ने 40 साल पहले ही बताया था, कुछ ही दिनों के अंदर चीन के मध्यवर्ती, दक्षिण और उत्तरी प्रांतों में दसियों करोड़ किसान एक प्रबल झंझावात या प्रचंड तूफान की तरह उठ खड़े होंगे। यह एक ऐसी अद्‌भुत वेगवान और विध्वंसकारी शक्ति होगी कि बड़ी से बड़ी ताकत भी उसे दबा न सकेगी। किसान अपने उन समस्त संबंधों को जो अभी उन्हें बांधे हैं, तोड़ डालेंगे और मुक्ति के मार्ग पर तेजी से चलेंगे। वे सभी साम्राज्यवादियों,

युद्ध सरदारों, भ्रष्ट अफसरों, स्थानीय अत्याचारियों और बुरे शरीफजादों को यमलोक भेज देंगे।

चेयरमैन माओ ने पहले ही स्पष्ट रूप से बताया था कि किसानों का सवाल जनता की क्रांति में अतिमहत्वपूर्ण स्थान रखता है। साम्राज्यवाद और उनके पिछलग्गुओं के खिलाफ राष्ट्रीय जनवादी क्रांति में किसान मुख्य ताकत है। वे सर्वहारा के बहुत ज्यादा विश्वसनीय और बहुसंख्यक मित्र हैं। भारत 50 करोड़ आबादी का एक अर्ध-औपनिवेशिक और अर्ध-सामंती देश है, जिसके पूर्ण बहुतम किसान, अगर एक बार जागृत किये जाएं, तो वे भारतीय क्रांति के एक अजेय ताकत बन जाएंगे। किसानों के साथ एकरूप होकर भारतीय सर्वहारा भारत के देहाती इलाकों में भूकंपकारी परिवर्तन ले आने और थर्रा देने वाले लोकयुद्ध में किसी ताकतवर दुश्मन को परास्त कर देने में समर्थ होंगे।

हमारे महान नेता चेयरमैन माओ हमें सिखाते हैं - शस्त्र-बल द्वारा सत्ता छीनना, युद्ध द्वारा मसले को सुलझाना, क्रांति का केंद्रीय कार्य और सर्वोच्च रूप है। क्रांति का यह मार्क्सवादी-लेनिनवादी उसूल सर्वत्र लागू होता है, चीन पर और अन्य सभी देशों पर लागू होता है।

चीनी क्रांति की तरह भारतीय क्रांति की ठोस विशेषता भी सशस्त्र संघर्ष ही एकमात्र सही रास्ता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं। गांधीवाद, संसदीय मार्ग और इस तरह के अन्य जाल भारतीय शासक वर्गों के द्वारा भारतीय जनता को पंगु बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला अफीम है। सिर्फ हिंसक क्रांति पर विश्वास करके और सशस्त्र संघर्ष के रास्ते को अपनाकर ही भारत को बचाया जा सकता है और भारतीय जनता पूरी मुक्ति प्राप्त कर सकती है। खासकर यह किसान जनता को निर्भीक रूप से जागृत करना, क्रांतिकारी सशस्त्र ताकतों की स्थापना और विस्तार करना, चेयरमैन माओ द्वारा खुद तैयार की हुई लोकयुद्ध की सारी रणनीति-कार्यनीति का इस्तेमाल कर साम्राज्यवादियों और प्रतिक्रियावादियों के सशस्त्र दमन पर चोट करना, जो अस्थायी तौर पर क्रांतिकारी ताकतों से ज्यादा शक्तिशाली है और दीर्घकालीन सशस्त्र संघर्ष पर डटे रहना तथा कदम-ब-कदम जीत हासिल करना है।

चीनी क्रांति की विशेषताओं की रोशनी में हमारे महान नेता चेयरमैन माओ ने देहाती क्रांतिकारी आधार इलाके कायम करने की महत्ता बताई है। चेयरमैन माओ हमें सिखाते हैं - दीर्घकालीन सशस्त्र संघर्ष पर डटे रहने तथा साम्राज्यवाद और उसके पिछलग्गुओं को हराने के लिए, क्रांतिकारी कतारों के लिए पिछड़े हुए गांवों को आगे बढ़े हुए सुसंगठित आधार क्षेत्रों में बदलना, क्रांति के सैनिक राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गढ़ के रूप में परिणत करना, जहां से वे अपने दुष्ट शत्रुओं से लड़ सकें, जो शहरों को ग्रामीण इलाकों पर हमला करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है और इस प्रकार धीरे-धीरे दीर्घकालीन लड़ाई के जरिए पूरी विजय प्राप्त कर लेना अनिवार्य है।

भारत एक विशाल भूभागों वाला देश है। इसका देहाती इलाका, जहां प्रतिक्रियावादी शासन कमजोर है, एक विशाल इलाका प्रदान करता है, जहां क्रांतिकारी स्वतंत्र रूप से कौशलों का इस्तेमाल कर सकते हैं जबतक भारतीय सर्वहारा क्रांतिकारी मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओ त्सेतुंग विचारधारा (अब माओवाद) की क्रांतिकारी लाइन पर डटे रहेंगे और अपने महान मित्र किसानों पर भरोसा रखेंगे तबतक उनके एक विशाल पिछड़े हुए देहाती इलाकों में एक के बाद एक आगे बढ़े हुए देहाती इलाके कायम करना और एक नये किस्म की जनसेना का निर्माण करना बिल्कुल संभव है। भारतीय क्रांतिकारियों को ऐसे क्रांतिकारी आधार इलाके कायम करने के दौरान चाहे जिन कठिनाइयों और चढ़ाव-उतार का सामना करना पड़े, अंततोगत्वा वे अलग-अलग पड़े बिंदुओं से एक विशाल फैलाव में, छोटे-छोटे इलाकों से एक विस्तृत इलाकों में, लहरों के एक श्रृंखला के विस्तार के समान ऐसे इलाके विकसित कर लेंगे। इस तरह शहरों और नगरों पर अंतिम रूप से कब्जा करने और राष्ट्रव्यापी जीत हासिल करने की राह साफ करने के लिए देहातों से शहरों को घेरने की स्थिति भारतीय क्रांति में धीरे-धीरे लाई जाएगी।

दार्जिलिंग में देहाती सशस्त्र संघर्ष के विकास से भारतीय प्रतिक्रांतिकारी आतंकित हो उठे हैं। वे आसन्न विपत्ति को भांप गए हैं और घबराहट से चीख रहे हैं कि दार्जिलिंग के किसानों का विद्रोह एक राष्ट्रीय विपत्ति में बदल जाएगा। साम्राज्यवाद और भारतीय प्रतिक्रियावादी दार्जिलिंग के किसानों के इस सशस्त्र संघर्ष को हजारों तरीकों से दबा देने और उसे कली की अवस्था में ही टूंग देने की कोशिश कर रहे हैं। डांगे गद्दार गुट और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संशोधनवादी सरगने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के क्रांतिकारियों पर और दार्जिलिंग के क्रांतिकारी किसानों पर, उनकी महान उपलब्धियों के लिए, भयंकर हमला कर रहे हैं और उन्हें बदनाम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की तथाकथित गैर-कांग्रेसी सरकार दार्जिलिंग के क्रांतिकारी किसानों के खूनी दमन में खुलेआम भारतीय प्रतिक्रयावादी सरकार का पक्ष ले रही है। यह अतिरिक्त सबूत पेश करता है कि ये गद्दार और संशोधनवादी साम्राज्यवाद के पालतू कुत्ते हैं तथा भारत के बड़े जमींदारों और पूंजीपतियों के पिछलग्गु हैं। जिसे वे गैर-कांग्रेसी सरकार कहते हैं, वह इन जमींदारों और पूंजीपतियों का एक हथियार भर है।

लेकिन, साम्राज्यवादी भारतीय प्रतिक्रियावादी और आधुनिक

शेष पृष्ठ संख्या 20 पर

संशोधनवाद के खिलाफ संघर्ष करके ही किसान संघर्ष को आगे बढ़ाना होगा

(यह लेख हमारी पार्टी के अग्रणी व अप्रतिम नेता कामरेड चारू मजुमदार के सुप्रसिद्ध आठ दस्तावेज का अंतिम यानी कि आठवां दस्तावेज है। इस लेख को अप्रैल, 1967 में लिखा गया था, इसके प्रकाशित हाने के बाद ही महान ऐतिहासिक नक्सलबाड़ी सशस्त्र किसान विद्रोह प्रारंभ हुआ था, जिसने भारत के कम्युनिस्ट आंदोलन में लम्बे समय से चली आ रही संशोधनवादी लाइन, व्यवहार व कार्यशैली के खिलाफ भारतीय क्रांति की सही लाइन को स्थापित किया। उस समय कामरेड चारू मजुमदार सीपीएम (मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी) के पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिला के नेता थे। - संपादकमंडल, लाल चिनगारी)

चुनाव के बाद पार्टी नेतृत्व हमारी आकांक्षा को सच साबित करने में जी-जान से लग गया है। पीबी (पोलित-ब्यूरो) ने हमारा काम निर्धारित किया है ''गैर-कांग्रेसी मंत्रिमंडल को प्रतिक्रिया के हाथ से बचाने का संघर्ष करना होगा'' अर्थात् वर्ग संघर्ष को तेज करना नहीं, मंत्रिमंडल के पक्ष में वकालत करना ही मार्क्सवादियों का मुख्य काम होगा। इसलिए मजदूर वर्ग के अंदर अर्थवाद को सुप्रतिष्ठित करने के लिए पार्टी सदस्यों का कन्वेंशन बुलाया गया और इसके बाद ही मंत्रिमंडल के नेतृत्व में उद्योगों में शांति-संधि संपन्न हुई। मजदूरों को घेराव करने से मना किया गया, वर्ग समझौता का इससे नंगा चेहरा और क्या हो सकता है? मालिक पक्ष को शोषण करने का पूरा अधिकार देकर मजदूरों को किसी भी तरह का संघर्ष न करने को कहा जा रहा है। विराट जनांदोलन के फलस्वरूप जो सरकार कायम हुई, उस सरकार में कम्युनिस्ट पार्टी के भाग लेने के साथ ही साथ उसने वर्ग संघर्ष का रास्ता चुना है। चीनी नेताओं ने बहुत पहले ही भविष्यवाणी की थी कि जो अंतरराष्ट्रीय मतभेदों के बारे में तटस्थ नीति अपना रहे हैं, वे बहुत जल्दी ही अवसरवादी रास्ता अपनाएंगे और अभी चीनी नेताओं ने कहा है कि ये तटस्थ नीति वाले दरअसल संशोध नवादी हैं, जो बहुत ही जल्दी प्रतिक्रांतिकारी खेमे में चले जाएंगे। हमने इस सच्चाई को अपने देश में प्रत्यक्ष रूप से देखा है। मजदूर वर्ग के प्रति गद्दारी हमने अपनी आंखों से देखी है और अब इसके साथ कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हरेकृष्ण कोणार की घोषणा को जोड़ दें, पहले उसने वादा किया था कि सारी भेस्ट जमीन (गैरमजरूआ खास, अर्थात् गैरमजरूआ मालिक जमीन, वैसी जमीन, जिसे सरकार ने ले ली हो) भूमिहीन किसानों के बीच बांट देंगे। इसके बाद उसकी मात्रा घट गई। आखिरकार उसने घोषणा किया कि इस साल ज्यों का त्यों रहेगा। टैक्स माफ करने का मामला जेएलआरओ (जूनियर लैंड रेवेन्यू अफसर) की दया पर छोड़ दिया गया। किसानों को दरखास्त देने का रास्ता बताया गया तथा निर्देश दिया गया कि वे जबरदस्ती जमीन पर कब्जा न करें। हरेकृष्ण बाबू सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय कमेटी के सदस्य ही नहीं बल्कि बंगाल के राज्य किसान सभा के सचिव भी हैं। उन्हीं की किसान सभा के आह्वान पर 1959 में किसानों ने भेस्ट जमीन तथा बेनामी (गैरमजरूआ आम) जमीन पर कब्जा करने का आंदोलन चलाया था। सरकार ने जमीन-मालिकों के स्वार्थ में दमन चलाया और जमीन पर से हट जाने की राय दी। फिर भी किसानों ने अनेक इलाकों में जमीन नहीं छोड़ी। गांव की एकता के बल पर जमीन पर जबदस्ती कब्जा बनाए रखा। क्या किसान सभा के नेता ने मंत्री होने के बाद उनके आंदोलन का समर्थन किया? नहीं, उसने जो कहा उसका मतलब है, भेस्ट जमीन फिर से बांटी जाएगी। कौन पाएगा? जेएलआरओ इस मामले में किसान सभा की सलाह लेंगे। लेकिन क्या यह सलाह मान ली जाएगी? हरेकृष्ण बाबू ने ऐसा कोई भी वक्तव्य नहीं दिया। अगर जेएलआरओ किसान सभा की सलाह नहीं मानते हैं, तब भी किसानों को जमीन पर किसी भी हालत में जबरदस्ती कब्जा नहीं करना होगा, इस मामले में स्पष्ट बताने में देर नहीं की। इसे क्या कहा जाएगा? क्या यह सरकार तथा जमींदार की दलाली नहीं है? सामंतवर्ग के पक्ष में कभी बेशर्म वकालत करने का साहस कांग्रेसी भी नहीं कर पाये। इसलिए पार्टी नेताओं के निर्देश को मानने का मतलब है सामंतवाद के शोषण तथा शासन को बिना विचारे मंजूर करना। इसलिए कम्युनिस्टों की जिम्मेवारी है, इस नेतृत्व की वर्ग विरोधी प्रतिक्रियावादी भूमिका को पार्टी सदस्यों व जनता के बीच बेनकाब करना तथा वर्ग संघर्ष को तेज करने की नीति से आगे बढ़ना। मान लिया जाए, हरेकृष्ण बाबू के प्रस्ताव को मानकर भूमिहीन व गरीब किसान अगर दरखास्त देते हैं, तो क्या होगा? यह सच है कि भेस्ट जमीन में से कुछ बंजर है, लेकिन उपजाऊ जमीन ही ज्यादा है। इस उपजाऊ जमीन में जो किसान है - वे आज या तो लाइसेंस के बल पर जमीन का उपभोग कर रहे हैं या जमींदार को हिस्सा देते हैं। उस जमीन का जब फिर से बंटवारा होगा, तब अनिवार्य रूप से भूमिहीन व गरीब किसानों के बीच विरोध पैदा होगा और इसका मौका पाकर सारे किसान आंदोलन पर धनी किसानों का नेतृत्व कायम हो जाएगा, क्योंकि धनी किसानों को जैसे पैरवी करने की सुविधा है, वैसे ही सामंती प्रभाव में हिस्सेदार

भी हैं। भविष्य में भी किसान संघर्ष के रास्ते पर न चले जाएं, उसका भी इंतजाम कर दिया है।

लेकिन, हमने जनता की जनवादी क्रांति का कार्यक्रम लिया है और इस क्रांति का काम ही है किसानों के स्वार्थ में भूमि सुधार करना। किसानों के स्वार्थ में भूमि सुधार तभी हो सकता है, जब हम देहाती इलाकों में सामंत वर्ग के प्रभुत्व को खत्म कर पाएंगे। इस काम को करने के लिए हमें सामंत वर्ग के हाथों से जमीन छीन लेनी होगी और इसे भूमिहीन व गरीब किसानों के बीच बांटनी होगी। इस काम को हम कभी भी नहीं कर सकेंगे, अगर हमारा आंदोलन अर्थवाद के दायरे में बंधा रहेगा। सभी इलाकों में भेस्ट जमीन के लिए आंदोलन हुआ, वहां जो किसान जमीन दखल कर पाए या लाइसेंस प्राप्त कर पाए, वे किसान आंदोलन में और सक्रिय नहीं रहे। इसका कारण क्या है? इसका कारण है, उस गरीब किसान का वर्ग चरित्र एक साल के अंदर बदल गया है।

वह आज मध्यम किसान में बदल गया है। इसलिए भूमिहीन व गरीब किसानों की आर्थिक मांग अब और उसकी मांग नहीं रही है। यह अर्थवाद लड़ाकू किसान एकता में दरार पैदा करता है और गरीब तथा भूमिहीन किसानों को हताश करता है। कितने मन धान कब्जा किये गये या कितने बीघे जमीन किसानों को मिले – अर्थवाद इसी तरह हर संघर्ष पर विचार करते हैं। वे इस आधार पर कभी विचार नहीं करते कि किसानों की लड़ाकू चेतना बढ़ी है या नहीं। इसलिए वे किसानों की वर्ग चेतना बढ़ाने की कोई भी कोशिश नहीं करते। लेकिन हम जानते हैं कि बिना त्याग किये कोई भी संघर्ष नहीं किया जा सकता। चेयरमैन माओ ने सिखाया है कि जहां कहीं भी संघर्ष होता है, वहां कुर्बानी करनी ही पड़ती है, संघर्ष के पहले स्तर में जनता की ताकत से प्रतिक्रिया की ताकत ज्यादा रहेगी, इसलिए संघर्ष दीर्घकालीन होगा। चूंकि जनता प्रगतिशील ताकत है, इसलिए उसकी ताकत दिन-ब-दिन बढ़ती जाएगी और चूंकि प्रतिक्रियावादी ताकत मरणोन्मुख है, इसलिए उसकी ताकत दिन-ब-दिन घटती जाएगी। इसलिए जनता को त्याग करने के लिए प्रेरित नहीं कर पाने से कोई भी क्रांतिकारी संघर्ष सफल नहीं हो सकता। अर्थवाद इस बुनियादी क्रांतिकारी दृष्टिकोण से खींचकर बुर्जुआ दृष्टिकोण की अंधेरी गलियों में ले जाता है। पार्टी के नेता अपने सारे कार्यकलापों के जरीये ठीक यही काम कर रहे हैं। अगर हम पहले के किसान आंदोलनों का सिंहावलोकन करेंगे तो देखेंगे कि पार्टी के नेताओं ने हमेशा ही किसानों पर समझौता लाद दिया है जबकि पार्टी नेतृत्व की जिम्मेदारी थी कि किसान आंदोलन पर मजदूर वर्ग का लड़ाकू नेतृत्व कायम करना, यह काम उन्होंने पहले भी नहीं किया, न आज ही कर रहे हैं। आज वे कानून व नौकरशाही पर भरोसा करने को कह रहे हैं, जबकि लेनिन ने लिखा है कि अगर कोई प्रगतिशील कानून पास किया जाए और इसे कार्यान्वित करने की जिम्मेवारी नौकरशाही पर छोड़ दिया जाए, तब उससे किसान कुछ नहीं पाएंगे। अतः हमारे नेता, लेनिन तथा क्रांतिकारी रास्ते से बहुत दूर हट गये हैं।

कृषि क्रांति आज इसी वक्त का काम है। इस काम को रोक कर नहीं रखा जा सकता और इसे बिना किये किसानों की कुछ भी भलाई नहीं की जा सकती। लेकिन, कृषि क्रांति के पहले राजसत्ता का ध्वंस किया जाना चाहिए, राज्य यंत्र का ध्वंस किए बिना कृषि क्रांति करने का मतलब सीधा-सीधी संशोधनवाद है। इसलिए राज्य यंत्र का ध्वंस करने का काम आज किसान आंदोलन का पहला तथा मुख्य काम है। सारे देश तथा राज्य के पैमाने पर इस काम को अगर नहीं किया जा सके, तब क्या किसान चुप बैठे रहेंगे? नहीं, मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओ त्सेतुंग विचारधारा हमें सिखाता है कि अगर किसी इलाके के किसानों को राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित किया जाए तो उसी इलाके में राज्य यंत्र को तोड़ने के काम में आगे बढ़ना होगा। इसे ही किसान का मुक्तांचल कहा जाता है। मुक्तांचल गठन करने का यह संघर्ष ही आज किसान आंदोलन का सबसे जरूरी तथा फौरी काम है। मुक्तांचल हम किसे कहेंगे? जिन किसान इलाकों से हम वर्ग दुश्मनों को उखाड़ फेंक पाएं, उन सभी इलाकों को हम मुक्तांचल कहेंगे। इस मुक्तांचल को बनाने के लिए चाहिए किसानों की सशस्त्र शक्ति। इस सशस्त्र शक्ति में जैसे हम किसानों के हाथों तैयार घरेलू हथियार को लेते हैं, ठीक उसी तरह बंदूक की भी जरूरत है। किसान राजनीति से प्रेरित हुए है या नहीं, इसे हम किसान बंदूक संग्रह करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं या नहीं, इस आधार पर समझेंगे। किसान बंदूक कहां पाएंगे? वर्ग दुश्मनों के पास बंदूकें है और वे गांवों में ही रहते हैं। उनसे बंदूकें छीन लेनी होगी। वे स्वेच्छा से हमें बंदूक नहीं देंगे, इसलिए जबरदस्ती हमें उन बंदूकों पर कब्जा करना होगा। इसके लिए जंगी किसानों को वर्ग दुश्मनों के घरों में आग लगाने से लेकर के हर तरह के तरीके सिखानें होंगे। इसके अलावे सरकारी सशस्त्र सेना पर अचानक हमला करने से भी हमें बंदूक मिलेगी। इस बंदूक दखल अभियान को हम जिन इलाकों में संगठित कर पाएंगे, वह इलाका जल्दी ही मुक्तांचल में बदल जाएगा। इसीलिए इस काम को करने के लिए किसानों के बीच सशस्त्र संघर्ष संगठित करने की राजनीति का प्रचार व्यापक तौर पर करना चाहिए और बंदूक संग्रह अभियान चलाने के लिए छोटे-छोटे गुप्त मिलिटेंट ग्रुपों (लड़ाकू दलों) को संगठीत करना चाहिए। इन ग्रुपों के सदस्य जिस तरह सशस्त्र संघर्ष की राजनीति का प्रचार करेंगे, उसी तरह बंदूक संग्रह के ठोस कार्यक्रम को भी साथ ही साथ

सफल बनाने की कोशिश करेंगे। बंदूक संग्रह करने से ही संघर्ष का रूप नहीं बदल जाता है - संग्रहित बंदूक का इस्तेमाल करना होगा। तभी किसानों की सृजन शक्ति का विकास होगा और संघर्ष में गुणात्मक परिवर्तन होगा। यह काम कर सकते हैं, मजदूर वर्ग के दृढ़ मित्र एकमात्र भूमिहीन व गरीब किसान। मध्यम किसान भी मित्र हैं, लेकिन इनकी लड़ाकू चेतना भूमिहीन व गरीब किसानों की तरह उतनी तेज नहीं है। इसी कारण वे संघर्ष में एक ही साथ हिस्सेदार नहीं बन पाते, उन्हें कुछ समय लगता है। इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी के लिए वर्ग विश्लेषण करना अनिवार्य है। इसलिए चीन के महान नेता चेयरमैन माओ त्सेतुंग ने पहले ही इस काम को किया था और इसी कारण वे निर्भूल रूप से क्रांतिकारी संघर्ष के रास्ते को निर्देशित कर पाए हैं। इसलिए हमारे सांगठनिक काम की मुख्य बात है, किसान आंदोलन में भूमिहीन व गरीब किसानों का नेतृत्व कायम करना। सशस्त्र संघर्ष की राजनीति लेकर किसान आंदोलन संगठित करने के जरिये ही भूमिहीन व गरीब किसानों का नेतृत्व कायम होगा, क्योंकि वही किसान वर्ग के बीच सबसे ज्यादा क्रांतिकारी शक्ति हैं। अलग खेत मजदूर संगठन इस काम में मदद नहीं करेगा, बल्कि अलग खेत मजदूर संगठन अर्थवादी ट्रेडयूनियन आंदोलन की रूझान बढ़ाता है और किसानों का अंतरविरोध बढ़ाता है, मित्र वर्गों की एकता नहीं बढ़ाता है, क्योंकि हमारी कृषि व्यवस्था में सामंत वर्गों का शोषण ही मुख्य चीज है। इस प्रसंग में एक और सवाल पैदा होता है, वह है छोटे मालिकों के साथ समझौते का सवाल। इस मामले में कम्युनिस्टों का दृष्टिकोण क्या होगा? समझौते के सवाल पर हमें सोचना होगा कि हम किसके पक्ष में हैं? अत: उसके पक्ष में हम दूसरे किसी वर्ग का समर्थन नहीं कर सकते हैं। किसान आंदोलन के कम्युनिस्टों ने बराबर मध्यवर्गीयों के हित में भूमिहीन व गरीब किसानों को अपना स्वार्थ त्याग करने को मजबूर किया है। इससे भूमिहीन व गरीब किसान लड़ाकू मनोबल खो देते हैं। मध्यम तथा धनी किसानों के बारे में भी हमारा अलग-अलग दृष्टिकोण होगा। अगर हम धनी किसान को मध्यम किसान के रूप में विचार करेंगे, तो भूमिहीन व गरीब किसान हताश हो जाएंगे और फिर अगर मध्यम किसान को धनी किसान के रूप में विचार करेंगे, तो मध्यम किसान का लड़ाकू जोश घट जाएगा। इसलिए कम्युनिस्ट हर इलाके में चेयरमैन के निर्देश के मुताबिक किसानों का वर्ग विश्लेषण करना सीखेंगे।

भारत में किसान बार-बार विक्षोभ से फट पड़े हैं। बार-बार उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के पास रास्ता बताने की मांग की है। हमने नहीं बताया कि सशस्त्र संघर्ष की राजनीति तथा बंदूक संग्रह अभियान ही एकमात्र रास्ता है। यही रास्ता मजदूर वर्ग का रास्ता है, मुक्ति का रास्ता है, शोषणविहीन समाज की स्थापना का रास्ता है। सारे भारत के हर राज्य के किसान आज विक्षुब्ध है। उनके सामने कम्युनिस्टों को रास्ता दिखाना होगा। वह रास्ता है, सशस्त्र संघर्ष की राजनीति तथा बंदूक संग्रह अभियान। मुक्ति के उस एकमात्र रास्ते को हमें दृढ़ता के साथ दिखाना होगा। चीन की महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति ने हर तरह के स्वार्थ, नस्लवाद, संशोधनवाद, बुर्जुआ वर्ग का पिछलग्गू बनने तथा बुर्जुआ विचार की जी-हुजूरी करने के खिलाफ युद्ध की घोषणा की है। इस क्रांति का ज्वलंत प्रभाव भारतवर्ष में भी आ पहुंचा है। उस क्रांति का आह्वान है, दृढ़ता के साथ हर तरह का त्याग करने को तैयार हो जाओ, रास्ते की रूकावटों को एक-एक कर दूर करो, विजय हमारी होगी ही। साम्राज्यवाद कितने भी भयंकर रूप में क्यों न आए, आधुनिक संशोधनवाद उसकी मदद करने के लिए कितने ही कुत्सित जाल क्यों न फैलाए, प्रतिक्रियावादी शक्तियों के नाश के दिन नजदीक आ गए हैं, मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओ त्से तुंग विचारधारा की उज्ज्वल किरणें सारे अंधेरे को धो-पोंछकर साफ कर देंगी। स्वाभाविक रूप से सवाल उठता है, तब क्या इस युग में आंशिक मांगों के आधार पर किसानों के किसी जनआंदोलन की जरूरत नहीं है? निश्चय ही है और भविष्य में भी रहेगी, क्योंकि भारतवर्ष एक विशाल देश है और किसान अनेक वर्गों में बंटे हैं। इस कारण, राजनीतिक चेतना का मान हर इलाके में और हर वर्ग में एक ही स्तर के नहीं रह सकते हैं। अत: आंशिक मांगों के आधार पर किसानों के जनांदोलन के मौके और उसकी संभावनाएं हर वक्त ही रहेगी तथा कम्युनिस्टों को इस मौकों का पूरा इस्तेमाल हर समय करना होगा। हम आंशिक मांगों का आंदोलन किस तरह से संचालित करेंगे और इसका लक्ष्य क्या होगा? हमारी कार्यनीति की बुनियादी बात है - व्यापक किसान गोलबंद हो रहे हैं या नहीं और हमारा बुनियादी लक्ष्य है- किसानों की वर्ग चेतना बढ़ी है या नहीं, व्यापक किसान सशस्त्र संघर्ष की ओर आगे बढ़े हैं या नहीं। आंशिक मांगों पर आधारित आंदोलन वर्ग संघर्ष को तेज करेगा, व्यापक जनता की राजनीतिक सचेतनता को बढ़ाएगा। व्यापक किसान जनता त्याग करने के लिए प्रेरित होगी और संघर्ष नये-नये इलाकों में फैल जाएगा। आंशिक मांगों पर आधारित आंदोलन के रूप चाहे किसी भी तरह के हो, लेकिन कम्युनिस्ट हर वक्त उच्चतर स्तर के संघर्षों की जरूरत का प्रचार आम किसानों के बीच करेंगे। किसी भी हालत में किसानों ने जो तरीका अपनाया हो, उसे ही सबसे अच्छा कहकर चलाने की कोशिश न करो। वास्तव में, कम्युनिस्ट हर वक्त किसानों के बीच क्रांतिकारी राजनीति, अर्थात् सशस्त्र संघर्ष की राजनीति और बंदूक संग्रह अभियान चलाने का प्रचार करेंगे। इस प्रचार के बावजूद हो सकता है,

किसान जनडेपुटेशन (प्रतिनिधि मंडल) का फैसला लें, तो हमें इस आंदोलन को संचालित करना होगा। श्वेत आतंक के इस काल में जनडेपुटेशन की कारगरता को किसी भी हालत में छोटा करके नहीं देखना है, क्योंकि यह जनडेपुटेशन ज्यादा-से ज्यादा किसानों को संघर्ष में खींच लाएगा। अर्थवादी मांगों पर आंदोलन कभी भी अन्याय नहीं है, लेकिन अर्थवादी तरीके से इस आंदोलन को संचालित करना एक अपराध है। अपराध यह प्रचार करना भी है कि अर्थवादी मांगों का आंदोलन खुद-ब-खुद राजनीतिक संघर्ष का रूप ले लेगा, क्योंकि यह स्वत:स्फुर्तता की पूजा करना है। इनमें से कोई भी जनता को रास्ता नहीं दिखा पाते हैं। दृष्टिकोण से स्पष्टता नहीं ला पाते हैं और संघर्ष में त्याग के लिए प्रेरित नहीं कर पाते हैं। संघर्ष एक स्तर में एक ही काम करता है और इस काम को किये बिना संघर्ष उच्चतर स्तर में नहीं पहुंच सकेगा। इस युग में यह खास काम, सशस्त्र संघर्ष की राजनीति तथा बंदूक संग्रह अभियान है। इस काम के बिना चाहे अन्य कुछ भी क्यों न करें, संघर्ष उच्च स्तर पर नहीं पहुंचेगा, संघर्ष टूट जाएगा, संगठन नहीं बनेगा। ठीक इसी तरह भारतीय क्रांति का एकमात्र रास्ता है जनता की सशस्त्र सेना तथा रिपब्लिक (लोकतंत्र) की स्थापना करने का रास्ता, जिसे लेनिन ने दिखाया था। 1905 में लेनिन ने कहा था कि अगर सारे रूस में यह संभव नहीं भी हो, जब भी जहां भी संभव हो, वहीं इन दोनों का गठन करो। चेयरमैन माओ त्सेतुंग ने लेनिन द्वारा दिखाए गये इस रास्ते को और भी समृद्ध किया है, लोकयुद्ध की पद्धति सिखायी है और इसी रास्ते से चीन की मुक्ति आई है। यही रास्ता वियतनाम, थाईलैंड, मलाया, फिलीपिन्स, वर्मा, इंडोनेशिया, यमन, लियोपोल्ड विले कांगो, अफ्रीका व लातिन अमेरिका के विभिन्न देशों ने अपनाया है। भारतवर्ष में भी नागा, मिजो तथा कश्मीर की जनता ने इसी सशस्त्र सेना और मुक्ति फ्रंट के शासन के रास्ते को अपनाया है। इसलिए मजदूर वर्ग को आज पुकार कर कहना होगा कि भारत की जनवादी क्रांति में मजदूर वर्ग को नेतृत्व देना होगा। और यह काम करना होगा मजदूर वर्ग को अपने मुख्य मित्र किसान वर्ग के संघर्ष में नेतृत्व देकर 'इसलिए किसान आंदोलन को संगठित करने तथा इस संघर्ष को सशस्त्र संघर्ष के स्तर में ले जाने की जिम्मेवारी उसकी है। मजदूर वर्ग के अगुआ हिस्से को देहाती इलाकों के सशस्त्र संघर्ष में भाग लेने के लिए जाना होगा। यह मजदूर वर्ग का मुख्य काम है। हथियार जमा करना तथा देहाती इलाकों में आधार इलाके का गठन करना - इसी का नाम है मजदूर वर्ग की राजनीति। यही राजनीति देकर हमें मजदूर वर्ग को प्रेरित करना होगा। ट्रेड यूनियन के अंर्तगत सारे मजदूरों को संगठित करो - का नारा मजदूर वर्ग की राजनीतिक चेतना को नहीं बढ़ाता है। निश्चय ही इसका मतलब यह नहीं है कि हम ट्रेड यूनियन संगठित नहीं करेंगे, इसका मतलब है - पार्टी के क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं को हम निश्चय ही ट्रेड यूनियन के कामों में फंसाए नहीं रखेंगे। इनका काम होगा मजदूर वर्ग के बीच राजनीतिक प्रचार आंदोलन चलाना, अर्थात् सशस्त्र संघर्ष की राजनीति तथा बंदूक संग्रह अभियान संगठित करने की राजनीति का प्रचार करना और पार्टी संगठन बनाना। मध्यम वर्ग के बीच भी राजनीतिक प्रचार करने का हमारा मुख्य काम है किसान संघर्ष के महत्व का प्रचार करना, अर्थात् पार्टी के हर फ्रंट (मोर्चे) की जिम्मेवारी है किसान संघर्ष के महत्व को समझाना तथा इस संघर्ष में हिस्सेदार बनने का आह्वान करना। यह काम हम जितना ही ज्यादा कर पाएंगे, उतना ही हम जनवादी क्रांति के सचेतन नेतृत्व के स्तर में जा पहुंचेंगे। पार्टी के इस बुनियादी मार्क्सवादी-लेनिनवादी रास्ते का विरोध सिर्फ संशोधनवादियों की ओर से ही नहीं हो रहा है। संशोधनवादी खुल्लमखुल्ला वर्ग समझौता का रास्ता अपना रहे हैं। अत: इसे बेनकाब करना आसान है। लेकिन और एक किस्म का विरोध पार्टी के अंदर है, जिसे कहते हैं कठमुल्लावाद। वे क्रांति की जरूरत मंजूर करते हैं, मंजूर करते हैं कि एकमात्र सशस्त्र संघर्ष के जरिये ही क्रांति संभव है। लेकिन वे ख्वाब देखते हैं कि सारे भारत में जनांदोलन फैला देने के बाद ही सशस्त्र क्रांति के रास्ते पर जाया जा सकता है। इसके पहले छोटे-छोटे यहां तक कि बड़े संघर्ष भी हो सकते हैं, लेकिन सत्ता कब्जा करना संभव नहीं है। सत्ता कब्जा करने के बारे में वे इस तरह की आशा रखते हैं कि भारतवर्ष में भी हु-ब-हू अक्टूबर क्रांति की आवृति होगी। अक्टूबर क्रांति किस तरह सफल हुई, इससे संबंधित अपने किताबी ज्ञान को वे ठीक उसी तरह भारत में भी लागू करते हैं। वे भूल जाते है कि अक्टूबर क्रांति के पहले फरवरी क्रांति हुई थी और बुजुर्आ पार्टी सत्ता में आई थी तथा मजदूर, किसान और सैनिकों के सोवियतों के हाथों में भी सत्ता थी। इस दोहरी सत्ता के कारण ही मजदूर वर्ग का नेतृत्व सोवियतों के अंदर कार्यान्वित हो सका था और इन सोवियतों के अंदर जब पेट्टी बुर्जुआ (निम्नपूंजीवादी) पार्टियों ने सत्ता धनी वर्ग के हाथों सौंप दी, तभी मजदूर वर्ग के लिए अक्टूबर क्रांति करना संभव हुआ था। वे भारतवर्ष की ठोस स्थिति का विश्लेषण नहीं करते हैं। भारतवर्ष में हो रहे संघर्षों से सबक नहीं लेते हैं। रूसी क्रांति की सफलता का मुख्य कारण था संयुक्त मोर्चे की कार्यनीति का सही व्यवहार। संयुक्त मोर्चे की कार्यनीति का सवाल भारत में भी उतना ही महत्वपूर्ण है, लेकिन भारत की जनवादी क्रांति की कार्यनीति का रूप दूसरा होगा। भारतवर्ष में भी नागा, मिजो तथा कश्मीर आदि इलाकों में पेट्टी बुर्जुआ नेतृत्व में संघर्ष हो रहे हैं। इसलिए जनवादी क्रांति में मजदूर वर्ग को इसके साथ संयुक्त

मोर्चा बनाकर ही आगे बढ़ना होगा और भी अनेक नये इलाकों में बुर्जुआ या पेट्टी बुर्जुआ पार्टियों के नेतृत्व में संघर्ष शुरू होंगे। इनके साथ भी मजदूर वर्ग अवश्य मैत्री करेगा। और इस मैत्री का मुख्य आधार साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष और आत्मनिर्णय का अधिकार होगा। मजदूर वर्ग इस अधिकार को निश्चित रूप से मंजूर करता है, साथ-ही-साथ अलग होने के अधि कार को भी।

अक्टूबर क्रांति के रास्ते से भारत में जो क्रांति का ख्वाब देखते हैं, वे क्रांतिकारी होते हुए भी अपने किताबी दृष्टिकोण के कारण संघर्ष में जोरदार नेतृत्व नहीं दे सकते हैं। वे किसान संघर्ष के महत्व को नहीं समझते हैं। फलस्वरूप: वे अनजाने ही मजदूर वर्ग के बीच अर्थवाद के प्रचारक बन जाते है। वे चेयरमैन माओ के शिक्षाओं को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। ग्रहण नहीं कर पाते हैं एशियाई, अफ्रीकी तथा लातिन अमेरिकी जनता के क्रांतिकारी संघर्ष के अनुभवों को। इनका ही एक हिस्सा चेग्वेवारा का भक्त बन जाता है और भारत की जनवादी क्रांति की मुख्य शक्ति किसान वर्ग को संगठित करने के काम में जोर नहीं देता है। फलस्वरूप, वे अनिवार्य रूप से वामपंथी भटकाव के शिकार हो जाते हैं। इसलिए हमें इन पर खास ध्यान देना होगा और धीरे-धीरे अनुभव के जरीये शिक्षित करना होगा। किसी भी हालत में इनके बारे में अधीर नहीं होना होगा। इसके अलावे हमारे बीच क्रांतिकारी कामरेडों का एक और दल है, जो चीनी पार्टी तथा महान माओत्से तुंग विचारधारा को मानता है और यही एकमात्र रास्ता है, इसे भी मंजूर करता है, लेकिन वे 'अच्छे कम्युनिस्ट कैसे बनें' को आत्मोत्थान की एकमात्र सीढ़ी मानते हैं और इसी कारण एक गंभीर भटकाव के शिकार हो जाते हैं। आत्मोत्थान का एकमात्र मार्क्सवादी रास्ता, जिसे लेनिन और चेयरमैन माओ ने सिखाया है वह है वर्ग संघर्ष का रास्ता। एकमात्र वर्ग संघर्ष की आग में तप कर ही कम्युनिस्ट शुद्ध सोना बन सकता है। वर्ग संघर्ष ही है कम्युनिस्टों का सच्चा स्कूल और हमें वर्ग संघर्ष के अनुभवों का मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओ त्सेतुंग विचारधारा की रोशनी में मूल्यांकन करना होगा तथा शिक्षा लेनी होगी, इसलिए पार्टी शिक्षा की बुनियादी बात है मार्क्सवाद-लेनिनवाद की शिक्षा के आधार पर वर्ग संघर्ष लागू करना और उस अनुभव से फिर आम नीति ग्रहण करना तथा अनुभवों से प्राप्त इस नीति को फिर जनता के बीच में ले जाना। इसे ही कहा जाता है जनता से लो, जनता को दो का सिद्धांत, पार्टी शिक्षा की मुख्य बात यही है। तमाम क्रांतिकारी कामरेड पार्टी शिक्षा की इस बुनियादी सच्चाई को महसूस नहीं कर पाते हैं, फलस्वरूप वे पार्टी शिक्षा के बारे में आदर्शवादी भटकाव के शिकार हो जाते हैं। चेयरमैन माओ त्सेतुंग ने हमें सिखाया है कि व्यवहार के बिना कोई भी शिक्षा संभव नहीं है। उनकी भाषा में काम करना ही सीखना है। एक मात्र क्रांतिकारी व्यवहार के जरिये परिस्थिति बदलने के दौरान ही आत्मोत्थान संभव है।

दुनिया के क्रांतिकारियों एक हों!

मजदूर-किसान की क्रांतिकारी एकता जिंदाबाद!!

चेयरमैन माओ त्सेतुंग, जिंदाबाद!!!

पृष्ठ संख्या 13 का शेष

लिए घर से निकल पड़ी। उनके एंटी पार्टी ने उसे रास्ते में ही हत्या कर देने के लिए पूरी एड़ी-चोटी एक कर दिया, पर ये सारा प्रयास विफल हो गया और आखिरकार कामरेड काजल पार्टी के पास सुरक्षित पहुंच गई। रास्ते में विभिन्न गांवों से होते हुए उसे गुजरना पड़ा। एक-दो गांवों में भी कई दिन तक ठहरा हर जगह उसे लोगों ने भड़काने का प्रयास किया। पर वह एक न सूनी। इस तरह वे एक पेशेवर क्रांतिकारी के रूप में रहने लगे। उन्हें धरहरा क्षेत्र में कार्यरत एलओएस का सदस्य बनाया गया। इसी बीच बीमार पड़ी, तब उसे एक जगह जनता के यहां रख दिया गया। वहां पर मौजूद साथियों ने उनका सही रूप से इलाज कई कारणों से नहीं कर सके। इसी बीच मलेरिया बीमारी गम्भीर होते गया। अन्ततः वे शहीद हो गई। हमने इस तरह से एक शिक्षित महिला साथी को सदा के लिए खो दिया। आवें, उनके अरमानों को साकार करें।

पृष्ठ संख्या 15 का शेष

संशोधनवादी विध्वंस और दमन के लिए चाहे आपस में जितना भी सहयोग क्यों न करें, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के क्रांतिकारियों और दार्जिलिंग के क्रांतिकारी किसानों के द्वारा प्रज्ज्वलित सशस्त्र संघर्ष की मशाल कभी बुझ नहीं सकती। एक चिनगारी सारे जंगल में आग लगा सकती है। दार्जिलिंग की चिनगारी दावानल बनकर धधक उठेगी और भारत के विशाल इलाकों को अपने लपटों में समेट लेगी। यह ध्रुव सत्य है कि क्रांतिकारी सशस्त्र संघर्ष की प्रचंड आंधी अंततोगत्वा भारत के कोने-कोने में फैल जाएगी। यद्यपि भारतीय क्रांतिकारी संघर्ष का रास्ता लंबा और कष्टकर होगा, तथापि मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओ त्सेतुंग विचारधारा (अब माओवाद) से निर्देशित भारतीय क्रांति निश्चय ही विजयी होगी।

नक्सलबाड़ी विद्रोह से संबंधित कविताएं

(महान ऐतिहासिक नक्सलबाड़ी सशस्त्र किसान विद्रोह ने हमारे देश के किसानों व मजदूरों को ही न सिर्फ झकझोरा, बल्कि इसने देश के तमाम विश्वविद्यालयों के छात्रों से लेकर लेखकों-कवियों तक को झकझोर दिया। लेखकों व कवियों को नक्सलबाड़ी विद्रोह पर कलम चलाने को मजबूर होना पड़ा। तमाम सरकारी दमन को धता बताते हुए नक्सलबाड़ी विद्रोह के प्रति छात्रों-युवाओं की दिवानगी, किसानों की प्रतिहिंसा के साथ-साथ मध्यमवर्गीय लोगों की सत्तापरस्ती को भी कवियों व लेखकों ने कागज पर उतारा। ऐसी ही दो पुरानी कविताओं को हम यहां पर दे रहे हैं। - संपादकमंडल, लाल चिनगारी)

1.

यह मृत्यु उपत्यका नहीं है मेरा देश

जो पिता अपने बेटे की लाश की शिनाख्त करने से डरे
मुझे घृणा है उससे
जो भाई अब भी निर्लज्ज और सहज है
मुझे घृणा है उससे
जो शिक्षक बुद्धिजीवी, कवि, किरानी
दिन-दहाड़े हुई इस हत्या का
प्रतिशोध नहीं चाहता
मुझे घृणा है उससे।

चेतना की बाट जोह रहे हैं आठ शव
मैं हतप्रभ हुआ जा रहा हूं
आठ जोड़ा खुली आंखे मुझे घूरती हैं नींद में
मैं चीख उठता हूं
वे मुझे बुलाती है समय-असमय, बाग में
मैं पागल हो जाउंगा
आत्म-हत्या कर लूंगा
जो मन में आए करूंगा।

यही समय है कविता लिखने का
इश्तिहार पर, दीवार पर, स्टेंसिल पर
अपने खून से, आंसुओं से, हड्डियों से कोलाज शैली में
अभी लिखी जा सकती है कविता
तीव्रतम यंत्रणा से क्षत-विक्षत मुंह से
आतंक के रूबरू वैन की झुलसाने वाली
हेड लाइट पर आंखें गड़ाए
अभी फेंकी जा सकती है कविता
38 बोर पिस्तौल या और जो कुछ हो हत्यारों के पास
उन सबको दरकिनार कर
अभी पढ़ी जा सकती है कविता।

लॉक-अप के पथरीले हिमकक्ष में
चीर-फाड़ के लिए जलाए हुए
पेट्रोमैक्स की रोशनी को कांपते हुए
हत्यारों द्वारा संचालित न्यायालय में
झूठे अशिक्षा के विद्यालय में
शोषण और त्रास के राजतंत्र के भीतर
सामरिक-असामरिक कर्णधारों के सीने में
कविता का प्रतिवाद गूंजने दो
बांग्ला देश के कवि भी तैयार रहें लोर्का की तरह
दम घोंट कर हत्या हो, लाश गुम जाये
स्टेनगन की गोलियों से बदन छिल जाये, तैयार रहें
तब भी कविता के गांवों से
कविता के शहर को घेरना बहुत जरूरी है।

यह मृत्यु उपत्यका नहीं है मेरा देश
यह जल्लादों का उल्लास-मंच नहीं है मेरा देश
यह विस्तीर्ण श्मशान नहीं है मेरा देश
यह रक्त रंजित कसाईघर नहीं है मेरा देश।

मैं छीन लाउंगा अपने देश को
सीने में छिपा लूंगा कुहासे से भीगी
कांस-संध्या और विसर्जन
शरीर के चारों ओर जुगनुओं की कतार
या पहाड-पहाड़ झूम खेती

अनगिनत हृदय, हरियाली, रूपकथा, फूल-नारी-नदी
एक-एक तारे का नाम लूंगा
डोलती हुई हवा,
धूप के नीचे चमकती मछली की आंख जैसा ताल
प्रेम जिससे मैं जन्म से छिटका हूं कई प्रकाश-वर्ष दूर
उसे भी बुलाउंगा पास क्रांति के उत्सव के दिन।

हजारों वाट की चमकती रोशनी आंखों में फेंक रात-दिन जिरह
नहीं मानती
नाखूनों में सुई, बर्फ की सिल पर लिटाना
नहीं मानती
होंठों पर बट, दहकती सलाख से शरीर दागना
नहीं मानती
धारदार चाबुक से क्षत-विक्षत लहूलुहान पीठ पर सहसा एल्कोहल
नहीं मानती
नग्न देह पर इलेक्ट्रिक शॉक, कुत्सित विकृत यौन अत्याचार
नहीं मानती
पीट-पीट कर हत्या, कनपटी से रिवाल्वर सटाकर गोली मारना
नहीं मानती
कविता नहीं मानती किसी वाधा को
कविता सशस्त्र है, कविता स्वाधीन है, कविता निर्भीक है
गौर से देखो: मायकोव्यस्की, हिकमत, नेरूदा, अरागां, एलुआर
हमने तुम्हारी कविता को हारने नहीं दिया
समूचा देश मिलकर एक नया
महाकाव्य लिखने की कोशिश में है
छापामार छंदों में जा रहे हैं सारे अलंकार।

गरज उठें दल मादल
प्रवाल द्वीपों जैसे आदिवासी गांव
रक्त से लाल नीले खेत
शंखचूड़ के विष-फेन सें आहत तितास
विषाक्त मरनासन्न प्यास से भरा कुचिला
टंकार में अंधा सूर्य उठे हुए गांडीव की प्रत्यंचा
तीक्ष्ण तीर, हिंसक नोंक
भाला, तोमर, टांगी और कुदाल
चमकते बल्लम, चरागाह दखल करते तीरों की बौछार
मादल की हर ताल पर लाल आंखों के ट्राइबल-टोटम
बंदूक दो, खुखरी दो और ढेर सारा साहस
इतना साहस कि फिर कभी डर न लगे
कितने ही हों क्रेन, दांतो वाले बुल्डोजर,
फौजी कन्वाय का जुलूस
डायनमो चालित टरबाइन, खराद और इंजन
ध्वस्त कोयले के मीथेन अंधकार में
सख्त हीरे की तरह चमकती आंखें
अद्‌भुत इस्पात की हथौड़ी
बंदरगाहों जुटमिलों की भट्ठियों जैसे
आकाश में उठे सैकड़ों हाथ
नहीं, कोई डर नहीं
डर का फक पड़ा चेहरा कैसा अजनबी लगता है
जब जानता हूं मृत्यु कुछ नहीं है प्यार के अलावा
हत्या होने पर मैं
बंगाल की सारी मिट्टी के दीयों में लौ बन कर फैल जाउंगा
साल-दर-साल मिट्टी में हरा विश्वास बनकर लौटूंगा
मेरा विनाश नहीं
सुख में रहूंगा, दुख में रहूंगा, जन्म पर सत्कार पर
जितने दिन बंगाल रहेगा मनुष्य भी रहेगा।

जो मृत्यु रात की ठंड में जलती बुदबुदाहट हो कर उभरती है
वह दिन, वह युद्ध, वह मृत्यु लाओ
रोक दें सेवेंथ फ्लीट को सात नावों वाले मधुकर
शृंग और शंख बजाकर युद्ध की घोषणा हो
रक्त की गंध लेकर हवा जब उन्मत्त हो
जल उठे कविता विस्फोटक बारूद की मिट्टी
अल्पना-गांव-नौकाएं-नगर-मंदिर
तराई से सुंदरवन की सीमा जब
सारी रात रो लेने के बाद शुष्क ज्वलंत हो उठी हो
जब जन्म स्थल की मिट्टी और वधस्थल की
कीचड़ एक हो गई हो
तब दुविधा क्यों?
संशय कैसा?
त्रास क्यों?

आठ जन स्पर्श कर रहे हैं
ग्रहण के अंधकार में फुसफुसाकर कहते हैं
कब कहां कैसा पहरा
उनके कंठ में हैं असंख्य तारापुंज-छायापथ-समुद्र
एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक आने-जाने का उत्तराधिकार
कविता की ज्वलंत मशाल
कविता का मालोतोव कॉक्टेल
कविता की टॉलविन अग्नि-शिखा
आहुति दें अग्नि की इस आकांक्षा में।

(पिछली शताब्दी के सत्तर के दशक में कोलकाता के आठ छात्रों की हत्या कर धान की क्यारियों में फेंक दिया था। उनकी पीठ पर लिखा था देशद्रोही।)

2.

गोली दागो पोस्टर

यह उन्नीस सौ बहत्तर की बीस अप्रैल है या
किसी पेशेवर हत्यारे का दायां हाथ या किसी जासूस का
चमड़े का दस्ताना या किसी हमलावर की दूरबीन पर
टिका हुआ धब्बा है
जो भी हो- इसे मैं केवल एक ही दिन नहीं कह सकता।

जहां मैं लिख रहा हूं
यह बहुत पुरानी जगह है
जहां आज भी शब्दों से अधिक तम्बाकू का
इस्तेमाल होता है

आकाश यहां एक सूअर की ऊंचाई भर है
यहां जीभ का इस्तेमाल सबसे कम हो रहा है
यहां आंख का इस्तेमाल सबसे कम हो रहा है
यहां कान का इस्तेमाल सबसे कम हो रहा है
यहां नाक का इस्तेमाल सबसे कम हो रहा है
यहां सिर्फ दांत और पेट हैं
मिट्टी में धंसे हुए हाथ हैं
आदमी कहीं नहीं है
केवल एक नीला खोखल है
जो केवल अनाज मांगता रहता है

एक मूसलाधार बारिश से
दूसरी मूसलाधार बारिश तक

यह औरत मेरी मां है या
पांच फीट लोहे की एक छड़
जिस पर दो सूखी रोटियां लटक रही हैं
मरी हुई चिड़ियों की तरह
अब मेरी बेटी और मेरी हड़ताल में
बालभर भी फर्क नहीं रह गया है
जबकि संविधान अपनी शर्तों पर
मेरी हड़ताल और बेटी को
तोड़ता जा रहा है

क्या इस आकस्मिक चुनाव के बाद
मुझे बारूद के बारे में
सोचना बंद कर देना चाहिए?
क्या उन्नीस सौ बहत्तर की इस अप्रैल को
मैं अपने बच्चे के साथ
एक पिता की तरह रह सकता हूं?
स्याही से भरी दवात की तरह
एक गेंद की तरह
क्या मैं अपने बच्चों के साथ
एक घास भरे मैदान की तरह रह सकता हूं?
वे लोग अगर अपनी कविता में मुझे
कभी ले भी जाते हैं तो
मेरी आंखों पर पट्टियां बांधकर
मेरा इस्तेमाल करते हैं और फिर मुझे
सीमा के बाहर लाकर छोड़ देते हैं
वे मुझे राजधानी तक कभी नहीं पहुंचने देते हैं
मैं तो जिला-शहर तक आते-आते जकड़ लिया जाता हूं!

सरकार ने नहीं, इस देश की सबसे
सस्ती सिगरेट ने मेरा साथ दिया

बहन के पैरों के आस-पास
पीले रेंड़ के पौधों की तरह
उगा था जो मेरा बचपन

उसे दारोगा का भैंसा चर गया
आदमियत को जीवित रखने के लिए अगर
एक दरोगा को गोली दागने का अधिकार है
तो मुझे क्यों नहीं?

जिस जमीन पर
मैं अभी बैठकर लिख रहा हूं
जिस जमीन पर मैं चलता हूं
जिस जमीन को मैं जोतता हूं
जिस जमीन में बीज बोता हूं और
जिस जमीन से अन्न निकालकर मैं
गोदामों तक ढोता हूं
उस जमीन के लिए गोली दागने का अधिकार
मुझे है या उन दोगले जमींदारों को जो पूरे देश को
सूदखोर का कुत्ता बना देना चाहते हैं

यह कविता नहीं है
यह गोली दागने की समझ है
जो तमाम कलम चलानेवालों को
तमाम हल चलानेवालों से मिला रही है।

पृष्ठ संख्या 59 का शेष

संस्कृति व विचारधारा के अनुसार जनमत तैयार करता है, वैसे ही पूंजीपति वर्ग अपनी निजी स्वार्थ वाली संस्कृति व विचारधारा को फैलाकर जनमत तैयार करता है।

सांस्कृतिक क्रांति से पहले चीन में पूंजीवाद का रास्ता अपनाने वाले जो पार्टी और सरकार के अन्दर जमा हो गये थे और लाल झंडा उठा कर लाल झंडे का ही विरोध कर रहे थे। वे भी यही रणनीति अपनाये, उन्होंने अपने प्रभाव से पत्रिकाओं, अखबारों, कला-साहित्य, शिक्षा व्यवस्था आदि का इस्तेमाल करते हुए अपने पक्ष में जनमत तैयार करने की कोशिश की। बुर्जुआ के इस हमले को रोकने और समाजवाद व सर्वहारा की तानाशाही को मजबूत करने के लिए पार्टी कैडरों के सैद्धांतिक आधार को मजबूत करना जरूरी था और निजी संपत्ति से पैदा हुए निजी स्वार्थ के चिन्तन, संस्कृति, पुरानी आदतों को बदलने के लिए का. माओ ने जन दिशा और वर्ग दिशा का इस्तेमाल करते हुए जो संघर्ष का नया रूप निकाला, वह थी 1966 की महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति का लक्ष्य मात्र उन मुट्ठी भर लोगों को सत्ता से हटाना, जो लोग पूंजीवाद का रास्ता ले चुके थे। का. माओ अपने प्रभाव के कारण इसे बहुत आसानी से कर सकते थे। सांस्कृतिक क्रांति का लक्ष्य गलत बुर्जुआ विचारों को उनकी जड़ों से उखाड़ना था। इस तरह सांस्कृतिक क्रांति सिर्फ भ्रष्ट नेताओं को हटाने के लिए नहीं थी बल्कि हजारों सालों से निजी सम्पत्ति के प्रभाव से लोगों के दिमागों में बैठ चुके स्वार्थी मूल्यों, बुर्जुआ चिन्तन और सामूहिकता के ऊपर 'स्वार्थ' की प्रधानता को खत्म करना था।

पृष्ठ संख्या 27 का शेष

व पूंजीपति-परस्त बजट ही पेश किया है। हमारी पार्टी भाकपा (माओवादी) का साफ मानना है कि इस सड़ी-गली व्यवस्था में सभी सरकारें अपने मालिक देशी-विदेशी पूंजीपतियों व कॉरपोरेटर लूटेरों के हित में ही बजट पेश करेगी। जनता का बजट एक जनवादी राज्य में ही संभव है और एक जनवादी राज्य के निर्माण के लिए हमें और भी मजबूती से इस अर्द्ध-सामंती व अर्द्ध-औपनिवेशिक व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए चल रही दीर्घकालीन लोकयुद्ध को तेज करना होगा, जिसका नेतृत्व हमारी पार्टी भाकपा (माओवादी) कर रही है। एक जनवादी राज्य का बजट ही जनोन्मुख हो सकता है, इस तरह की शासन प्रणाली से जनोन्मुख बजट की अपेक्षा करना बेमानी ही होगी।

अपील

लाल चिनगारी के तमाम पाठकों से अपील है कि वे अपने क्षेत्र में हो रहे तमाम संघर्षों, शहीद साथियों की जीवनी व तस्वीर, पुलिस जुल्म की घटनाएं आदि हमें जरूर भेजें -सम्पादकमंडल, लाल चिनगारी

गरीब-विरोधी व पूंजीपति-परस्त है केन्द्रीय बजट 2017-2018

मई 2014 में केंद्र की सत्ता संभालने के बाद चौथी बार चरम ब्राह्मणवादी, हिंदू-फासीवादी मोदी सरकार ने अपना केंद्रीय बजट पेश किया। मोदी सरकार की तरफ से केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने 1 फरवरी को इस बजट को संसद में प्रस्तुत किया, अमूमन प्रत्येक वर्ष फरवरी के अंतिम कार्य दिवस के दिन इसे पेश किया जाता था। लेकिन इस बार फरवरी के प्रथम कार्य दिवस पर ही पेश किया गया यानी कि 27 दिन पहले। इसके साथ ही पहली बार रेल बजट भी साथ में ही पेश किया गया, जो कि पहले आम बजट के एक दिन पहले पेश किया जाता था। बजट पेश करने के एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण आधा यानी आंकड़े रहित प्रस्तुत किया गया। आंकड़े, जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का हाल तथ्यगत रूप से बयान करते हैं, वह जून के बाद आएगा। आंकड़े वाले हिस्से के नहीं छपने के कारण वर्ष 2016 में अर्थव्यवस्था में कितना उत्पादन किस क्षेत्र में बढ़ा या घटा (यानी देश की आय का ब्यौरा), विदेशी कर्ज भारत पर कितना बढ़ा, संगठित रूप से रोजगार कितना बढ़ा, रूपये का मूल्य नोटबंदी के बाद कितना घटा आदि जरूरी प्रश्नों का खुलासा नहीं हो सका यानी जनता से ये जानकारियां छिपा ली गई। वैसे सच कहा जाए तो अब केंद्रीय बजट मात्र एक रस्म अदायगी भर रह गई है। इसका कोई विशेष महत्व अब जनता के लिए नहीं रहा है। क्योंकि कई महत्वपूर्ण निर्णय बजट पारित होने से पहले या बाद भी सरकार द्वारा ले लिए जाते हैं। जैसे, हाल में गैस सिलेंडर और पेट्रोल का दाम बढ़ाने का सरकारी फैसला। वैसे ही रेलवे के भाड़ा बढ़ाने के निर्णय भी लिए गये। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2014 से लेकर 2016 तक पेट्रोल पर 152 फीसदी टैक्स बढ़ा है।

केंद्रीय बजट 2017-2018 मोदी सरकार के तुगलकी फरमान नोटबंदी के बाद हुए भारी अस्त-व्यस्तता के बाद आया। नोटबंदी की वजह से देश के अधिकांश मेहनतकश लोगों ने भारी परेशानी झेली थी। उद्योग जगत और अन्य कारोबारों में सुस्ती से बड़ी तादाद में मजदूर बेरोजगार हुए। लाखों असंगठित क्षेत्र की इकाइयां एवं अन्य 120 बड़ी कम्पनियां नोटबंदी के दौरान बंद हो गये। लाखों श्रमिक अपने गांव-घर को लौट गये। जैसे, उत्तर प्रदेश के भदोई में कालीन उद्योग, पीतल के बने आकर्षक वस्तुओं का उद्योग, भिवंडी (महाराष्ट्र) का पावरलूम (देश का सबसे बड़ा कपड़ा उद्योग), आगरा का पेठा उद्योग, बनारसी साड़ी उद्योग आदि। नोटबंदी के दौरान छोटे काम-धंधों में लगे गरीब लोग तबाह हो गए और पहले ही 2 साल सूखा झेल चुके किसान अपनी नई फसल को औने-पौने दाम में बेचने को मजबूर हुए। सरकार के अनुसार काला धन, जाली नोट और आतंकवाद को मिटाने के लिए नोटबंदी की गई थी। इस दौरान आम जनता को हुई भारी तकलीफ के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगर वह देश हित के लिए इस परेशानी को सहन करते हैं, तो देश की बहुत सी समस्याएं हल हो जाएंगी, अर्थव्यवस्था को दूरगामी लाभ होगा। कई जगह मोदी समर्थक जनता को समझा रहे थे कि नोटबंदी से अमीरों का जो काला धन जब्त होगा, उससे मोदी उसके जनधन खातों में अच्छी-खासी रकम जमा कर देंगे। इसके साथ ही मध्य वर्ग को भी टैक्स में भारी छूट मिलने के हसीन सपने दिखाये गये थे। इसलिए इस बजट से आम लोग भी बड़ी आशाएं लगाए हुए थे।

31 जनवरी को बजट से एक दिन पहले प्रस्तुत किये जाने वाले आर्थिक सर्वे में सरकार ने कहा कि नोटबंदी के असर से अर्थव्यवस्था में गिरावट हुई है, कारोबार बंद हुए हैं, श्रमिक बेरोजगार हुए हैं, किसान और खेत मजदूर की आमदनी कम हुई है और इसका असर अगले साल भी जारी रहेगा तथा इसका फायदा मिलने में और ज्यादा वक्त लगेगा। साथ ही यह भी कहा गया कि नोटबंदी से काला धन, फर्जी नोट, आतंकवाद और कैशलेस अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा बड़ा मकसद तो मकानों और जमीनों की कीमतें कम करना था। सर्वे में यह भी बताया गया कि मोदी सरकार की नीतियों से अर्थव्यवस्था में बड़ी तेजी आई है, लेकिन बैंकों के डूबे कर्ज इस साल बढ़कर पिछले साल से दोगुने हो गये हैं। इस सर्वे में एक बात और खुलकर आई कि ना चुकाये कर्ज में 71 प्रतिशत हिस्सा सिर्फ 50 बड़ी कम्पनियों द्वारा दबाया गया है। जिन्होंने औसतन प्रति कम्पनी 20 हजार करोड़ रूपये दबा लिए है। इनमें से भी सबसे बड़ी 10 कम्पनियों ने तो प्रति कम्पनी 40 हजार करोड़ रूपये दबा लिए हैं। पूंजीपतियों के द्वारा बैंको से लिए गये कर्ज ना चुकाने के कारण बैंक अब और कर्ज देने में सक्षम नहीं है, इसलिए सर्वे में इसके उपाय के बतौर रिजर्व बैंक के पास पड़े 4 लाख करोड़ रूपये की फालतू पूंजी को सरकारी बैंकों को देने का सुझाव दिया गया। ताकि बैंक पूंजीपतियों को फिर से कर्ज दे सके और जब तक ऐसा नहीं हो पा रहा है, सरकार बजट से 75 हजार करोड़ रूपये तब तक के लिए बैंकों को देगी। रोचक बात यह है कि पूंजीपतियों की रहमोकरम पर चलने वाली मोदी सरकार इस वर्ष में पहले ही 25 हजार करोड़ रूपये बैंकों को दे चुकी है और अगले ही दिन बजट में वित्त मंत्री ने अपने मालिक पूंजीपतियों के लिए आए सुझाव को मानते हुए 10 हजार करोड़ की पूंजी बैंकों को दे दी। आर्थिक सर्वे में और एक बात का खुलासा किया गया कि हर साल औसतन 90 लाख

लोग रोजी-रोटी कमाने के लिए अपने घर-बार से उजड़कर प्रवासी बन जाते हैं और यह संख्या सालाना 4.5 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। प्रवासी मजदूरों की खस्ताहाल स्थिति व नारकीय जिंदगी के बारे में आर्थिक सर्वे ने चुप्पी साध ली।

खैर, इस आर्थिक सर्वे के बाद 1 फरवरी को वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया उससे भारी उम्मीदें लगाये आम गरीब मेहनतकश मजदूरों, किसानों, महिलाओं, बेरोजगार युवाओं, छात्रों, दलित-आदिवासियों को तो कुछ भी हासिल नहीं हुआ। ना उनके रोजगार के लिए किसी व्यवस्था की बात हुई, ना जनधन खातों में कुछ मिला और ना ही औने-पौने दामों में फसल बेचने को मजबूर किसानों के लिए किसी राहत की बात हुई। हां! शेयर बाजार को बजट बड़ा पसंद आया। देशी-विदेशी कॉरपोरेट पूंजीपति खुश हुए और बजट की तारीफों के पुल बांधे गए। सरकार की गुलाम टीवी व अखबारों ने इस बजट को जनपक्षीय बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी।

आइये, बजट की मुख्य बातों को समझें!

बजट, इस बात का वार्षिक ब्यौरा होता है कि सरकार को कहां-कहां से कितनी आमदनी होगी और सरकार इसे किन मदों और किनके लिए खर्च करेगी? सरकार की आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत टैक्स होता है, जिसे वह अपने देश के लोगों से विभिन्न रूपों में वसूलती है। मोटा-मोटी यह दो प्रकार के होते हैं। प्रत्यक्ष कर, जो व्यक्तियों की आय से सीधा वसूला जाता है और अप्रत्यक्ष कर जो विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर वसूला जाता है, जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। हमारे देश में उदारीकरण, निजीकरण व भूमंडलीकरण की नीतियों को अपना लेने के बाद सरकार की आय का एक और स्त्रोत हो गया है, देश की सार्वजनिक कम्पनियों, परिसम्पत्तियों व प्राकृतिक संसाधनों को पूरी तरह या आंशिक तौर पर बेचकर आय जुटाना। अन्य भी कुछ आय के स्रोत हैं। माना यह जाता है कि देश में कहीं से भी किसी तरह की सरकार की आमदनी होती है, तो वह जनता के हित के लिए खर्च होनी चाहिए। लेकिन यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारी सरकार अपनी बजट का अच्छा-खासा हिस्सा पूंजीपतियों की पूंजी बढ़ाने व उनकी सुविधाओं पर खर्च करती है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए 2147000 करोड़ रूपये का अनुमानित बजट मोदी सरकार द्वारा पेश किया गया, अर्थात् सरकार को विभिन्न स्रोतों से इस बार 2147000 करोड़ की आमदनी होगी और इसे वह विभिन्न मदों में और विविध तबकों-समुदायों के लिए खर्च करेगी। अगर बजट में प्रस्तुत क्षेत्रवार और मंत्रालयवार बजट आवंटन पर सरकारी नजर दौड़ाई जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि सरकार का मुख्य फोकस कहां है और सरकार को हमारे देश की खस्ताहाल कृषि व सरकारी शिक्षा का कितना खयाल है। वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए प्रस्तुत बजट में रक्षा मंत्रालय को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। मंत्रालयवार बजट आवंटन में रक्षा 274114 करोड़, महिला एंव बाल विकास 22095 करोड़, जल संसाधन और गंगा 6887 करोड़, सामाजिक अधिकारिता 7763 करोड़, कौशल विकास 3016 करोड़, ग्रामीण विकास 107758 करोड़, सड़क परिवहन 64900 करोड़, रेलवे 55000 करोड़, नवीन एवं अक्षय उर्जा 5473 करोड़, अल्पसंख्यक मामले 4195 करोड़, सूक्ष्म, छोटे व मंझोले उद्योग 6482 करोड़, मानव संसाधन विकास 79686 करोड़, आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन 6406 करोड़, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 48853 करोड़, पेयजल एवं स्वच्छता 20011 करोड़, पूर्वोत्तर विकास 2682 करोड़ एवं कृषि एवं कृषक कल्याण 51026 करोड़ रूपये बजट में आवंटित किया गया है। वहीं क्षेत्रवार बजट आवंटन में रोजगार व कौशल 17273 करोड़, जनकल्याण 65258 करोड़, शिक्षा और स्वास्थ्य 130215 करोड़, सामाजिक क्षेत्र 195473 करोड़, परिवहन 241387 करोड़, आधारभूत संरचना 396135 करोड़, ग्रामीण विकास 128560 करोड़ व कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्र के लिए 58663 करोड़ रूपये आवंटित किए गये हैं।

हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। यहां की एक बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है और यहां की कृषि प्रकृति पर निर्भर है। हर साल देश के कई क्षेत्र बाढ़ व सुखाड़ का सामना करते हैं, लेकिन सरकार ने केंद्रीय बजट में सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण पर खर्च 2016-17 के 1105 करोड़ से घटाकर 1025 करोड़ कर दिया। यह बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लिए असहनीय है। ग्रामीण विकास में भी केंद्रीय योजना परिव्यय में 3027 करोड़ से घटाकर 2751 करोड़ कर दिया गया। पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन के केन्द्रीय योजना परिव्यय में 1142 करोड़ से घटाकर 1058 करोड़ कर दिया गया। प्रधानमंत्री खेती सिंचाई योजना के तरह हर खेत के लिए पानी को मात्र 500 करोड़, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के लिए मात्र 1377 करोड़, प्रति बूंद अधिक फसल के लिए मात्र 2340 करोड़ और एकीकृत जलसंभर प्रबंधन के लिए मात्र 1500 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है। इतने बजट में हर खेत को पानी पता नहीं कितने वर्षों में पहुंच पाएगा। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार मोदी सरकार ने किसानों को समर्थन मूल्य डेढ़ गुणा देने का वादा किया था। साथ ही किसानों की आमदनी दोगुना करने का भी वादा किया था, किंतु समर्थन मूल्य में मात्र 50 रूपये की वृद्धि की गई। इस तरह कहा जा सकता है कि किसानों को इस बजट में मात्र झुनझुना ही थमाया गया, उनके जिंदगी के व्यापक बदलाव के लिए कुछ भी नहीं किया गया।

किसानों की तरह ही युवाओं से भी इस बजट में सरकार ने हर बार की तरह गद्दारी ही की। मोदी सरकार ने हर साल दो करोड़ नये रोजगार पैदा करने का वादा देश के युवाओं से किया था। इस तरह मोदी सरकार का आधा कार्यकाल बीत जाने के बाद कम से कम 5 करोड़ रोजगार पैदा तो करना चाहिए था, लेकिन सरकार का ही श्रम ब्यूरो बताता है कि देश में रोजगार देने वाले आठ प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में अप्रैल से दिसंबर 2014 के दौरान 4.57 लाख, जनवरी से दिसंबर 2015 के दौरान 1.35 लाख और जनवरी से दिसंबर 2016 के दौरान 1.50 लाख रोजगार जोड़े गये हैं। यानी कुल मिलाकर अब तक रोजगार के 7.42 लाख नये अवसर बने हैं, जो मोदी सरकार के वादे का बमुश्किल डेढ़ प्रतिशत ठहरता है। ऐसे में वित्त मंत्री अरूण जेटली से इस बजट में युवाओं को बड़ी अपेक्षा थी कि रोजगार के बारे में जरूर कुछ ठोस उपाय करेंगे। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा, इस बार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का बजट आवंटन 2016-17 के 1120 करोड़ रूपये के संशोधित अनुमान से घटाकर 1024 करोड़ रूपये कर दिया गया। रोचक बात यह है कि नोटबंदी के कारण असंगठित क्षेत्र की लगभग ढाई लाख इकाइयां बंद हो गयी। एक इकाई में 5 मजदूर भी गिनें, तो इससे 7.5 लाख मजदूर बेरोजगार हो गए। वित्त मंत्री ने बजट में ऐसे लाखों मजदूरों के लिए कोई स्कीम पेश नहीं की। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सरकार के हर कारिंदे रोजगार की प्राथमिकता की बात करते थकते नहीं हैं। सवाल उठता है कि ढाई साल के कार्यकाल में जितने रोजगार पैदा किये गये, उससे ज्यादा उसकी एक नीति ने मात्र दो महीने में छीन लिया, तो आखिर इस जनविरोधी सरकार से युवा क्या रोजगार की उम्मीद लगाए?

हां! इस बजट से अगर कोई खुश है तो वह है यहां के पूंजीपति, ठेकेदार, सरकारी दलाल व कारपोरेट्स, क्योंकि किसी को टैक्स में छूट मिली है, किसी को इंफ्रास्ट्राक्चर के नाम पर सस्ती जमीन मिल गयी है और खेती के नाम पर एग्रो प्रोसेसिंग उद्योगों को सस्ते कर्ज मिल गये हैं। देश के विकास के लिए एयरपोर्ट बनाने के लिए किसानों से सस्ते दामों पर ली गई जमीनों में से हवाई अड्डे चलाने वाली कम्पनियों को 50 हजार एकड़ जमीन होटल, दुकानें आदि बनाने के लिए मिल गयी है।

मध्यवर्ग के मोदी भक्तों को भी 5 सौ एक हजार रूपये महीने का आयकर छूट का टुकड़ा फेंक दिया गया है। सम्पत्ति में दीर्घावधि पूंजीगत लाभ का फायदा भी अब 3 साल के बजाय 2 साल में ही मिलेगा, इससे भी इन्हें कुछ टैक्स बचाने का मौका मिलेगा। नोटबंदी से थोड़ा घायल और मोदी से थोड़ा असंतुष्ट चल रहे छोटे-मंझौले कॉरपोरेट तबके के बड़े हिस्से - 96 प्रतिशत कम्पनियों - को भी टैक्स में पांच प्रतिशत की छूट मिल गयी, लेकिन इन्होंने नोटबंदी के बाद जिन मजदूरों की छंटनी की थी उनका क्या, उन्हें कुछ राहत नहीं है। बड़े कारपोरेट तो खुद सरकारी आंकड़ों के अनुसार पहले ही 30 प्रतिशत की दर होते हुए भी 21 प्रतिशत टैक्स ही देते हैं, वह भी जितनी आमदनी दिखाते हैं उसपर, जो झूठे खाते बनाकर छिपा ली जाती है, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं।

विदेशी वित्तीय पूंजी मालिक भी खुश हैं। संस्थागत निवेशकों को अप्रत्यक्ष करों से छूट का वादा मिला है, तो बैंकिंग क्षेत्र को उनके डूबे कर्जों के नाम पर सजा के बजाय इनाम यानी टैक्स में छूट मिल गयी है। मोदी ने पूंजीगत लाभ पर टैक्स लगाने का जिक्र कुछ दिन पहले किया था, पर मालिकों की घुड़की के सामने वह भी धरा रह गया, फिर भी जेटली शिकायत करते हैं कि बहुत कम लोग टैक्स देते हैं। 2014 में मोदी ने 6 करोड़ सस्ते घर बनाने का वादा किया था, इस बार वह घटकर 1 करोड़ पर आ गया (बनेगा कितना किसी को पता नहीं), पर इसके नाम पर नोटबंदी के बाद से सरकार से असंतुष्ट बिल्डर तबके को आयकर में छूट और सस्ते कर्ज का इंतजाम भी हो गया है।

जहां जक सियासी पार्टी को व्यक्तिगत नकद चंदे की सीमा 20 से 2 हजार कर राजनीतिक भ्रष्टाचार कम करने का शोर है, तो इससे थोड़े अकाउंटेंट ही ज्यादा लगेंगे, ज्यादा रसीदें और वाउचर बनाने के लिए। फिर जितना पैसा असल में चुनाव और रैलियों में खर्च किया जाता है, उसका दसवां हिस्सा भी खातों में दिखाया जाता हो इसमें शक है। अडानी के हेलीकॉप्टर में जब मोदी (या और कोई और!) उड़ानें भरते हैं, तो क्या उसका कोई वाउचर बनता है? हां, इस शोर के पीछे बगैर घोषणा के ही राजनीतिक दलों को विदेशी चंदा लेने की छूट भी फाइनेंस बिल में घुसा दी गयी है।

पर पिछले कई साल से नौकरियों की कमी, घटती आमदनी और बढ़ती महंगाई झेल रहे मजदूर, छोटे-मध्यम किसानों, गांवों से उजड़कर शहरों में छोटे-छोटे धंधे करने वालों को क्या मिला? एक झुनझुना तक भी नही! हां, श्रम कानूनों में बदलाव से मालिकों द्वारा आसानी से निकाल बाहर करने की तलवार गर्दन पर तनी रहती जरूर है! इसी तरह छोटे-मध्यम किसानों की कब्रगाह तैयार करने के लिए ठेका खेती शुरू करने का भी ऐलान किया गया है, जिसके जरिये मेहनतकश किसान को कॉरपोरेट गुलामी में बांध दिया जायेगा।

निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 का केन्द्रीय बजट भी पुरानी बोतल में नयी शराब की तरह ही है। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी सरकार ने गरीब विरोधी

शेष पृष्ठ संख्या 24 पर

आर्थिक असमानता : अमीरों की सम्पत्ति में बेहिसाब वृद्धि

ऑक्सफेम की रिपोर्ट के अनुसार केवल 62 लोगों के पास दुनिया की आधी आबादी के बराबर सम्पत्ति है। इसमें 53 पुरूष और 9 महिलाएं है। दुनिया भर के नेताओं ने बढ़ती असमानता की समस्या को हल करने के बारे में बातें की, बड़े-बड़े सम्मेलन आयोजित किये और इसे हल करने की दिशा में कई योजनाएं भी बनाई। लेकिन 2010 से लगातार असमानता में बढ़ोत्तरी हो रही है। इसका पता इसी बात से चलता है कि 2010 में 388 लोगों की सम्पत्ति दुनिया की 350 करोड़ गरीब लोगों की सम्पत्ति से अधिक थी। 2015 तक आते-आते केवल 62 लोगों की सम्पत्ति दुनिया की आधी गरीब आबादी की सम्पत्ति से ज्यादा हो गयी। जाहिर है कि एक तरफ सम्पत्ति का केन्द्रीकरण मुट्ठी भर लोगों के हाथों में तेजी से बढ़ रहा है और दूसरी तरफ दुनिया की आधी गरीब जनता का कंगालीकरण भी उसी रफ्तार से बढ़ता जा रहा है। 2010 के बाद से दुनिया की आधी गरीब जनता यानी 350 करोड़ लोगों की सम्पत्ति में 38 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गयी है। इसी समय दुनिया के 62 सबसे अमीर लोगों की सम्पत्ति में 3 लाख करोड़ रूपये की वृद्धि हुई। अब उनकी सम्पत्ति 10 लाख करोड़ रूपये हो गयी है।

लगभग सभी देशों की सरकारों ने इन मुट्ठी भर अति ध नाढ्य लोगों को टैक्स में छूट देकर उन्हें अपनी सम्पत्ति बढ़ाने का मौका दिया है। टैक्स में छूट पाये इन अय्याशों ने अपने सारे सामाजिक कर्त्तव्यों को छोड़ दिया है। इनमें से अधिकांश धनपशु जवानी की उम्र से गुजर रहे हैं। ये कानून को अपने जूते की नोंक पर रखते हैं। इनकी संख्या इतनी कम है कि इन्हें एक बस में भरा जा सकता है या दो सैनिक बंदूक की नोंक पर जेल में ठूंस सकते हैं। लेकिन अपनी अथाह पूंजी के दम पर ये सरकारों को भी अपनी उंगलियों पर नचाते हैं।

पिछले साल जनवरी में स्विट्जरलैंड के पांच सितारा होटल दावोस में भव्य पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें दुनिया के सबसे महंगे पकवान परोसे गये। इस पार्टी में दुनिया भर के 2500 सबसे अमीर और शक्ति सम्पन्न लोग शामिल हुए। यहां उन्होंने विश्व आर्थिक फोरम की मीटिंग की। इस मीटिंग में इन अमीरों ने अपनी सम्पत्ति को बढ़ाने के लिए तरह-तरह के उपायों पर चर्चा की। इनके बीच ऑक्सफेम की कार्यकारी निदेशिका विन्नी ब्यानीयमा भी उपस्थित थीं। उन्होंने कहा कि अरे भाई आप लोगों की करतूतों के चलते असमानता बहुत बढ़ गयी है, दुनिया भर में 100 करोड़ लोग रोजाना 100 रूपये से कम पर गुजारा करते है। स्थिति बहुत विस्फोटक होती जा रही है। गरीबी दूर करने के लिए कुछ करो, नहीं तो खतरा सिर पर मंडरा रहा है। उन्होंने कहा कि 2009 में 1 प्रतिशत सबसे अमीर लोगों के पास दुनिया की सम्पत्ति का 44 प्रतिशत था, जो 2014 में बढ़कर 48 प्रतिशत हो गया। इतनी सम्पत्ति के बावजूद आप लोग और अधिक सम्पत्ति जुटाना चाहते हैं?

रिपोर्ट के अनुसार अफ्रीकी अर्थव्यवस्था का 30 फीसदी विदेशों में है। जिसका प्रत्येक वर्ष का टैक्स इतना है कि अफ्रीकी मांओं और उनके बच्चे के लिए स्वास्थ्य सेवा की गारन्टी हो सकती है और प्रत्येक अफ्रीकी बच्चे के पास पर्याप्त अध्यापकों की व्यवस्था की जा सकती है। ऐसे ही तमाम देशों की पूंजी विदेशों के स्विस बैंकों में जमा है। लेकिन उन्हें सार्वजनिक क्षेत्रों में इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है।

हरून ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार, 2016 में दुनिया में 99 नये अरबपति जुड़े, जिसमें भारत के 27 अरबपति शामिल है। ज्यादातर अमीरों की तिजोरी भरने के स्त्रोत दवा, नशीले पदार्थ, तेल और गैस के कारोबार हैं। इन अमीरों का रूपया इन्फ्रास्ट्रक्चर, रियल स्टेट और सट्टा बाजारी में लगा हुआ है। इन मुट्ठी भर अमीरों को सरकार की तरफ से छूट मिलती है। मुकेश अम्बानी भारत के सबसे धनी व्यक्ति हैं, जो रिलायंस इन्डस्ट्री के मालिक हैं जिसका मुख्य कारोबार तेल और गैस है। मई 2014 में इस कम्पनी पर ओएनजीसी (सरकारी कम्पनी) के कुएं से गैस चोरी करने का आरोप लगा था। इसने 30 हजार करोड़ रूपये की गैस चुराई थी। अपनी विशाल पूंजी के दम पर मुकेश अम्बानी का सभी सरकारों पर भारी प्रभाव है। इन्हें सस्ती दर पर कर्ज और बेहद सस्ती दर पर जमीन मुहैया कराना सरकारों का काम रहा है। आज सरकारें ऐसे चन्द अमीरों की गोद में बैठकर उनकी दौलत बढ़ा रही है। 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाले में टाटा समूह का नाम भी सामने आया था, लेकिन उन पर कोई खास कार्रवाई नहीं की गयी। आज कानून व्यवस्था केवल गरीब जनता को धमकाने-डराने तक सीमित रह गयी है। जनता के लिए कानून व्यवस्था का चरित्र बेहद दमनकारी है। यह केवल मुट्ठी भर अमीर लोगों का हुक्म बजाती है।

धनी-गरीब के बीच की इस बढ़ती खाई के साथ भारत में आम लोगों का जीवन स्तर भी बदतर होता जा रहा है। मानव सूचकांक में भारत का 133वां स्थान है। यहां तक कि कम संसाधन वाला क्यूबा मानव सूचकांक में 67वां और श्रीलंका 73वां स्थान रखता है। भारत इस दौड़ में चीन से भी पीछे है। मानव सूचकांक किसी भी देश के नागरिकों के जीवन जीने के स्तर को प्रदर्शित करता है जिसमें भोजन में जरूरी पोषक तत्वों की मात्रा, शिक्षा का स्तर, रोजगार की

स्थिति और सामाजिक जीवन आता है। भारत की अधिकांश जनता बेहद गरीब और बदहाली में जिंदगी गुजार रही है। इसके बावजूद भारत दुनिया भर में सातवां सबसे धनी देश है। इसकी कुल सम्पत्ति 364 लाख करोड़ है। अमेरिका पहले पायदान पर है, जिसकी कुल सम्पत्ति 3178 लाख करोड़ है। दूसरे और तीसरे पायदान पर चीन और जापान है, जिनकी कुल सम्पत्ति क्रमशः 1133 लाख करोड़ और 981 लाख करोड़ है। चौथे, पांचवे ओर छठे पायदान पर क्रमशः इंग्लैंड, जर्मनी और फ्रांस है।

अमीर-गरीब की खाई को चौड़ी करने में सरकार की सचेत भूमिका रही है। 2008 में दुनिया मन्दी के संकट से जूझ रही थी, भारत में भी 2011 में मन्दी ने दस्तक देना शुरू कर दिया। 2011 से 2014 के बीच 1 प्रतिशत अमीरों की सम्पत्ति में खास इजाफा नहीं हुआ। उन्होंने मनमोहन सिंह सरकार के उपर सुधारों के दूसरे चरण के लिए दबाव बनाया। लेकिन, आम जनता के भारी दबाव के चलते कांग्रेस सुधारों के दूसरे चरण को शुरू न कर सकी। पूंजीपतियों का गुस्सा कांग्रेस पर फूट पड़ा। उन्होंने कांग्रेस का एक-एक करके साथ छोड़ दिया और भाजपा के खेमे में चले गये। तालिका से स्पष्ट है कि 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद से ही 1 प्रतिशत अमीरों की सम्पत्ति 49 प्रतिशत से बढ़कर 2016 में 58.4 प्रतिशत हो गयी। यह स्पष्ट है कि देश की सम्पत्ति में अमीरों का हिस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है और उसी अनुपात में गरीबों का हिस्सा घटता जा रहा है। 2016 में देश के सबसे धनी 10 प्रतिशत अमीरों का देश की कुल सम्पत्ति में हिस्सा 80.7 प्रतिशत था। यानी बाकि की 90 प्रतिशत आबादी केवल 19.3 प्रतिशत सम्पत्ति की मालिक है। सबसे चौंकाने वाली तस्वीर यह है कि भारत की आधी जनता केवल 2.1 प्रतिशत सम्पत्ति की मालिक है। यानी भारत की 65 करोड़ की आबादी की औसत सम्पत्ति मात्र 11760 रूपये हैं। इतनी कम संपत्ति में खाने, पहनने और दवा आदि पर खर्च करने के बाद कोई व्यक्ति अपनी दिनचर्या कैसे चला सकता है?

असमानता को गिनी गुणांक से भी मापा जाता है। 1990 में, भारत का ''गिनी गुणांक'' 45 था, जो कि 2013 में बढ़कर 51 हो गया। वहीं 1990 में पड़ोसी देश नेपाल का गिनी गुणांक 40 था, जो कि 2013 में घट कर 33 हो गया। भारत ऐसे देश से भी पीछे है जिसके पास कम संसाधन हैं। किसी भी देश का ''गिनी गुणांक'' नागरिकों के बीच आर्थिक असमानता और असमान आय के अन्तर को प्रदर्शित करता है। गिनी गुणांक बढ़ने का मतलब आर्थिक असमानता का बढ़ना है।

तालिका : भारत में अमीरों की सम्पत्ति में सालाना इजाफा

सन्	1 प्रतिशत अमीरों की सम्पत्ति	10 प्रतिशत अमीरों की सम्पत्ति
2010	40.3	68.8
2011	46.8	72.6
2012	48.8	73.8
2013	48.7	73.8
2014	49.0	74.0
2015	53.0	76.3
2016	58.4	80.7

स्रोतः- क्रेडिट सुईस ग्लोबल वेल्थ डेटाबेस

1990 के दौर में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण जैसी नीतियां लागू की गयी। सट्टेबाजी और शेयर मार्केट सामने आये, जिसमें कोई भौतिक उत्पादन नहीं होता है, लेकिन कुछ शेयर धारकों की पूंजी दिन-दूनी और रात-चौगुनी होने लगी। पूंजीपतियों के मुनाफे को बनाये रखाने के लिए डब्लू.टी.ओ., आई.एम.एफ, फिक्की, एसोचैम और विश्व बैंक आदि संस्थाओं ने खुलकर काम किया। बढ़ती आर्थिक असमानता ही सामाजिक असमानता को जन्म देती है, आर्थिक गैर-बराबरी बढ़ने के चलते सामाजिक असमानता में भी बेतहाशा बढोत्तरी हुई है।

बस्तर में पुलिसिया गुंडागर्दी पर पीयूडीआर की रिपोर्ट

हाल ही में अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत बस्तर के पूर्व आईजी (पुलिस) एसपीआर कल्लूरी को दो कारण बताओ नोटिस और एक चेतावनी पत्र दिए गए और एसपी सुकमा आईके एलसेला और एसपी बस्तर आरएन दास के तबादले कर दिए गए। पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स का मानना है कि कानून लागू करने वाले ऑफिसरों की हैसियत से उनके द्वारा किए गए अपराधों की तुलना में यह कारवाई किसी भी लिहाज से नाकाफी नहीं है। इन दो नोटिसों में उन्हें निजी समारोहों में भाग लेने और सरकार की सोशल मीडिया की नीति के खिलाफ बयान देने के लिए धमकाया गया है, परन्तु इसमें उसके द्वारा नागरिकों को खुले आम धमकी देने के खिलाफ कुछ भी नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार के अनुसार आरएन दास का तबादला बस्तर से बाहर बलोदा बाजार में कर दिया गया है और आई के एलसेला को रायपुर के स्टेट इंटेलीजेंस ब्यूरो में भेज दिया गया है। पर समस्या यह है कि ये पोस्टिंग किसी भी लिहाज से सजा की पोस्टिंग नहीं कही जा सकती।

दो मार्च 2017 को वाहनों के एक निजी शो रूम के उद्घाटन के अवसर पर कल्लूरी और दास की उपस्थिति में एलसेला ने खुलेआम यह पैरवी की कि मानव अधिकार कार्यकर्त्ताओं को 'वाहनों के नीचे कुचल दिया जाना चाहिए' और ऐसे बयान देने को उन्होंने बोलने की आजादी के बहाने सही ठहराया। बस्तर पुलिस के ऑफिसर काफी धड़ल्ले से सार्वजनिक रूप से हर उस व्यक्ति को देशद्रोही और गद्दार घोषित करते रहे हैं, जो 'मिशन 2016' (और अब मिशन 2017) को पूरा करने के तहत की गई उनकी किसी भी कारवाई की आलोचना करता है। ये पुलिस ऑफिसर खासकर मानव अधिकार कार्यकर्त्ताओं और संवाददाताओं पर हमले करने के लिए गुंडों को संरक्षण देते रहे हैं और प्रोत्साहित करते रहे हैं। इस तरह से खुलेआम हत्या करने का आह्वान करना उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। याद रहे पिछले कुछ समय में पुलिस और निजी मिलिशिया के मिले-जुले हमलों ने कई वकीलों, संवाददाताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं को बस्तर से बाहर कर दिया है। जो बस्तर नहीं छोड़ सके या जिन्होंने बस्तर न छोड़ने का फैसला किया, उन्हें तरह-तरह से प्रताड़ित किया गया और उनमें से कुछ जेलों में बंद हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय और जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के शिक्षक भी इनमें शामिल हैं। कई औरों को आरोपित किये जाने या गिरफ्तार करने की धमकियां भी दी गई। बस्तर पुलिस को कुछ भी करने की जो खुली छूट मिली हुई है, उसने उन्हें इतना दु:साहसी बना दिया है कि वे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खुद पर आगजनी और बलात्कार के आरोप लगाए जाने की भी खिल्ली उड़ा सकते हैं और उन सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं के पुतले भी जला सकते हैं, जिन्होंने ये मामले दर्ज किए थे। इस तरह की कार्यवाहियां उन सभी नागरिकों के खिलाफ बेशर्मी से हिंसा भड़काने के बराबर है, जो आदिवासियों के खिलाफ युद्ध में पुलिस की गैरकानूनी कार्यवाहियों और इन घटनाओं के संबंध में पुलिस के विवरणों पर सवाल उठाने की हिम्मत कर रहे हैं। यहां यह ध्यान रखना जरूरी है कि राजसत्ता द्वारा आदिवासियों के खिलाफ चलाए जा रहे युद्ध का असली उद्देश्य खनन और खनन आधारित उद्योगों के खिलाफ हो रहे विरोध को कुचलना है जो कि जगह-जगह अहिंसक तरीकों से भी संघर्षरत हैं। जो भी 'विकास' के इस मॉडल का विरोध करता है, वह बस्तर पुलिस की निगाहों में अपराधी है।

छत्तीसगढ़ पुलिस एक्ट-2007 की धारा 12 (1) के तहत पुलिस की प्रमुख जिम्मेदारी लोगों की जिंदगी, स्वतंत्रता की रक्षा करना और उनकी गरिमा बनाए रखना है। यह संविध ान के अनुच्छेद 21 में से निकलता है जिसके अनुसार लोगों के जिंदगी और स्वाभिमान को बनाए रखने की जिम्मेदारी राजसत्ता की होती है। पुलिस एक्ट की धारा 24 के तहत एक पुलिस अधिकारी 24 घंटे ड्यूटी पर होता है। इस तरह से जिस समय इन अधिकारियों ने नाम लेकर मानवाधिकार कार्यकर्त्ता ईशा खंडेलवाल और शालिनी गेरा को जान से मारने की वकालत की, उस समय भी वे ड्यूटी पर थे। इस तरह कानून लागू करने के लिए जिम्मेदार इन अधिकारियों द्वारा खुलेआम नागरिकों के खिलाफ हिंसा भड़काने को एक गंभीर अपराध माना जाना चाहिए। पर ऐसा हो, इसकी संभावना न के बराबर है और अगर गलती से एफआईआर दर्ज हो भी गई, तो भी उसी पुलिस द्वारा ईमानदारी से इसकी तहकीकात की उम्मीद नहीं की जा सकती और वैसे भी सीआरपीसी के धारा 197 के तहत पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति मिलना बहुत मुश्किल है। ऐसा कुछ ही मामलों में केवल अत्यधिक नागरिक दबाव के कारण ही हो पाया है।

कल्लूरी का यह अपराध और भी गंभीर हो जाता है क्योंकि आईजी बस्तर का उनका कार्यकाल हिरासत में बलात्कार, यातनाएं दिए जाने, फर्जी मुठभेड़ों, महिलाओं के साथ यौनिक हिंसा, लोगों को झूठे 'नक्सल अपराधों' में पकड़कर बड़ी संख्या में जेलों में ठुंसने से भरा पड़ा है। यह कार्यकाल हर उस व्यक्ति को प्रताड़ित करने से भी भरा पड़ा है, जिसने भी पुलिस की कहानियों पर सवाल उठाए या इन

शेष पृष्ठ संख्या 52 पर

एक दूसरे से सीखने और आत्मसन्तुष्टि व घमण्ड पर काबू पाने के लिए केन्द्र का निर्देश

(यह लेख कामरेड माओ की चयनित रचनाएं, ग्रंथ-9 का से लिया गया है, यह लेख दिसम्बर, 1963 में चीन में समाजवादी शिक्षा आंदोलन के दौरान लिखा गया था। इस लेख के महत्व को देखते हुए व पार्टी में चल रहे बोल्शेविकरण अभियान के तहत अध्ययन के लिए यहां प्रकाशित किया जा रहा है। - संपादकमंडल, लाल चिनगारी)

आत्मसन्तुष्ट व घमण्डी होना; मार्क्सवादी द्वन्द्वात्मक विश्लेषण के तरीके यानी एक को दो (उपलब्धियां और कमियां) में बांट कर देखने के तरीके को इस्तेमाल करने से इन्कार करना; सिर्फ अपने ही क्षेत्र में सीमित होकर काम करना, उपलब्धियों का अध्ययन करना, कमियों और गलतियों का नहीं, पर चापलूसी पसंद करना लेकिन आलोचना को नहीं, सक्षम उच्च और मध्यम स्तरीय कैडरों को संगठित कर अन्य राज्यों-शहरों या विभागों के काम की जांच-पड़ताल कर उनसे सीखने और अपने राज्य, शहर, क्षेत्र या विभाग के काम को सुधारने में जरा भी दिलचस्पी न लेना, आंखें मून्द कर घमण्डी होना यानी कि खुद को अपने ही जिले या विभाग की छोटी सी दुनिया तक सीमित कर लेना, अपनी हदों को विस्तार करने में असमर्थता और अन्य कार्यक्षेत्रों के बारे में जानकारी नहीं हासिल करना; विदेशियों, दूसरी जगह से आये पर्यवेक्षकों और केन्द्र द्वारा भेजे गये लोगों को सिर्फ अपनी उपलब्धियां ही दिखाना और उन्हीं के बारे में बातें करना, कमजोरियों के बारे में नहीं, सारहीन व सरसरी बातें करना, हमारे सभी कामरेडों से यह गलतियां हो रही है। केन्द्रीय कमेटी ने कई बार इस समस्या पर हमारे साथियों का ध्यान दिलाया है। एक कम्युनिस्ट के पास 'एक को दो में विभाजित करना' सभी विषय (आर्थिक, राजनीतिक, सैद्धांतिक, सांस्कृतिक, सैनिक, पार्टीगत आदि) हमेशा विकास की प्रक्रिया में ही होते हैं; यह मार्क्सवादियों की आम समझ है। फिर भी केन्द्र व क्षेत्रों के कई साथी इस सोच और काम करने की इस विधि का इस्तेमाल नहीं करते। उनके दिमागों में एक औपचारिक तर्क गहरा बैठा हुआ है, जिससे वह पीछा नहीं छुड़ा पा रहे। यह औपचारिक तर्क 'विरोधियों की एकता' को, विरोधियों के बीच एकता व संघर्ष को, विशेष हालातों में विरोधी पहलुओं के एक दूसरे में रूपांतरण को नकारता है। इसलिए वे कामरेड आत्मसंतुष्ट, अहंकारी, सिर्फ उपलब्धियों को देखने वाले, कमजोरियों की तरफ आंख मूंदने वाले, सिर्फ प्रशंसनीय बातें सुनने वाले, आलोचनाओं को नहीं सुननेवाले, खुद की आलोचना (यानी एक को दो में विभाजित करके देखना) न करनेवाले और दूसरों के द्वारा आलोचना किये जाने से डरने वाले बन जाते है। पुरानी कहावत ''अहंकार अहितकारी है और विनम्रता हितकारी'' जनहित और सर्वहारा के दृष्टिकोण से आज भी लागू होती है।

1. अहंकार सभी हालातों और रूपों में बढ़ता है। आमतौर पर यह सफलता और जीत के साथ बढ़ता है, क्योंकि प्रतिकूल हालातों में अपनी कमजोरियों को कोई भी आसानी से देख सकता है, अपेक्षाकृत थोड़ी सावधानी से काम लेता है। कठिनाइयों के दबाव में विनम्रता और सावधानी ही अनुसरणीय रवैया है। पर सफलता के साथ दूसरों की कृतज्ञता भी मिलती है। एक समय का दुश्मन भी मन बदल कर उस व्यक्ति (उसकी क्षमताओं और शक्ति) की प्रशंसा कर सकते हैं। इस लिए अनुकूल हालातों में सिर घूम सकता है और वह धरती पर पैर रखना छोड़ देता है। वह विश्वास करता है, ''अब से पूरे राज्य में अमन-चैन रहेगा'' हम सभी जानते है कि जब जीत और सफलता प्राप्त हो जाती है, पार्टी के अहंकार नामक विषाणु की चपेट में आने की अत्यधिक संभावनाए होती है।

2. जीत के हालातों में अहंकार बढ़ जाता है यानी सिर पर घमण्ड सवार हो जाना और अहम् बढ़ जाना। यह एक तरह का अहंकार है। दूसरी तरह का अंहकार साधारण हालातों में बढ़ता है। बिना किसी शानदार जीत या शर्मिंदा करनेवाली हार में, अगर यह विचार दिमाग में बैठ जाये कि 'उतना अच्छा भले ही नहीं है, पर मूर्ख से तो बेहतर है', 'बीस साल तक बहु बने रहने का अनुभव सहज ही सास बना देगी' तो अहंकार बढ़ जाता है।

तीसरी तरह का अहंकार पिछड़े हुऐ हालातों में बढ़ता है। कुछ लोगों को अपने पिछड़ेपन पर भी गर्व महसूस होता है,

क्योंकि वह सोचते है, हालांकि हमारा काम अच्छा नहीं रहा, फिर भी वह पहले की तुलना में बेहतर है या फलाना-फलाना आदमी तो हमसे भी गया-गुजरा है और जब-जब वे अपने इतिहास पर रोशनी डालना चाहते हैं, वे तुरन्त विषय बदल देते है, उनके चेहरे खिल जाते है और वे बोलना शुरू कर देते है, ''एक बार की बात है.....''

3. जैसे ही हम जनता की ताकत को नजरअंदाज करते हैं, वैसे ही हमारी मनोगत समझ वास्तविक हकीकत के विकास क्रम से पीछे रह जाती है, जैसे ही हम अपनी उपलब्धियों का आकलन बढ़ा-चढ़ा कर करते है, हम घमंडी बन जाते हैं।

4. मूल रूप से अहंकार व्यक्तिवाद से जन्म लेता है और व्यक्तिवाद का पालन-पोषण करता है, यह व्यक्तिवादी होता है।

5. वर्ग विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से कहा जाए, तो अहंकार पहले शोषक वर्ग की विचारधारा से आता है और बाद में छोटे उत्पादकों की।

6. श्रमिकों की तरह छोटे उत्पादकों में कई अच्छे गुण हैं। वह मेहनती और मितव्ययी है, कठिनाइयों से नहीं डरते, चौकस तथा यथार्थवादी है। पर छोटे मालिकों के तौर पर, वे व्यक्तिवादी है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने काम के हालातों और पुराने उत्पादन के साधनों के इस्तेमाल के कारण सीमित होकर, वह बिखरे हुए संकीर्ण और कम जानकार होते है। आम तौर पर वह सामूहिकता की ताकत के बारे में बेखबर होते है; वह सिर्फ व्यक्ति की ताकत को देखते है। इसके अलावा, वे तुरन्त संतुष्ट हो जाते है। एक छोटी सी उपलब्धि उन्हें ऐसा सोचने को प्रवृत करती है कि, ''यह खराब तो नहीं है, यह बेहतरीन है'' 'आह; थोड़ा मजा करेंगे' और 'उतना उत्तम भले ही नहीं है पर मूर्ख से तो बेहतर है।'

7. अहंकार बुर्जुआ आदर्शवादी विश्व दर्शन पर आधारित है। वह हमें वास्तविकता के विकास के नियमों के उलट वास्तविकता से व्यवहार करने पर विवश कर सकता है, जिसका सीधा नतीजा असफलता ही होती है। ऐतिहासिक भौतिकवादी दर्शन बताता है कि सामाजिक विकास का इतिहास बड़े लोगों का इतिहास नहीं बल्कि मेहनतकश जनता का इतिहास है। फिर भी अहंकारी लोग हमेशा व्यक्ति की भूमिका को बढ़ा-चढ़ा देते हैं। अपनी पीठ खुद ही थपथपाते हैं। वे जनता के ताकत को कम आंकते है या पूरी तरह नजरअंदाज करते हैं।

8. अत: अहंकार मार्क्सवाद-लेनिनवाद के खिलाफ है और हमारी पार्टी के द्वन्द्वात्मक व ऐतिहासिक भौतिकवादी विश्व दृष्टिकोण के खिलाफ है।

9. अहंकारी लोग अपनी खूबियों को कभी नहीं भूलते हैं। वे अपनी कमियों पर परदा डालते हैं और दूसरों के मजबूत पहलुओं को नजरअंदाज करते हैं। वे आमतौर पर अपनी खूबियों की तुलना दूसरों की कमियों से कर संतुष्टि प्राप्त करते हैं। जब दूसरों की खूबियों की बात आती है, वे कहते है ''कुछ खास नहीं'' या ''खुश होने की कोई बात नहीं है।''

10. असल में, कोई खुद को जितना ज्यादा आंकता है, उतना ही बुरा नतीजा निकलता है। महान रूसी लेखक टालस्टॉय ने मजाकिया टिप्पणी की है, ''आदमी गणित के अपूर्ण अंक के समान होता है, जिसके असल प्रतिभा की तुलना गणक से की जा सकती है। उसके खुद के आकलन की तुलना 'भाजक' से। भाजक जितना ज्यादा होगा, अपूर्ण अंक उतना ही कम होगा।

11. एक क्रांतिकारी के लिए विनम्रता एक जरूरी गुण है। यह जन हित के लिए फायदेमंद है, अहंकार जनहित को हार की तरफ ले जाता है। इस तरह विनम्रता जन हित के लिए किसी की जिम्मेदारी को जाहिर करती है।

12. नाम और व्यवहार से किसी क्रांतिकारी को जरूर ही इन बातों में योग्य होना चाहिए; सबसे पहले, जनता की रचनात्मकता का आदर करना, उनके विचारों को सुनना और खुद को उन्हीं में से एक मानना। उसमें तनिक भर भी स्वार्थ नहीं होना चाहिये या अपनी भूमिका को बढ़ाना-चढ़ाना नहीं चाहिए और उसे जनता के लिए इमानदारी से काम करना चाहिए। इसी भावना को लू-शुन ने इस तरह बयान किया है, ''अपना सिर नीचे झुकाए, अपनी स्वेछा से मैं जनता का बैल बनने के लिए तैयार हूं।'' यह विनम्रता है।

13. दूसरा, उसमें अथक और प्रगतिशील चेतना जरूर होनी चाहिए और वह हमेशा सचेत व समझदार होना चाहिए। उसे नये विषयों पर जरूर गौर करना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए, इसलिए उसमें विनम्रता जरूर होनी चाहिए ताकि वह अनुचित रूप से गुणों का श्रेय न ले, और न ही अपनी उपलब्धियों से संतुष्ट हो जाये। यह एक उचित रवैया है।

विनम्रता का महत्वपूर्ण लक्षण।

14. यदि एक मनुष्य काम से, जीवन से और संघर्षों से गम्भीरता से सीख ले सकता है, यदि अपनी कमियों, और गलतियों को पहचानने के उद्देश्य से अपने अहंकार और आत्मसंतुष्टि के खिलाफ दृढ़ता से और बेरहमी से लड़कर पूर्ण रूप से इन पर काबू पा सकता है, तो निश्चित ही वह खुद को विनम्र मनुष्य बनाने के काबिल होगा।

15. एक सही विनम्र इन्सान एक ऐसा इन्सान भी होता है, जो पार्टी, जनता और समूह के हित के लिए उत्साहपूर्वक, बिना शर्त, निष्ठापूर्वक और सक्रिय रूप से काम करता है। वह दिखावे के लिए, नाम कमाने या इनाम पाने के लिए काम नहीं करता और न ही उस का कोई खुदगर्ज हित होता है, बल्कि वह जनता की खुशी और हितों के लिए दिलो-जान से काम करता है। इसलिए वह हमेशा पार्टी और जनता के फायदे के लिए मेहनत में डूबा रहता है और अपनी पहचान, रूतबे, प्रतिष्ठा और वेतन पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देता। वह अन्य लोगों के सामने अपनी उपलब्धियों की शेखी नहीं बघारता है, ऐसे खयाल मन में आने ही नहीं देता। जनता की और बेहतर सेवा करने के सिवा दूसरा कुछ नहीं सोचता।

16. एक सच्चे समूहवादी को खुद को विनम्र बनाने की तमन्ना क्यों रखनी चाहिये?

पहला, क्योंकि वह समझता है कि ज्ञान या दूसरे नतीजे हासिल करने से उसकी भूमिका के बावजूद, जनता की भूमिका उससे बहुत बड़ी है। जनता के समर्थन और मदद के बिना, न तो वह ज्ञान हासिल कर पाता और न ही उसका काम सफल हो पाता। एक समूहवादी होने के नाते उसे जनता की मेहनत की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए या दूसरों को उनकी उपलब्धियों से वंचित नहीं करना चाहिए। वह जानता है कि अहंकारी होना शर्मनाक बात है।

दूसरा, वह समझता है कि उसने जो कुछ भी सीखा या किया, क्रांतिकारी ज्ञान व कार्य के समुद्र में एक छोटी सी बूंद मात्र है और अति सूक्ष्म है। इसके अलावा, क्रांतिकारी ज्ञान व कार्य लगातार विकसित हो रहे है। एक समूहवादी होने के नाते, उसे ज्ञान हासिल करने की अत्यधिक कोशिश करनी चाहिए, जो कि जनता के लिए फायदेमंद हो और अपनी संपूर्ण क्षमताएं क्रांति को अर्पित कर देनी चाहिए। इसलिए, उसे यह अहसास होना चाहिए कि आत्मसंतुष्ट होकर निष्क्रिय बनने की कोई गुंजाईश नहीं है।

तीसरा, वह समझता है कि काम एक बड़ी मशीन की तरह है, जो कि अलग-अलग आकार और प्रकार के चक्कों, पेंचों, इस्पात के ढांचों और दूसरे कल-पुर्जों से बनती है और हर एक पुर्जा अनिवार्य है। एक समूहवादी के तौर पर उसे हर आदमी के काम तथा हर आदमी की उपलब्धियों का सम्मान करना चाहिए। क्रांतिकारी कार्य में पूर्णता लाने के लिए उसे जरूर ही अपने काम का दूसरों के काम के साथ ताल-मेल बैठाना चाहिए। उसे महसूस करना चाहिए कि समूह के बाहर हो जाना वह सहन नहीं कर सकता और वह अपने साथियों से अपार स्नेह करता है। इस वजह से, लोगों के साथ विनम्रतापूर्वक पेश आना चाहिए, घमंड से कभी नहीं।

चौथा, वह समझता है कि एक व्यक्ति की धारणा का दायरा संकुचित व सीमित है, जबकि क्रांतिकारी कार्य और ज्ञान का दायरा बहुत बड़ा होता है और उसके घटक बेहद समृद्ध और जटिल होते हैं। इस प्रकार वह समझ जाता है कि व्यक्ति में कमियां रहना अनिवार्य है और संभवतः गलतियां होती ही है। कभी-कभी ये कमियां और गलतियां इन्सान के ध्यान में नहीं आती, क्योंकि वह समूहवादी है, इसलिए अपनी खामियों और गलतियों को शीघ्रता से व गहराई से समझकर उन्हें सुधारना चाहता है, ताकि वह क्रांतिकारी कार्य अच्छी तरह से कर सके और जनता के प्रति जिम्मेदार बन सके। यही वजह है कि वह विनम्रता व ईमानदारी से दूसरों से सीखता है।

इन मुख्य बिन्दुओं से हम देख सकते हैं कि एक सच्चा समूहवादी विनम्रता से ओत-प्रोत होता है। यह एक ऐसा तथ्य है, जो उसके प्रगतिशील विचारों और वास्तविकतावादी रवैये को दर्शाता है।

17. अहंकार पर काबू पाने और विनम्रता को बढ़ाने का एक तरीका अपनी कम्युनिस्ट चेतना को बढ़ाना है। इसके लिए मार्क्सवाद-लेनिनवाद के गहन अध्ययन की जरूरत होती है। ऐसा किस लिए?

18. क्योंकि दुनिया को वैज्ञानिक ढंग से समझने और व्यक्तियों व जनता के बीच, व्यक्तियों व समूह के बीच, व्यक्तियों व संगठन के बीच तथा व्यक्तियों और पार्टी के बीच संबंधों को वैज्ञानिक ढंग से समझने के लिए मार्क्सवाद-लेनिनवाद के सिद्धांत हमारी मदद कर सकते हैं।

क्रांतिकारी संघर्षों में जनता और व्यक्तियों की भूमिकाओं को सही तरीके से समझने के लिए भी हमारी मदद करते है।

मार्क्सवाद-लेनिनवाद हमें बताता है कि मेहनतकश जनता ही सामाजिक संपत्ति की निर्माता है और क्रांतिकारी संघर्ष का मुख्य आधार है। चीन में समाजवाद और साम्यवाद का निर्माण करने के लिए हमें उनके हिरावल दस्ते के नेतृत्व में, मजदूरों और लाखों मेहनतकश जनता की रचनात्मक ताकत पर निर्भर होना चाहिए। जहां तक व्यक्ति का सवाल है, क्रांतिकारी कार्य में वह एक छोटे से पेंच से ज्यादा कुछ नहीं होता। मार्क्सवाद-लेनिनवाद हमें बताता है कि सभी उपलब्धियां सामूहिकता की ताकत का ही नतीजा है। कोई भी व्यक्ति खुद को सामूहिकता से अलग नहीं कर सकता। नेतृत्व करने वाली पार्टी या उसका समर्थन करने वाले संगठन और लोगों के बिना व्यक्ति कुछ भी पूरा नहीं कर सकता। अगर हम इतिहास में जनता और व्यक्ति की भूमिकाओं और उनके आपसी संबंध ों को सही अर्थों में समझने लगें, तो हम अपने आप ही विनम्र बन जाएंगे।

मार्क्सवाद-लेनिनवाद हमारे भविष्य और हमारी मंजिल पर हमारी समझ को जागृत करता है। हमारी सोच के दायरे को बढ़ा सकता है और हमारे सोच-विचार को संकीर्णता से मुक्त कर सकता है। जब लोग सिर्फ यही देखते हैं कि उनके पैरों के नीचे क्या है और यह नहीं देखते कि पर्वतों से ऊपर और समुंदरों के पार क्या है, तो वह 'कुएं के मेढ़क की तरह' शेखीबाज ही हो जाएगा, लेकिन जब वह सिर उठाकर दुनिया की विशालता को मनुष्य के रंग-बिरंगे कार्यकलापों को मानवता के उद्देश्य की बहु-मूल्यता को, इन्सान की योग्यताओं की समृद्धता को और ज्ञान की व्यापकता को देखते हैं, तो वह विनम्र बन जाते है। हम उस कार्यभार के लिए समर्पित हैं, जो दुनिया को झकझोरने वाला है। हमें सिर्फ आंखों के सामने मौजूद संसार को और सुख-शान्ति पर ही ध्यान केन्द्रित करना नहीं चाहिए, बल्कि दूरगामी भविष्य में हम सबके काम और खुशियों पर केन्द्रित करना चाहिए। एक छोटी सी जीत या एक छोटी सी उपलब्धि भर से आत्मसंतुष्ट हो जाने वाले छोटे उत्पादक की मानसिकता से उबरने में मार्क्सवाद-लेनिनवाद हमारी मदद करता है। यह निरंतर प्रगति की हमारी चाह को जगाता है, उसके साथ-साथ यह हमें आदर्शवादी मनोगत सोच-विचार को खत्म करने में मदद करता है।

19. विनम्रता और आत्म तिरस्कार पर्यायवाची नहीं है। विनम्रता का मतलब अपने आप को छोटा समझना नहीं है। यह यथार्थवादी दृष्टिकोण और प्रगतिशील सोच-विचार की अभिव्यक्ति है, जो तथ्यों को वस्तुनिष्ठता से देखती है। जबकि आत्मतिरस्कार यथार्थ के विरोध की अभिव्यक्ति है, आत्मविश्वास की कमी और कठिनाइयों के प्रति डर है। आत्मतिरस्कार, अपनी शेखी बघारना या श्रेष्ठता की भावना- यह सब मनोगतवाद पर आधारित है और गलत है। यह खुद के दो एकदम विपरीत और गलत आंकलनों को दर्शाती है। शेखीबाज वास्तविकता से अपने आप को अलग करता है और खुद का अधिक मूल्यांकन करता है, अपनी वास्तविक योग्यता और भूमिका को बढ़ा-चढ़ाकर बताता है। वह समझता है कि वह सामान्य व्यक्ति नहीं है और दूसरे से श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्रगति रूक जाती है और वह नये विषय सीखना बंद कर देते हैं और निस्सन्देह वह गलतियां करता है। आत्मतिरस्कार करने वाला व्यक्ति शेखीबाज के विपरीत होने के बावजूद, अवास्तविकतावादी ही होता है। वह खुद को कम आंकता है। वह भूल जाता है कि वह अपने काम को सुधार सकता है और व्यवस्थित कर सकता है। वह क्रांति में अपनी अब तक की भूमिका को और आगामी भूमिका को कम आंकता है। नतीजतन वह प्रगति के लिए जरूरी आत्मविश्वास और धैर्य को गंवा बैठता है और अपनी लड़ाकू भावना को कम कर बैठता है।

संक्षेप में कहा जाए तो आत्मतिरस्कार और अहंकार दोनों ही गलत है, क्योंकि दोनों क्रांति में अपनी खुद की भूमिका के गलत आंकलन को दर्शाते है। दोनों ही क्रांति के लिए नुकसानदायक है। इसलिए हमें जरूर ही अहंकार और शेखीबाजी का विरोध करना चाहिए और विनम्रता को आत्मतिरस्कार से कड़ाई से अलग-अलग करके देखना चाहिए। ऐसा करने से हम एक छोर से दूसरे छोर पर गिरने से बच सकते हैं।

पृष्ठ संख्या 47 का शेष

अभियान हाथ में लिए हैं। गैर-सर्वहारा रूझान, पितृसत्ता की विचारधारा के बुनियादी कारणों का भी विश्लेषण किया गया है। पार्टी के भीतर मौजूद गैर-सर्वहारा रूझान, पितृसत्ता तथा भाववाद, अधि-भौतिकवाद के दृष्टिकोण को छोड़कर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के दृष्टिकोण को अपनाकर पार्टी का बोल्शेवीकरण करना है, जिससे क्रांतिकारी आंदोलन-महिला आंदोलन को मजबूत करते हुए भारत के व्यापक शोषित महिलाओं को दीर्घकालीन लोकयुद्ध में शामिल करके नवजनवादी क्रांति को सफल करने की ओर आगे बढ़ेंगे।

साम्राज्यवादियों के गुलाम, मोदी नेतृत्व के भाजपा सरकार, ब्राह्मणीय हिन्दुत्व फासीवाद के खिलाफ में व्यापक संयुक्त मोर्चा बनाकर संघर्ष करेंगे

(यह लेख हमारी पार्टी के केन्द्रीय कमेटी के अंग्रेजी मुखपत्र 'पीपुल्स वार' अंक-10, जून, 2016 के संपादकीय का हिन्दी अनुवाद है। - संपादकमंडल, लाल चिनगारी)

मोदी के नेतृत्व में भाजपा, केंद्र में सत्तासीन होते ही अपने मालिक साम्रज्यवादी, दलाल शासकों के एजेंडा को आक्रामक रुप से आगे बढ़ा रही है, मोदी सरकार ब्राह्मणीय हिन्दुत्व फासीवाद को लागू करते हुए जनता का तीव्र दमन कर रही है। देश के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा अन्य सभी क्षेत्रों में फासीवाद राज कर रही है। देश, विगत के सभी हालातों से ज्यादा आज गंभीर चुनौतीपूर्ण हालातों का सामना कर रही है।

मोदी सरकार ने 'मेक इन इंडिया', 'डिजिटल इंडिया', 'स्किल इंडिया', 'स्वच्छ भारत' जैसी योजनाओं को बड़े ताम-झाम से शुरुआत किया तथा उन नारों का अत्यधिक प्रचार-प्रसार किया गया। 150 से ज्यादा ऐसे नयी लोक-लुभावन परियोजनाओं पर से परदा हटाया गया है। कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत करने की घोषणा की गई, लेकिन इसके कई योजनाएं शुरु ही नहीं किये गये। गरीबों के नाम पर घोषित 'जनधन योजना' लागू किया जो कि वास्तविकता में गरीबों के पेट पर लात मारने एवं बड़े पूँजीपतियों के हितों के लिए 35 करोड़ रु. का राशि बैंकों में जमा किया गया है। ये सब योजनाएं जनता को ठगते हुए उनको लूटने की मंशा से बनाया गया है। इससे जनता को खास फायदा नहीं पहुँचने वाला है। इन योजनाओं की आड़ में मोदी सरकार ने आक्रामक रुप से नव उदारवादी नीतियां ही लागू की है।

भारत में सुलभतापूर्वक विदेशी निवेश करने योग्य माहौल बनाने के लिए कानूनों में नियमों का संशोधन मोदी सरकार कर रही है। इसके तहत 100 से ज्यादा संशोधन किया गया है। इस दो साल के कार्यकाल में मोदी 40 से उपर विदेशों का दौरा करते हुए 'मेक इन इंडिया' का खूब प्रचार किए हैं। साम्राज्यवादी निवेश को आकर्षित करने की कोशिश किये हैं। भारत में एकाधिकारी पूँजी को मुनाफा कमाकर देने का वादा किया है। इसके लिए भारत में मौजूद अपार संसाधनों का, सस्ता श्रम, बाजार को बेरोकटोक लूटने के लिए साम्राज्यवादियों के साथ कई समझौते किये हैं। रेलवे, रक्षा, खुदरा क्षेत्रों में 100 प्रतिशत विदेशी पूँजी निवेश (FDI) के लिए द्वार खोल दिए हैं। मोदी सरकार सार्वजनिक-निजी साझेदारी में ढांचागत सुविधाओं के क्षेत्र (राजमार्ग, फ्लाई ओवर, बंदरगाह, हवाई अड्डों आदि) में विदेशी निवेश के लिए आमंत्रित किया है। सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थाओं में विनिवेश के द्वारा 56,500 करोड़ रु. उगाहने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यूपीए-2 सरकार के शासन से जारी नवउदारवादी नीतियों को मोदी सरकार और तेज रफ्तार से आगे बढ़ाई है।

भाजपा सरकार, विश्व स्तर पर जारी आर्थिक मंदी के बावजूद भारत का आर्थिक विकास तेज गति से बढ़ने की घोषणा कर रही है। इसके लिए आनेवाले वर्षों में 8 प्रतिशत का विकास दर हासिल करने का दावा कर रही है। 2016-17 में 7.8 प्रतिशत विकास दर दिखा रही है। अंक गणित से साम्राज्यवादियों के निवेश पर आधारित होकर दिखाया जाने वाला विकास दर देश का सही तस्वीर नहीं हो सकता है। इसके अलावा, यह विकास दर वित्तीय गुणा-भाग का आधार वर्ष में (Base Year) किया गया संशोधन पर आधारित है। लेकिन यह वास्तविक विकास दर नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था आज भी गिरावट का शिकार है। उत्पादक क्षेत्र में वृद्धि नहीं है। आज भी भारत का निर्यात क्षेत्र में वृद्धि नहीं है। डॉलर की तुलना में रुपये की कीमत दिन-ब-दिन गिरती जा रही है। मुद्रास्फीति में गिरावट का ढिंढोरा पीटने वाली सरकारी झूठे प्रचार तंत्र के बावजूद आम आदमी पर महंगाई का बोझ बढ़ता जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल की कीमत रिकार्ड स्तर में गिरावट के चलते सरकारी व्यय में कमी आयी है लेकिन जनता को इसका कोई लाभ नहीं मिला। विदेशी पूँजी निवेश धारा प्रवाह के रुप में भारत में आ रही है और यह वृद्धि दर 50 फीसदी होने का ढिंढोरा पीटकर जमीन आसमान को एक किया गया जबकि यह आंशिक सच्चाई है। क्योंकि मुख्य रुप से यह पूँजी मंत्रियों के विभाग (फोर्ट फोलियो) क्षेत्र में हो रहा है जो कि लघु अवधि के लिए आ रही है। यह कभी भी निकलकर जा सकता है। ऐसी पूँजी पर आधारित योजनाएं कभी भी ठप्प हो सकती है। यह मुख्य रुप से भारत की संसाधनों का दोहन करने के लिए पूँजी निवेश

किया जाता है न कि स्थायी औद्योगीकरण के लिए किया जाता है। ऐसी पूँजी से रोजगार में वृद्धि नहीं होने के कारण जनता का क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगा। इजारेदार पूँजीपतियों का लक्ष्य है कि भारत से अत्यधिक मुनाफा (Super profits) बटोरना है। इसी तरह सार्वजनिक-निजी साझेदारी पर शुरु किया गया परियोजनाओं से निजी पूँजी निकल जाने के चलते ऐसी कई परियोजनाएं ठप्प पड़ चुके हैं।

भाजपा सरकार युवाओं के लिए रोजगार सृजन, कौशल विकास, स्टार्ट अप, स्टैंड अप जैसी योजनाओं के द्वारा मेक इन इंडिया परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का दावा करती है। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था को इससे कोई लाभ नहीं है। इस बजट में खाद्यान्न, खाद, पेट्रोल, डीजल के अनुदान में 7 हजार करोड़ का कटौती किया गया है। शिक्षा, चिकित्सा को दिये जाने वाले अनुदान में भी कटौती किया गया है। पिछले वर्ष के बजट में सामाजिक अनुदान 14.2 प्रतिशत था जबकि इस वर्ष 12.6 प्रतिशत तक रह गया है। जनता को दिया जाने वाला कुल अनुदान राशि को 10 हजार करोड़ तक घटाया गया। मनरेगा (MANREGA) पर आवंटन राशि 34 हजार करोड़ तक रखा गया। सरकार अपने राजस्व घाटा को 3 प्रतिशत तक लाने के लिए अनुदानों में कटौती कर रही है। लेकिन इस राजस्व घाटा में देश को गिरवी रखकर लाया गया विदेशी ऋण पर भुगतान किया जाने वाला ब्याज भुगतान का भार प्रतिवर्ष 4.92 लाख तक पहुँच गया है। देश का अर्थव्यवस्था और भी कर्ज में डूब चुका है।

मजदूर, कर्मचारियों के जीवन भर का मेहनत का फल भविष्य निधि (PF) पर सरकार ब्याज कमा रही है। लघु उद्यमी, जिन्होंने मोदी द्वारा घोषित मुद्रा (MUDRA) योजना के द्वारा कर्ज पाने की आस लगाये बैठे थे वे भी निरुत्साहित हुए हैं। ''फसल बीमा'' योजना में निर्धारित किस्त (प्रीमियम) की राशि कम होने के बावजूद नुकसान को निर्धारित करने वाले नियम, किसानों के प्रतिकूल बनाया गया है। मोदी सरकार ने इस बजट में निगम कर में 5 प्रतिशत कटौती कर दलाल नौकरशाह पूँजीपतियों को फायदा पहुँचायी है। इतना ही नहीं लाखों-करोडों रुपये का अप्रत्यक्ष मुनाफा उनके खातों में पहुँचायी है।

मोदी ने पिछले मई महीने में अमेरिकी दौरे के दौरान रक्षा, व्यापार आदि क्षेत्रों में पहले से मौजूद करारों को और पुख्ता ही नहीं बल्कि विश्व में, विशेष कर एशिया महाद्वीप में अमेरिकी दबदबा को बढ़ाने वाला रणनीति के तहत रक्षा समझौता किए हैं। यह समझौता भारत के संवैधानिक प्रभुसत्ता के खिलाफ है। विस्तारवाद के अग्रणी मोदी, दक्षिण एशिया में अमेरिका के कनिष्ठ साझेदार साबित हुए हैं। अमेरिकी नेतृत्ववाली साम्राज्यवादी समूह के लक्ष्य को साकार करने हेतु चीन का मुकाबला करने के लिए इन्होंने देश को एक मोहरा बना दिया है। अमेरिका ने भारत के साथ साझा सैन्य अभ्यास हिन्द महासागर में किया है। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप (NSG) में भारत की सदस्यता का समर्थन का लालच अमेरिका दिखा रहा है। व्यापार के क्षेत्र में अमेरिका के साथ किया गया समझौता भारत के लिए काफी नुकसान पहुँचा रही है। भारतीय शासक वर्गों के हित के लिए ही नहीं बल्कि चीन के प्रभाव को सीमित करने के लिए भी मोदी ने अफ्रीका का दौरा किया है। दूसरी तरफ ब्रिक्स (BRICS) का सदस्य होने के नाते शंघाई को-ऑपरेशन (शंघाई सहकारिता) में जगह पाया है। भारत सरकार ने भारतीय शासक वर्गों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाकर नेपाल के शासक वर्गों पर खुन्नस निकालने की मंशा से उस देश की आंतरिक मामलों में दखल देकर आर्थिक नाकेबंदी ही नहीं बल्कि धमका भी रही है। नेपाल का बनाया गया नया संविधान में भारतीय शासक वर्गों का हित सुनिश्चित करने का दबाव बना रही है। दक्षिण एशिया के देशों के साथ 'अच्छे रिश्ते' की दुहाई देते हुए उन देशों पर बड़े भाई जैसा बर्ताव पहले से अधिक बढ़ गया है।

भाजपा के सत्ता में लौटने के बाद संघ परिवार की शक्तियां बहुत सक्रिय हुई हैं। धार्मिक आधार पर समाज को विभाजित कर भारत को हिन्दु राज्य के रुप में बदलने का प्रयास कर रही है। वाजपेयी सरकार के दौर में शुरु किया गया इतिहास के पाठ्यांश का फेर-बदल को मोदी सरकार दोबारा जारी रखे हुए है। गुजरात के शिक्षा क्षेत्र में चलाया जा रहा हिन्दु पाठ्यांशों को पूरे भारत में लागू करने का प्रयास कर रही है। शिक्षणालयों की शिक्षा को भगवा रंग में रंगने की मंशा से विश्वविद्यालयों में जनवादी क्रांतिकारी शक्तियों पर हमले कर रही है।

हिन्दुत्व फासीवादी गिरोह विवेकशील, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, क्रांतिकारी शक्तियों पर जानलेवा हमले कर रही है। कलबुर्गी का हत्या किया गया। हैदराबाद के (HCU) छात्र रोहित वेमुला का आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया है, दरअसल इस सरकार ने ही उनकी हत्या की है। दिल्ली के जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय में देश विरोधी नारे लगाने का झूठा आरोप लगाकर बजरंगदल ने छात्रों पर हमला ही नहीं किया,

बल्कि सरकार ने उनको राजद्रोह के जुर्म में गिरफ्तार कर जेल में डाल कर कई तरीकों से उन्हें परेशान की है। विश्वविद्यालय में जनवादी, क्रांतिकारी विचारों के छात्रों का दमन करने के लिए संघ परिवार योजनाबद्ध ढंग से काम कर रही है। दिल्ली के JNU, हैदराबाद के HCU, पूना के फिल्म इंस्टीट्यूट, मद्रास के IIT, कोलकाता के जादवपुर यूनिवर्सिटी में खुलेआम दिनदहाड़े हमले कर रही है। रोहित वेमुला हत्या, JNU घटनाओं के विरोध में अखिल भारतीय स्तर पर छात्र, शिक्षक, कर्मचारी विरोध दर्ज किए हैं। पूरे देश भर के यह आंदोलन छात्र आंदोलनों में एक मील का पत्थर साबित हुआ है।

जनता के खान-पान, सांस्कृतिक रीति-रिवाजों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। गो-मांस खाने का आरोप लगाकर उत्तर प्रदेश के दादरी में अखलाक अहमद की हत्या किया है। ऐसी हत्याएं व हमले देश भर में अंजाम दे रहे हैं। ''राष्ट्रवाद, देशभक्ति, भारत माता की जय'' जैसे मानदंडों को सामने लाकर ब्राह्मणवाद हिन्दुत्व फासीवादी, हिटलर की नाजी सेना जैसा, ऐसे नारों के बल पर जनता में उन्माद भड़का सकते हैं, ऐसा साबित किए हैं। धर्मनिरपेक्ष, कवि, कलाकार, छात्र, अल्पसंख्यक मुसलमान, इसाई व दलितों पर हमले बढ़ रही है। देश के क्रांतिकारी, उत्पीड़ित राष्ट्रीय संघर्षों का पहले से ज्यादा तीव्र दमन कर रही है। इस फासीवाद के विरोध में कई वैज्ञानिक, कवि, कलाकार, लेखक, जनवादपसंद लोग सरकारी अवार्डों को लौटा दिए हैं। मोदी सरकार के ब्राह्मणीय हिन्दुत्व फासीवादी हमले, दमन नीतियों के खिलाफ में जन आंदोलन बढ़ रहे हैं।

लोकसभा के चुनाव प्रचार में भारत के जनता के लिए ''अच्छे दिन लाएंगे'' का मोदी ने वादा किया था। विदेशों में छिपाया गया ''काला धन'' 100 दिनों में वापस लाकर प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में 15-15 लाख रु. देने का झूठा वादा किया था। मोदी के इन दो सालों के शासन में जनता सच्चाई को समझ रही हैं। आम आदमी मंहगाई से पस्त हैं। किसानों के आत्महत्या दर दिन-ब-दिन बढ़ रही है। शिक्षा के क्षेत्र में निजीकरण के चलते आम आदमी से शिक्षा दूर होती जा रही है। जनता के लिए सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलना असंभव हो गयी है। रोजगार सृजन में वृद्धि न होने के चलते बेरोजगारों की संख्या बढ़ते जा रहा है। मोदी सरकार का भारत के दलाल नौकरशाह पूँजीपति, सामंती वर्ग, साम्राज्यवादियों के हित साधने को समर्पित होने की बात स्पष्ट हो रही है।

अपनी नीतियों से उत्पन्न हुई आर्थिक मंदी से बाहर आने के लिए साम्राज्यवादियों ने मोदी को सत्ता में बैठाने के जरिए भारत को नया औपनिवेशिक लूट का और ज्यादा शिकार बना रहे हैं। इसलिए मोदी को साम्राज्यवादियों ने तवज्जो दिया है। इन दो सालों के दौरान भी अपनी समस्याओं का हल नहीं निकल पाने के हालात में मजदूर-किसान, छात्र, दलित, अल्पसंख्यक, महिलाएं, व्यापक जनता जुझारू संघर्ष कर रहे हैं। देश के संसाधनों के लूट के चलते बड़े पैमाने पर विस्थापन के शिकार हो रहे हैं। इसमें मुख्य रुप से किसान, आदिवासी विस्थापन के शिकार हो रहे हैं। पर्यावरण को भारी नुकसान पहुँच रहे है। इसके खिलाफ जनता बड़े पैमाने पर संघर्ष में उतर रहे हैं। इन संघर्ष को दमन करने के लिए सरकार फासीवादी दमन नीति लागू कर रही है। मजदूर वर्ग ने श्रम कानूनों में संशोधन के खिलाफ, किसान अपने जीविका के लिए, आदिवासी अपने मूलभूत अधिकारों के लिए, विस्थापन के खिलाफ में, दलित जमीन के लिए, अपने सम्मान के लिए, छात्र अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं।

बढ़ रही असंतोष के कारण जनता लड़ने के लिए तैयार हो रही है तो इसका नेतृत्व शासक वर्गों को सत्ता से बेदखल करने के इरादे से लड़ रहे माओवादियों के हाथों में न चला जाय इसके लिए शासक वर्ग बेचैन हैं। इसलिए क्रांतिकारी आंदोलन पर 5.50 लाख पुलिस, अर्धसैनिक बल, वैमानिक (हवाई) बलों के द्वारा तीव्र दमन कर रही है।

क्रांतिकारी आंदोलन का दमन करने के लिए सरकार कारपेट सेक्यूरिटी को मजबूत कर रही है। राजमार्गों का निर्माण की गति बढ़ा रही है। संचार जाल को बढ़ाने के लिए मोबाइल टावरों को बढ़ा रही है। हवाई हमलों के लिए हवाई अड्डों का निर्माण कर रही है। देश भर के खुफिया एजेंसियों को प्रौद्योगिकी से लैस कर समन्वय बढ़ा रही है। पुलिस, अर्धसैनिक बल क्रांतिकारी आंदोलन के क्षेत्रों में तीव्र अत्याचार के साथ-साथ सैकड़ों की तादाद में फर्जी मुठभेड़ों में हत्या कर रही है। दण्डकारण्य, ओड़िशा, एओबी, बिहार, झारखंड आदि क्षेत्रों में महिलाओं पर सामूहिक अत्याचार कर रहे हैं और महिलाओं को निर्वस्त्र (नंगा) कर उन्हें अपमानित कर रहे हैं। जन पक्षधर नागरिक, जनवादी अधिकार कार्यकर्ता, पत्रकार, वकील, आदिवासी हितैषियों को प्रताड़ित कर बस्तर से बलपूर्वक निकाल रहे हैं। झूठा केस लगा कर जेल भेज रहे हैं। अंततः न्यायाधीशों भी नहीं बख्श रहे हैं जो कि न्यायपालिका के हिस्से है। क्रांतिकारी आंदोलन के क्षेत्र में जारी पुलिस बलों के अत्याचारों का बाहरी समाज को पता न चल सके इसके

लिए ''पत्रिका स्वेच्छा'' पर प्रतिबंध लगा रही है। अपने संसाधनों का दोहन कर विस्थापन करने वाली सरकार के खिलाफ संघर्ष करने वाली ओड़िशा के जनता का दमन करने के लिए मलकानगिरी, कोरापुट, कंधमाल, कालाहांडी, रायगढ़, नवापाड़ा जिलों में सरकार फर्जी मुठभेड़ों में आदिवासियों की हत्या कर रही है। भाजपा सरकार मिशन 2016, महा अभियान, सारंडा मॉडल अभियानों के नाम से क्रांतिकारी आंदोलन का दमन करने के लिए तीव्र भारी हमले कर रही है।

इन सब कोशिशों के बावजूद शासक वर्गों की मंशा पूरी नहीं हो सकी, बल्कि माओवादी आंदोलन नये इलाकों में विस्तार कर रही है। देश भर के जनता माओवादी पार्टी के प्रति आकर्षित हो रही है। सरकारी दमन का जनता, पीएलजीए जहां-तहां प्रतिरोध करते हुए सरकार को माकूल जवाब दे रही है। सरकारी मंशा जो भी हो, ब्राह्मणीय हिन्दुत्व फासीवाद के चलते क्रांतिकारी आंदोलन के लिए और समर्थकों का हुजूम बढ़ना अनिवार्य है। हिन्दुत्व ब्राह्मणीय फासीवाद के खिलाफ अत्याचार का शिकार बने वर्गीय, सामाजिक तबकों के साथ धर्म निरपेक्ष, जनवादी शक्तियों, सच्चे देशभक्तों के साथ-साथ शामिल होने वाले सभी शक्तियों को एकजुट करके विभिन्न स्तरों पर व्यापक संयुक्त मोर्चा का गठन करना है। इसके नेतृत्व में जुझारू जन संघर्षों का संचालन करना है।

जम्मू-कश्मीर विधान सभा के चुनावों में भाजपा अपने दम पर सरकार बनाने की मंशा से एड़ी-चोटी एक कर दी पर आंशिक सफलता ही मिली। केवल जम्मू में सफल रही। पीडीपी के साथ मिलकर जम्मू-कश्मीर में गठबंधन सरकार बना ली है। भाजपा केन्द्र में भी सत्ता में रहने के कारण कश्मीरी जनता का तीव्र दमन कर रही है। सेना के द्वारा फर्जी मुठभेड़ में बुरहान वानी के साथ अन्य तीन की हत्या किये जाने के विरोध में जनता का गुस्सा फूट पड़ा। जनता कर्फ्यू को नजरअंदाज करते हुए हजारों की तादाद में विरोध मार्च में शामिल हो रही है। इस घटनाक्रम में सेना के द्वारा की गयी गोलीबारी में दसियों की तादाद में लोग मारे गए तथा हजारों जनता हताहत हुए हैं।

"Act East" नीति को सफल बनाने हेतु पूर्वोत्तर राज्य के मुख्य द्वार के रुप में चिन्हित कर वहां के राज्यों में सत्ता हासिल करने के लिए भाजपा विशेष जोर लगायी है। बांग्ला राष्ट्रीयता के लोगों को राज्य से बाहर निकालने का वादा के साथ असमिया समाज में ध्रुवीकरण की राजनीति की है तथा जनता में कांग्रेस के प्रति मौजूद प्रतिकूलता को भुनाकर भाजपा सत्ता में आयी है। इन प्रदेशों में विशेष सैनिक कानूनों को लागू करते हुए राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों का दमन कर रही है। कश्मीर, पूर्वोत्तर के राज्यों में गंभीर दमन के बावजूद विभिन्न रुपों में जनता प्रतिरोध की राह पर आगे बढ़ रही है।

मोदी साम्राज्यवादियों, दलाल नौकरशाह पूँजीपतियों, सामंती वर्गों के हितों की बखूबी रक्षा करते हुए देश-विदेश में अपने जुमलेदार भाषणों के द्वारा मध्यम वर्गीय जनता को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। मोदी ने मध्यम वर्ग के आकांक्षाओं को उभारने के लिए देश के 125 करोड़ आबादी का सेवा करना, देश का प्रधान सेवक, भविष्य में भारत को विश्व गुरु बनाने का लफ्फाजी झाड़ रहे हैं। विगत में वाजपेयी के नेतृत्व का भाजपा सरकार भी इसी तरह 'चमकता भारत' के नारे के साथ 2004 के चुनावों में कूद पड़ा, लेकिन जनता ने उन्हें सत्ता से उतार दिए। मोदी के वादे जमीन पर लागू नहीं हो रही है। उनकी लफ्फाजी जनता समझ गयी है। इसलिए 2014 की मोदी की चुनावी हवा की गति धीमी होती जा रही है। साम्राज्यवादी, देश की संसाधनों का दोहन कर रही है। जनता पर दमन बढ़ाने का नए तौर-तरीकों का जनता रोज झेल रही है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अंबानी, अडानी जैसे बड़े दलाल पूँजीपतियों के लिए किये जाने वाले सेवा को स्वयं जनता अपनी आँखों से देख रही है। मोदी नेतृत्व के भाजपा सरकार कितने भी वादे करने के बावजूद जनता उसपर विश्वास करने की स्थिति में नहीं है। क्योंकि भाजपा सरकार के नव उदारवादी नीतियों के द्वारा देश के अमीर और अमीर तथा गरीब और गरीब बनाये जा रहे हैं। इसलिए जनता अखिल भारतीय स्तर पर जहां-तहां आंदोलन में उतर रही हैं। इसलिए साम्राज्यवादियों के कट्टर गुलाम मोदी नेतृत्व के भाजपा सरकार व ब्राह्मणीय हिन्दुत्व फासीवाद के खिलफ संघर्ष कर उसे हराने के लिए क्रांतिकारी मजदूर-किसान शक्तियों, जनवाद पसंद लोगों, प्रगतिशील संस्थाओं, आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक जनता, धर्मनिरपेक्ष ताकतों को मिलाकर मजबूत संयुक्त मोर्चा का गठन कर जुझारू आंदोलन का निर्माण करना है। भाजपा सरकार ने संघर्षशील जनता, क्रांतिकारियों, आम जनता, जनवादी लोगों, उत्पीड़ित राष्ट्रयताओं का फासीवादी दमन करने के लिए अपने सिर पर बड़ा पत्थर उठा लिया है। यह बड़ा पत्थर अपने सर पर गिराकर मोदी सरकार खुद तहस-नहस हो जाएगी। इतिहास में ऐसी सच्ची घटनाएं कई बार साबित हो चुकी है।

महिला सवाल- जनयुद्ध-जनमुक्ति

(यह लेख हमारी पार्टी के केन्द्रीय कमेटी के अंग्रेजी मुखपत्र 'पीपुल्स वार' के अंक-10, जून, 2016 से लिया गया है। - संपादकमंडल, लाल चिनगारी)

जब से वर्गीय समाज का उदय हुआ है, तब से महिलाओं पर उत्पीड़न, लूट, शोषण, असमानता, भेदभाव बदस्तूर जारी है। समाज बदलने पर भिन्न-भिन्न रूपों व तरीकों में उसे लागू किया जा रहा है। मुख्य रूप से समाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक तौर पर उत्पीड़न का शिकार बनाया जाता रहा है, बल्कि प्रत्येक समाज में अपने-अपने भिन्नताओं के साथ महिलाओं को दोयम दर्जे में न्यूनतम हक-अधिकारों से भी वंचित किया जा रहा है। जब से वर्गीय समाज बना है, तभी से समाज मुख्य रूप से दो वर्गों में विभाजित हो गया है। यानी गुलामी (दास) समाज में गुलाम और मालिक थे। सामंती समाज में जमींदार और अर्ध गुलाम थे। पूँजीवादी समाज में पूँजीपति और मजदूर हैं। कुल मिलाकर गुलामी समाज से आज तक देखा जाय तो प्रत्येक समाज में लूटने वाले हैं और लूट का शिकार बनने वाले। महिलाएं भी अर्ध गुलाम और मजदूर थीं। शोषण और उत्पीड़न के अलावा, महिलाएं पुरुष सत्ता का भी सामना कर रही हैं।

हमारी एकता कांग्रेस-9वीं कांग्रेस में पारित किया गया पार्टी कार्यक्रम नामक बुनियादी दस्तावेज में महिला सवाल पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए **''वर्गों में विभाजित समाज उद्‌भव से ही महिलाओं को समाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और विभिन्न तरह के कष्ट व भेदभाव का शिकार बनाया गया है। जाति व्यवस्था, दहेज-प्रथा, बाल विवाह, विधवा का जीवन बिताना, देव दासी प्रथा जैसी अन्यायपूर्ण रीति-रिवाज प्रमुखता से आज भी लागू है। हमारे देश की आबादी के आधा हिस्सा महिलाएं, सामंती, साम्राज्यवादी लूट-शोषण के साथ-साथ परिवार रूपी पितृसत्तात्मक व्यवस्था के द्वारा पुरुष प्रधानता धर्म, जाति, व्यवस्था, संपत्ति के रिश्ते, संस्कृति के उत्पीड़न के शिकार है।''**

वर्गीय समाजों में महिलाओं का शोषण करने और लूटेरी समाज को बनाये रखने के लिए पितृसत्ता को एक औजार के रुप में इस्तेमाल किया गया। इस पर विवाद नहीं है कि विभिन्न वर्गीय समाज उत्पादन व्यवस्था पर निर्भर होकर परिवार, विवाह, धर्म, संस्कृति, सभ्यता, राज्य, संविधान आदि टिका हुआ है। सभी वर्गीय समाजों में इनके रुप बदलते हैं पर पितृसत्ता का उत्पीड़न नहीं बदला है। लूट-शोषण नहीं बदला है। यह ढांचागत अंश महिलाओं का उत्पीड़न कर पितृसत्ता बरकरार रख कर अपना लूट जारी रखने के लिए शोषकों ने इजाद किये हैं।

आदिम समाज में सत्ता महिलओं के हाथों में थी। मातृसत्तात्मक व्यवस्था में अपने लोगों के साथ शिकार में भी हिस्सेदारी रखती थी। वे अपने दल का नेतृत्व भी करते थे। अपने लोगों का देखभाल और सुरक्षा उनका दायित्व होता था। विरासत की पहचान माँ के द्वारा होता था। पशु पालन, कृषि का विकास होना, महिला-पुरुष के बीच काम का विभाजन, शिकार, कृषि, पुरुषों के काम तथा पशु पालन, घरेलू कामकाज, बच्चों का पालन महिलओं के काम के तौर पर विभाजित हुआ था। लेकिन समाज का विकास क्रम में कृषि की अहमियत बढ़ने के चलते उत्पादन में पुरुषों को प्रथम दर्जा, महिलाओं को द्वितीय दर्जा में शामिल किया गया। मातृसत्तात्मक व्यवस्था के स्थान पर पितृसत्ता को स्थापित किया गया। निजी संपत्ति का उद्‌भव ही पितृसत्तात्मक व्यवस्था का मजबूत होने का कारण रहा है। समूह के साथ विवाह के स्थान पर एक जोड़े के बीच का विवाह का रुप सामने में आया। अपनी संपत्ती अपने ही संतानों को उपलब्ध करने के उद्देश्य से पिता की सत्ता को मजबूत किया गया। कामरेड एंगेल्स के शब्दों में, ''माता का हक रद्द करना ही महिला जाति के लिए ऐतिहासिक महत्व रखने वाला भयानक पराजय साबित हुआ।'' महिलाओं का सामाजिक उत्पीड़न को झेलते हुए न सिर्फ सामाजिक उत्पादन से नाता छुट गया बल्कि घर, परंपराएं, रीति-रिवाजों में कैद किया गया। इसलिए पुरुष प्रधानता किसी एक व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला उत्पीड़न नहीं है। यह वर्गीय समाज के उद्‌भव से लागू हो रहा है। जब तक वर्ग रहेगा, वर्गीय शोषण रहेगा, तब तक उत्पीड़न जारी रहेगा।

सामंती समाज में महिलाओं को घरों तक सीमित कर दिया गया। खेत मजदूरों का शोषण बेगारी के द्वारा लूट-शोषण का शिकार बनाते थे। उत्पीड़ित वर्गों के महिलाओं व दस्तकारी जातियों के महिलाओं के श्रम को सस्ते दर में लूट का, यौन शोषण का, उत्पीड़न का शिकार बनाते थे। इन महिलाओं के श्रम का कोई महत्व, कोई पहचान नहीं रहता था। तत्कालीन

सामंती समाज में अपने सत्ता के बल पर अंधविश्वास को जबरदस्ती लागू करवाया जाता था ताकि कोई सवाल उठाने की जुर्रत न कर सके। इसके लिए भारत देश में वर्ण व्यवस्था, मनु विधान नीति उत्पीड़ितों का, श्रमिकों का, महिलाओं का शोषण करने हेतु सामंती व्यवस्था का लूट जारी रखने हेतु रामबाण साबित हुआ। धर्म, शास्त्र ने महिलाओं को अबला व तुच्छ के तौर पर चित्रित किया है। उत्पीड़ित लोगों के द्वारा भी अपने वर्गीय महिलाओं पर तानाशाही चलाने के अधिकार को धार्मिक परंपराओं, अंधविश्वासों के द्वारा पाला-पोसा गया। पूँजीवादी समाज ने महिलाओं को घर के चारदिवारी से बाहर लाकर सामाजिक उत्पादन में भागीदारी करवाया है। बावजूद इसके अपने आवश्यकता के लिए कम वेतन पर ज्यादा उत्पादन करवाने के लिए महिलाओं को अधिक लूटने के लिए ऐसा किया गया। महिलाएं सामाजिक उत्पादन में शामिल होने के बावजूद घरेलु काम, बच्चों के देखभाल से मुक्त नहीं हुई हैं। तद्नुसार उत्पादन के साधनों पर, संपत्ति व अपने बच्चों पर किसी भी किस्म के अधिकार से वंचित किया गया। इससे महिलाएं घर में समाज में दोनों प्रकार के लूट-शोषण का शिकार बने हैं। आर्थिक लूट, सामाजिक उत्पीड़न के साथ-साथ पितृसत्ता भी घर पर पति, पिता, कार्यस्थल पर मालिक की धमकियां, शोषण, अपमान, अत्याचारों का शिकार बने हैं। कम वेतन, दूषित वातावरण में काम आदि कारणों से महिलाओं को शारीरिक, मानसिक रुप से प्रताड़ित किया जा रहा है।

अर्ध सामंती-अर्ध औपनिपेशिक भारत में महिलाओं की स्थिति और बदतर हो गयी है। ब्रिटिश साम्राज्यवाद भारत पर अपना कब्जा जमाने के बाद सामंती विधि-विधान को सुरक्षा प्रदान करते हुए भारतीय समाज में व्याप्त सभी किस्म के लूट शोषण के साथ महिलाओं पर लूट शोषण, उत्पीड़न व सामंती मूल्यों को संरक्षित करते हुए जारी रखा हुआ है।

ब्रिटिश औपनिवेशिकवादियों ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तबाह कर, लाखों लोगों को बेरोजगार कर, गरीबों में तब्दील कर दिए। महिलाएं अपने कुटीर उद्योग से वंचित किये गये। कॉफी-चाय-रबड़ बगानों में दिहाड़ी मजदूर बनकर लूट, शोषण, अत्याचार का शिकार बने हैं। कपड़े-जूट मिलों में महिला मजदूर अत्यधिक कम वेतन पर बेतहाशा लूट का शिकार बने हैं।

अंग्रेजों के लिए जरुरी आधुनिक शिक्षा, सामाजिक सुधार आंदोलनों के प्रभाव से महिलाओं के लिए शिक्षा उपलब्ध हो पाया है। लेकिन, यह शिक्षा केवल उच्च वर्गों के लिए सभव हुआ है, मजदूर महिलाओं के लिए शिक्षा कोसों दूर रहा।

मुट्ठीभर उच्च वर्गीय महिलाओं को शिक्षित होने का मौका मिलने के बावजूद वे मुख्य रुप से अध्यापन, चिकित्सा जैसे अनुत्पादक क्षेत्रों तक ही सीमित रहे हैं। इसके साथ-साथ महिलाएं शिक्षित होने के बावजूद न तो नौकरी कर पाएंगे और न ही गांवों का राजपाट सभांल पाएंगे, संभालना तो चुल्हा-चौका ही है आदि सामंती विचार भी शिक्षित होने से निरुत्साहित करता रहा। हकीकत में आज भी भारत देश में पुरुषों की तुलना में महिला शिक्षितों की अनुपात कम है। ग्रामीण आदिवासी इलाकों में अत्यधिक महिलाओं के लिए शिक्षा कोसों दूर है, ऐसा कहा जा सकता है।

आज के अर्ध सामंती-अर्ध औपनिवेशिक समाज में शोषक वर्गीय महिलाओं को छोड़कर, बाकी वर्गों की शोषित महिलाएं गरीब, मध्यम वर्ग, धनी किसान परिवार के महिलाएं, मजदूर महिलाएं, छात्राएं, कामकाजी महिलाएं, धार्मिक अल्पसंख्यक महिलाएं विभिन्न तरीकों से साम्राज्यवादी, सामंती, दलाल निरंकुश पूँजीपति विधि-विधान के वर्गीय लूट व शोषण का शिकार बन रहे हैं। आर्थिक शोषण के अलावा, राजनीतिक, सामाजिक उत्पीड़न के साथ-साथ घर में, समाज में पुरुष प्रधानता एवं पुरुषोन्माद के शिकार बनाया जाता है। महिलाओं पर हिंसा व अत्याचार आम बात हो गयी है। जायज तौर पर महिलाओं को उपलब्ध होने वाले अधिकार, सुविधाओं से वंचित किया गया है। जाति व्यवस्था, बाल विवाह, विधवा जीवन बिताना, देवदासी प्रथा, अन्यायपूर्ण परंपराएं आज जारी है। सामंती व्यवस्था आज और भी जड़ जमाए हुए उन इलाकों में अंतरजातीय विवाह करने पर पत्थर मारकर हत्या करना, सार्वजनिक तौर पर नंगा करके जुलूस निकाल कर आग के हवाले करना जैसी दुष्ट परंपरायें लागू हो रही है।

दहेज प्रथा महिलाओं के लिए अभिशाप सिद्ध हो रही है, जिसके चलते अनगनित महिलाओं को शारीरिक, मानसिक रुप से प्रताड़ित कर उनके जीवनों को लील रही है। महिलाओं को कानूनन प्राप्त संपत्ति का अधिकार, महिला सशक्तिकरण के नाम पर प्राप्त आरक्षण का असलियत जगजाहिर है। महिलाओं को आरक्षण के कोटे से कारखानों में वहां नियुक्त करते हैं, जहां कम वेतन दिया जाता है।

कार्य स्थलों पर महिलाएं सभी प्रकार के यातनाओं को झेल रही हैं। मानव को माल बनाने वाला साम्राज्यवाद अपने मुनाफे के लिए जहरीली (रुग्न) संस्कृति के हिस्से में

महिलाओं के शरीर को व्यापारिक विज्ञापनों अर्ध नग्न, नग्न प्रदर्शित करना, देह व्यापार व शेयर बाजार में सट्टा भी लगाता है। अंततः विज्ञान का भी दुरुपयोग करते हुए महिला की कोख में पल रहे शिशु लड़कियों को बाहर की दुनिया में प्रवेश करने से पहले ही खत्म कर दिया जाता है। इससे आबादी में महिलाओं की प्रतिशत पुरुषों की तुलना में भारी तादाद में कम हो रहे हैं। धर्मोन्माद मुख्य रूप से हिन्दु धर्मोन्माद को शासक वर्ग ने भड़काकर धार्मिक अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न करने के लिए महिलाओं को लक्ष्य बनाकर हत्या, अत्याचार गर्भवती महिलाओं का पेट फाड़कर शिशु का हत्या करने जैसे क्रूर अमानवीय घटनाएं सैकड़ों की तादाद में मौजूद है। विगत के गुजरात जनसंहार में, दण्डकारण्य में जारी सलवा जुडूम में, आज के मुजफ्फरनगर दंगों में यह स्पष्ट दिखता है। अपने जायज अधिकारों के लिए संघर्षरत महिलाओं पर जमींदारी गुण्डों के हमले, मुख्य रुप से दलित, आदिवासी महिलाओं पर अत्याचार व हत्याएं जारी है।

राज्य भी संघर्षरत महिलाओं पर हिंसा का प्रयोग करते हुए गिरफ्तारियां, अत्याचार व हत्याएं कर रही है। इस तरह महिलाएं अर्ध-औपनिवेशिक अर्ध-सामंती समाज के भारत देश में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा सभी किस्म के उपेक्षा, भेदभाव, राज्य हिंसा का शिकार बन रही है। इसलिए महिलाओं को अपने पर जारी वर्गीय उत्पीड़न, राज्य हिंसा के खिलाफ संगठित होने की जरुरत के साथ सभी प्रकार के पितृसत्ता के खिलाफ घर, बाहर संघर्ष करने की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। इस संघर्ष को वर्ग संघर्ष का हिस्सा बनना होगा। आदिवासी समाज में भी कबीलाई परंपराएं, रीति-रिवाज आदि तरीकों में महिलाओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। महिलाएं उत्पादन में भागीदारी करने के बावजूद उत्पादन के साधनों पर अधिकार से वंचित है। कबीलाई मुखिया लोग पितृसत्ता को लागू करते हुए महिलाओं का उत्पीड़न कर रहे हैं। इसके साथ-साथ पूँजीपति, साम्राज्यवादी संस्कृति महिलाओं के जीवन को और भी दुभर बना रही है।

अंग्रेज भारत में आने के बाद प्रमुखता से अपने हित साध ने के लिए शुरुआत में यहां उद्योगों का निर्माण किए। भारत देश में 20वीं सदी में ही महिला मजदूर संघ का गठन हो चुका है। मजदूर महिलाओं की संख्या दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। संगठित, असंगठित क्षेत्र की महिलाओं का आर्थिक शोषण का, पितृसत्ता का शिकार बनने के तरीकों पर इसके पहले ही रोशनी डाला गया है। इसके साथ-साथ आज भी कृषि ही प्रधान होने का अपने भारत में भूमिहीन किसानों की तादाद 65-70 प्रतिशत तक मौजूद है। इनमें मजदूर, किसान महिलाएं, गरीब महिलाएं, मजदूर महिलाओं की संख्या ज्यादा ही है। मध्यम, धनी किसान की महिलाएं उत्पादन में एक हद तक ही सही भागीदारी करने के बावजूद, उन्हें संपत्ति में अधिकार नहीं है। पितृसत्ता के प्रतीक दहेज इत्यादि के उत्पीड़न के शिकार हैं। इसी तरह छात्राएं, कर्मचारी महिलाएं, बुद्धिजीवी के साथ आदिवासी, दलित, धार्मिक अल्पसंख्यक महिलाओं को भी सामंती, बड़ा पूँजीवादी, साम्राज्यवादी शोषण, उत्पीड़न भेदभाव के खिलाफ एक होने की आवश्यकता है। चार उत्पीड़ित वर्गों की महिलाएं एक होकर वर्ग संघर्ष में भागीदारी करने के द्वारा पितृसत्ता, वर्गीय उत्पीड़न का मुकाबला कर ध्वस्त करने के रास्ता को सुगम बनाएगा। वर्ग संघर्ष में महिलाओं के शामिल होन के द्वारा, वे सभी प्रकार के उत्पीड़न को चेतनाबद्ध तरीके से पहचानने के अलावा उसके प्रमुख कारणों को पहचानकर उसे हल करने हेतु चेतना प्राप्त करते हुए, लक्ष्य प्राप्ति में आगे बढ़कर निजी संपत्ति की बुनियाद पर टिकी पितृसत्ता व शोषणकारी समाज के खात्मे में भागीदार बन पाएंगे। इसके लिए सर्वहारा पार्टी को चाहिए कि वह इस संघर्ष में आगे रहकर नेतृत्व करे।

विगत संपूर्ण इतिहास, अपने अधिकारों के लिए, अपने पर जारी शोषण-उत्पीड़न का मुकाबला करते हुए वीरता के साथ, जुझारू संघर्षों का इतिहास है। इसी तरह राष्ट्रीय आंदोलनों के पहले सामाजिक सुधार आंदोलनों में- प्रमुखता से महिला शिक्षा के लिए इसी तरह कन्या शुल्क, बाल विवाह, सती प्रथा जैसी सामाजिक दुराचारों के खिलाफ संघर्ष किए हैं। राष्ट्रीय आंदोलनों के दौर में सशस्त्र रुप से अंग्रेजों का मुकाबला किए हैं। चटगांव इलाके में कामरेड सूर्यसेन के नेतृत्व में बनी सेना में कम संख्या में ही सही महिलाओं ने भी भाग ली हैं, इनमें कल्पना दत्त, प्रीतिलता वादेदार शस्त्रागार पर किए गये हमले में शामिल हुई हैं। इसी तरह अंग्रेज साम्राज्यवादियों के खिलाफ आदिवासी क्षेत्रों में हुए सशस्त्र विद्रोह में महिलाएं उल्लेखनीय स्तर की भूमिका निभाये हैं। आंध्रा के मन्यम आदिवासी किसान विद्रोह में, झारखंड के बिरसा मुंडा के नेतृत्व में, ओड़िशा के लक्ष्मण नायक के नेतृत्व में, तेलंगाना के आदिलाबाद, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ के बस्तर, महाराष्ट्र आदि क्षेत्रों में हुए विद्रोहों में महिलाएं वीरतापूर्वक भागीदारी निभाए हैं। इनमें से कुछ लोगों द्वारा अपने जान की बलि देनेवाली घटनाएं इतिहास की पृष्ठों

में दर्ज होकर रोशनी बिखेर रही है।

इसके बावजूद अपने अधिकार के लिए किये गये संघर्ष को, समाज सुधार आंदोलनों, अंग्रेज साम्राज्यवाद, सामंती शोषण उत्पीड़न के खिलाफ किये गये संघर्ष को भी स्पष्ट सैद्धांतिक, राजनीतिक बुनियाद के अभाव में वह शोषित जनता के, शोषित महिलाओं के, महिला सवाल के लिए सही समाधान के रास्तों को सुझाने में असफल रहे हैं।

सन 1941-46 में हुए कई जन संघर्षों में महिलाएं भागीदारी किए हैं। 1945-51 के तेलंगाना के सशस्त्र किसान संघर्ष में महिलाएं बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिए हैं। जमीन के लिए, मजदूरी बढ़ोत्तरी के लिए, जमींदारों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के खिलाफ, सामाजिक बदलाव के लिए हथियारबंद होकर लड़ाकू शक्ति के बतौर आगे बढ़े हैं। मिर्च बुकनी (मिर्च पाउडर) के साथ, मूसलों के साथ पुलिस बलों को खदेड़कर शोषकों के दिल के धड़कन को तेज किए हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में तत्कालीन तेलंगाना के 3000 गांवों को मुक्त किया गया है। क्रूर दमन का बहादुरीपूर्वक धज्जियां उड़ाते हुए उभरकर आया तेलंगाना सशस्त्र किसान संघर्ष, तत्कालीन कमुनिस्ट पार्टी के नेतृत्वकारी गलत लाइन के चलते पीछे हटने (Set-back) का शिकार हुआ है। इसी दौर में अखिल भारतीय स्तर पर तहलका मचाने वाली, तेभागा, पुनप्रा वायलार किसान संघर्ष में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। इसके बावजूद इन संघर्षों को भारत की शोषित जनता की मुक्ति के लिए तत्कालीन कम्युनिस्ट पार्टी सही लाइन का निर्धारण नहीं कर पायी है। तदनुसार शोषित जनता की मुक्ति के भागीदार, महिला की मुक्ति के लिए भी रास्ता नहीं सुझा पाया है।

साम्राज्यवाद विरोधी संघर्षों में, राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों में, सामंतवाद विरोधी आंदोलनों में महिलाओं की बहादूराना भागीदारी इसी तरह अपने जायज अधिकारों के लिए, पितृसत्ता के खिलाफ इकट्ठे होना, वर्ग संघर्ष में उनके द्वारा प्रदर्शित किया गया साहस, हिम्मत, कुर्बानियां, लड़ाकूपन भारत की शोषित महिलाओं के लिए एक अनुभव के अलावा सबक भी दिए हैं।

नक्सलबाड़ी की चिनगारी ने भारत देश में क्रांतिकारी आग को फैलायी है। भारत की शोषित जनता की मुक्ति के लिए शोषित महिलाओं के मुक्ति के लिए भोर का तारा बनकर आसमान में चमक रहा है।

मार्क्सवादी-लेनिनवादी-माओवादी सैद्धांतिक बुनियाद पर निर्भर होकर भारत को अर्ध-औपनिवेशिक अर्ध-सामंती समाज के रुप में चिन्हित कर यहां दीर्घकालीन लोकयुद्ध के द्वारा क्रांति सफल बनाने हेतु नव जनवादी क्रांति को लक्ष्य के तौर पर निर्देशित किया गया है। महिलाएं नक्सलबाड़ी सशस्त्र किसान संघर्ष में अग्र भाग में रहकर संघर्ष किए हैं। गांवों पर हमला करने के लिए आने वाले पुलिस बलों को, जनता सामूहिक रुप से आगे बढ़कर खदेड़ दिए हैं। डरपोक पुलिस पहले भाग खड़े हुए फिर बाद में लौटकर गांवों पर हमला करके 8 महिलाओं को गोली मारकर हत्या कर दी। इनमें दो बच्चे भी शामिल हैं। सशस्त्र संघर्ष ही शोषित जनता को मुक्ति का मार्ग के बतौर अपने गरम लहू को बहाकर भारत की शोषित जनता, शोषित महिलाओं के लिए संघर्ष का संदेश दिए हैं।

नक्सलबाड़ी के उत्तेजना से कांकसा, सोनापुर, श्रीकाकुलम, डेबरा-गोपीवल्लभपुर, लखीमपुर-खीरी, वीरभूम आदि सशस्त्र किसान संघर्ष उत्पन्न हुए हैं। श्रीकाकुलम के आदिवासी किसान संघर्ष में आदिवासी महिलाएं, ग्रामीण महिलाएं, जमींदारों के खिलाफ रोटी, भूमि मुक्ति के लिए संघर्ष किए हैं। इस संघर्ष में पंचादी निर्मला सहित पद्मा, सरस्वती, अंकम्मा, सुक्कि के साथ 12 महिलाएं शहीद हुए हैं।

नक्सलबाड़ी, श्रीकाकुलम संघर्षों की पृष्ठभूमि में गया, हजारीबाग, मगध में, बाद के समय में उत्तर तेलंगाना किसान संघर्षों के ज्वार ने बिहार-झारखंड, आंध्रप्रदेश के पूरे इलाके को अपने चपेट में ले लिया। गांव, शहर, विद्यालय, कारखाना, कोयला खदानों से आंध्रप्रदेश के गोदावरी, प्राणहिता को पार कर दण्डकारण्य तक, बिहार उसके बाद झारखंड के सोनगंगा, कोयल नदियों को पार कर कैमूर, सारंडा के वनों तक विस्तार किया है। इन संघर्षों के द्वारा कई महिलाएं, छात्र, बुद्धिजिवी, मजदूर, नौजवान, कलाकार, कर्मचारी वर्गीय संगठनों में संगठित हुए हैं। कई छात्र-छात्राएं, युवक-युवतियां अपनी पढ़ाई को छोड़कर पार्टी के पेशेवर क्रांतिकारी बनकर आंदोलन के विस्तार में भागीदारी निभाये हैं।

भाकपा (माओवादी) के नेतृत्व में पूरे भारत वर्ष में आंध्र, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, दण्डकारण्य (छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र), ओड़िशा आदि में अपने-अपने भिन्नताओं के बावजूद मैदानों में, जंगलों में भूमिहीन गरीब किसानों, आदिवासी, दलित, महिलाओं को संगठित करते हुए लाल प्रतिरोध इलाके - गुरिल्ला जोन, गुल्लिा बेस-आधार इलाका का निर्माण की प्रक्रिया में क्रांतिकारी आंदोलन आगे बढ़ रहा है। इसी तरह

पश्चिम बंग, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरलम, असम, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आदि राज्यों में, विभिन्न तरीकों में, जन संघर्ष, वर्ग संघर्ष को जारी रखकर जनयुद्ध के लिए मार्ग प्रशस्त कर रही है। सभी जन आंदोलनों में महिलाएं भागीदारी कर रही है। दण्डकारण्य जैसे इलाके के पार्टी, पीएलजीए, जनता की जनसत्ता की अंगों में 40 प्रतिशत महिलाएं अपनी भूमिका वखूबी निभा रही है। आज मजबूती से मौजूद आंदोलन के इलाकों की हजारों महिलाएं क्रांतिकारी महिला संगठनों में संगठित हुए हैं। शहर-कस्बों के मजदूर, छात्र, महिला आंदालनों में, सांस्कृतिक क्षेत्र में महिलाएं जुझारू रुप से भाग लेने के चलते शहरी क्रांतिकारी महिला आंदोलन विकास करता आया है। दिल्ली, कोलकाता, मुम्बई, हैदराबाद, वारंगल, नागपुर, चेन्नई, बेंगलुरु आदि शहरों, अन्य कई कस्बों में विभिन्न रुपों में महिला आंदोलन जारी है।

पार्टी ने जंगल, जमीन पर व यहां की सभी संपदाओं पर गरीब आदिवासी किसान का ही अधिकार का नारा के साथ राज्य के खिलाफ जंगल अधिकारी, ठेकेदार, साहुकार के लूट-शोषण के खिलाफ और महिलाओं पर जारी सभी किस्म के शोषण-अत्याचार, यातनाओं के खिलाफ आंदोलन संगठित किया है। ग्रामीण वन क्षेत्र के कबीलाई मुखियाओं के रीति-रिवाज के नाम पर महिलाओं पर लागू किया जानेवाला सभी प्रकार के उत्पीड़न, जबर्दस्ती शादी, जुर्माना, डायन के नाम पर हत्या करना इत्यादि के खिलाफ महिलाओं को संगठित किया गया, विशेष कर राज्य हिंसा के खिलाफ, काले कानूनों के खिलाफ, सलवा-जुडूम, सेंद्रा जैसी क्रांति विरोधी प्रतिक्रियावादी अभियानों के खिलाफ जेजेएमपी, टीपीसी, जेपीसी, पीएलएफआई, नागरिक सुरक्षा समिति, शांति-सभा, हर्मद वाहिनी, भैरव सेना, दलमा आंचलिक समिति जैसी क्रांति विरोधी प्रतिक्रियावादी गोपनीय गिरोहों के खिलाफ, हाल के ऑपरेशन 'ग्रीन हंट' में पुलिस, अर्ध-सैनिक बलों के द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों के खिलाफ, विस्थापन समस्या, दैनिक मजदूरी में बढ़ोत्तरी, जमीन पर कब्जा, फसल का समर्थन मूल्य के साथ-साथ विभिन्न समस्याओं पर, ज्यादा ब्याज लेकर शोषण करने वाले सूदखोर, महाजनों के खिलाफ, दहेज हत्याओं के खिलाफ, देश-विदेश में वेश्या गृहों (कोठों) के लिए महिलाओं को सप्लाई करने के खिलाफ राजनीतिक बंदियों के रिहाई के लिए महिलाएं संगठित हो रही हैं। जनता पर निर्भर होकर जन संगठन, क्रांतिकारी महिला संगठन, ग्राम मिलिशिया अस्तित्व में आए हैं। आदिवासी किसान महिलाओं पर जारी सभी प्रकार के शोषण-उत्पीड़न का विरोध करते हुए हजारों की तादाद में आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। जन संघर्षों में महिलाएं आधा हिस्सा बन चुकी हैं। सांस्कृतिक दलों में, प्रचार दलों में, मिलिशिया में, जनसत्ता की इकाइयों में महिलाएं अपनी जिम्मेदारी वखूबी निभा रही है। पीएलजीए में भर्ती होने के बाद कमांडर, संगठक के बतौर पार्टी कमेटीयों में, पार्टी विभागों में महिलाएं अपना दायित्व वखूबी निभा रही हैं।

सरकारी सशस्त्र बलों का पुरुषों के साथ-साथ महिलाएं भी मुकाबला करते हुए गुरिल्ला जोन, आधार इलाका के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभा रही हैं। हम तब तक जन युद्ध को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे जब तक कि जनसेना जनयुद्ध के बीच का द्वंद्वात्मक रिश्ते को नहीं समझ पाएंगे। जैसा कामरेड माओ ने कहा है कि 'जनसेना के बिना जनता के लिए कुछ नहीं' यह जनवादी क्रांति का कर्त्तव्य है कि आम जनता को बड़े तादाद में शामिल करना, जिसका अवधारणात्मक बुनियाद है कि सर्वहारा पार्टी के नेतृत्व में ''सशस्त्र बल के द्वारा सत्ता पर कब्जा करना, युद्ध के द्वारा मसले को हल करना।'' यह जनता के द्वारा किया जाने वाला एक जनयुद्ध है। इस जनयुद्ध में महिला भागीदारी का महत्व बढ़ जाता है। हम देखते हैं कि आबादी के आधा हिस्सा महिला होने के नाते संघर्ष में आधा, जनयुद्ध को आगे बढ़ाने में आधा के तर्ज पर शोषक-शासक वर्गीय राज्य यंत्र को ध्वस्त करने के लिए पार्टी, पीएलजीए, जन संगठनों में उनकी योगदान और भूमिका बढ़ रही है।

पीएलजीए के हिस्से के तौर पर महिलाओं की भूमिका

पीएलजीए द्वारा संचालित कई बड़े, मध्यम, छोटे किस्म के हमलों में महिलाओं की भागीदारी के कई घटनाएं मौजूद है। डीके के रानीबोदली, मुकरम से झीरमघाटी तक, झारखंड के गिरिडीह शस्त्रागार पर किये गये हमले से इस्टर्न, सेंट्रल रीजियन के संयुक्त कमांड के अधीन ओड़ीशा में किये गये ''ऑपरेशन रोपवे नयागढ़'' हमले में महिलाओं ने बहादूराना भूमिका निभायी है। पार्टी के नेतृत्व में लिये जाने वाले कार्यनीतिक प्रतिहमले के अभियानों (टीसीओसी) में दुश्मन के सशस्त्र बलों के साथ टक्कर लेते हुए पुलिस बलों का सफाया करने में महिलाओं की महत्पूर्ण भूमिका के कई उदाहरण मौजूद है। महिलाएं एम्बुश, रेड, छोटे-बड़े किस्म के हमलों में शामिल होकर वीरतापूर्वक लड़ रही हैं।

इतना ही नहीं बल्कि पुलिस बलों के साथ हुए कई

मुठभेड़ों में हिम्मत के साथ मुकाबला, संघर्ष करते हुए दलों को सुरक्षित निकालने की घटनाओं में अपने जान को भी कुर्बान कर रहे हैं। गढ़चिरौली जिले में सी-60 के कमांडो पुलिस ने घेरकर गोली चलाने पर कामरेड रनिता ने बेधड़क अकेली लड़ते हुए तीन कमांडो को मार गिरायी और अपने अंतिम सांस तक लड़ती रही। कामरेड माओ ने कहा है ''जब तक जान है, तब तक संघर्ष करो।'' कामरेड लेनिन ने कहा है, ''आत्मसमर्पण से मृत्यु भला'' को सार्थक करते हुए सच्चे कम्युनिस्ट, वीर योद्धा, आदर्श महिला गुरिल्ला के तौर पर अपने आपको साबित की है। ऐसा ही एक और वाक्य का जिक्र करना चाहूंगी। दूसरे गुरिल्ला जोन में टेक्निकल डिपार्टमेंट (टीडी) के शिविर पर पुलिस बलों के द्वारा घेरकर हमला करने पर प्रतिरोध करते हुए पीछे हटने के क्रम में एक महिला कामरेड गड्ढे में गिर गयी। वह उसी गड्ढे में खड़ी होकर आखिरी गोली तक पुलिस का मुकाबला करते हुए अपनी जान दी है। यह मात्र कुछ उदाहरण है। गुरिल्ला युद्ध में साहसी गुरिल्ला, कमांडर्स के तौर पर मिलिटरी कार्रवाईयों में महिलाएं आज शानदार भूमिका निभा रही हैं।

हम देखते हैं कि पीएलजीए के तीनों बलों में मुख्य व द्वितीय बलों में मौजूद महिलाएं एक तरफ गुरिल्ला युद्ध में भागीदारी निभाते हुए दूसरी तरफ उत्पादन में भी भागीदारी निभा रही हैं। वे अन्य कई विभागों की जिम्मेदारियां संभाले हुए हैं। जैसे डॉक्टर, टेक्निकल क्षेत्र के मेकनिक, संचार व्यवस्था के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में राजनीतिक शिक्षक, टेलरों तथा अन्य दायित्व संभाल रही हैं। डॉक्टरों के तौर पर पीएलजीए के साथ जनता का इलाज करते हैं। शिक्षकों के तौर पर गावों में जनता के विद्यालयों में बच्चों को शिक्षित करते हैं। बन्दूकों की तैयारी से लेकर बन्दूक उठाकर लड़ने तक सभी कामों में व सभी क्षेत्रों में अपना वर्चस्व स्थापित कर रहे हैं।

महिलाएं रोड, घातक कार्पेट सेक्यूरिटी के बीच कई दिनों तक लगातार चलते रहना, डिविजनों के बीच, जोनों के बीच समन्वय के पुल (सेतु) बनकर अथक गुरिल्ला के तौर पर सप्लाई करनेवाली दलों की जिम्मेदारी संभाल रही हैं।

पार्टी, पीएलजीए की महिलाओं को विकास के लिए पार्टी कमेटियां, एक हद तक ध्यान दिये हैं। महिलाओं को कुशल संगठनकर्त्ता (ऑर्गनाइजर) के तौर पर विकसित करने पर ध्यान दिया जा रहा है। उचित योग्यता वाले लोगों को एरिया कमेटी, बाद में जोनल/डिविजन/जिला कमेटियों के लिए पदोन्नति दे रही है। वर्तमान में कई एसी, जेडसी/डीवीसी/डीसी में महिलाएं उल्लेखनीय संख्या में मौजूद हैं। महिलाओं को साहसी गुरिल्ला, कमांडरों के तौर पर विकसित करने के लिए विशेष महिला सैन्य शिविरों का आयोजन किया जाता है और पुरुषों के साथ किया जानेवाला साझा सैन्य शिविरों में भी महिलाएं भागीदारी करती हैं। कई युद्ध कार्रवाईयों में प्रत्यक्ष भागीदारी करते हुए, अनुभव हासिल करते हुए, अपने सैन्य क्षमता को बढ़ा रही हैं। क्रमिक रुप से विभिन्न स्तर के सैन्य कमांड्स के सदस्य, विभिन्न मौकों पर बनाये गये यूनिफाइड कमांडों में सदस्य, कमांड प्रभारी, कमांडर-इन-चीफ, पोलिटिकल कमिसार के रुप में विकसित हो रहे हैं।

शोषक वर्गीय समाज के पितृसत्तात्मक विचार का क्रांतिकारियों पर भी उल्लेखनीय असर है। पार्टी, पीएलजीए व क्रांतिकारी जन संगठनों में मौजूद कामरेड्स के पहल करने में, विकास में, साहस बढ़ाने में सहायक बनी हुई है। महिला सवाल पर हमारे पार्टी श्रेणियों में, पीएलजीए के बलों में, जन संगठनों में, जनता में सर्वहारा वर्गीय चेतना को विकसित करने के लिए ''महिला सवाल पर हमारा दृष्टिकोण'' नामक नीति पत्र तैयार किया गया। इस पर विभिन्न मौकों पर विभिन्न स्तर के पार्टी कमेटियों, कमांडों के महिला-पुरुष कामरेडों के लिए कक्षाएं, कार्यशालाएं आयोजित कर उनके समझदारी को विकसित कर रहे हैं। निर्धारित अवधि में होने वाले पार्टी कमेटियों की बैठकों में जरुरत के मुताबिक एजेंडा में जोड़कर पितृसत्ता के रूझानों के खिलाफ बहस, आलोचना-आत्मालोचना के द्वारा सुधारा जा रहा है। गैर-सर्वहारा रूझानों के खिलाफ 2009-10 में लिया गया रेक्टिफिकेशन अभियान में पितृसत्ता पर भी कतारों ने संघर्ष की है। पार्टी में ऐसी अभियान विगत में भी लिया गया है। जनता तक इन अभियानों को ले जाकर शिक्षित किया गया है। पितृसत्तात्मक विचारों के खिलाफ लिये गये संघर्ष महिला कामरेड्स के मनोबल को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुआ है। युद्ध कार्रवाइयों में भी यह बदलाव दिखयी दे रही है।

जन संघर्ष, जनप्रतिरोधी आंदोलनों में महिलाओं की भूमिका

मिलिशिया में महिलाओं की संख्या पहले की तुलना में बढ़ी है। मिलिशिया की महिलाएं दुश्मन को हैरान-परेशान करनेवाले कार्रवाइयों के साथ-साथ बाजारों में पुलिस के समाचार इकट्ठा करने में, गांवों में आनेवाले खुफिया लागों

को, मुखबिरों को गिरफ्तार कर पीएलजीए के हवाले करने में, विभिन्न अवसरों पर पार्टी के द्वारा लिये जानेवाले टीसीओसी में पीएलजीए के साथ मिलकर फौजी कार्रवाइयों में भागीदारी निभा रही है। गांवों के सुरक्षा के लिए संतरी करने से लेकर विभिन्न तरह के उत्पादन के कार्यों में अपना योगदान दे रही हैं। पीएलजीए तक सामानों की सप्लाई करना, गांव के गरीब परिवारों को, विधवा, निराश्रित औरतों के लिए घर बनाने के साथ-साथ कृषि कार्यों में भी मदद पहुँचा रही हैं।

गुरिल्ला जोन, आधार इलाका, लाल प्रतिरोधी इलाकों से सटे हुए मैदानी इलाकों की महिलाएं, जन संघर्ष, प्रतिरोधों में भागीदारी करते हुए सरकारी सशस्त्र बलों के हमलों के खिलाफ जुझारू संघर्ष कर रही हैं।

दमन का मुकाबला करते हुए जुलूस, धरना, बंद जैसे कार्रवाइयों में पुलिस थानों को घेरकर पुलिस अधिकारियों से सीधे सवाल करना, ग्रामीणों की फर्जी मुठभेड़ों में हत्या किये जाने पर पुलिस थानों पर इकट्ठा होकर पुलिस के लाठी, बंदूकों से बिना डरे, कई दिनों तक संघर्ष कर लाशों को लेकर लौट रही हैं।

गांवों पर हमला करने वाले पुलिस से जूझकर उनके हथियार जब्त करने की कई घटनाएं मौजूद हैं। बिहार के जाखिम कार्रवाई, मगध के पंथी इलाके में महिलाएं विद्रोह कर पुलिस के हथियार जब्त करनेवाली घटना, 1985 में करीमनगर के देवता जानकी ने आटो रिक्शा में, फरार होने वाले पुलिस पर किया गया फायरिंग की घटना आदि ने अनेक महिलाओं को प्रेरित किया है।

झारखंड में महिला आंदोलन के विकास के साथ-साथ पुलिस दमन के खिलाफ महिलाएं वीरतापूर्ण संघर्ष कर रही हैं। पुलिस बल द्वारा गांवों पर हमला करने की सूचना पाते ही नगाड़ा बजाकर जनता (महिला, पुरुष, बच्चे) द्वारा उन्हें घेरना, धुनाई करना, पत्थर फेंकना, हाथ लगे हथियार का इस्तेमाल करना, लगभग हर मौके पर पुलिसवालों से उनकी गलतियों पर माफी मंगवाना, ऐसा गलती आइंदा न करने की और कभी गांवों पर हमला करने न आने का करार लिखवाना आदि तरीकों से प्रतिरोधी संघर्ष कर रही हैं।

कारागार को ही संघर्ष का मंच बनाकर महिलाएं लड़ रही है, भारत देश के विभिन्न जेलों में महिला क्रांतिकारियों के साथ, क्रांतिकारी जनता, क्रांतिकारी हमदर्दी, जन संगठनों के नेता, नेतृत्वकारी महिलाएं, पुरुष, बच्चे जेलों में नाजायज तरीके से सड़ रहे हैं। जेलों की महिलाएं अपने अधिकारों के लिए जेल अधिकारियों के दबंगई के खिलाफ बंदियों की रिहाई की मांगों को लेकर जूझते हुए इतिहास बना रही हैं।

पश्चिम बंगाल के लालगढ़ संघर्ष में महिलाएं पारंपरिक हथियारों (कुल्हाड़ी, तलवार) से लैस होकर पुलिस को खदेड़ दिए हैं। राज्य हिंसा, सीपीएम सामाजिक फासीवादी हमले के खिलाफ लालगढ़ की जनता, विशेषकर महिलाएं शानदार भूमिका निभाए हैं। यह संघर्ष देश के सभी जनांदोलनों के लिए प्रतीक (आदर्श) हैं। तेलंगाना के आदिलाबाद जिला में इन्द्रावेल्लि (सन् 1981) में किसान-मजदूर संगठन के अधिवेशन पर पुलिस बल द्वारा हमला करने पर एक आदिवासी महिला ने एक पुलिस जवान को मौत के घाट उतार दी थी। भारत के लोकयुद्ध में महिलाएं द्वारा जान की बाजी लगाकर संघर्ष करने की ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं।

गावों के जन संगठन के नेताओं को पुलिस पकड़कर ले जाते समय महिलाओं द्वारा उन्हें रोककर अपने नेताओं को छुड़ाने की घटनाएं अनगिनत हैं। पीएलजीए के फौजी कार्रवाइयों के दौरान काफी दूर से भोजन लाकर पहुंचाना, एम्बुश-रेड के दौरान घायल होनेवालों को, शहीद होने वालों के शवों को ढोना, पीएलजीए द्वारा जब्त किये गये बंदूक, गोला-बारुद को लाने के लिए युद्ध क्षेत्र में जाकर युद्ध के बीच से उन्हें लेकर आना आदि कार्रवाइयों में ग्रामीण महिलाएं बड़े पैमाने पर भागीदारी निभाते हुए गुरिल्ला युद्ध को ताकत प्रदान कर रही हैं।

पुलिस कैंपों में किये गये हमलों में महिलाएं अगुवाकारी भूमिका निभायी हैं। हाल में दण्डकारण्य के बस्तर जिला, लोहंडीगुडा पुलिस थाना के हरीकोडेर में पुलिस शिविर लगाने के लिए आने पर महिलाएं कई दिनों तक भोजन-पानी बाधित कर उन्हें भागने पर मजबूर किये हैं। सुकमा जिला के मिनपा गांव में नया पुलिस शिविर बनाने की कोशिश के खिलाफ लगभग एक महीने तक जारी प्रतिरोधी आंदोलन में महिलाओं ने प्रमुख भूमिका निभयी हैं। अंततः पुलिस, अर्ध-सैनिक बलों को वहां से हटना पड़ा। इसी तरह झारखंड के उदाबु, राट्के, उलीहातु गांवों की जनता विशेषकर महिलाओं द्वारा जुझारू संघर्ष करने के चलते उन तीनों गांवों में पुलिस शिविर का निर्माण नहीं कर पाए हैं। ओड़िशा के (रायगढ़ा, कालाहांडी जिलों के सीमाओं पर) नियमगिरी इलाके में रणनीतिक महत्व के गांवों में विगत एक साल से पुलिस शिविर लगाने का सरकारी षड्यंत्रकारी मंशा पर जनता, विशेषकर महिलाओं के प्रतिरोध से पानी फिर गया।

पूर्वी घाट विशाखा, मालि, देवमाली से लकर महाराष्ट्र में गढ़चिरौली के सुरजागढ़ खदान, बड़े बांध, पन-बिजली परियोजना के खिलाफ छत्तीसगढ़ के रावुघाट से लेकर पोलवरम् तक, पश्चिम बंगाल के सिंगुर, नंदीग्राम, ओड़िशा के कलिंगनगर, नियमगिरी से लेकर झारखंड के सारंडा तक कई विस्थापन विरोधी संघर्षों में, लालगढ़, नारायनपटना जैसी जन विद्रोह में साम्राज्यवाद, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ शासक वर्गों के सशस्त्र बलों से जूझते हुए लाठी के मार से, फायरिंग से भी न डरते हुए हाथ को ही हथियार बनाकर, हाथ लगे पत्थर को हथियार बनाकर पुलिस पर फेंकते हुए उन्हें भगाकर जल-जंगल-जमीन की रक्षा करते हुए आत्म-सम्मान, अस्तित्व, स्वावलंबन (आत्मनिर्भर) का नारा लेकर महिलाएं संघर्ष कर रही हैं।

इसके साथ-साथ पश्चिमी घाट में ''परिस्थितियों और पर्यावरण सुरक्षा'' (Protection of ecology and environment) नाम से देश के अत्यंत लम्बा, ऊँचाईयुक्त पूरी पर्वतमाला को देश के दलाल पूँजीपति, साम्राज्यवादियों के हवाले कर उस पूरे पर्वतमाला को तबाह करने के लिए भारत के शासक वर्गों के षड़यंत्र, कोशिशों को नाकाम करने के लिए केरलम्-कर्नाटक-तमिलनाडु के सीमाओं में पार्टी के नेतृत्व में स्थानीय जनता जनयुद्ध के रास्ते पर तैयारी कर रही है। इस जनवाहिनी में महिला वाहिनी भी एक अभिन्न हिस्सा के तौर पर उभरकर आयी है।

शोषण और उत्पीड़न के तर्ज पर शासक वर्ग जन संघर्ष, क्रांतिकारी संघर्षों पर पहले के मुकाबले ज्यादा दमन नीति को लागू कर रही है। संघर्षरत महिलाओं पर राज्य हिंसा का प्रयोग कर रही है। मुख्य रुप से झारखंड, बिहार, दण्डकारण्य, पश्चिम बंगाल के सरकारों ने निजी हत्यारी गिरोहों, क्रांति विरोधी प्रतिक्रियावादियों के सलवा-जुडूम्, सेंद्रा, टीपीसी, हर्मदवाहिनी, शांति-सेना का गठन कर हत्या, अत्याचार, घर जलाना, लूट, खाद्यान्न जलाना, सैंकड़ों लोगों को राहत शिविरों (यातना शिविरों) में जबरदस्ती ले जाने के द्वारा जनता भारी दहशत में जीने को मजबूर हैं। सलवा जुडूम, सेन्द्रा के द्वारा किये गये उत्पातों में महिलाओं पर हत्या, अत्याचार किये हैं। बच्चों को खोने वाली माँ, पतियों को खोने वाली पत्नियां, माँ-बाप को खोने वाले बच्चे, अनाज, फसल, मवेशी की बर्बादी, घर ढहा दिये जाने के चलते परिवार का भार महिलाओं के दिक्कतों को और बढ़ाया है। राहत शिविर महिलाओं के लिए यातना शिविर साबित हुए हैं। ऐसी भयानक हैवानियत के खिलाफ अपने बच्चे, पतियों को क्रांतिकारी आंदोलन में भेज दिये हैं, जिससे जनयुद्ध में पीएलजीए को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रुप से मजबूत किये हैं और क्रांति विरोधी प्रतिक्रियावादी सलवा जुडूम, सेन्द्रा जैसी हथियारबंद अभियानों को हराये हैं।

भारत के शासक वर्गों ने साम्राज्यवाद के नेतृत्व में एलआईसी नीति को लागू करते हुए ऑपरेशन ग्रीन हंट का शुरुआत किये हैं। जनता पर नाजायज युद्ध, गांवों पर लगातार हमले, गिरफ्तारियां, हत्यायें, गांवों को पुलिसवालों ने श्मशान घाट में बदल डाले हैं। हजारों की तादाद में विशेष पुलिस बलों को जंगल क्षेत्रों में भेजा जा रहा है। इन पुलिस बलों के हमलों का पहला शिकार महिलाएं बन रही हैं। पुलिस शिविर के आसपास के गांवों में अत्याचार, दमन बढ़ गया है। महिलाओं की आबरु (इज्जत) को, जान को भयंकर खतरा उत्पन्न हुआ है। गैर कानूनी गिरफ्तारियां कर कुछ युवतियों का एसपीओ गुण्डों से जबरदस्ती शादी करना, शादी के बाद इस्तेमाल कर छोड़ देना और कुछ लोगों को गैर कानूनी गिरफ्तारी, अत्याचार कर जेलों में ठूंस रहे हैं। पुरुषों को कई सालों तक जेलों में बंद करने के चलते परिवार का पालन-पोषण का भार महिलाओं पर आ पड़ा है, जिससे महिलाओं की स्थिति और बदतर हो गयी है।

संघर्षरत महिलाओं पर राज्य हिंसा का प्रयोग किया जाता है। हथियारबंद गिरोह के द्वारा उन पर अत्याचार, हत्यायें करवाने का लोमहर्षक कई उदाहरण हमारे सामने मौजूद हैं। पृथक तेलंगाना आंदोलन में गायकी बेल्लि ललिता पर क्रांति विरोधी प्रतिक्रियावादी नईम गिरोह ने अत्याचार करके हत्या की है। लालगढ़ संघर्ष में तापसी मलिक की भी अत्याचार करके हत्या किया गया। माड़ में कृषि विभाग में कार्यरत कामरेड कुमिलि, प्रेस विभाग के कामरेड चैते हत्यारी गिरोह अत्याचार करके हत्या की है। तेलंगाना के ताड्वायी मण्डल के सोमला गड्ढा गांव के पास पुलिस के द्वारा किया गया मुठभेड़ में कामरेड श्रुति, कामरेड सागर 15 अगस्त, 2015 को गिरफ्तार कर क्रूर यातनाएं देकर, कामरेड श्रुति पर अत्याचार करके इन दोनों की हत्या कर दी गयी। इन क्रूर हत्याओं के खिलाफ में तेलंगाना के समाज ने आवाज बुलंद की है।

साम्राज्यवाद का वस्तु विनिमय संस्कृति आज महिलाओं को पहले से ज्यादा माल के रुप में बदल दिया है। देश भर में महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों की घटनाएं दिन-प्रतिदिन

बढ़ते जा रही है। दिल्ली जैसे महानगर में सामूहिक बलात्कार (गैंग रेप) की संख्या प्रति वर्ष देश भर में हजारों की संख्या में हो रही है। इनमें से कुछ घटनाएं ही पूरे देश को पता चल पाता है। बच्चों व महिलाओं को गायब करना, विदेश भेजना, वेश्या गृहों (कोठों) में बेच देने की घटनाएं हजारों में मौजूद है। हाल में, छत्तीसगढ़ के 16 हजार महिला, बच्चों को गायब करने की घटना पूरे समाज को पता चल गया। इसमें धमतरी की घटना एक ताजा मिसाल है। साम्राज्यवाद के अराजकतावाद द्वारा सामाजिक कुरीतियों को पैदाकर नौजवानों को भटकाती है। छात्राएं, महिला कर्मचारी, कामकाजी महिलाएं पहले से ज्यादा असुरक्षा की शिकार बनी हैं। 6 साल की बच्ची से लेकर 60 साल की बूढ़ी औरतों तक को यौन हिंसा का शिकार बनने की आंकड़े दिल दहला देने की स्थिति उत्पन्न कर चुकी है।

ब्राह्मणीय हिन्दुत्व फासीवादी भाजपा (संघ परिवार) के मोदी सत्ता संभालते ही भारत को हिन्दु राज्य में बदलने पर जोर दे रहे हैं। हिन्दु धर्म, महिलाओं को पितृसत्ता के तले कैसे दबाती, कुचलती है? हम सब जानते हैं। विगत में धार्मिक अल्पसंख्यक महिलाओं पर कार सेवकों द्वारा किया गया अत्याचार, गुजरात में, बाबरी मस्जिद ढहाने में, मुजफ्फरनगर, ओड़िशा में..... ऐसे कई खूनी जनसंहार की घटनाएं महिलाओं के दुखद गाथाओं में दर्ज है, जो हिन्दु मठाधीशों के कारनामे रहे हैं।

आज साम्राज्यवाद के आर्थिक, मुद्रा संकट ने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया है। बेरोजगारी, भूखमरी, निर्धनता, विस्थापन, महंगाई व महिलाओं पर हिंसा बढ़ने के चलते सभी वर्ग की जनता, महिलाएं, देश-विदेश में साम्राज्यवादी, बड़े दलाल पूँजीपतियों के खिलफ संघर्ष कर रही हैं। यह संघर्ष जुझारू बनकर और भी संगठित होकर आगे बढ़ना है। कई दमन अभियानों को तोड़कर, तानाशही काले कानूनों के लोहे के जंजीरों को तोड़कर, गांव, मैदान, शहर जेलों के जेल जीवन से मुक्ति के लिए वर्ग संघर्ष में कदम बढ़ा रहे हैं।

आज अमेरिका सहित औद्योगिक रुप से विकसित देश ब्रिटेन, फ्रांस, इटली आदि देशों में साम्राज्यवादी, पूँजीपतियों के खिलाफ जन संघर्ष उभरकर विस्तार हो रही है। वे क्रांतिकारी समूह, क्रांतिकारी पार्टियों में संगठित होकर भारत में जारी जनयुद्ध के समर्थन में हाथ बढ़ायी है। यह बहुत अच्छी बात है। उपरोक्त क्रांतिकारी धाराओं के साथ-साथ क्रांतिकारी महिला धाराएं बनकर भारत के क्रांतिकारी आंदोलन में महिला आंदोलन को मदद पहुंचा रही है। हाल में इटली में ''अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस'' के अवसर पर गठित किया गया क्रांतिकारी महिला संगठन इसका ताजातरीन उदाहरण है।

अंतरराष्ट्रीय व घरेलू स्तर पर जनयुद्ध के लिए हालात बहुत अनुकूल है, ऐसा प्रतीत होता है। भारत में नवजनवादी क्रांति दीर्घकालीन लोकयुद्ध के द्वारा ही सफल होगी। इस जनयुद्ध में और बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना है। शासक वर्गों के द्वारा शोषित जनता पर लादा गया नाजायज युद्ध 'ऑपरेशन ग्रीन हंट' को इस जनयुद्ध के द्वारा ही परास्त कर सकते हैं।

मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद की सिद्धांत के बुनियाद पर जनयुद्ध खड़ा है। यह सर्वहारा वर्ग के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। जैसे सभी समस्याओं का समाधान मार्क्सवाद है, वैसे ही महिला सवाल का भी। मार्क्सवाद यह कहता है कि प्रकृति और वस्तुओं के बीच का रिश्ता एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और एक दूसरे को प्रभावित करनेवाला भी है। इसलिए मार्क्सवाद वैज्ञानिक, समग्र और सत्य भी है। यह शोषित जनता की मुक्ति और महिला मुक्ति को अलग-अलग नजरिए से नहीं देखता है। यह कहता है कि इन दोनों के बीच में द्वंद्वात्मक रिश्ता है। ''हमारी पार्टी की एकता कांग्रेस-9वीं कांग्रेस में तैयार किया गया बतौर ''पार्टी कार्यक्रम'' नामक बुनियादी दस्तावेज ''इसलिए वर्ग संघर्ष के साथ-साथ समान अधिकार स्थापित करने के लिए राजनीतिक, आर्थिक, सैद्धांतिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में महिलाओं को विकसित करने हेतु समान अवसरों के लिए हमें संघर्ष करना चाहिए। नवजनवादी क्रांति के दौर में, उसके बाद पूरा समाज समाजवादी बदलाव से आगे बढ़कर साम्यवादी समाज की स्थापना होने पर ही महिला-पुरुष के बीच समानता की स्थापना होगी। इसलिए हमारी पार्टी को चाहिए कि महिलाओं को जागृत कर संगठित करने के लिए जारी विभिन्न संघर्षों में महिलाओं की भागीदारी करने लायक, मुख्य रुप से जनयुद्ध, क्रांतिकारी महिला संगठनों में शामिल होने लायक उन्हें मदद करने के लिए विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उनमें से पक्के इरादे, दूर दृष्टि के कम्युनिस्ट नेता के तौर पर विकसित करने के लिए केन्द्रीकरण करना आवश्यक है।''

आज भारत का क्रांतिकारी आंदोलन कठिन दौर से गुजर रहा है। पार्टी के भीतर मौजूद गैर-सर्वहारा रूझानों के साथ-साथ पितृसत्ता को दूर कर पार्टी को बोल्शेवीकरण करने का

शेष पृष्ठ संख्या 34 पर

8 मार्च अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की रिपोर्ट

(बीजे सैक के सभी जोन में दुश्मन के घेराव-दमन व विभिन्न ऑपरेशनों के बीच अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च से 31 मार्च, 2017 तक विभिन्न छापामार कैम्पों व कई गांवों में आम जनता के बीच पूरे जोश-खरोश के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सभी जगह रैली व सभा का आयोजन किया गया। ऐसे ही एक पीएलजीए कैम्प में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की रिपोर्टिंग हम यहां दे रहे हैं। - संपादकमंडल, लाल चिनगारी)

दिनांक 17 मार्च, 2017 को डी. जोन अंतर्गत एक पीएलजीए कैम्प में पीएलजीए योद्धाओं और ग्रामीणों की उपस्थिति में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। कार्यक्रम स्थल को बैनर और झण्डा से आकर्षक ढंग से सजाया गया था। शहीद कामरेडों की तस्वीरों की प्रदर्शनी भी लगायी गयी थी। इनमें अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के महान नेत्री कामरेड क्लारा जेट्कीन और कामरेड चियांङ के अलावे भारत के क्रांतिकारी जनयुद्ध में शहीद हुए कामरेडों की तस्वीरें भी थी। सभी कामरेड अपने प्यारे शहीदों की तस्वीरें देखकर उन्हें याद कर रहे थे। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 09:00 बजे झण्डोत्तोलन के साथ की गयी। झण्डा फहराये जाने के ठीक बाद सांस्कृतिक टीम के द्वारा 'नारी मुक्ति झण्डा हम फहरायेंगे' गीत की प्रस्तुति दी गई। इस गीत में नारियों के ऊपर होने वाले शोषण-जुल्म और अत्याचार को काफी अच्छे तरीके से लयबद्ध किया गया है। पीएलजीए की सांस्कृतिक टीम की ओर से 'अन्याय का दाहक है, न्याय का वाहक है' गीत पेश किया गया। शहीद वेदी पर अलग-अलग कमेटियों के कामरेड और पीएलजीए की इकाइयों के द्वारा माल्यार्पण कर शहीद साथियों को श्रद्धांजलि दी गयी। फिर शस्त्र उल्टे कर, सर से टोपी उतार कर और शर्ट की बांह कोहनी तक मोड़कर शहीदों की याद में दो मिनट का मौन-धारण किया गया। मौन भंग होते ही शहीदों की याद में नारा लगाया गया और उनके अध ूरे सपनों को पूरा करने का प्रण सभी कामरेडों ने लिया। उसके बाद दस मिनट का मध्यांतर (ब्रेक) की घोषणा हुई।

मध्यांतर का समय समाप्त होते ही सभी कामरेड कार्यक्रम स्थल तक पुन: पहुँच गये। कामांडर का काशन के साथ सभी साथी अपना-अपना स्थान ग्रहण कर बैठ गये। इसके बाद सभा शुरुआत की प्रक्रिया आरंभ की गयी। सभा की शुरुआत अध्यक्ष मण्डल के चुनाव के साथ की गयी। निर्वाचित सभा अध्यक्ष-मण्डल पदभार ग्रहण किये। उसके बाद सभा का उद्घाटन के लिए सांस्कृतिक टीम के साथियों को आमंत्रित कर एक गीत पेश करने को कहा गया। गीत समाप्त होते ही वक्ताओं द्वारा अपना-अपना बात रखने का सिलसिला शुरू हुआ। सभी वक्ताओं ने वर्तमान समय में नारियों की स्थिति और उनके ऊपर होने वाले शोषण-जुल्म और अत्याचार का उल्लेख अपने-अपने वक्तव्यों में किया। साथ-ही उससे मुक्ति पाने का रास्ता क्या होना चाहिए, उसपर भी चर्चा की गयी।

सभा के दौरान वक्ताओं ने महिला-उत्पीड़न संबंधी जिन बातों पर जोर दिया, वे हैं:

मौजूदा समय में मेहनतकश महिलाओं के उत्पीड़न में भारी बढ़ोत्तरी हो रही है और महिलाओं को सिर्फ निजी संपत्ति की तरह ही देखी जा रही है। लेकिन ये प्रथा आज ही नहीं बल्कि हजारों साल पहले से चली आ रही है। यानी जब मनुष्य ने जंगल-पहाड़, गुफा-कंदराओं से निकलकर मानव-सभ्यता की ओर कदम बढ़या तब से ही निजी संपत्ति की प्रथा अस्तित्व में आयी और उस प्रथा का आरंभ होते ही नारियां पुरुष-सत्ता के अधीन होती चली गयी। क्योंकि, यहीं से श्रम-विभाजन की प्रक्रिया का शुरुआत हुआ और नारियों को समाजिक उत्पादन से बेदखल कर घरेलू उत्पादन तक सीमित कर दिया गया और उन्हें घरों में ही कैद करने की प्रथा चलन में आया। निजी संपत्ति की प्रथा के साथ ही वर्ग समाज का भी उदय हुआ। ज्यों-ज्यों वर्ग समाज का विकास होता गया, त्यों-त्यों महिलाएं पुरुष-सत्ता के बंधन में जकड़ती चली गयीं। फलत: आज नारियों को भी निजी संपत्ति की तरह ही देखी जा रही है और उन्हें सिर्फ भोग की वस्तु के सिवा कुछ नहीं समझा जाता है।

आज हमारे देश में नरेन्द्र मोदी नेतृत्वाधीन बीजेपी सरकार कट्टर हिन्दुत्ववादी-ब्राह्मणवादी नीतियों को लागू कर रही है। सांप्रदायिकता और जातिवाद का बढ़ावा देकर यह सरकार दलितों, धार्मिक अल्पसंख्यकों और महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचार व हमलों में भारी वृद्धि कर रही है। आज देश भर में चरम फासीवाद कायम है। इस दौरान आरएसएस के गुण्डों द्वारा सांप्रदायिक कत्लेआम, यौन उत्पीड़न, छेड़खानी और लूटपाट आदि घृणित अपराध कर हर जगह महिलाओं की आजादी छीनने की पूरी कोशिश की जा रही है। ऐसी स्थिति में महिलाएं भी चुप नहीं हैं और अपने ऊपर होने वाले शोषण-जुल्म व अत्याचार से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। गांवों से शहर तक और स्कूलों से विश्वविद्यालय तक सभी जगह आज महिला मुक्ति का संघर्ष जारी है। जिस तरह आदिकाल से ही शोषित वर्ग, समुदाय व जातियों को नीचा

दिखाने, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाने के लिए महिलाओं पर हमले किये जाते रहे हैं, ठीक वैसे ही आज भाकपा (माओवादी) के नेतृत्व में जारी जनयुद्ध के इलाकों (झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओड़िशा, छत्तीसगढ़ के दण्डकारण्य, तेलंगाना और महाराष्ट्र आदि राज्यों) में भी भाड़े के फौजों द्वारा महिलाओं की नृशंस हत्या की जा रही है। साथ ही बलात्कार, यौन-प्रताड़ना व मारपीट जैसे घृणित अपराध को अंजाम देकर जनयुद्ध की गति को कुंद करने की कोशिश भी की जा रही है। जब कभी भी जन आंदोलन आगे बढ़ती है, तो शोषक-शासक वर्गों द्वारा महिलाओं पर तीव्र दमन चलाया जाता है, जिसका वर्णन पूर्व में किया जा चुका है। इसे एक चुनौती के रुप में लेना चाहिए और संगठित होकर सरकारी दमन-अभियान का मुंहतोड़ जवाब देते हुए इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठानी चाहिए।

संस्कृतिक मामलों पर बोलते हुए एक वक्ता ने सामंती संस्कृति, धार्मिक रीति-रिवाजों व मान्याताओं द्वारा महिलाओं को दिमागी रुप से गुलाम बनाने के षड़यंत्र को उजागर किया। किस तरह से समाजिक रीति-रिवाज के जरिए महिलाओं को गुमराह कर गुलाम बनाते हैं और उनके विकास में बाधा खड़ी करते है। फलतः महिलाएं अपने-आपको कमजोर, असहाय व बच्चे पैदा करने वाली मशीन और घर संभालने वाली के रुप में देखने लगते हैं। इस तरह से उनका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है और वह पहलकदमी खो देती हैं। इसलिए नारियां सचमुच में मानसिक गुलामी, विभिन्न तरह के प्रताड़ना और पुरुष सत्ता से मुक्ति पाना चाहती हैं तो उन्हें फिर से एक वर्ग विहिन समाज का निर्माण करना होगा, एक ऐसा समाज जहां नारियां स्वतंत्र थी। यानी मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद की विचारधारा से लैस होकर हमारे देश में जारी सशस्त्र कृषि-क्रांतिकारी संघर्ष में कूद पड़ना होगा और पीएलजीए में भर्ती होकर सबसे पहले अपने-आपको एक योद्धा, कमांडर और फिर नेतृत्व के रुप में विकास करना होगा। साथ ही इस अर्ध-सामंती व अर्ध-औपनिवेशिक व्यवस्था यानी लूटेरी व्यवस्था को उखड़ फेंककर समाजवादी समाज तथा साम्यवादी सामाज की स्थापना करनी होगी, तभी नारियां तमाम तरह के उत्पीड़न के साथ-साथ पुरुष सत्ता से भी मुक्त हो सकती हैं। लेकिन हमारी पार्टी यानी भाकपा (माओवादी) के नेतृत्व में मालेमा से लैस होकर जो संघर्ष जारी है, उसमें महिलाओं की भागीदारी जिस तरह होनी चाहिए उस तरह आज नहीं देखी जा रही है। इसलिए इस संघर्ष में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर विशेष बल दिया जाना चाहिए, तभी हम इस क्रांति के लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि महिलाओं के बिना क्रांति नहीं और क्रांति के बिना महिला मुक्ति नहीं होगी।

संस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ शाम 04 बजे अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस समारोह का संपन्न हुआ। झण्डे को विधिवत पूरे सम्मान के साथ उतारा गया। सभी कामरेड पितृसत्ता के खिलाफ लड़ने व जन आंदोलन को आगे बढ़ाने का प्रण लेकर समारोह स्थल से विदा लिये।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कामरेडों द्वारा लिखी गई कुछ कविताएं

आज की विद्रोही नारी

तू जोश की सागर है
तू शक्ति का सागर है
तू नारी नहीं आग की ज्वाला है
तू न बन वह सीता
जिसे देनी पड़ी थी अग्नि-परीक्षा
तू न बन बह द्रोपदी
जिसे किया गया था अपमानित
तू बन क्रांति युग की नारी
जो हो सब पुरुष सत्ता पर भारी
तू बन वह चिनगारी
जिसके अधीन हो दुनिया सारी
तू मत बन एक बेचारी
क्योंकि तू आज की है नारी
तू ही बदल सकती है
इस स्वार्थी संसार को
तू बन वह सबला
जिसे दुनिया न बोले अबला
कल का युग बीत चुका है
यह युग अब तेरा है
तेरे सामने पड़ा है
मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद का
शक्तिशाली हथियार
अब समय आ गया है,
हथियार उठाने का
उठा लो हाथ में हथियार

उखाड़ फेंको पुरुष प्रधान सत्ता को
इस शोषणयुक्त व्यवस्था को
करो निर्माण नव जनवादी समाज व्यवस्था को
सचमुच में वही होगा मजदूर-किसान
मेहनतकाशों को अपना राज
समाजवादी समाज की स्थापना हेतु
वर्ग संघर्ष जारी रखना होगा
समाजवादी समाज में ही मुक्त होगा किसान,
मुक्त होगा मजदूर
मुक्त होगा सारे मेहनतकश आवाम
होगी मुक्ति मेहनतकश महिलाओं की
इसलिए,
साम्यवादी क्रांति भी लानी होगी दुनिया में।

8 मार्च अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस

8 मार्च अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस
एक उपलब्धि है महिला संघर्ष की
जिसे मिली मान्यता अंतरराष्ट्रीय स्तर पर
जिसने छेड़ी एक बहस महिला मुक्ति की
उसकी स्वाधीनता की, जनवाद की, समानाधिकार की
एक सही लाइन की,
जिससे आधी आबादी
सही मायने में मुक्त हो सके,
पुरुषों की दासता से
वर्ग शोषण-उत्पीड़न से,
उन सारी सांमती, रुढ़ीवादी समाजिक मान्यताओं से
जो बाधा है स्त्रियों के स्वतंत्र विकास में

8 मार्च अंतरराट्रीय महिला दिवस
गाथा है उन महिलाओं की
जिसने पुरुषों की सत्ता नहीं स्वीकारी
जिसने बांटनी चाही घरेलू कार्य की उस जिम्मेवारी को
जो पूँजीवाद को सस्ता श्रम
बेचने को मजबूर होती है
जिसने भाग ली समाजिक उत्पादन में
मिलायी पुरुषों के साथ कंधों से कंधा
और दिखा दी दुनिया को
हम भी नहीं हैं किसी से कम

8 मार्च अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस
गाथा है उन वीरांगनाओं की
जिन्होंने थामी अपनी हाथों में बंदूक
और माना हम भी नहीं हैं अपने भाइयों से कम
उतर के जंगे मैदान में
जिन्होंने कर दिए दुश्मन के दाँत खट्टे
कर दिए प्राण न्यौछावर हँसते-हँसते
अपनी मातृभूमि के लिए,
अपने वर्ग हित के लिए
एक नवजनवादी राज के लिए,
एक समाजवादी वतन के लिए

8 मार्च अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस
एक संघर्ष वर्त्तमान की उन शोषित-उत्पीड़ित महिलाओं की
जो जंग के मैदान में मजबूती से दुश्मनों से ले रही लोहा
गढ़ रहीं हैं सपने, एक नवजनवादी भारत के निर्माण की,
जिसने थामी है मशाल क्रांति की
जो अडिग है अपने इरादों पर
कर रही हैं सामना दुश्मन के तीव्र हमलों का
दे रही हैं अपने प्राणों की आहुति हँसते-हँसते
8 मार्च अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस
गाथा इन्हीं शोषित-उत्पीड़ित संघर्षशील महिलाओं की।

हमारी आवाज

हम हैं आदिवासी-मूलवासी महिलाएं
शोषण व जुल्म से बौखलाए
हमें सरकार बेदखल कर रही है
जल-जंगल-जमीन से
हम जान देंगे पर जमीन नहीं छोड़ेंगे
अपने पैर पर खड़े होकर अपना संगठन बनाएंगे।

हमें समाज में मान-सम्मान व प्रतिष्ठा नहीं है
सच्ची मान-सम्मान, इज्जत-प्रतिष्ठा पाने के लिए
मालेमा के राह पर आगे बढ़ेंगे
पूँजीपति लोग मेहनतकश महिलाओं से घृणा करते हैं

हमारी मेहनत से वे दौलत का मालिक बनते हैं
हमें लड़ना है सरकार से अधिकार के लिए।

गरीब बेटियों को बना दिया बाजार का माल
गुण्डा-गिरोह को सेट कर
हमें बेच रहा है दिल्ली, मुम्बई और राजस्थान में।

जब किसी से हो जाती है शादी तो
बन जाते हैं पति की गुलाम
सारी जिंदगी हो जाती है बर्बाद
फिर भी सम्पत्ति पर हक नहीं।

व्यक्ति पूँजी ने हमें बना दिया पराधीन
मजदूर-किसान के राज में हम हो जाएंगे स्वाधीन
मालेमा के राह पर आगे बढ़ेंगे
वर्ग संघर्ष में शामिल होकर
वर्ग विहीन समाज हम कायम करेंगे।

बहनों, तू एक लाल चिनगारी हो

तू हो एक लाल चिनगारी
तेरे लिए बनी है दुनिया सारी
तू नहीं तो समाज नहीं
फिर भी क्यों आज तेरा संपत्ति पर अधिकार नहीं?

समाज का विकास की थी तूने
हर कामों में भाग ली थी तूने
फिर भी क्यों समानता नहीं है आज?

जिस समाज में भेदभाव न था
ऐसे समाज का नेतृत्व की थी तूने
गुलामी व्यवस्था आया इस दुनिया में
शोषण की बेड़ियों में तू बंध गई
गुलामी की बेड़ियों में डूबी हो तू आज भी
जागो बहनों उठाओ आवाज
लड़ाई के सिवा दूसरा कोई भी राह नहीं,
शोषण की बेड़ियों में बंधी है जनता सारी,
मुक्त करेंगे क्रांति की मशाल से
तीन पहाड़ खड़ा है आगे तेरे
उसे तोड़कर लाएंगे एक लाल सवेरा
अमर शहीदों का यही है सपना
साकार करेंगे हम सभी और बनाएंगे शोषणमुक्त समाज।।

दहेज का दानव

दहेज के नाम पर महिलओं को
जान से मार दिया जाता है
और केरोसिन तेल से जलाया जाता है
दहेज-प्रथा आसमान छुती है
गरीब माँ-बहन की इज्जत के मूल्य नहीं
इसलिए, महिलाओं को संगठित होना है
तभी हम महिलाओं को समाज में हक-अधिकार मिलेगी
लड़कियां जन्म लेते ही समाज का बोझ बन जाती है
दहेज के चलते माता-पिता सोचते हैं दिन-रात
महिलाएं पराधीन होकर ही जिंदगी बिताती हैं
माँ-बाप के घर में पिता के अधीन
शादी होने के बाद पति के अधीन
विधवा होने से पुत्र के अधीन
इसी कारण महिलाएं समाज में गुलाम बन गयी हैं
इसलिए हम करते हैं आह्वान
सारे मेहनतकश नारियां हो जाएं एक।।

हम हैं आधा आसमान

हम हैं आधा आसमान
हर जगह पर मेहनत हमारी
फिर भी नहीं है किसी पर हक हमारी
हमारी मेहनत से ही सजी है धरती
फिर भी समाज में हमें समानता नहीं
हमारे धन लूट कर देशी-विदेशी लूटेरे बने हैं मालामाल
धन अपना छीनेंगे दीर्घकालीन लोकयुद्ध के संघर्ष से
हमें बना दिये हो तुम भोग के वस्तु व बाजार के माल
हम रुतबा ऊँचा करेंगे मालेमा के सैद्धांतिक संघर्ष से।

8/11/16 को घोषणा किया तुम नोटबंदी का
धन रखा हुआ हमारा लूट लिया तुम अपनी चाल से

आओ बहना बन जाओ वीरांगना
हम लाएंगे नारी अधिकार
हजारों नारियां हो जाओ एकजुट
नवजनवाद के लिए कदम बढ़ाएंगे जोर से।

तुम्हारे पालतू कुत्ते ने लूट लिया इज्जत अस्मिता
और जल-जंगल-जमीन
हटा दो पालतू कुत्ते को,
हमारे जल-जंगल-जमीन से
नारी विकास के नाम पर
बढ़ रहा है शोषण जुल्म व अत्याचार
आगे बढ़ेंगे मुक्ति संघर्ष के राह पर
कोई न रोक सकेगा नारी मुक्ति के ज्वार को
नारी कोमल हैं, कमजोर नहीं
नारी ला सकती है शोषण मुक्त समाज को
नारी कमजोर नहीं हैं लड़ने का दम है
देश में आया है मालेमा पथ प्रदर्शक
वही दिला सकता है हर चीज पर अधिकार हमें।।

इस व्यवस्था में माँ की स्थिति

जिस माँ ने जन्म दिया है
जिस माँ ने दूध पिलायी है
जिस माँ ने ज्ञान सीखायी
उसी माँ के साथ आज हो रही है
इस व्यवस्था में अत्याचार व बलात्कार
कहां है इस समाज-व्यवस्था की सरकार?
इस पर कभी सोचा है तूने?

जिस माँ ने इस समाज को बनायी है
जिस माँ ने हर चीजों का अविष्कार की है
जिस माँ ने अपनी बेटियों की,
इज्जत-मान-मर्यादा व प्रतिष्ठा की
रखवाली की है
उसी माँ को आज बाजारों में
वस्तु व खिलौने की तरह बेची जा रही है
देश और विदेशों में
कहां है इस समाज-व्यवस्था की सरकार
इस पर कभी सोचा है तूने?

जिस माँ ने अपने अधिकार के लिए
आवाज उठायी है
जिस माँ ने जल-जंगल-जमीन पर अधिकार के लिए
और समाजवादी समाज के निर्माण के लिए
मा-ले-मा से लैस होकर हथियार उठायी है
उसी माँ के उपर आज लाठी-डंडा और
गोलियां बरसायी जा रही है
क्या सही कर रही है इस समाज-व्यवस्था की सरकार?
इस पर कभी सोचा है तूने?

पृष्ठ संख्या 30 का शेष

कहानियों के झूठ से विपरीत रिपोर्टिंग की, आदिवासियों के केस लड़े, उन्हें कानूनी मदद दी या पुलिस द्वारा प्रताड़ित किए जाने के खिलाफ केस दर्ज करवाने में उनकी मदद की।

जब सरकारी अधिकारियों के व्यवहार पर न तो शांति की स्थिति के विधि नियम का नियंत्रण रहता है, न संघर्ष क्षेत्र के युद्ध के नियमों का, तो ऐसे में न केवल सच की हार हो जाती है बल्कि उससे भी बुरा यह होता है कि नागरिकों को एक क्रूर व्यवस्था का सामना करना पड़ता है, जो संविधान का उल्लंघन और अवहेलना करती है। यह बहस का मुद्दा है कि क्या हमारा संविधान ऐसी नकली और अन्यायी व्यवस्था की इजाजत देता है? गंभीर अपराधों को अंजाम देने वाले पुलिस अधिकारी के खिलाफ मुकदमा चलाने और उसे दंडित करने की जगह एक धमकी भर देना, वह भी तब जबकि ये अपराध लाखों नागरिकों के दुखों और बर्बादी का कारण बने हों, इस देश की न्याय व्यवस्था की दोहरी चाल की ओर इशारा करता है। केंद्र और राज्य सरकार जिस तरह से बस्तर में आदिवासियों के खिलाफ युद्ध चला रहे हैं, उससे इसी तरह के यूनिफार्म वाले अपराधी जन्म लेते रहेंगे और पनपते रहेंगे।

(नोट - इस रिपोर्ट के लिखे जाने के कुछ ही दिनों बाद आई जी कल्लूरी पर भी सरकार ने 'दरियादिली' दिखाते हुए सजा देने के बजाय तीन महीने की लंबी छुट्टी पर भेज दिया।)

महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति एक समझदारी

(भाग एक)

मई 1966 में चीन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई, जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। समाजवादी रूस तब तक सामाजिक साम्राज्यवादी बन चुका था। 1966 में चीन में आंतरिक संघर्ष तेज हो गया। यह सत्ता के लिए संघर्ष था, जो 10 साल 1976 में कामरेड माओ की मृत्यु तक चलता रहा। यह संघर्ष था 'महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति।' 1917 की रूसी समाजवादी क्रांति के बाद अगर कोई दूसरी घटना थी, जिसने समकालीन दुनिया और मानव समाज पर सब से ज्यादा प्रभाव डाला तो वह 'महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति' ही थी। समाज के अलग-अलग वर्गों ने इसे अपने-अपने विश्व दृष्टिकोण से देखा और आज तक भी अपने-अपने दृष्टिकोण से इस की व्याख्या करते आ रहे हैं। लेकिन मजदूर वर्ग व दूसरे मेहनतकश उत्पीड़ित वर्गों को इसने समाजवाद से साम्यवाद तक जाने में आनेवाली समस्याओं को हल करने का तरीका बता दिया। चीन में उस समय मजदूर वर्ग जो कुछ कर रहा था, उसने पूरी दुनिया के उत्पीड़ित, शोषित जनता के सामने उनके उन दुश्मनों को नंगा करके सामने रख दिया, जो लाल झंडा उठाकर, लाल झंडे से ही धोखा कर रहे थे और जनता की लड़ाई को गुमराह करके पूंजीवाद की उम्र लम्बी करते हुए बुर्जुआ वर्ग की सेवा कर रहे थे।

मजदूर वर्ग के नेतृत्व में की गई ''महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति'' ने दुनिया भर के क्रांतिकारियों को सिखाया कि किसी समाजवादी देश में क्रांति को कैसे आगे बढ़ाना है और पूंजीवाद की दोबारा वापसी को कैसे रोकना है?

क्या थी महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति?

1917 की रूस की समाजवादी क्रांति और 1949 की चीन की नयी जनवादी क्रांति समाज के आर्थिक आधार को बदलने की क्रांति थी। उन क्रांतियों के बाद मजदूर वर्ग ने अपनी सत्ता स्थापित की। वह उत्पादन के साधनों का समूहीकरण करते हुए समाजवाद का निर्माण कर रहा था। भले ही मेहनतकश जनता ने मजदूर वर्ग के नेतृत्व में सामंतों व पूंजीपतियों की संपत्ति जब्त कर ली थी, पर हजारों सालों से सत्ता पर काबिज रहे लूटेरे शासक वर्गों ने जनता के विचारों और संस्कृति पर अपना एकाधिकार कायम कर रखा था। उत्पादन के साधनों पर समाज का सामूहिक अधिकार होने पर भी जनता के अंदर पुराने विचारों रीति-रिवाज, संस्कृति और आदतों से छुटकारा नहीं पाया गया था। समाजवाद में भी वर्ग रहते हैं और वर्ग संघर्ष भी रहता है। सत्ता छीन जाने के बाद भी बुर्जुआ दोबारा सत्ता हासिल करने की फिराक में रहता है। जैसे कि लेनिन ने हमें बताया था कि समाजवादी काल के दौरान भी नई परिस्थितियों में नया बुर्जुआ पैदा होते रहता है। कामरेड माओ ने भी हमें सिखाया था कि मजदूर वर्ग और पूंजीपति वर्ग के बीच संघर्ष समाजवाद के दौर में भी रहता है। मजदूर वर्ग अपने विश्व दृष्टिकोण के अनुसार दुनिया को बदल कर वर्गरहित-शोषणरहित समाज बनाने की कोशिश करता है और पूंजीपति वर्ग अपने विश्व दृष्टिकोण से समाजवाद को पलट कर दोबारा पूंजीवाद की स्थापना करना चाहता है। कामरेड माओ का कहना था कि समाजवाद के उस दौर में अभी तक तय नहीं हुआ था कि समाजवाद और पूंजीवाद में से कौन जीतेगा। 1949 में चीन में क्रांति की जीत होने के बाद से ही, मजदूर वर्ग की सत्ता आ जाने के समय से ही चीन के अंदर बुर्जुआ वर्ग और मजदूर वर्ग के बीच संघर्ष जारी था। पार्टी और सरकार के अंदर यह समाजवाद के निर्माण को लेकर दो विपरीत विचारों, दो विपरीत कार्यभारों और दो विपरीत कार्यशैलियों के रूप में प्रकट हुआ। यह दो लाइनों का संघर्ष था, एक सर्वहारा की लाइन, और दूसरी पूंजीवादी रास्ता अपनाने वालों की लाइन। स्तालिन की मृत्यु के बाद 1956 तक रूस की सरकार व कम्युनिस्ट पार्टी पूंजीवाद का रास्ता अपना चुकी थी। रूसी पार्टी संशोधनवादी पार्टी में बदल चुकी थी। 1959 में चीन में भी पूंजीवादी रास्ता अपनाने वाला गद्दार व देशद्रोही ल्यू-शाओ-ची चीन सरकार का अध्यक्ष बन गया था। ल्यू-शाओ-ची के नेतृत्व में बुर्जुआ वर्ग ने जनता के दिलों के अंदर हजारों सालों से जड़ जमाए हुए बैठे निजी संपत्ति की अवधारणा के कारण पुराने विचारों, संस्कृति, रीति-रिवाजों व आदतों का फायदा उठाते हुए ही सत्ता पर कब्जा करना चाहा था। अब बुर्जुआ वर्ग ने लाल झंडा अपने हाथ में लेकर, कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ही एक समानांतर हेडक्वार्टर बना कर राज्य सत्ता पर कब्जा कर लिया था। उसने जो नीतियां अपनाई, वह समाजवाद को खत्म कर पूंजीवाद की पुनर्स्थापना करने की थी। संशोधनवादी रूसी सरकार व पार्टी से उसे मदद भी मिली। पूरी दुनिया में

साम्राज्यवादियों ने प्रचार करना शुरू कर दिया था कि समाजवाद विफल हो गया है और क्रांति एक पागलपन है। इसके लिए उन्होंने प्रचार साधनों जैसे अखबारों, पत्रिकाओं, नाटकों, कहानियों व गीत-संगीत तक का इस्तेमाल किया। इस तरह देखते हैं कि बुर्जुआ ने सबसे पहले समाज के उपरी ढ़ांचे यानी सरकार, विचारधारा, कला, कानून व संस्कृति के क्षेत्र पर कब्जा जमा लिया। अब वह इन सब का इस्तेमाल करते हुए जनता द्वारा खड़ी की गई समाजवादी व्यवस्था को ध्वस्त कर दोबारा पूंजीवाद खड़ा करना चाह रहे थे। मजदूर वर्ग के लिए यह एक चुनौती थी। सर्वहारा के महान शिक्षक कामरेड माओ उस समय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे। उन्होंने रूसी अनुभवों का विश्लेषण किया, पूरे चीन का भ्रमण कर हालातों का जायजा लिया और पूंजीवादी पुनर्स्थापना को रोकने के लिए और पार्टी व चीनी सरकार पर कब्जा जमाए बैठे पूंजीवाद का रास्ता अपनाने वालों को बाहर निकाल फेंकने के लिए जो रास्ता अपनाया, वह ही था ''महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति।''

सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति ने रूस के अंदर समाजवाद के निर्माण के 40 सालों के सकारात्मक और नकारात्मक अनुभवों का संपूर्ण और सही सार प्रस्तुत किया था। यह समाजवादी समाज के अंदर, राज्यसत्ता पर कब्जा किये हुए बुर्जुआ को हटाने के लिए थी। लेकिन सब से महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह न केवल लूटेरे वर्गों द्वारा पोषित पुरानी विचारधारा, सांस्कृतिक, पुराने रीति-रिवाज और आदतों, जिन्होंने हजारों सालों से जनता के दिलों को दूषित कर रखा था। न सिर्फ उसे नष्ट करने की कोशिश की बल्कि इसने जनता के बीच मजदूर वर्ग की एकदम नयी विचारधारा, संस्कृति, एकदम नये रीति-रिवाजों और आदतों को बनाया और फैलाया।

यह एक महान क्रांति थी, जो मुख्य रूप से विचारधारा और संस्कृति के क्षेत्र में चलाई गई, जिसने जनता के अंदर हजारों साल पुराने निजी स्वामित्व की अवधारणा का नष्ट करने और जन स्वामित्व की समाजवादी अवधारणा को स्थापित करने का काम किया।

महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति (1966) से पहले रूस और पूर्वी यूरोप के कुछ देशों में समाजवादी क्रांतियों के अनुभवः-

लेनिन ने 1917 की रूसी समाजवादी क्रांति का नेतृत्व किया था। उन्होंने अपने क्रांतिकारी व्यवहार से समाजवाद के दौरान भी वर्ग संघर्ष को और पूंजीवादियों द्वारा फिर से सत्ता छीन लेने के खतरे को देख लिया था। लेनिन ने कहा था, ''पूंजीपति वर्ग का प्रतिरोध उसका तख्ता उलट दिए जाने के बाद, दस गुणा ज्यादा बढ़ जाता है। उसकी ताकत छोटे पैमाने के उत्पादन में, पुरानी आदतों की शक्ति में होती है। छोटे पैमाने का उत्पादन हर दिन हर घंटा पूंजीवाद को और पूंजीपति वर्ग को जन्म देता रहता है। लेनिन ने कहा था कि ''नये बुर्जुआ हमारी सोवियतों (सरकार) के कर्मचारियों में से पैदा हो रहे हैं।''

समाजवादी निर्माण में रूस ने बहुत उपलब्धियां हासिल की। लेनिन के बाद स्तालिन के नेतृत्व में रूस में समाजवाद का निर्माण हुआ और उन्होंने सर्वहारा के राज्य को पूंजीवादियों के कब्जे में आने से बचाए रखा। स्तालिन की मृत्यु के बाद ख्रुश्चेव ने 1956 में ''समाजवाद की तरफ शान्तिपूर्ण संक्रमण, शान्तिपूर्ण प्रतियोगिता और शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व'' के घातक संशोधनवादी सिद्धांत, मजदूरों से सत्ता छीन लेने और समाजवाद को पूंजीवाद में दोबारा बदलने के लिए प्रस्तुत किया। यह वर्ग संघर्ष को नकारता था और मजदूरों द्वारा पूंजीपतियों पर तानाशाही कायम रखने के मार्क्सवादी सिद्धांत का खण्डन करता था।

1966 तक नयी परिस्थिति पैदा हो गयी। क्रांतियां पूंजीवादी पुनर्स्थापना की समस्या को हल करने में असफल हो रही थी। क्योंकि जनता की चेतना को केवल अंशिक रूप से ही बदला जा सका था और समाज के उपरी ढांचे (विचारधारा, राजनीति, रीती रिवाज व संस्कृति) को और शिक्षा, कला-साहित्य व पुरानी आदतों को सिर्फ आंशिक रूप से ही बदला जा सका था। इसी कारण ही रूस और पूर्वी यूरोप के ज्यादा देशों में मजदूर वर्ग की सत्ता पलट दी गयी थी।

ख्रुश्चेव ने रूसी बोल्शेविक पार्टी की प्रतिष्ठा का फायदा उठाते हुए अंतरराष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन को रास्ते से भटकाया और संशोधनवाद के दलदल में गिरा दिया। थोड़ी देर से ही सही, इस आधुनिक संशोधनवाद के खिलाफ कामरेड माओ के नेतृत्व में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने खुला विचारधारात्मक राजनीतिक वाद-विवाद चलाया। 1963-64 में चले इस वाद-विवाद को ही 'महान बहस' कहा जाता है। 'महान बहस' ने ख्रुश्चेव के संशोधनवाद को नंगा किया और आंदोलन को सही रास्ता दिखाया। 'महान बहस' ने सांस्कृतिक क्रांति के लिए आधार तैयार किया।

चीन में समाजवादी निर्माण का नियम और दो लाइनों का संघर्ष

1949 में चीन ने जमींदारी व्यवस्था और साम्राज्यवाद से छुटकारा पा लिया था। अब उसके सामने समाजवाद के निर्माण का काम था। पूंजीवादी समाज और समाजवादी समाज के बीच एक बदलाव का काल होता है। यह काल इस लिए अनिवार्य है, क्योंकि समाजवाद की संपूर्ण विजय के लिए जरूरी आर्थिक तथा सांस्कृतिक हालातों को पैदा करने तथा गैर-समाजवादी आर्थिक तत्वों को समाजवादी उसूलों के अनुसार ढालने के लिए समय की जरूरत होती है। कोई देश आर्थिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से जितना ज्यादा पिछड़ा होगा, बदलाव के काल का समय उतना ही ज्यादा होगा।

चीन में अब सत्ता मजदूर वर्ग के हाथ में थी, उसे समाजवाद का निर्माण करना था। पूंजीपति वर्ग दोबारा पूंजीवाद का निर्माण करने के लिए व मजदूर वर्ग से सत्ता छीन लेने की दीर्घकालीन लड़ाई लड़ने वाला था। चीन में समाजवाद के निर्माण का इतिहास पूंजीवाद को दोबारा स्थापित करने की कोशिशों के खिलाफ लड़ी गई लड़ाई का ही इतिहास है।

नव जनवादी अर्थव्यवस्था का निर्माण क्रांति से पहले ही शुरू हो गया था। दिसम्बर 25, 1947 को जारी एक रिपोर्ट 'वर्त्तमान परिस्थिति और हमारे कार्यभार' में कामरेड माओ ने आर्थिक बदलावों की रूप-रेखा बता दी थी। जमींदारों की जमीन को किसानों में बांटना था, साम्राज्यवादियों और उनके दलालों की संपत्ति को जब्त कर सरकार के अधीन करना था, राष्ट्रीय पूंजीपतियों की संपत्तियों को छोड़ देना था।

30 जून, 1950 में चीनी सरकार ने कृषि-सुधार कानून लागू किया व जनता ने कृषि-सुधार संघर्ष शुरू किया, फलस्वरूप 35 करोड़ एकड़ जमीन 30 करोड़ किसानों में बांटी गई। 3 करोड़ टन अनाज, जो पहले जमींदारों को चला जाता था, उस पर किसानों का कब्जा हो गया। 1952 के अन्त तक यह कृषि सुधार पूरे कर लिये गये थे।

1951 में पार्टी ने चरणबद्ध तरीके से समाजवादी निर्माण शुरु किया। व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था पर आधारित विशाल कृषि तथा हस्तशिल्प के समाजवादी रूपांतरण के साथ-साथ पूंजीवादी-उद्योग व व्यापार का समाजवादी रूपान्तरण करते हुए चीन का औद्योगिकरण करना था। कामरेड माओ ने रूस के समाजवादी निर्माण का विश्लेषण किया, उसके सकारात्मक व नकारात्मक अनुभवों से सबक लिया। इसके साथ कामरेड माओ ने चीन के अनुभवों का भी विश्लेषण किया और समाजवादी निर्माण के लिए नयी अवधारणा विकसित की। उन्होंने ''कृषि को बुनियाद बनाओ और उद्योग को नेतृत्वकारी भूमिका में रखो'' की नयी अवधारणा रेखांकित की।

कृषि-सुधारों के बाद कृषि में अभी भी छोटी किसानी ही मुख्य थी। पार्टी के नेतृत्व में किसानों ने स्वेच्छा से तथा आपसी हितों पर आधारित आपसी सहायता के ग्रुप बनाने का आंदोलन शुरू किया। इन आपसी सहायता ग्रुपों को सहकारिता समितियों मे बदला गया। यह समाजवादी समाज के तरफ पहला कदम थी।

पार्टी के पोलित ब्यूरो सदस्य व पूंजीवाद का रास्ता अपनाने वाले ल्यू-शाओ-ची ने इसका विरोध किया और पार्टी की अनुमति के बिना ही उसने अपने विचारों को फैलाया व किसानों के आपसी सहायता व सहकारिता ग्रुप बनाने को ''गलत, खतरनाक और दु:स्वप्न'' बताया। यह जुलाई, 1951 की घटना थी। ल्यू-शाओ-ची का कहना था कि समाजवादी निर्माण नहीं करना चाहिए, क्योंकि जनता उसके लिए तैयार नहीं थी बल्कि पूंजीवादी तरीके से उत्पादन को बढ़ावा देना चाहिए। इसका खण्डन करते हुए आपसी सहयता और सहकारिता बढ़ाने के लिए कामरेड माओ ने केन्द्रीय कमेटी की तरफ से 15 दिसम्बर, 1951 को कृषि में आपसी सहायता व सहकारिता को प्रमुख कार्यभार के रूप में लेने के लिए सर्कुलर जारी किया।

किसानों को औजार और उपकरण चीनी हस्तशिल्पी (दस्तकार) मुहैया करवाता था। उन्होंने भी उत्पादकों को सहकारी समितियों, सप्लाई और बेचनेवालों की सहकारी समितियों में संगठित किया।

पूंजीवादी उद्योग तथा वाणिज्य के बारे में पार्टी की नीति उससे फायदा उठाने, उसे कंट्रोल में रखने और उसका समाजवादी रूपांतरण करने की थी।

1951-52 की तीन बुराइयों और पांच बुराइयों के खिलाफ आंदोलन

कामरेड माओ ने सही समय पर ल्यू-शाओ-ची की बेवकूफियों की आलोचना की और सरकारी कर्मचारियों और पार्टी में तीन बुराइयों (भ्रष्टाचार, फिजूलखर्ची और नौकरशाही) के खिलाफ और उद्योगपतियों और व्यापारियों को रिश्वत देने, कर चोरी, सरकारी संपत्ति की चोरी, सरकारी ठेकों में धांधली और आर्थिक सूचनाओं की चोरी के खिलाफ आन्दोलन

चलाया। मुक्ति के बाद के तीन सालों के दौरान पूंजीपति वर्ग द्वारा मजदूर वर्ग के खिलाफ लगातार किये गये हमलों का यह सटीक जवाब था।

1951 के अंत तक 300 से ज्यादा सहकारी समितियां बनी थी। लेकिन आंदोलनों के दौरान 1952 में इनकी तादाद बढ़कर 4,000 हो गई थी। इसने 60 करोड़ चीनी जनता की अनाज की समस्या हल कर दी और मध्यम व बड़े उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध करवाने के साथ-साथ उद्योगों के लिए बाजार भी उपलब्ध करवाया।

1949 से 1952 के बीच जन-सरकार ने कई बड़ी निर्माण योजनाओं पर काम किया। 42,000 किलोमीटर लम्बी नहरों को मरम्मत किया गया। रेल मार्ग का निर्माण किया गया। यह जनता की सामूहिक शक्ति की वजह से हो पाया।

इस तरह क्रांति से 3 सालों के अन्दर ही, पार्टी के सही नेतृत्व, देश की जनता, मजदूरों और किसानों के प्रयासों से पूरी अर्थव्यवस्था का पुनरूद्धार हो गया। समाजवाद की ओर कदम आगे बढ़ने लगे।

असल में देश में तेज गति से हो रहे औद्योगिक विकास के लिए कृषि की प्रगति भी जरूरी थी, क्योंकि उद्योगों को कच्चा माल कृषि से उपलब्ध होता था और कृषि विकास से उद्योगों को बाजार उपलब्ध होता था।

कृषि की विकास के लिए कृषि सहकारिता को आगे बढ़ाना जरूरी था। छोटे सहकारिता समूह कृषि के साधनों को (जमीन, कृषि के उपकरण, उर्वरक, पानी की व्यवस्था आदि) बहुत ज्यादा विकसित नहीं कर सकते थे। इसीलिये कृषि सहकारिता की उच्च लहर चलाई गई। ल्यू-शाओ-ची, पेंग हुई, डेंग-जियाउ-पेंग आदि ने कृषि सहकारिता के बारे में दक्षिणपंथी विचार व्यक्त किये। वे उत्पादन बढ़ाने के लिए सहकारिता से पहले खेती में मशीनीकरण लागू करने की बात कर रहे थे। उन्हें सामूहिकता पर भरोसा न था, वह सहकारी जमीनों को दोबारा निजी हाथों में देकर, मशीनों के जरिए उत्पादन बढ़ाने की लाइन लेकर आए। ल्यू-शाओ-ची के गुट ने बहुत सारी सहकारी समितियों को भंग कर दिया। लेकिन कामरेड माओ ने 31 जुलाई, 1955 में 'कृषि सहकारिता का सवाल' नाम के लेख में, इन गलत विचारों का खण्डन किया और सिद्ध किया कि उत्पादन बढ़ाने तथा कृषि साधनों के विकास के लिए सहकारिता ही सही रास्ता है। 7 सितम्बर, 1955 में अपने एक लेख में सहकारिता को आगे बढ़ाने की नीति भी प्रस्तुत की। सहकारी समितियों की स्थापना के लिए जनता व कैडरों में शिक्षा चलाकर आधार तैयार किया गया। कुछ महीनों में सहकारिता की एक महान लहर उठी और केवल एक साल से कुछ ज्यादा समय में ही देश भर के 50 करोड़ किसान उन्नत व उच्च स्तर की सहकारी समितियों में शामिल हो गये।

1954 में निजी और सरकारी उद्योगों के माध्यम से पूंजीवादी उद्योगों का रूपान्तरण शुरू किया गया। 1956 में पूंजीवादी उद्योग और व्यापार में समाजवादी बदलावों का ज्वार आया। कुछ ही महीनों में पूरे देश के बड़े व मध्यम दर्जे के शहरों के सभी निजी उद्योग व व्यापार सरकारी-निजी संयुक्त उद्योगों में बदल गये। 1955-56 के समाजवादी उभार का भी भरपूर विरोध किया गया। उस समय के पार्टी महासचिव ल्यू-शाओ-ची की गुट ने एक बार फिर सर उठाया, इस बार उन्हें रूस में ख्रुश्चेव के आधुनिक संशोधनवाद से मदद व ताकत मिली थी। उन्होंने समाजवादी उभार को 'उतावलेपन और जल्दबाजी में आगे बढ़ना' बताया। उनका कहना था कि चीनी जनता समाजवाद के लिए तैयार नहीं है, पहले बड़े उद्योगों को प्रोत्साहन देकर उत्पादक शक्तियों का विकास करना चाहिए। यह बहाना बनाकर वह समाजवाद को रोकना चाह रहे थे। वह हुबहू रूसी नीतियों की नकल करना चाहते थे।

कामरेड माओ ने रूस से सबक लेते हुए और चीन के अनुभवों से यह निष्कर्ष निकाला कि चीन के ऊपर भी संशोधनवाद का खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने इन रूझानों को हराने के लिए तुरन्त ही संघर्ष शुरू किया। 25 अप्रैल, 1956 में पोलित ब्यूरो की विस्तारित बैठक में अपने भाषण ''दस प्रमुख संबंधों के बारे में'' रूस के समाजवादी निर्माण की समीक्षा प्रस्तुत की और उसकी कमजोरियों को दिखाया। उनके भाषण ''दस प्रमुख संबंधों के बारे में'' की खासियत यह थी कि उसमें कामरेड माओ ने समाजवाद के निर्माण में द्वंद्ववाद और वर्ग-संघर्ष व अन्तरविरोधों को केन्द्र में ला दिया, जो कि समाजवाद के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में एक नई व उच्च स्तर की वैज्ञानिक समझदारी थी। इसके अगले ही साल 27 फरवरी, 1957 को कामरेड माओ ने अपने भाषण, ''जनता के बीच के अंतरविरोधों को सही ढंग से हल करने के बारे में'' में हमारे और दुश्मन के बीच के दुश्मनागत अन्तरविरोध और जनता के बीच के अन्तरविरोध में फर्क करने और उन्हें अलग-अलग तरीके से हल करने के बारे में

बताया। ''सौ विचारों को भिड़ने दो, सौ फूल को खिलने दो'' के नारे को आत्मसात करते हुए देशव्यापी दक्षिणपंथी विरोधी शुद्धिकरण अभियान शुरू हो गया, जिसने ल्यू-शाओ-ची और उसके समाजवाद विरोधी गुट को आत्मरक्षा में डाल दिया। 1956 के शुद्धिकरण अभियान के दौरान कृषि, उद्योग और व्यापार में समाजवादी रूपांतरण का काम पूरा हो गया। आर्थिक मोर्चे पर समाजवाद की जीत हो गई थी। उत्पादन के साधनों पर अब निजी मिलकियत नहीं बल्कि सामूहिक मिलकियत लागू हो गई थी, पर इसका मतलब यह नहीं था कि वर्ग संघर्ष खत्म हो गया था, बल्कि वर्ग संघर्ष नया रूप लेने वाला था। अब वर्ग संघर्ष राजनीतिक, विचारधारा, संस्कृति, शिक्षा व प्रचार के मोर्चों पर होने वाला था।

1958 की बड़ी छलांग

1958 की बड़ी छलांग अभियान खेती और उद्योग में उत्पादन बढ़ाने की योजना थी। यह रूसी तरीके से भिन्न थी। रूस में बड़े उद्योगों को आधार बनाया गया था और उन्हीं पर ज्यादा ध्यान दिया गया था। चीन मॉडल में बड़े उद्योगों व छोटे उद्योगों पर बराबर ध्यान दिया गया। उसके समानान्तर ही खेती में उत्पादन बढ़ाने की नीति थी। 1958 में 7,50,000 कृषि सहकारी समितियां थी। किसानों ने पूरे उत्साह के साथ उन्हें आपस में मिलाकर 26,000 कम्यून बना लिया। प्रत्येक कम्यून में औसतन 5000 के करीब परिवार आते थे। कुल मिलाकर लगभग 13 करोड़ परिवार अब कम्यूनों में संगठित हो गये थे। कम्यून सिर्फ आर्थिक इकाई नहीं थी, वह नयी सामाजिक व्यवस्था भी थी, जो राजनीतिक, सांस्कृतिक व शिक्षा के काम-काज को भी देखती थी।

कम्यून बनने से बड़ी संख्या में किसानों को लामबंद करके सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और जमीन में सुधारों के बड़े कार्यों को पूरा करना सम्भव हो सका। जनता की सृजनशीलता का द्वार खुला गया। देहाती क्षेत्र में भी औद्योगिकरण शुरू हो गया। लाखों महिलाएं अपने घरों से बाहर कम्यूनों में काम करने लगी, उनके घरेलू कार्य को कम करने के लिए कम्यूनों ने सुविधाएं दी। कम्यून ही प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और कॉलेजों को धन देते थे।

शहरों में नये तरह की कारखाना व्यवस्था जन्म लेने लगी। एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों द्वारा प्रबंधन की जगहों पर मजदूरों के प्रबंधन में भागीदारी वाली व्यवस्था थी। कुछ मजदूर, तकनीकी विशेषज्ञ और प्रबंधन मिलकर उत्पादन की समस्याएं हल करने लगे। मजदूरों के प्रशिक्षण के लिए कम्यून स्कूल भी चलाया जाता था।

ऊपर दिये गये परिवर्तन बड़ी छलांग की उपलब्धियां थी, पर इसमें कुछ आंशिक असफलताएं भी थी, जो बिना तैयारी के काम करने व कुछ नीति को लागू करने के तरीकों की गलतियों के कारण हुई। 1959 की पार्टी कॉन्फ्रेंस में कामरेड माओ ने इनके बारे मे व्याख्या भी दी थी। फिर भी बड़ी छलांग अभियान के दौरान प्राप्त सफलताओं ने सांस्कृतिक क्रांति के दौरान बड़ी भूमिका निभाई। बड़ी छलांग पूंजीवादी रास्ता अपनाने वालों के लिए बड़ी हार थी। ल्यू-शाओ-ची और उस समय के रक्षा मंत्री पेंग-तेह-हुई ने इस आंदोलन को अस्पष्ट समाचारों और गलत सूचनाओं के आधार पर 'हड़बड़ी' में किया जा रहा आंदोलन साबित करने की कोशिश की। पेंग-तेह-हुई ने बड़ी छलांग को ''निम्न-पूंजीवादी कट्टरपन'' और ''एक ही बार में साम्यवाद में जाने'' की दुस्साहसपूर्ण कोशिश बताया। कामरेड माओ ने पेंग के हमलों का जवाब दिया और बड़ी छलांग की राजनीति का बचाव किया। पेंग को बर्खास्त कर दिया गया, पर पेंग ने अप्रत्यक्ष तरीके से कामरेड माओ पर हमले जारी रखे। मुख्यत: पत्रिकाओं में लेख लिख कर, नाटकों व सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा माओ और समाजवादी निर्माण की नीति पर हमले जारी रहे। उधर ल्यू-शाओ-ची ने भी सरकारी विभागों व पार्टी के अंदर कमजोर व ढुलमुल लोगों को अपने अधीन संगठित करने का काम जारी रखा। नीतियों के लागू होने में बाधा डाली जाने लगी।

1958-59 की बड़ी छलांग के बाद के तीन साल प्राकृतिक आपदाओं के थे, कुछ जगह वर्षा नहीं हुई, तो कुछ जगह भयानक बाढ़ आ गई। जिस वजह से चीन को समस्याओं का सामना करना पड़ा। 1960 में रूस ने अपने तकनीकी विशेषज्ञ वापस बुला लिये, जिस कारण कुछ उच्च तकनीक वाले उद्योगों में समस्या पैदा होने लगी। 1956 में खुश्चेव के आधुनिक संशोधनवाद के उभरने के कारण चीनी पार्टी में बैठे संशोधनवादियों व पूंजीवादी रास्ता लेने वालों को बल मिल रहा था। 3 साल की प्राकृतिक आपदाओं से फायदा उठाते हुए और पार्टी के अंदर व सरकार में पैदा हुए नये बुर्जुआ की मदद से ल्यू-शाओ-ची 1959 में चीन का प्रधान बन गया, भले ही कामरेड माओ पार्टी के अध्यक्ष थे, पर उन्हें एक किनारे पर करने की नीति अपनाई गई।

समाजवादी शिक्षा आंदोलन व वर्ग संघर्ष को कभी

न भूलें

इस समय कामरेड माओ ने अपना संघर्ष जारी रखा। कामरेड माओ ने संशोधनवादियों के हमले का जवाब देने और चीन में पूंजीवाद की पुनर्स्थापना रोकने के लिए 1962 में समाजवादी शिक्षा आंदोलन चलाने का प्रस्ताव सामने लाया। 8वीं केन्द्रीय कमेटी के 10वीं प्लेनम में कामरेड माओ ने फिर से बताया कि समाजवाद का काल एक लम्बा काल होता है। वर्ग भी रहते है और वर्ग संघर्ष भी रहता है। यह संघर्ष लम्बा चलने वाला संघर्ष होता है। इमें अपनी सतर्कता बढ़ानी चाहिए और समाजवादी शिक्षा अभियान चलाना चाहिए। जिस बात पर माओ ने जोर दिया, वह यह था कि सर्वहारा और बुर्जुआ वर्ग के बीच संघर्ष जारी है और हमें इस वर्ग संघर्ष को जारी रखना है।

प्रधान ल्यू-शाओ-ची और उसके मंत्री देंग-जिओ-पेंग ने भले ही समाजवादी शिक्षा आंदोलन पर सहमति जता दी थी, पर उन्होंने अपने षड़यंत्रों द्वारा शिक्षा आंदोलन को विफल करने की पूरी कोशिश की और काफी हद तक वह सफल भी हुए। 1963 से 1965 तक विचारधारा के क्षेत्र में कामरेड माओ ने ख्रुश्चेव के संशोधनवाद के खिलाफ डट कर लड़ाई लड़ी। उस समय में हुए वाद-विवाद को ही महान बहस कहा जाता है। इस महान बहस ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा, संशोधनवाद को नंगा किया और सर्वहारा के लिए समाजवादी निर्माण के बारे में ऐतिहासिक सबक दिये। महान बहस ने चीन के अंदर सांस्कृतिक क्रांति के लिए आधार तैयार कर दिया। समाजवादी शिक्षा आंदोलन समाजवादी चेतना और सामूहिक प्रयास को विकसित करके कम्यूनों को मजबूत बनाने के लिए शुरू किया गया था, इसका निशाना देहातों के वह लोग थे, जो पार्टी के उच्च अधिकारी थे व पूंजीवादी रास्ता अपना रहे थे। लेकिन जैसे ही यह समाजवादी शिक्षा-आंदोलन शुरू हुआ, ल्यू-शाओ-ची और अन्य लोगों ने एक नया निर्णय जारी कर दिया और हमले को पूंजीवादी रास्ता अपनाने वालों से हटा कर आम कैडरों की ओर मोड़ दिया तथा ''चार सवालों (राजनीति, विचारधारा, संगठन और अर्थव्यवस्था) के संदर्भ में साफ-सुथरा होने और न होने के बीच के अन्तरविरोध को सुलझाये जाने'' का लक्ष्य निर्धारित किया। जहां-जहां पूंजीवादी रास्ता अपनाने वाले सत्ता में थे। उन्होंने आंदोलन को तोड़ा-मरोड़ा। इसे चलाने के लिए केन्द्रीय कमेटी ने 'सांस्कृतिक क्रांति ग्रुप' बनाया था, जिसकी जिम्मेदारी समाजवादी शिक्षा आंदोलन को चलाना था।

समाजवादी चीन के अंदर वर्ग-शक्तियां

हमने ऊपर देखा है कि 1949 से लेकर 1956 तक के पूरे काल में वर्ग संघर्ष लगातार जारी रहा। पूंजीवादी रास्ता अपनाने वालों ने समाजवाद के निर्माण को रोकने के लिए बेहद कोशिश की थी, लेकिन 1956 तक समाजवादी अर्थव्यवस्था खड़ी कर ली गई थी। 1956 के बाद वर्ग संघर्ष समाजवाद को बचाने तथा उसे और विकसित करने वाली शक्तियों और समाजवाद को उल्टाने वाली शक्तियों के बीच था। आइये जरा देखें कि चीन में कौन-कौन सी वर्ग शक्तियां मौजूद थी, जो मजदूर वर्ग की सत्ता को चुनौती दे सकती थी।

1) जनता की सरकार ने जिन राष्ट्रीय पूंजीपतियों की सम्पत्ति जब्त कर ली थी, वे 60 के दशक में भी बचे हुए थे। इनमें से कुछ लोग कम्पनियों में अधिकारियों के तौर पर काम कर रहे थे। कुछ तकनीशियन के रूप में काम कर रहे थे। समाजवाद के लिए यह बड़ी चुनौती नहीं थी, क्योंकि हर आदमी को यह पता था कि वे कौन थे और लोगों ने उन्हें राजनीतिक और वैचारिक तौर पर खारिज कर दिया था, लेकिन फिर भी उनका कुछ न कुछ महत्व तो था।

2) दूसरी शक्ति पूंजीवादी बुद्धिजीवी थे। वे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण थे। वे शिक्षा व्यवस्था में, स्वतंत्र पेशों में और सरकारी संस्थाओं में भरे पड़े थे। कला और विज्ञान के क्षेत्र में तो वे बहुत प्रभाव रखते थे, लेकिन उनमें से कई लोग क्रांतिकारी थे। वे सामन्तवाद व साम्राज्यवाद की वकालत भी करते थे। लेकिन जैसा कि कामरेड माओ कहा करते थे, एक पूंजीवादी बुद्धिजीवी को सर्वहारा क्रांतिकारी में बदलने में कम से कम दस साल की शिक्षा-दीक्षा और तीखे वर्ग संघर्ष में हिस्सेदारी की जरूरत होती है। पर उस समय बहुतों बुद्धिजीवियों ने सर्वहारा शिक्षा ग्रहण नहीं की थी, बहुतों ने वर्षों वर्ग-संघर्ष में हिस्सेदारी नहीं की थी। जिन लोगों ने यह कार्यभार पूरा कर भी लिया था, लेकिन व्यवहार में उनका पक्के तौर पर सर्वहाराकरण नहीं हो पाया था। शिक्षा व्यवस्था, कला, संस्कृति और विज्ञान के क्षेत्र में अपने प्रभाव के कारण वह नयी पीढ़ी को भी अपनी धारणा के अनुसार ढालते रहते थे।

3) पुराने उच्च-मध्यम वर्गीय और मध्यम वर्गीय किसानों में पूंजीवादी रास्ते के बारे में भ्रम बना हुआ था। भले ही वह कम्यून में शमिल हो गये थे, पर अभी भी वह सामूहिक हित के मुकाबले निजी हितों को ऊपर रखते थे। उनका प्रयास

रहता था कि निजी खेत मिल जाए, मुक्त बाजार का विस्तार हो जाए, बेचने-खरीदने में आजादी और आपसी निर्भरता वाली टीमों या ब्रिगेडों के रूप में उत्पादन की जगह परिवारों के रूप में उत्पादन हो। समाज में ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा तो नहीं थी, फिर भी करोडों की जनसंख्या में उनकी कुल संख्या काफी हो जाती थी। महत्वपूर्ण पदों पर बैठे बुद्धिजीवियों द्वारा उठाये गये पूंजीवादी कदमों का वह स्वागत करते थे। वह निम्न-मध्यम वर्गीय किसानों को भी निजी स्वार्थ की तरफ धकेल सकते थे।

4) एक नया पैदा हुआ अभिजात्य वर्ग भी था, यह था प्रशासन और प्रबन्धन करने वाले, जिन्हें क्रांति ने ही पैदा किया था। ये वे क्रांतिकारी थे, जो 1949 में सत्ता में आए तथा क्रांति के बाद अपने विशेषाधिकारों और प्रभावों का इस्तेमाल करते थे। जिस कारण वह भ्रष्ट हो गये। 1952 की तीन बुराइयों के खिलाफ आंदोलन इन्हीं भ्रष्ट लोगों के खिलाफ था। पर वह पुरानी व्यवस्था के कारण अभी तक पैदा हो रहे थे।

5) सबसे खतरनाक वे नेतृत्वकारी कार्यकर्ता थे, जो कम्युनिस्ट पार्टी में पैर जमाए बैठे थे और सब कुछ जानते हुए भी जान-बूझकर सिद्धांतों में बदलाव करते थे, इनका नेता ल्यू-शाओ-ची था। औद्योगिक व्यवस्था, कृषि, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र के साथ-साथ वह लोग कम्युनिस्ट पार्टी, सरकार और सेना में भी महत्वपूर्ण पदों पर आसीन थे।

ऊपर दिए गए वर्गों के अस्तित्व के साथ पुरानी व्यवस्था के बहुत सारे अंतर अभी भी कायम थे। जैसे कि गांव और शहरों के बीच का अन्तर, मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम में अन्तर, तकनीकी विशेषज्ञ और मजदूरों के बीच में अन्तर, 8 स्तरीय वेतन का होना, पुरूष और महिलाओं में अन्तर आदि अभी तक अस्तित्व में थे। शिक्षा उत्पादन और श्रम से कटी हुई थी। परीक्षा प्रणाली भी पुराने तरह की थी जो बहु-संख्यक छात्रों की छंटनी कर देती थी। पूरी शिक्षा व्यवस्था पर बुद्धिजीवियों का कब्जा था। कुल मिलाकर शिक्षा समाज की जरूरतों के अनुरूप नहीं थी, सामूहिक भावना, श्रम का सम्मान करने की बजाय श्रम से दूर भागने व निजी हितों को आगे रखने को बढ़ावा देने वाली थी।

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और जन सरकार पर संशोध नवादियों का प्रभुत्व कायम हो जाने के बाद चीनी समाज में नौकरशाही का बोलबाला बढ़ गया था। ल्यू और डेंग ने समाजवाद और बड़ी छलांग की उपलब्धियों को पलटना शुरू कर दिया, उन्होंने कारखानों में फिर से अधिकारियों और तकनीकी विशेषज्ञ का वर्चस्व कायम करना शुरू किया। उत्पादन बढ़ाने के लिए राजनीति का इस्तेमाल न करते हुए ''भौतिक प्रोत्साहन'' को बढ़ावा दिया। यह सीधी-सीधी पूंजीवादी लाइन थी जो निजी स्वार्थ को बढ़ावा देती थी। देहातों में सामूहिक खेतों को ठेके पर देना शुरू कर दिया। पहले सिर्फ 5 प्रतिशत जमीन निजी हाथों में थी, जो बढ़ा कर 12 प्रतिशत कर दी गई।

इस सब के पीछे तर्क यह था कि 1956 के बाद चीन में प्रधान अन्तरविरोध बुर्जुआ वर्ग और सर्वहारा वर्ग में नहीं था बल्कि पिछड़ी हुई उत्पादक शक्तियों और विकसित समाजवादी व्यवस्था में था। जिसका सीधा-सीधा मतलब यह था कि जनता पिछड़ी हुई है और समाजवाद उनके लिए अति विकसित व्यवस्था है। यानी कि अभी समाजवाद स्थापित करने का समय नहीं आया है।

सांस्कृतिक क्रांति के समय प्रधान अन्तरविरोध का सवाल

1949 में ही कामरेड माओ ने सिद्ध कर दिया था कि चीन में क्रांति के बाद प्रधान अन्तरविरोध बुर्जुआ वर्ग और सर्वहारा वर्ग के बीच में है और समाजवाद से साम्यवाद तक के पूरे संक्रमण काल में यही प्रधान अन्तरविरोध रहेगा। उत्पादन के साधनों पर सामूहिक मालिकाना स्थापित होने के बाद यानी कम्यून बनने के बाद यह संघर्ष सर्वहारा की तानाशाही को बरकारार रखने के लिए होगा। यह मुख्यत: विचारधारा, राजनीति, संस्कृति, धर्म, रीति-रिवाज व शिक्षा आदि के क्षेत्र में होगा। कहने का मतलब यह है कि आधार में समाजवादी रूपांतरण होने के बाद संघर्ष समाज के उपरी ढांचे में बुर्जुआ और सर्वहारा के बीच में ही चलने वाला था। पूंजीवादी रास्ता अपनाने वालों ने 1956 के बाद यह प्रचार करना शुरू कर दिया कि चीन में अब बुर्जुआ वर्ग और सर्वहारा के बीच अन्तरविरोध खत्म हो गया है, बल्कि अब विकसित समाजवादी व्यवस्था और पिछड़ी हुई उत्पादक शक्तियों में है। यह विचार सर्वहारा की तानाशाही पर हमला था। यह मार्क्सवाद, लेनिनवाद और माओ विचारधारा (अब माओवाद) पर हमला था। किसी भी सत्ता को हथियाने के लिए जनमत तैयार करना जरूरी होता है। मजदूर वर्ग अपनी

शेष पृष्ठ संख्या 24 पर

कविताएं

एक अपील

(यह कविता अमर शहीद कामरेड किशन जी ने एक कामरेड की याद में, जो जनयुद्ध में एक समय तक जनता के साथ रहा, उसके बदलते हुए चरित्र और आचरण पर 1983 में लिखी थी, जो उस समय तेलुगु पत्रिका अरुणतारा में प्रकाशित हुई थी। - संपादकमंडल, लाल चिनगारी)

कॉमरेड!
याद करता हूं वह समय
जब हम साथ-साथ थे
साथ-साथ काम करते हुए
साथ-साथ घुमते हुए
रूखा-सूखा खाते हुए
लोगों के बीच
उनके दुखों के बीच
उनके दुखों को बांटते हुए
एक धरातल पर खड़े हुए
हमने साथ-साथ किया था
आंदोलन का आह्वान
लड़ाइयों के उतार-चढ़ाव में
हम जनता के बीच
खड़े रहे साथ-साथ
याद है, वह दिन?

जब लड़ाइयां अपने चरम पर है
आंदोलन है तेज
तुमने भ्रमित होकर
धैर्य खोकर
चुन लिया एक अलग जीवन
सिर झुकाकर जा मिले
दुश्मनों के साथ
आज नहीं पूछना चाहता
तुम्हारी शपथ के बारे में
नहीं पूछना चाहता
कहां गयी तुम्हारी उम्मीदें?
उम्मीद अब भी है
कि बिताओगे अपना पूरा जीवन
जनता के पक्ष में
खड़े होकर।

लेकिन साथी
लोग पूछेंगे तुम्हारे बारे में
कहां हो आज तुम?
मैं भी पूछना चाहता हूं
तुमसे यही
साथी !
भरसक प्रयास करता हूं
तुम्हें भाई, सर, कामरेड कहते हुए पुकारूं
तुम, जनता के विरूद्ध हुए....
जहां से तुमने हासिल की ये मुकाम
तुमने बेच दिया पार्टी का मान
गिरवी रख दिए
जनता के गौरव
अब
जबकि खड़े हो
जनता के कातिलों के बगल में
जूठन जैसी किसी चीज को
पाने के आशा में
लोग तुम्हें साथी नहीं कह पा रहे
मैं तुम्हें कामरेड नहीं कह पा रहा।
फिर भी!
मेरे भाई , कुछ तो सोचो
जूठन की उम्मीदें मत करो
पार्टी की प्रतिष्ठा को
आग में मत झोंको
संभव हो तो
आखिर तक, खड़े रहो
जनता के पक्ष में।

कॉलेज में पढ़नेवाली एक छात्रा के द्वारा भेजी गयी दो कविताएं

1.

हम लड़ेंगे

हम लड़ेंगे तुम्हारे विरूद्ध
तुम्हारी कोई भी चाल हमें
नहीं कर सकती नेस्तनाबूद।
क्योंकि हम लड़ेंगे तुम्हारे विरूद्ध
अपनी अंतिम जीत तक।
तुम्हारी चाल हम समझते हैं अच्छी तरह
जब हमारी जमीन न थी मजबूत
तब खूब दबाया तुमने सामंतवाद के पैरों तले हमें,
पर जब हम नक्सलबाड़ी की जमीन से खड़े हुए
तो तुमने कुचल देना चाहा हथियार के बल पर
तब से आज तक तुम्हारी चाल हम समझते हैं।
जब हमारी शाख फैलने लगी माओवादी नाम से
तब तुमने भड़काना शुरू किया आम जनता को
हमारे ही नाम पर।
जब तुम्हारी दाल न गली,
तब तुमने डराना शुरू किया आम जनता को
किया दमन उनका गुंडावाहिनियों के बल पर
जब जनता न डरी
तब तुमने फुसलाना शुरू किया आम जनता को
योजनाओं के नाम पर
मगर उसके बाद भी हमारे साथी न हो सके तुम्हारे
तब आज तुम नौकरियों के नाम पर
विकास के नाम पर, झारखंड मोमेंटम के नाम पर
जीतना चाहते हो हमारे साथियों के विश्वास को।
मगर हम समझते हैं तुम्हारी चाल
हमारी जमीन पर उद्योग बसाने की चाल
हमारे खेतिहर जमीन को खंगाल देने की चाल
खनिज संपदा निकाल हमारी माटी को बंजर बनाने की चाल
कभी हथियार दिखाकर हमें कुचलने की चाल
तो कभी लालच देकर हमें लुभाने की चाल
पर मालूम है हमें यह सब मुखौटा है,
तेरे विकास के चेहरे के पीछे
छुपा है रहस्य हमारे सर्वस्व लूट का
और चूंकि हम और हमारे ग्रामीण साथी
समझते हैं तेरी हर चाल को
इसलिए हम बढ़े है और लड़े हैं
आगे भी बढ़ेंगे और लड़ेगें तुम्हारे विरूद्ध।
और गढ़ेगें इतिहास किसान-मजदूरों की जीत का।

2.

जोंक

तुम खून चूसने वाले जोंक थे
और जोंक ही रहोगे शासक वर्ग।
कभी हमारा शोषण उत्पीड़न करके
चूसते थे खून,
आज जब हम उठ खड़े हुए हैं तुम्हारे खिलाफ
तो हमारे ही कुछ अपनों को
बनाकर बेवकूफ
खून चूस रहे हो उनका
उन्हें फौजी के रूप में
हमारे खिलाफ खड़े करके।
हमारे अपनों को अपने रक्षक बनाकर
सिपाही, सैनिक, अर्द्ध-सैनिक बल बनाकर
तो कहीं कोबरा बटालियन के रूप में
खून चूस रहे हो उनका।
वो भी हमारे वर्ग के ही हैं।
तभी तो तुम्हारे शिकार हुए हैं
समझ नहीं पा रहे तुम्हारी साजिश को
लड़ रहें हैं वो अपनों से ही
अपनों का खून बहाकर।
मगर याद रखना इतिहास कहता है
एक दिन ऐसा आएगा
जैसे हम तुम्हारे खिलाफ
उठ खड़े हुए हैं अपने दम पर,
वे हमारे अपने भी जिन्हें तुमने
हमारे खिलाफ भड़का रखा है,
हम अपनों से उन्हें लड़वा रखा है
वे भी एक दिन बगावत करेंगे तुम्हारे खिलाफ।
पहचानेंगे कि हम ही उनके अपने हैं
तुम तो खून चूसने वाले जोंक हो शासक वर्ग।

अपने हित के लिए स्वार्थ के लिए
चूस रहे हो उनका खून
तब तुम सोचना कहां छुपोगे
वे रक्षक ही तुम्हें उखाड़ फेकेंगे
हमारे साथ मिलकर सत्ता से
और करेंगे निर्माण नवजनवाद का।
एक वक्त आएगा जब समझ जाएंगे
हम सभी मेहनतकश लोग
कि तुम खून चूसने वाले जोंक थे
और जोंक ही रहोगे शासक वर्ग।

एक छापामार कैम्प में आयोजित क्रांतिकारी विवाह समारोह में प्रस्तुत एक कामरेड की कविता

क्रांति की राह में मिले दो साथी
आज बन गए जीवन साथी
दोनों का इतिहास है जुदा-जुदा
अब दोनों का इतिहास होगा मिला-मिला।

एक ने पैदा लिया मध्यमवर्गीय परिवार में
आँख खुली तो देखा पक्के मकान
पढ़ने को मिला अच्छे स्कूल-कॉलेज
पढ़ते-पढ़ते ही समझे इस समाज को
इस व्यवस्था के असली चरित्र को
इस व्यवस्था में पिसती आम जिंदगी को
और साथ ही साथ समझ में आई बात
तोड़ना होगा इस जुल्मी समाज को
मिटाना होगा शोषण के प्रत्येक रुप को
और साथ में समझ में आया क्रांति पथ
दीर्घकालीन जनयुद्ध ही है एक मात्र क्रांति पथ
भाकपा (माओवादी) ही है एक मात्र क्रांतिकारी पार्टी
समझ में आते ही यह बात
छोड़ दिए सारे ऐशो-आराम
जोड़ लिया नाता क्रांति पथ से
और कर गए कूच जंगल की ओर।

दूसरे ने पैदा ली एक गरीब किसान के घर
आँख खुली तो दिखी झोपड़ी
पढ़ने को भी नहीं मिली अच्छे स्कूल
लेकिन इन्होंने हकीकत में देखी गरीबी
इन्होंने देखी शोषण-जुल्म के अनेक रूप
और इससे पैदा हुई इनके अंदर एक आग
इस व्यवस्था को जलाने वाली एक आग
ये बचपन में ही चल पड़ी क्रांति पथ पर
इन्होंने तोड़ दी पितृसत्ता के प्रारंभिक रुप को
बचपन में समझी क्रांति का सही रास्ता
दीर्घकालीन जनयुद्ध ही है एकमात्र रास्ता।

आज जब दो भिन्न इतिहास हुए हैं एक
तो मेरी भी दोनों से गुजारिश है एक
भूलना नहीं कभी जिंदगी में बात एक
''महिलाओं के बिना क्रांति मुमकिन नहीं''
और ''क्रांति के बिना महिला मुक्ति नहीं''
इसलिए क्रांति के खातिर पकड़े रहना इस राह को
कभी एक लड़खड़ाए तो संभालना दूसरे को
बनना एक मिसाल क्रांतिकारियों के लिए
खड़े उतरना पार्टी की कसौटी पर
दोनों मिलकर लड़ते रहना अंत तक
इस जुल्मी-अत्याचारी व्यवस्था के खिलाफ
जब तक कर न दो जमीन्दोज इस व्यवस्था को
और बना न लो एक शोषण-विहिन समाज।।

पृष्ठ संख्या 63 का शेष

जा रहे दमन अभियानों के खिलाफ आवाज बुलंद करनी चाहिए।

केकेसी की ओर से चार कामरेडों ने भी अपनी-अपनी बात रखी। उन्होंने आज की परिस्थिति जनता द्वारा झेलने वाली समस्या को अठाया। साथ ही जन मिलिशिया को बढ़ाने, सभी लोगों को हथियारबंद होने और हमारे इलाके में घुसने वाले दुश्मन को पारंपरिक हथियारों से टक्कर देने का आह्वान किया। पूरे कार्यक्रम के दौरान बीच-बीच में पीएलजीए की टीम ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया।

चिलचिलाती धूप के बावजूद जनता पूरे कार्यक्रम में जोश-खरोश के साथ भागीदारी की और शाम 04 बजे कार्यक्रम संपन्न हुआ। सभा-मण्डली ने सभी को धन्यवाद दिया। जनता ने मैदान से विदाई ली।

मई दिवस की रिपोर्टिंग

(अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर इस साल हमारी पार्टी के बीजे सैक अंतर्गत सभी जोन में 1 मई से 31 मई, 2017 तक मई दिवस मनाया गया, जिसमें हमारी पार्टी के नेतृत्व में आम जनता के बीच रैली व सभा का आयोजन किया गया। ऐसे ही एक कार्यक्रम की रिपोर्टिंग हम यहां पर दे रहे हैं। - संपादकमंडल, लाल चिनगारी)

इस साल पार्टी के आह्वान के अनुसार मजदूर दिवस 13 मई, 2017 को दक्षिणी जोन के कोल्हान इलाके में जनता के बीच मनाया गया। दुश्मन के दमन अभियान, कॉम्बिंग ऑपरेशन के बीच व प्रतिकूल स्थिति के बावजूद भी जनता, जन संगठन व मिलिशिया की मदद से गुरिल्ला नियमों का पालन करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाया गया।

कार्यक्रम की तैयारियां:

कार्यक्रम कोल्हान एरिया कमेटी की तरफ से की गई। दुश्मन के दमन के चलते तैयारी के लिए सिर्फ दो दिन का समय लिया गया। कुल 13 गांवों की जनता को उनके जन संगठन क्रांतिकारी किसान कमेटी के जरिए संदेश भेजा गया। कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले गांवों की जनता ने तैयारियों और सुरक्षा में मुख्य भूमिका निभाई। दो दिन की कम अवधि की तैयारियों के बावजूद लगभग 350 लोगों ने 13 मई के कार्यक्रम में शिरकत की।

13 मई, 2017 को एक गांव के फुटबॉल-मैदान में कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम की सुरक्षा के लिए हमारे पीएलजीए की एक टुकड़ी साथ-साथ गांव के मिलिशिया को भी बाहर के हर रास्ते पर पहरा लगाया गया। मैदान को एरिया कमेटी द्वारा जारी किये गये बैनर व पोस्टर से सजाया गया। तय समय के अनुसार सुबह 10 बजे जनता खेल मैदान में जमा होने लगी थी। कार्यक्रम में हिस्सा लेने आये हुए जनता के लिए नाश्ता-पानी की भी व्यवस्था की गयी थी।

दोपहर 12:30 बजे कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गयी। सबसे पहले सभा-मण्डली का चुनाव किया गया। उसके बाद सभा का उद्घाटन गीत के जरिए किया गया। शिकागो के शहीदों की याद में ''अमेरिका दिशोम रे शहर शिकागो रे, हागा मजदूर को लड़ाई केना हो शोषण ते मुक्ति लागिन'' गीत पेश की गयी। उसके बाद जोन की ओर से एरिया प्रभारी कामरेड ने मजदूर दिवस पर अपना विचार रखा। उन्होंने मुख्यत: काम के घंटे कम करने के लिए मजदूरों द्वारा किये गये संघर्ष का परिचय दिया।

जोन कमेटी की ओर से बोलते हुए दूसरे कामरेड ने मई दिवस का ऐतिहासिक विवरण बताया। उन्होंने बताया कि 19वीं सदी में कैसे पूँजीपति लोग मजदूरों को 18 से 20 घंटे तक काम करवाते थे। मजदूर सूर्योदय से काम शुरु करता और सूर्यास्त के बाद तक काम करता रहता था। तब भी वह फटेहाल ही रहता था। उसका जीवन नर्क बन गया था। इन्हीं हालातों में सबसे पहले 1827 में अमेरिका के फिलाडेल्फिया में काम के घंटे दस करने के लिए आवाज उठाई गयी।

'आठ घंटे काम, आठ घंटे मनोरंजन, आठ घंटे आराम' की मांग का नारा सबसे पहले अस्ट्रेलिया के फैक्ट्रियों में काम करने वाले ने लगाया था। यह नारा बाद में पूरी दुनिया के मजदूरों का नारा बन गया। लेकिन काम के घंटे कम करने के लिए मुख्यत: अमेरिका में ही संघर्ष हुआ।

1866 में अमेरिका की नेशनल लेबर यूनियन के स्थापना समारोह में काम के घंटे आठ करने के लिए संघर्ष की प्रतिज्ञा ली गई। उसी साल कामरेड मार्क्स के नेतृत्व वाले पहले इंटरनेशनल ने भी इस मांग को अपने एजेंडे में दर्ज कर लिया। इसके बाद यह आंदालन तेजी से पूरी दुनिया में फैल गया। पर संघर्ष का मुख्य केंद्र अमेरिका ही बना रहा। 1886 की शिकागो के हे-मार्केट की घटना के बाद 1889 में दूसरे इंटरनेशनल की पेरिस कांग्रेस में पहली मई को उस दिन का रुप दिया गया, जिस दिन पूरी दूनिया भर के मजदूर आठ घंटे के कार्य दिवस की मांग पर संघर्ष कार्यक्रम करते थे। 1890 से शिकागो के शहीदों की याद में मई दिवस अंतरराष्ट्रीय मजदूर बन दिवस बन गया।

उन्होंने बताया कि आज के साम्राज्यवाद के युग में पूरी दुनिया, पूरे भारत देश व हमारे अपने इलाके हो चाहे बिहार, बंगाल, ओड़िशा, झारखंड, आंध्र-प्रदेश, छत्तीसगढ़ सभी राज्यों में साम्राज्यवादी शोषण जोरों पर है। हमारे यहां की जल-जंगल-जमीन, नदी व पहाड़ों को छीन कर खदान व फैक्ट्री बना दी गयी है। लाखों लोगों को विस्थापित किया जा रहा है; और जो काम कर रहे हैं उनका रोज शोषण बढ़ रहा है। शोषण-उत्पीड़न का विरोध करने वाले मेहनतकश जनता आवाज को सैन्य बलों के जरिए दबाया जा रहा है। इसलिए इस व्यवस्था को बदलने के लिए लड़ रही जनता पर चलाए

शेष पृष्ठ संख्या 62 पर

पीएलजीए की महत्वपूर्ण कार्रवाइयों की रिपोर्ट

जेआरसी की रिपोर्टः

यूजोन की रिपोर्टः-

पारसनाथ एक्शन प्लान के नवनिर्मित भवन को उड़ाया गया

गिरिडीह के मधुबन थाना से महज दो सौ मीटर की दूरी में कल्याण निकेतन में सीआरपीएफ का बेस कैम्प है, फिर उतने ही दूर में झारखण्ड भवन में भी सीआरपीएफ रहता है। फिर एक किलोमीटर दूर रियूबारी में दो कम्पनी सीआरपीएफ का कैम्प है। इस सब के बीच में कोठाटांड़ में पारसनाथ एक्शन प्लान भवन को पीएलजीए ने 03 नवंबर, 2016 को माईन लगाकर विस्फोट कर ध्वस्त कर दिया। कोठाटांड़ का यह जमीन गरीब घटवार जाति का है। जो जैन प्रबंधन प्रकाश चन्द्र जैन द्वारा डरा-धमका कर जमीन पर कब्जा जमाकर राज्यपाल के नाम पर दान करा दिया। इसी जमीन में तत्कालीन राज्य मुख्य सचिव राजीव गौवा के नेतृत्व में पारसनाथ एक्शन प्लान का ऑफिस नियुक्त कर व मजदूर का बोर्ड लगाकर काम शुरू किया गया।

दरअसल पारसनाथ इलाके में माओवादी आन्दोलन को दमन करने के लिए सीआरपीएफ बेस कैम्प होना जरूरी है, तभी दमन अभियान चलाने में सुविधा होगी, इसी को केन्द्रित कर पारसनाथ एक्शन प्लान का ऑफिस बना था। यह स्थानीय क्रांतिकारी जनता और मजदूरों को समझने में देर नहीं लगी कि यहां डोली मजदूर नहीं रहेंगे बल्कि पारसनाथ एक्शन प्लान चलाने वाले बड़े-बड़े पुलिस अधिकारी बैठकर क्रांतिकारी आन्दोलन को खत्म करने की योजना बनाएंगे। इसलिए ही पीएलजीए योद्वाओं ने विस्फोट करने का फैसला लेकर माईन से उड़ाने से पहले विल्डींग के अन्दर सर्च कर 56 मजदूरों को पाया। उससे बातचीत कर व उन्हें बाहर निकालने के बाद विल्डींग को ध्वस्त कर दिया गया।

गद्दार कोकिल महतो उर्फ उदय के घर को उड़ाया गया

03 नवंबर, 2016 को गद्दार कोकिल महतो उर्फ उदय का मधुबन में स्थित पक्का घर को पीएलजीए योद्धाओं ने माईन विस्फोट कर ध्वस्त कर दिया। गद्दार उदय महतो भाकपा (माओवादी) पार्टी में 1996-97 से कार्यरत था और यूजोन के जोनल प्लेनम द्वारा 2010 में निर्वाचित होकर जोनल सदस्य बना। इसी दरमियान 2011 में गद्दार उदय महतो गुप्त रूप से पुलिस के साथ समझौता कर व गिरफ्तारी का नाटक कर धनबाद पुलिस के पास सरेंडर किया और तेनुघाट जेल चला गया। वहां भी रहकर जेल से रिपोर्ट संग्रह कर दुश्मन को रिपोर्ट करता था और क्रांतिकारी बंदियों को भी बहकाने का कोशिश करता था कि पार्टी कहां मदद करता है, कैसे जेल से निकलेंगे आदि।

जेल से बाहर निकलकर आने के बाद पार्टी से सम्पर्क बनाया व झूठा आत्मालोचना करते हुए पहले जैसे पार्टी में काम करने का प्रस्ताव रखा। वह पार्टी कमिटी ने उसके प्रस्ताव को मंजूर कर पुनः पार्टी में रख लिया और फिर से जोनल कमिटी में को-ऑप्ट करते हुए जोनल सदस्य के बतौर जिम्मा देकर इलाका में काम करने का जिम्मा दिया। भीतरघाती उदय महतो सुनियोजित ढंग से पार्टी नेतृत्व को सफाया करने के लिए जुट गया, जिसका ताजा उदाहरण है 30 जून, 2014 की रात्रि 2:30 बजे जी. टी. रोड में सीआरपीएफ के आईजी विके टोप्पो और गिरिडीह एसपी के नेतृत्व में एम्बुश कर हमारे नेतृत्वकारी कामरेडों को निशाना बना कर दुश्मन द्वारा किए गए हमले में उदय का ही हाथ था। हालांकि हमारे पीएलजीए योद्धाओं ने मोर्चा संभला और दुश्मन को करारा जबाव देते हुए नेतृत्वकारी कामरेडों को सुरक्षित निकाल लिया। फिर भी गद्दार उदय पहचान में नहीं आया। फिर वर्ष, 2015 में यूजोन के द्वितीय प्लेनम के जरीये वह जोनल सदस्य चुन लिया गया। 27 फरवरी, 2015 को उसके जिम्मा में रखे गये डम्प से रूपये लाने के लिये उसे भेजा गया। दूसरे दिन ही दो एसएलआर, चार थ्रीनट थ्री राइफल व 16 लाख 60 हजार रूपये लेकर डायरेक्ट पुलिस के पास चला गया। इसके बाद खुलकर पार्टी विरोधी काम करना शुरू किया। जैसे पार्टी कैडर को सफाया करने के मकसद से हर जगह दुश्मन को लेकर छापामारी में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेना, पार्टी के नाम पर लेवी वसूलना, पुराना डम्प खोजना, जनता के उपर मार-पीट, डराना-धमकाना, बेइज्जती व बलात्कर चलाना आदि।

उसके इस तरह के कारनामे को देखते हुए ही मधुबन स्थित उसके घर को उड़ाया गया।

फिर 08 नवंबर, 2016 को गिरिडीह जिला के पीरटांड़ थाना अन्तर्गत पाण्डेडीह स्थित उसके पुराने घर को पीएलजीए योद्धाओं ने ध्वस्त करने से पहले पाण्डेडीह की ग्रामीण जनता

को जमा कर जनअदालत लगाकर गद्दार उदय महतो पार्टी विरोधी काम में उतर गया है, उसके बारे में यानी उदय के काले करनामे का राजनीतिक भण्डाफोड़ किया गया। इसलिए गद्दार उदय महतो का नया घर मधुबन में ध्वस्त किया गया है, अब पुराने घर को भी ध्वस्त करेंगे। साथ ही उदय महतो की सारी सम्पत्ति पर सदा प्रतिबंध रहेगा। उसने पार्टी विरोध ी काम किया है इसलिए उदय हमेशा जन विरोधी ही रहेगा आदि फैसला जनअदालत में सुनाकर पुराने घर को भी ध्वस्त कर दिया गया।

यह समाचार बिजली की गति से पूरे इलाके में फैल गया कि उदय महतो का दोनों जगह का घर पीएलजीए ने उड़ा दिया है। यह समाचार सुनने के बाद से पारसनाथ इलाके के अन्दर जितना भी एसपीओ व जनविरोधी काम में लिप्त रहने वाले लोग थे, सभी डर गया, बहुत लोग गांव छोड़ कर बाहर कमाने के नाम पर चला गया और कुछ लोग पार्टी के सामने अपने कसूर को स्वीकर करते हुए आइन्दा ऐसा गलती नहीं करने का बात बोलने लगा और जनता से माफी मांगा। उन्हें जनता माफ करते हुए दोबारा साफ-सुथरा जीवन जीने का मौका देकर छोड़ दिया।

एसपीओ डुमका मुर्मू का सफाया

दिनांक 3 जुलाई, 2016 को गिरिडीह जिला पीरटांड़ थाना अन्तर्गत डेगापहाड़ी गांव के रहने वाले डुमका मुर्मू बहुत दिनों से पुलिस मुखबिरी का काम करते आ रहा था। डुमका मुर्मू को कई बार समझाया-बुझाया गया था, फिर भी पुलिस आने से पुलिस के साथ घुमना-फिरना लगा ही रहता। पार्टी के खिलाफ में बोलना, इधर का बात उधर ले जाना, इसका पेशा बन गया था। उसका काम पुलिस मुखबिरी करना और पार्टी का सामान डम्प में कहां-कहां है, उसको दिखाना था। डुमका मुर्मू को समझाने के बाद भी नहीं सुधरा। सुधारने के लिए जनअदालत लगाकर सुधारने का प्रयास किया गया, पर फिर भी नहीं सुधरा तब बाध्य होकर 3 जुलाई को 7-8 बजे रात को पकड़ कर और 12-01 बजे रात को पीएलजीए ने उसको मृत्युदण्ड का सजा दिया।

डुमका मुर्मू पारसनाथ के तराई के एक छोटे से गांव का रहने वाला एक गरीब आदिवासी (संथाल) था। डुमका मुर्मू गरीब रहने के बावजूद उसका सोच व चिन्तन गलत रूझान रखने वाले थे, इसी कारण से वह पुलिस के बहकावे में आकर पुलिस दलाल यानी स्पेशल पुलिस ऑफिसर (एसपीओ) के रूप में भाकपा (माओवादी) पार्टी को खत्म करने के लिए शपथ खाया था। उदहारण के तौर पर कहा जाय तो 2014 के जुलाई माह में पार्टी के डम्प का सामान पुलिस को ले जाकर दिखाना तथा कई बार मुठभेड़ करवा देना, जैसे 6 अप्रैल, 2016 को पारसनाथ डेगापहाड़ी गांव के बगल में पुलिस मुठभेड़ करावाया था, इस तरह से कई छोटे-बड़े प्रमाण हैं। फिर भी इसको पार्टी की ओर से एक-दो बार समझाने का काम किया गया, लेकिन वो नहीं सुधरे। अंततः जनता, जनमिलिशिया और पीएलजीए के वीर योद्धाओं ने बाध्य होकर उसका सफाया किया।

पुलिस जुल्म के खिलाफ मधुबन थाना का घेराव

दिनांक 04 जनवरी, 2017 को गिरिडीह जिला अन्तर्गत तधुबन थाना को सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण जनता (महिला-पुरुष, बच्चों-बूढ़ों) ने पारम्परिक हथियार तीर-धनुष, लाठी-फरसा आदि के साथ मधुबन थाना का घेराव किया। पारसनाथ पर्वत के तराई में बसा छोटा सा गांव मोहनपुर, संताल आदिवासियों का गांव है। सुबह 5:30 बजे सैकड़ों की संख्या में सीआरपीएफ, झारखण्ड जगुआर पुलिसकर्मी गांव में पहुंचकर माओवादी कहां है? तुमलोग माओवादी को खाना खिलाते हो, तुमलोग सामान पहुंचा देते हो आदि सवाल करने लगे। जब ग्रामीण जनता ने साफ-साफ जवाब दिया कि हमलोग माओवादी को नहीं जानते हैं, जो बदहवास सीआरपीएफ, झारखंड जगुआर आदि पुलिसकर्मियों ने ग्रामीण जनता के उपर कहर बरपाना शुरु कर दिया। जिसमे कई ग्रामीण युवाओं की पुलिस की पिटाई से मुंह से खून निकलने लगा। खून बन्द नहीं होने पर गांव वालों का गुस्सा पुलिस पर भड़क उठा व जनता पुलिस पर भारी पड़ी, तो पुलिसकर्मी वहां से भागने लगे। आक्रोशित ग्रामीण जनता तीर-धनुष व लाठी-फरसा लेकर पुलिसकर्मियों को पीछा करते हुए थाना तक पहुंच गई। थाना पहुंचकर ग्रामीण जनता बुलन्द आवाजों के साथ पुलिस वालों से जवाब मांग रहे थे। निर्दोष ग्रामीण जनता को मारना-पीटना बन्द करो, माओवादी दमन के नाम पर निर्दोष जनता के उपर मार-पीट बन्द करो, माओवादी करार देकर निर्दोष आदिवासी जनता पर मार-पीट आखिर क्यों? पुलिस-प्रशासन जवाब दो! आदि नारों के साथ मधुबन थाना का कई घंटों तक घेराव किया। अंततः थाना प्रभारी ने आक्रोशित ग्रामीण जनता से माफी मांगते हुए कहा कि अब से पुलिसकर्मी ऐसा नहीं करेंगे। तब आक्रोशित ग्रामीण जनता शांत हुई और थाना घेराव मुक्त हुआ।

पुलिस जुल्म के विरोध में थाना का घेराव

दिनांक 19 जनवरी, 2017 को गिरिडीह जिला के पीरटांड़ थाना अन्तर्गत डेगापहाड़ी गांव में सीआरपीएफ व झारखण्ड जगुआर पुलिस द्वारा महिलाओं के उपर लाठी चार्ज किया गया। यह गांव गिरिडीह जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर पारसनाथ पर्वत के तराई में एक छोटा सा गांव है। इस गांव में 9-10 घर है। 10-11 बजे दिन को पुलिस डेगापहाड़ी गांव में आकर एक घर में घुसी, उस घर में कोई पुरूष सदस्य न मिलने पर पुलिस पूछने लगी कि तुम्हारा पति कहां है? वह बतायी कि मधुबन काम करने गये है, तभी पुलिस उस महिला को गाली-गलौज करते हुए बोलने लगा कि तुम्हारा पति माओवादी है, बन्दूक ढोता है, पुलिस को मारता है, बताओ कहां है? कहते हुए मार-पीट करना शुरू किया। जब उस महिला को बचाने 70 वर्षीय उसकी सास आयी, तो उसे भी 7-8 डंडा लगा दिया। बगल के घर में एक छोटी बच्ची रोने लगी, तो उसे भी पीट दिया। इस पिटाई को देखकर जब गांव का एक लड़का भागने लगा, तो उसे दौड़ाकर पकड़कर उसको पूरा पीटते हुए उसका मोबाईल भी छीन लिया। इस तरह से गांव के महिला, बच्ची, बूढ़ी और युवक को पुलिस द्वारा पीटते हुए देखकर ग्रामीण जनता गोलबंद होकर तीर-धनुष व लाठी-फरसा निकालने लगी। तो पुलिस भड़के माहौल को देखते हुए उस युवक को लेकर थाना भाग आई। तो आक्रोशित ग्रामीण जनता पुलिस वालों का पीछे करते मधुबन थाना पहुंचकर सैकड़ों महिलाओं ने पुलिस वालों को अपनी भाषा (संताली) में खरी-खोटी सुनाई। संताल आदिवासी पुलिस इस संताली भाषा को समझते थे, वो मुंह चुराते भाग खड़े हुए। महिलाओं के प्रतिरोध को देखते हुए उस युवक को एक घण्टा के अन्दर छोड़ दिया गया।

एसपीओ सतेन्द्र का सफाया

गिरिडीह जिला के बिरनी थाना का रहने वाला एसपीओ सतेन्द्र गोमिया थाना अन्तर्गत स्वांग कोलयरी में रह रहा था। उसका पेशा बन गया था दलाली करना, पार्टी के सामने में चापलूसी करना और भीतर ही भीतर पार्टी विरोधी क्रियाकलाप व षड़यंत्र रचना। इनके इस रवैये को लेकर जनअदालत लगायी गयी, जहां से समझा-बुझाकर उसको छोड़ दिया गया। लेकिन ये अपने हरकत से बाज आने के बजाय पार्टी विरोधी गद्दार उदय महतो के साथ मिलजुल कर पार्टी के अन्दर का बात जानने के उद्देश्य से अपना नेटर्वक बनाना और पार्टी के नाम पर पत्र लिखना तथा लेवी लेना आदि काम करने लगा। उनके जन विरोधी व पार्टी विरोधी काम करते जाने के कारण को देखते हुए जनता और पार्टी के नेतृत्व में हुई जनअदालत में जनता की राय के अनुसार 8 अप्रैल 2016 को सफाया किया गया।

आजसू नेता व ठेकेदार ठाकुरदास महतो का सफाया

ग्राम-कोरांबे, प्रखंड-गोला, जिला-रामगढ़ का रहने वाला ठाकुरदास महतो गोला-मगनपुर ब्रजेश कंस्ट्रक्शन का ठेकेदार सह आजसू पार्टी का नेता था। ग्रामीणों की रिपोर्ट के अनुसार ठाकुरदास महतो पार्टी विरोधी प्रतिक्रियावादी गद्दार उदय महतो के सहयोग से पुलिस महानिदेशक डीके पाण्डे और रांची, बोकारो, हजारीबाग, रामगढ़, गिरिडीह जिला के एसपी के साथ मिलकर एक गुण्डा गिरोह बनाया है। इस गिरोह का काम ही है, यूजोन के नाम पर लेटर पैड व रसीद छपवाकर पार्टी के नाम से ठेकेदारों को पत्र देना और लेवी वसूली करना, यूजोन और डी जोन के बीच रास्ता के बारे में पुलिस को बताना तथा पुलिस को रास्ता में दिन-रात एम्बुश पर बैठाना और केकेसी, जन मिलिशिया व जनता को धमकी देना, फिर पार्टी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करवाना आदि-आदि। उक्त गिरोह में सक्रिय रहे ठाकुरदास महतो को जनता के राय या निर्णय के मुताबिक पार्टी की ओर से 22 जनवरी, 2017 को सफाया किया गया।

रेलवे विभाग की संपत्ति को क्षति पहुंचाया गया

बोकारो जिला के गोमिया थाना अंतर्गत गोमो-बड़काकाना रेलखंड में दो दिवसीय चक्का जाम के दौरान 6-7 अक्टूबर 2016 को डुमरी-बिहार स्टेशन में एक रेल इंजन को आग लगा दिया गया और रेलवे टेक को तोड़ दिया गया। दो दिवसीय भारत बंद के दौरान 11-12 अक्टूबर 2016 को दनिया-जगेवशर बिहार स्टेशन के बीच रेल पटरी को विस्फोट कर उड़ा दिया गया, दूसरे दिन भी डुमरी बिहार-दनिया स्टेशन के बीच रेल पटरी उड़ा दिया गया। यह कार्रवाई ऐसे समय किया गया जब दुश्मन अपना सारे तैयारी करके रखा था। पर दुश्मन अधिक क्षति उठाने से वंचित रह गया।

झुमरा एक्शन प्लान का सच

सरयू व सारण्डा एक्शन प्लान के तर्ज पर बोकारो जिला में झुमरा एक्शन प्लान के नाम से जनता की जल-जंगल जमीन को बड़े-बडे पूंजीपतियों के हाथों में सौंपने के लिए गरीब आदिवासी मेहनतकश लोगों को सरकार मजबूर कर रही है। विकास के नाम पर सिर्फ रोड, पुल, सामुदायिक भवन, मोबाईल टावर और क्षेत्र में कारपेट सिक्यूरिटी का विस्तार हुआ है। झुमरा, राहवान, लइयो, दनिया, चतरोचट्टी, अरजरी, कोनार डैम, जागेश्वर बिहार, संवाग आदि जगहों में पुलिस अर्ध-सैनिक बलों का कैम्प बनाकर बड़े पैमाने पर पुलिस बलों को रखकर मेहनतकश गरीब जनता को जल-जंगल-जमीन से बेदखल करने के लिए बूटों तले रौंदा जा रहा है। जनता को माओवादी बताकर उनके साथ मार-पीट, अपहरण, लूट-पाट, बलात्कार जैसा घिनौना हरकत किया जा रहा है। झुमरा पहाड़ व लुगू पहाड़ को केन्द्रित करके जून, जुलाई, अगस्त, सितम्बर 2016 को ऑपरेशन प्रलय चलाया गया। इस दौरान धमधड़वा गांव में पुलिस चार दिन कैम्प करके वहां के महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने, बेरहमी से मार-पीट करने आदि हरकत किया गया। इससे ये कहना कतई गलत नहीं होगा कि झुमरा एक्शन प्लान के नाम पर विकास नहीं मेहनतकश इंसानों पर जुल्मो-सितम का कहर बरपाया गया और बरपाया जा रहा है।

डीजोन की रिपोर्ट

पुलिस मुखबिर सनिका पूर्ति से बांड भरवाया गया

आराअः सेरेंग एरिया अन्तर्गत ग्राम रोगोद, थाना टेबो, प्रखण्ड बन्दगांव, जिला प. सिंहभूम का रहने वाला सावना पूर्ती का बेटा सनिका पूर्ति ने 11 अगस्त, 2016 को ग्राम सिलादोन का रोड ठेकेदार शिव कुमार एवं सरदा मरला का जदोराथ, इन दोनों के कहने के अनुसार पार्टी को लेवी का झांसा देकर 11 अगस्त, 2016 को सनिका पूर्ती ने पुलिस को लेकर हमारे पड़ाव ऊलीलोर गांव में सुबह 10 बजे हमारे नजदीक करीब 50 मीटर दूरी तक सामने लाया। 8 बजे जिस साथी का संतरी था, वह बुखार होने के कारण बैठे-बैठे उंघ रहा था। इसलिए दुश्मन को दूर से आते नहीं देखा, जब दूसरा साथी संतरी छुड़ाने गया, तो दुश्मन को देखा कि दो दिशा से सामने में ही आकर सटा हुआ है। हम सभी साथियों को जैसे दुश्मन का रिपोर्ट मिला, वैसे हम लोग वहां से सुरक्षित निकल गये, पर वहां हम लोगों का काफी सामान छूट गया। बाद में पुलिस ने गांव के कई घरों में लूट-पाट को भी अंजाम दिया और कई के साथ मार-पीट भी किया। इसी जुर्म में सनिका पूर्ति को दिनांक 15 अगस्त, 2016 दिन सोमवार को पीएलजीए ने पकड़कर जन अदालत में हाजिर किया और जनअदालत में पूछ-ताछ किया गया। पूछ-ताछ करने के बावजूद भी अपनी गलती को कबूल नहीं करने से शारीरिक दण्ड भी दिया गया। शारीरिक दण्ड देने के बाद ही अपनी सारी गलती को कबूल किया। कबूल करने के बाद जनअदालत में बैठे जनता के निर्णय के अनुसार आइंदे दोबारा ऐसे गलती नही करूंगा, दोबारा गलती करने से मुझे मौत का सजा दिया जाए, का बांड लिखवाकर जनता के जिम्मे में छोड़ दिया गया।

पुलिस दलाल समुएल सिन्दुरो को जनअदालत में चेतावनी

आनन्दपुर एरिया अंतर्गत ग्राम उसगिद थाना गोइलकेरा, प्रखण्ड गोइलकेरा, जिला प. सिंहभूम का रहने वाला समुएल सिन्दुरो जनता के कहने के अनुसार 2012 से सोनुवा, गोइलकेरा व सोदे पुलिस का मुखबिर व एसपीओ का काम करता था। जनता के कहने के अनुसार 2012 के उसगिद मुठभेड़ में समुएल का ही हाथ था, इसलिए तुरंत एक कामरेड के इलाज के दौरान ही सोदे पुलिस आ गई थी, दो दिन तक मुठभेड़ हुआ था, उसी समय से समुएल सिन्दुरो घर से भागकर गोइलकेरा और सोनुवा में रहता था। उन्होंने दिनांक 26 दिसम्बर, 2016 दिन सोमवार को हमारे भाकपा (माओवादी) के पास सरेण्डर किया। सरेंडर करने के बाद समुएल सिन्दुरो से पूछ-ताछ किया गया, लेकिन समुएल सिन्दुरो ने अपना गलती कबूल नहीं किया। समुएल सिन्दुरो को बचाने के लिए उसगिद की जनता हर बातों पर उसकी हर गलती को छिपाता रहा, इललिए समुएल सिन्दुरो को पार्टी की ओर से चेतावनी देकर छोड़ दिया गया।

पुलिस संपोषित सशस्त्र खुफिया गुंडा गिरोह पर हमला

बन्दगांव प्रखण्ड के टेबो थाना अन्तर्गत राईगडा टोला टोनटो मर्चा में दिनांक 25 जुलाई, 2016 को पीएलजीए ने पीएलएफआई के ऊपर घात लगाकर हमला किया। इस हमले में जनता के रिपोर्ट के अनुसार दो पीएलएफआई मारे गये व दो बुरी तरह घायल हुआ। 13 बैग जब्त किया गया, जो पैन्ट शर्ट से भरा हुआ था। चार पीस टेन्ट वाला तिरपाल, दो पीस वर्दी, चाकू 10-12 पीस, चार पीस बड़ा वाला 50 मीटर रस्सी, एक पेटी सुई-दवा, एक सिंगल कट्टा पिस्तोल, तेल

साबुन आदि सामान जब्त किया गया। इस तरह की लड़ाई को देखकर जनता का काफी मनोबल बढ़ा है। इस मुठभेड़ में पीएलजीए के साथ में पीएमएस, केकेसी सदस्य भी शामिल थे।

बीआरसी की रिपोर्ट

युद्ध ऑपरेशन प्रचंड के बारे में:

2016 के जुलाई महीने में ''घेराव व विनाश करो'' के नीति के तहत एक केन्द्रीय नेतृत्व एवं पीएलजीए की इआरबी कम्पनी के योद्धाओं के खिलाफ सरकार की ओर से युद्ध अभियान चलाया गया, इस युद्ध अभियान का नाम ऑपरेशन ''प्रचंड'' रखा गया था। झारखण्ड, छत्तीसगढ़ सीमांत क्षेत्र में झारखण्ड के लातेहार व गढ़वा जिले तथा छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिला के बुढ़ा पहाड़ पर अवस्थित बुढ़ा गांव व उसके सटे जोंकपानी को केन्द्रित कर यह अभियान चलाया गया।

यह अभियान एरिया स्तर के एक लोकल स्कवाड के भानु नामक व्यक्ति के गत जून में पार्टी छोड़कर भाग खड़े होने तथा कुछ ही दिनों के बाद आत्मसमर्पण कर विकास के गद्दार बन जाने के तुरंत ही उपरांत यह ऑपरेशन शुरू किया गया, इनके जरिए दुश्मन को हमारी कमजोर शक्ति करीब 30-40 की संख्या, इसके पहले के अभियान में हम लोग किस दिशा में स्थित पहाड़ी पर रिट्रीट किये थे और बुढ़ा गांव के किस पानी प्वाइंट का इस्तेमाल किये थे तथा कौन-कौन रास्ता पर माईनिंग किया हुआ है, इसके बारे में दुश्मन को आसानी से ठोस से ठोस रिपोर्ट मिल गया था। क्योंकि भानु और विकास दोनों यहीं से भागा था। भानु के बारे में तो हमें जानकारी मिल गई थी, लेकिन विकास के आत्मसमर्पण की जानकारी तब तक हम लोग को नहीं मिली थी। विकास के गद्दार बन जाने के उपरांत तुरंत ही यह ऑपरेशन शुरु किया गया।

विकास के आत्मसमर्पण करने के बाद आनन-फानन में तुरंत ही सरकारी ऑपरेशन कमाण्ड में पूरे आत्मविश्वास के साथ युद्ध अभियान चलाने की योजना बनाई। उन्होंने एक प्रकार का बटालियन ऑपरेशन चलाया, लगभग तीन बटालियन फोर्स लगाया गया था। जिसमें अग्रिम मोर्चे पर हर बार की तरह इस बार भी सीआरपीएफ का कोबरा बटालियन था। इस आभियन में दुश्मन ने ''हाक लगाओ-घात लगाओ'' लड़ाई के तरीकों का अनुसरण किया।

ऑपरेशन प्रचंड गत 6 जुलाई से प्रारम्भ कर 17 जुलाई तक यानी 12 दिनों तक चलाया। हम लोग पूर्व की तैयारी के साथ जोंकपानी में ही थे। गत 9 जुलाई के दोपहर होते न होते पिपरदाब और पूंदाग में बारी संख्या में फोर्स का आगमन हो चुका था। जिसमें झारखण्ड के अलवा छत्तीसगढ़ के फोर्स भी शामिल थे। उसी दिन दोपहर बाद पिपरदाब के फोर्स का एक हिस्सा अपने कैम्प के नजदीक आकर टेन्ट गिरा दिया। लेकिन हमारा एक साथी किसी काम से उधर गया हुआ था कि अचानक उससे देखा-देखी हो गया लेकिन कोई इनकाउंटर नहीं हुआ। फिर थोड़ी देर के बाद पूंदाग में भी भारी संख्या में फोर्स आ जाने की हमको सूचना दी गई चूंकि हम लोग पहले से ही दुश्मन के हमले का मुकाबला करने के लिए तैयारी किये हुए थे। इस लिए रात भर विभिन्न प्रकार की युद्ध सामग्री सहित अन्य साथियों को व्यवस्थित करने तथा सुबह दुश्मन के हमले का मुकाबला करने के लिए अलर्ट रहने का आवश्यक निर्देश दिया गया।

दुश्मन द्वारा हमला गत 11 जुलाई की सुबह 5:30-5:45 बजे शुरू हुआ, दुश्मन ने माईनिंग वाले सारे रास्तों को काटते हुए दूसरे साइड से आकर हमला किया। पहले घंटे दुश्मन रॉकेट सहित विभिन्न हथियारों से गोले दागता रहा, अंत में फायरिंग का बौछार करने लगा। हमारे बहादूर योद्धा अत्यंत साहस व धैर्य का परिचय देते हुए दुश्मन को दृढ़ता से क्लामोर माइंस व फायरिंग से जवाब देते रहे, इतना नहीं दोनों ओर ग्रेनेड लांचरों से कई गोले दागे गए और वे गोले दुश्मन के बीच में ही गिरे, लेकिन दुर्भाग्यवंश एक भी ग्रेनेड विस्फोट नहीं किया। कारण स्पष्ट है, पॉईन्ट टूटू व पलिता का फेल होना। करीब 2:30 बजे तक मुठभेड़ चली, इसी दौरान कोबरा का एक जवान मारा गया, और एक दूसरा जवान घायल हुआ, जो समाचार में भी आया। इन दोनों को बूढ़ा गांव से ही हेलिकॉप्टर से उठा कर ले गया। बाद में पता चला कि उनके अपने ही रॉकेट के गोले के असर से उनके सपोर्ट वाली टुकड़ी के दो या तीन सिपाही घायल हो गये थे। जिसे टांगकर पिपरदाबा ले गया। फिर वहां से उन्हें हेलिकॉप्टर से रांची ले जाया गया। यह खबर कोई समाचार में नही आया। इस प्रकार दुश्मन के मरने वालों की संख्या तो एक रही लेकिन घायलों की संख्या चार या पांच हो गई थी। हमारे तरफ से भी एक साथी घायल हो गये थे, लेकिन उन्हें अपने सामान्य ट्रिटमेंट की बदौलत करीब-करीब ठीक कर लिया गया।

गत 11 जुलाई लड़ाई के उपरांत दुश्मन ने आगे बढ़ने का साहस नहीं किया, हम लोग भी इधर-उधर जगह बदल कर 11 तारीख की रात वहीं गुजारे, फिर 12 तारीख के शाम को ही बुढ़ा गांव में स्थित दुश्मन के नजदीक दूसरे दिशा से जाकर एक माईन और क्लोमोर विस्फोट कर वापस चले आये। थोड़ी देर के बाद दुश्मन द्वारा एक तरफ अंधाधुंध गोला-गोली का बौछर शुरू हो गया। दुश्मन को डाईभर्ट करने के लिए दूसरे दिन 13 जुलाई को शाम में जोंकपानी जाकर स्पेशल ऑफेंस टीम पुनः वही काम किये, यानी एक क्लेमोर और एक माइन विस्फोट कर वापस चल आया। इसके कुछ ही देर के उपरांत दुश्मन एकतरफा ढंग से गोला-गोली बौछार करने लगा।

दुश्मन को भटकाने के लिए वाकी-टॉकी के जरिए यह भी संदेश देने की कोशिश किया गया कि जोंकपानी में विभिन्न जगहों पर बुबी ट्रैप भी लगा हुआ है। हालांकि सच्चाई यह भी है कि सिर्फ एक स्थान पर बुबी ट्रैप लगा हुआ था। 14 जुलाई को दुश्मन की दूसरी बैच बुढ़ा गांव से वापस पूंदाग चला गया। पुनः 15 तारीख को फोर्स की दूसरी टुकड़ी बुढ़ा गांव आ गई। 15 जुलाई को ही रॉकेट और गोला सहित उसको हैण्डिल करने वाला स्पेशल टीम एक हेलिक्पटर से पिपरदाबा पहुंचा और वहीं से रात्रि 10:30 बजे से 12 बजे तक रॉकेट से अंधाधुंध गोला दागता रहा, गोले का निशाने का मुख्य केन्द्र जोंकपानी ही था। लेकिन कई गोले दूर-दूर तक इधर-उधर भी गिराये गए। कुछ गोले हमलोग के पास भी गिरे, लेकिन हमलोग पत्थर के कवर में सुरक्षित रहकर गोले गिनने का प्रयास करते रहे, सिर्फ रॉकेट का करीब 75-80 गोले 15 जुलाई की रात में गिराया गया, गत 16 जुलाई से दुश्मन वापस जाने लगा। गत 17 जुलाई को ऑपरेशन समाप्त हो गया।

इस पूरी लड़ाई के दौरान अनुमानतः दुश्मन की तरफ से 1200 से 1400 तक गोलियां दागी गई होगी। और विभिन्न किस्म की सवा दौ सौ से 250 गोले दागे गए। इस अभियान में दुश्मन द्वारा तीन हेलिकॉप्टर इस्तेमाल किया गया। प्रतिरोध के दौरान हमारे तरफ से 91 गोलियां 6 क्लेमोर और माईन कारगर रूप से इस्तेमाल किया गया।

इस ऑपरेशन में सटीक रिर्पोट पर आधारित होकर दुश्मन के ऑपरेशन कमाण्ड ने बड़े ही आत्मविश्वास और मनोबल के साथ ऑपरेशन प्रचंड के नाम से हम लोगों के उपर हमले की योजना बनाई थी और सचमुच यह हमारे लिए नुकसान पहुंचाने व आतंकित करने वाल एक भीषण योजना थी, लेकिन पूरी लड़ाई में छोटी शक्ति में होने के बावजूद हमारे नये व पूराने सभी योद्धाओं के हौसले बुलंद रहे। हमारे पीएलजीए के बहादूर योद्धाओं ने सही सुझ-बूझ, साहस, शौर्य और नये-नये कला कौशल का प्रदर्शन करते हुए तथा कम से कम गोली बम का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन की अत्यंत ही खतरनाक योजना को जिस तरह शानदार तरीके से विफल किया है, वह अत्यंत ही सराहनीय व प्रशंसनीय है। दुश्मन आया था हमारे पीएलजीए के उपर आंतक पैदा करने के लिए, लेकिन उल्टे पीएलजीए ने दुश्मन के आंतक को युद्ध के साथ वापस कर दिया। हमारे पीएलजीए के लोगों ने एक के बाद एक चाल चल करके इस बात के लिए भ्रमित व आतंकित किये रखा कि वे अंत-अंत तक जोंकपानी में ही डटे हुए है। साथ-साथ विभिन्न जगहों पर बुबी ट्रैप लगाये हुए हैं। फलस्वरूप दुश्मन जोंकपानी में उतरने का साहस नहीं किया। हम सभी लोगों को दो बात का अफसोस रह गया, पहला तो यह दुश्मन माईन पर नही चढ़ा तथा दूसरा ग्रेनेड का विस्फोट नहीं हो सका और ऐसा नहीं होने से दुश्मन भारी नुकसान उठाने से बचा गया।

लौटते वक्त दुश्मन बल काफी आतंकित हताश-निराश और थका हुआ था। उस दौरान भी हमला करने का अच्छा अवसर था। लेकिन जरूरी सशस्त्र बल का अभाव हमें कदम उठाने में अक्षम बनाये हुआ था। 17 जुलाई को ऑपरेशन समाप्त हुआ। इस ऑपरेशन के दौरान बुढ़ा गांव की आम जनता के उपर पुलिस वालों ने जुल्म व अत्याचार ढाहने का एक से एक मिशाल पेश किया। ऑपरेशन के दौरान 3 ग्रामीण युवकों क्रमशः चन्दन यादव, जितेन्द्र किसान, तथा जगदीश किसान को पुलिस वालों ने अपने साथ रखा। उनके साथ वे बार-बार लाठी से पिटाई, पत्थर से कुंचाई और छुरी से कटाई का बुरा बर्ताव करते रहा। गांव के एक दूसरे बीमार युवक को बुरी तरह से इतनी पिटाई की गई कि अभी भी उसकी हालत खराब है। इस प्रकार कुल 11 ग्रामीण युवकों व बुढ़ों की पिटाई के साथ उनके साथ बूरा बर्ताव किया गया। इतना नहीं आम महिलाओं के साथ लप्पड़-थप्पड़ और गाली-गलौज जैसा दुर्व्यवहार किया गया। हर बार की तरह इस बार भी दमनकारी पुलिस निहत्थी असहाय व निरीह गरीब जनता पर निर्लज्जतापूर्वक कितनी बहादूरी दिखाती है तथा उनके प्रति

कितना क्रूर से क्रूर रवैया अपनती है, एक बार पुनः साबित कर दिया।

दुश्मन के खुफिया नेटवर्क को ध्वस्त करने हेतु पीएलजीए जवाबी अभियान

2016 के 16 जुलाई को जगह बदलकर हमलोग दूसरे जगह ठहरे हुए थे। इस संभावना को देखते हुए कि हमलोग कहां हैं, इसको पता करने के लिए दुश्मन फिर किसी एजेंट को हमारे पास भेज सकता है। इधर सभी साथियों को इसके लिए अलर्ट कर दिया गया था कि यदी कोई व्यक्ति आये उसे रोक लेना है और इसी तरीके से उससे पूछताछ करनी है। यह संभावना सच साबित हुआ। गत 18 जुलाई को दुश्मन द्वारा भेजा हुआ एक एजेंट आ पहुंचा, उसे भंडारिया का डीएसपी ने निर्देश देकर भेजा था। पहला कि जोंकपानी से लेकर बुढ़ा पहाड़ तक हमलोगों के बारे में पता कर रिर्पोट देने के लिए तथा दूसरा माओवादी पार्टी के किसी नजदीकी आदमी को माध्यम बनाकर कम्पनी के अन्दर भर्ती होकर कोवर्ट की भूमिका निभाने का और उसे यह भी कहा गया था की कॉ. साकेत, कॉ. मृत्युंजय तथा कामरेड अरविन्द की मौका मिलते ही हत्या करके भाग आओ। जहर देकर हत्या करो, चाहे गोली मारकर, आने हेतु उसके लिए एक मोबाइल की व्यवस्था भी कर दी गई थी। इसके लिए उसे काफी पैसा प्रलोभन भी दिया गया था। इस काम के लिए डीएसपी ने तीनों का फोटो भी दिखाया था। वह आदमी सनेया का रहने वाला सत्यनरायण यादव उर्फ जटू था। जटू जब यहां पहुंचा, तो साथी लोग रोक लिए और जांच किये तो कुछ दवा के साथ एक मोबाइल मिला, बाद में टॉर्चर और इन्टरोगेशन के बाद उसने सारी सच्ची कहानी उगल दिया। स्थानीय तौर पर मुखबिरी करनेवाले कई लोगों का नाम बताया। जटू के द्वारा जब दुश्मन के कुछ स्थानीय नेटवर्क का खुलासा हुआ, तो यहा हमलोगों ने फैसला लिया कि इस नेटवर्क को ध्वस्त करने का हमें भी जवाबी अभियान चलाना चाहिए। तब से हम लोग इस काम में लग गए।

प्रित यादव पार्टी के एक स्थानीय कार्यकर्ता था, वह बलरामपुर जिला (छत्तीसगढ़) के सामरिक थाना अंतर्गत पूंदाग गांव का निवासी है। पैसे और नौकरी के प्रलोभन में आ करके उसके बेटों ने आत्मसमर्पण करने का दबाव बनाया। दबाव में आकर आज से दो साल पहले आत्मसमर्पण कर दिया था। उसके कुल पांच बेटे में से दो छोटे-छोटे बेटे हैं। शेष उसके तीनों बेटे पुलिस का विश्वस्त दलाल बना हुआ था। उन तीन बेटों में से सबसे बड़ा बेटा श्रवण अपनी मां और अन्य छोटे-छोटे अपने भाईयों के साथ पूंदाग में रह रहा था, लेकिन अन्य दो बसंत और हिरालाल बड़गढ़ थाना के डिपाटोली में रह रहा था, जो बरकोल पिकेट से करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर है। अभी जो अभियान चला, उसमें हिरालाल प्रत्यक्ष रूप से उन लोगों के साथ शामिल था। जबकि इनडायरेक्ट रूप से श्रवण और बसंत भी लगातार सूचना देने का काम कर रहा था। जटू इनलोगों के ट्रैक्टर का ड्राइवर था। बंसत ही इसको मुखबिर बनने के लिए तैयार कर डीएसपी के पास ले गया था। यह तीनों भाई अन्य लोगों को भी मुखबिर बनाने के काम में लगा हुआ था। शिवलाल यादव को भी इन लोगों ने ही मुखबिर बनाया था जो गारू थाना भौरा बांध घाघर टोला गांव के थे।

24 जुलाई की आधी रात के बाद करीब 1:30 बजे डिपाटोली में श्रवण यादव का सफाया किया गया। फिर वहां से जाकर टेड़ही गांव से पकड़कर राजा बांध ले जाकर सुबह 5 बजे हिरालाल यादव, शिवलाल यादव को सफाया किया गया। इसके कुछ रोज पहले पूंदाग में ही श्रवण यादव को पकड़कर टॉर्चर कर पूछताछ किया था, लेकिन उसी समय पूंदाग गांव की जनता और उसकी मां ने पार्टी से यह वादा करते हुए श्रवण को बचा ली थी कि तुरंत सभी लोगों को यानी हिरालाल, बंसत को बुलाकर रखेंगे, लेकिन ऐसा करने के बजाय उसकी मां श्रवण और दो छोटे-छोटे बच्चों को लेकर वहीं भाग गई।

ऐसी स्थिति में ही वहां जाकर उनलोगों का सफाया करना पड़ा। जहां सफाया किया गया, वह जगह दुश्मन अपना सेफ जोन मानता है, क्योंकि घटनास्थल चार बेस कैम्पों के बीच में स्थित है। पुनः 5 अगस्त को पूंदाग में जन अदालत किया गया, जिसमें चूनचूना की जनता भी शामिल थी जिसमें छः लोगों को बुलाया गया जिसमें तीन लोगों पर स्पष्ट रूप से मुखबिरी करने का अरोप था। जन अदालत में उन लोगों ने स्वीकर भी किया। अंततः उन तीनों को अंतिम चेतवानी देकर छोड़ दिया गया। शेष तीन लोगों पर संदेह था। इसलिए उन तीनों लोगों को भी समझाते हुए आरोप से बरी कर दिया गया। जन अदालत में महिला पुरूष 250 लोग शामिल थे। जिन लोगों पर कारवाई की गई, उस कारवाई को भी लोगों ने स्वीकार किया। उन लोगों को लोगों ने काफी फटकार लगाया

था। वहा गांव कमेटी की भी बैठक हुई, इसी प्रकार बुढ़ा गांव, पिपरदाब, चूनचूना इन सभी गांवों में मुखबिर गद्दार विकास और भानु के सवालों पर केन्द्रित कर गांव कमेटियों व जनता की बैठक की गई।

दिनांक 22/11/2016 को फॉलोरेश खड़िया ग्राम -बोड़ाडीह, थाना पालकोट, जिला गुमला एवं नन्दलाल सिंह ग्राम बसलापानी, थाना पालकोट, जिला गुमला का सफाया किया गया, जो एसपीओ व शान्ति सेना का सक्रिय सदस्य होने और हमारे पीएलजीए दस्ता का कई बार पुलिस को खबर करके धोखा देने व घेरवाने का काम किया था और कामरेड आशीष दा को इन्काउंटर में घेरवाकर हत्या करवाने में भी इन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इन दोनों लोगों को हमारे पीएलजीए की एक छोटी टुकड़ी के द्वारा पकड़कर पूछ-ताछ करने के बाद सफाया किया गया।

दिनांक 6/11/2016 को सुगम्बर उरांव ग्राम तोंजो सेमरटोली, थाना-घघरा, जिला गुमला का सफाया किया गया, जो जेजेएमपी का सक्रिय सदस्य व दुश्मन का खुफिया नेटर्वक एसपीओ का सदस्य भी था। जिसे हमारे पीएलजीए द्वारा पकड़कर पूछ-ताछ करने के बाद सफाया किया गया।

दिनांक 11/12/2016 को रसूल अंसारी ग्राम-लूटो, पंसो थाना, जिला गुमला का सफाया किया गया, जो खुंखार एसपीओ व जेजेएमपी का सक्रिय सदस्य था, जो बाजारों से छोटे-छोटे सब्जी विक्रेताओं से व मवेशी व्यापारियों से पैसा वसूली कर जेजेएमपी गिरोहों के पास जमा करता था। बाजार व अन्य जगहों में आने जाने वाले लोगों से पार्टी के बारे में जानकारी लाना और सीधे दुश्मन को बताने का काम करता था। निर्दोष ग्रामीण आम जनता को भी पुलिस से मार-पीट करवाता था। इसे हमारे पीएलजीए के कामरेडों ने रास्ता में एम्बुश कर पकड़ लिया और पूछ-ताछ कर मेन रास्ता में ही सफाया कर दिया। जिसके बाद उस क्षेत्र की जनता ने राहत की सांस ली है।

दिनांक 19/3/2017 को चरकू यादव उर्फ संदीप यादव ग्राम- जोरी, थाना घघरा, जिला गुमला का सफाया किया गया, जो जेजेएमपी व पुलिस के लिए काम करता था। जिससे हमारे पीएलजीए के द्वारा कई बार चेतावनी देते हुए सुधारने का मौका भी दिया लेकिन सुधार करने के जगह और बढ़-चढ़कर पुलिस व जेजेएमपी के लिए काम करना शुरू किया। चरकू यादव दिखावे के पारा शिक्षक भी था। हमारे प्रभाव वाले क्षेत्रों से बाजार व अन्य कामों से आने-जाने वाले हर ग्रामीणों के साथ पार्टी संगठन की जानकारी लेने के मकसद से पूछ-ताछ करना और वैसे संधिग्ध व्यक्ति मिलने से पुलिस व जेजेएमपी गिरोह से मार-पीट करवाना, इसका मुख्य पेशा था। एसपीओ व गिरोह का काम करने के चलते घर-द्वार छोड़कर थाना पिकेट में ही शरण लिया था। जिसकी तलाश हमारे पीएलजीए के कामरेड लम्बे दिनों से कर रहे थे। जो अखिकर हमारे पीएलजीए के हाथों पकड़ा गया और पूछ-ताछ करने के बाद ग्रामीणों के आने-जाने के मुख्य मार्ग पर सफाया किया गया। जिससे दुश्मन व एसपीओ वर्गो के अन्दर हड़कंप मचा हुआ है।

दिनांक 18/3/2017 को झुतरा लोहरा ग्राम लोटवा, थाना पालकोट, जिला-गुमला जो एसपीओ व पीएलफआई गिरोह के लिए काम करता था। जिसे हमारे पीएलजीए के द्वारा सफाया किया गया ।

दिनांक 25/5/2016 को एसपीओ एतेश्वर उरॉव का सफया किया गया, ये पेशेवर रूप से दलाल था। पुलिस को कई महत्वपूर्ण सफलता दिलवाया था, इससे पुलिस अधिकारी खुश होकर ग्राम-आंजन में जनवितरण प्रणाली का दुकान दिलवाया था। ये 14-15 साल से पेशवर दलाली का काम करता था। एसपीओ बनने से पहले ये गुण्डा गिरोह झारखंड जन मुक्ति मोर्चा का सक्रिय सदस्य था।

दिनांक 9 अक्टूबर 2016 को ग्राम सिविल थाना चैनपुर के संजिता कुमारी का सफाया किया गया, यह लड़की साधारण पुलिस अधिकारी से लेकर डीजीपी तक से मिली हुई थी। सशस्त्र खुफिया गिरोह जेजेएमपी के कमाण्डरों से भी इसका गहरा संबंध था एवं हमारे पीएलजीए के साध रण सदस्यों, कमाण्डर से लेकर सैक स्तर के नेतृत्व सदस्य तक गहरा संबंध रखती थी। यह दुश्मन को हमारी गतिविधि के बारे में पल-पल का रिपोर्ट देती थी। अमर शहीद कामरेड सिलवेस्टर की हत्या कराने में इसकी मुख्य भुमिका थी। एक सैक सदस्य को भी गिरफ्तार करवायी और एक बार कम्पनी के उपर भी हमला करवायी थी।

दिनांक 30/5/2016 को जैप के स्पेशल ब्रांच का अधिकारी बद्रीनाथ तिवारी उर्फ विनोद तिर्की का सफाया किया गया। यह डालटेनगंज का रहने वाला था। इन्हें झारखंड सरकार गुमला जिला के चैनपुर प्रखण्ड के अंर्तगत कुरूमगढ इलाके में ड्यूटी कराता था। यह हमारे संघर्ष के अन्दरूनी गांव नवाटोली में अपना नाम बदलकर बद्रीनाथ तिवारी से विनोद तिर्की नाम रखकर एक आदिवासी उम्रदराज महिला से दूसरी शादी कर लिया था और हमारी पीएलजीए को ध्वस्त करने का काम करता था। इन्होंने अमर शहीद कामरेड सिलवेस्टर की हत्या करवाने और दो जोनल सदस्य और दो सबजोनल सदस्य को गिरपतारी करवाने में भी इनका महत्वपूर्ण भूमिका था। यह पांच-छः सालों से चैनपुर इलाके में ही काम करता था।

बीआरसी में दुश्मन के हमले की रिपोर्ट

दिनांक 21-25 अगस्त 2016 तक कोयल-शंख जोनल कमिटी की तृतीय प्लेनम भारी घेराव व दमन के बीच सफल किया गया। प्लेनम के दो माह पहले एक सैक सदस्य गद्दार बिकास पार्टी फंड का पैसा लेकर अचानक पार्टी से भाग खड़ा हुआ और दुमश्न के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। वह नेतृत्व व पीएलजीए के सफाया की बुरी मानसिकता से लातेहार में झारखंड छत्तीसगढ़ बॉर्डर में स्थित बुढ़ा पहाड़ पर हजारों की संख्या में राजकीय व केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों के साथ ईआरबी कम्पनी की एक टुकड़ी से लगातार दो दिनों तक हमला कराया व सैकड़ों गोला दागवाया। इस मुठभेड़ में हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। उल्टा इस मुढभेड़ में एक कोबरा का जवान मारा गया और दो गम्भीर रूप से घायल हो गया। इस हार से गुस्से में आकर पुलिस बलों नें बुढ़ा पहाड़ पर स्थित गांव के ग्रामीण महिला व पुरूषों की निर्मम रूप से पिटाई व आत्याचार किया। गद्दार बिकास पूर्व से ही प्लेनम की तिथि सहित सभी योजना को जानता था व प्लेनम में ही नेतृत्व व पीएलजीए को नुकसान पहुंचाने तथा विफल करने के इरादे से दुश्मन ने इस जोन के भीतर स्थित तीन नम्बर सबजोन के पूरे इलाके व जंगलों में लगभग बीस हजार से भी अधिक की संख्या में सीआरपीएफ, कोबरा, झारखंड जगुआर सहित विभिन्न केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों को उतार कर पुलिस छवनी में तब्दील कर इलाका की घेराबंदी कर लगातार दमन अभियान चलाने लगा। इसी घेराव दमन के बीच नेतृत्व से लेकर पीएलजीए की पूरी कतार के साथियों ने लगभग एक महीना तक कठिन मेहनत व कड़ी सुरक्षा के बीच पहले से ही निर्धारित समय पर कोयल-शंख जोन का तृतीय प्लेनम सफल किया। प्लेनम सफल करने के तुरंत बाद 26 अगस्त से 1 सितम्बर तक कोयल-शंख जोन की बैठक चली, बैठक में ही सूचना मिली कि दुश्मन इलाका को पूर्ण घेराबंदी करते हुए हमारे कैम्पों की तरफ बढ़ रही है। 2 सितम्बर, 2016 को 10 बजे दिन में दुश्मन हजारों की संख्या में आकर अचानक हमला कर दिया। इस मुढभेड़ में एक .303 व एक .315 रायफल कुछ युद्ध समाग्री व खाद्य समाग्री, एक जेनरेटर सहित अन्य सामान दुश्मन के हाथ लग गई। उसके दूसरे दिन 3 व 4 सितम्बर को पीएलजीए की टुकड़ियां जहां थी, उसी के निकट दुश्मन आ धमकी और हेनार गांव से सिरिस पानी जंगल व जयगीर पहाड़ में सैकडों गोला दागा तथा ग्राम कोरगी के दो भैंस चरवाहा ग्रामीण को सिरिस पानी जंगल मे माओवादी होने के संदेह पर जमकर पिटाई किया और चाकू से पैर काटकर खून जांच किया।

13 जनवरी 2017 को झारखंड-छत्तीसगढ़ की सीमा पर बुढ़ा पहाड़ में हमारे पीएलजीए बलों के उपर हजारों की संख्या में आकर दुश्मन द्वारा हमला किया गया, इसके जवाबी हमला में हमारे पीएलजीए बलों ने जवाबी करवाई व बुबी ट्रैप की मदद से कोबरा बटालियन के दो अफसर एक हवलदर के अलावा दो दारोगा और एक कांस्टेबल को घायल किया गया। इसमें दुश्मन का एक कुत्ता भी मारा गया। दुश्मन मार खाने के बाद लगातार तीन दिनों तक गोला-बारी करता रहा।

दिनांक 26 अक्टूबर, 2017 को बुढ़ा पहाड़ स्थित हमारे पीएलजीए के सैनिक कैम्प पर हमला किया गया, जिसमें दुश्मन हमारी पीएलजीए बलों को भारी पड़ता देख दुम दबाकर भागता रहा, जिसे हमारे पीएलजीए योद्धाओं ने पीछा करते हुए दिनांक 28 अक्टूबर, 2016 को पलटवार हमला किया, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ।

मध्य जोन में एसपीओ का सफाया

दिनांक 27/1/2017 को संजय सिंह भोक्ता उर्फ लक्ष्मण का सफाया किया गया। संजय भोक्ता पार्टी में सबजोनल स्तर का था। यहां रहते हुए टीपीसी एवं पुलिस के लिए काम कर रहा था। 27 मार्च 2013 को लकड़मंदा घटना में भी वह शमिल था। टीपीसी द्वारा बंधक बनाकर छोड़ा गया था। तभी से इसके अंदर गिरावट देखा जा रहा था। परमजीत के भागने के बाद ये भी प्लानिंग के तहत पार्टी को नुकसान देने के फिराक में था तथा टीपीसी के रघु भोक्ता से बराबर सम्पर्क रखता था तथा सूचना दे रहा था। 7 जनवारी 2017 को पुलिस के साथ मुठभेड़ भी करवाया था।

दिनांक 13/3/2017 को कौशल पासवान ग्राम-महुरॉव, थाना- डुमरिया, जिला- गया (बिहार) का सफाया किया गया एव सर्वेस पासवान उर्फ पिन्टु पासवान (पूर्व में सीसी इन्सट्रक्टर) भी घायल हुआ । ये दोनों टीपीसी एवं पुलिस के लिए काम कर रहे थे। इमामगंज में रहकर अपना नेटर्वकिग चला रहा था तथा अभियान में पुलिस के साथ रहता था।

मौजूदा समय के लिए कुछ जरूरी नारे

★ पार्टी के अंदर पनपे आत्मसमर्पणवाद तथा वर्ग-आत्मसमर्पणवाद के रूझान का तीव्र विरोध करें!

★ आत्मसमर्पणवादी विचार शोषक-शासकों की गुलामी कर जिंदगी बिताने का विचार है। अतः इससे घृणा करें, विरोध करें!

★ दुश्मन की एल.आई.सी. (कम तीव्रतावाला युद्ध) नीति के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं को शोहरत व दौलत तथा शराब व औरत के जरिए आचरण भ्रष्ट करने के नापाक इरादे को पूरी तरह विफल कर दें!

★ आत्मसमर्पण करवाने खातिर रूपए-पैसे का लोभ-लालच देने की प्रतिक्रियावादी एल. आई.सी. नीति को घृणा के साथ ठुकरा दें, इन्कार कर दें!

★ आत्मसमर्पण का मतलब ही है दुश्मनों के पैर चाटनेवाला कुत्ता की भूमिका पालन करना!

★ आत्मसमर्पण करनेवाले मुट्ठीभर अधःपतित, भ्रष्ट व गद्दार तत्वों का जन-अदालत में विचार करें, सजा दें!

★ दुश्मन के पैर चाटनेवाले कुत्ता बनकर पार्टी, क्रांति व जनता की भारी क्षति करने वाले गद्दार दिनेश, विकास, नकुल, कुन्दन, राहुल, कान्हू मुण्डा इत्यादि गद्दार तत्वों को जनता के दुश्मन के रूप में प्रचार करें, जनअदालत में विचार कर उचित दण्ड दें!

★ पार्टी-क्रांति व जनता के साथ गद्दारी करनेवाले गलत आदमियों को गद्दार के रूप में खुली घोषणा करें, जनता से अलग-थलग करें!

★ आत्मसमर्पण करने का अर्थ ही है, साम्राज्यवाद-सामंतवाद व दलाल नौकरशाह पूंजीपति तथा कॉरपोरेट घराने का शोषण-जुल्म व अत्याचार को बरकरार रखना व मौजूदा जुल्मी व्यवस्था को टिकाए रखना!

ऐतिहासिक महान नक्सलबाड़ी सशस्त्र किसान संघर्ष की 50वीं वर्षगांठ पर भाकपा (माओवादी) के बीजे सैक द्वारा जारी पोस्टर